https://t.me/AllNewsPaperPaid

# पार्टी चलती रहती है

**आप के केजरीवाल लगातार आश्चर्यचकित कर रहे हैं, साथ ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी रेखांकित कर रहे हैं**

टी आम आदमी पार्टी (आप) अपने समर्थकों और विरोधियों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है, लेकिन एक बात जो अब इसके नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में पूर्वानुमानित हो गई है, वह है तमाशा खड़ा करने की उनकी जन्मजात क्षमता। ताजा घटनाक्रम में, श्री केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह आप मंत्री आतिशी को चुना है। भ्रष्टाचार के आरोपों में श्री केजरीवाल के लंबे समय तक जेल में रहने के दौरान सुश्री आतिशी कई विभागों का कार्यभार संभाल रही थीं। श्री केजरीवाल जेल में रहने के दौरान भी मुख्यमंत्री बने रहे, जिससे एक नई मिसाल कायम हुई और उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। श्री केजरीवाल को भ्रष्टाचार की जांच के आधार पर केंद्रीय एजेंसियों ने घेर लिया था - ऐसा आचरण जिस पर न्यायालय ने नाराजगी जताई है। अपने अचानक कदम और अपने चुने हुए समय के साथ, श्री केजरीवाल अब दिल्ली और उसके बाहर की राजनीति की दिशा बदलने और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले तीन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि दो विधानसभा चुनावों में आप ने लगभग सभी सीटें जीती हैं, जो दोनों पार्टियों के बीच एक दूसरे से जुड़े राजनीतिक आधार को दर्शाता है। आप भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गई है, और भाजपा को उम्मीद है कि भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में शामिल होने के आधार पर चुनाव में इसकी गति धीमी हो जाएगी।

श्री केजरीवाल का यह दावा कि वे भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, राजनीति में उनके नाटकीय उत्थान में सहायक रहा है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि वोट सस्ती या मुफ्त सेवाओं के वितरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दिल्ली के लिए भाजपा की रणनीति में आप के भ्रष्टाचार विरोधी दावों को कमज़ोर करना और उसकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की क्षमता को सीमित करना शामिल है। श्री केजरीवाल की जमानत शर्तें उनकी शक्तियों को सीमित करती हैं और एक पूर्ण रूप से सशक्त मुख्यमंत्री फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। आप भी चुनाव को पहले ही कराना चाहती है और इसे नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ जोड़ना चाहती है। एक स्वतंत्र चुनाव के रूप में, भाजपा अपना पूरा ध्यान दिल्ली पर दे सकती है, एक ऐसी स्थिति जिससे आप बचना चाहती है। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी प्रशासक के रूप में अपनी अलग पहचान रखती हैं, लेकिन उन्होंने अपने नेता के लिए दोयम दर्जे की भूमिका निभाने का फैसला किया है, उन्होंने घोषणा की है कि जब तक पार्टी जीत नहीं जाती और श्री केजरीवाल वापस नहीं आ जाते, तब तक वह सिर्फ एक पदधारक रहेंगी। इस बीच, श्री केजरीवाल के पास राष्ट्रीय भूमिका निभाने और अब भीड़ भरे विपक्षी खेमे में नेता के रूप में उभरने की बड़ी योजनाएँ हैं।

# उचित हिस्सा

**वित्त आयोग को उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए**

ए पिछले सप्ताह तिरुवनंतपुरम में हुई बैठक में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बजट में बढ़ोतरी की मांग की थी।

करों का विभाज्य पूल 41% से - पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश - 50% तक का विभाजन, और केंद्र द्वारा उपकर और अधिभार के रूप में एकत्र की जा सकने वाली राशि की सीमा जो आमतौर पर विशिष्ट केंद्र सरकार की परियोजनाओं को निधि देने के लिए चालान पर टॉप-अप के रूप में दिखाई देती है और हस्तांतरण तंत्र के दायरे से परे है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्ध-रमैया ने भी जीएसटी ढांचे की शुरूआत के बाद से करों को इकट्ठा करने के लिए राज्यों की स्वायत्तता पर बढ़ते उल्लंघन और बेहतर आर्थिक सूचकांक वाले राज्यों को दंडित करने पर चर्चा करने के लिए विपक्षी और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने में अपनी रुचि की घोषणा करके बहस को फिर से हवा दे दी है। यह बैठक 2024-25 के केंद्रीय बजट में बेंगलुरु की उपनगरीय रेल परियोजना या केरल के विझिनजाम बंदरगाह और चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण जैसी प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटित की गई मामूली राशि की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है। बैठक को भारत भर के विभिन्न राज्यों में आई प्राकृतिक आपदाओं की पृष्ठभूमि में भी देखा जाना चाहिए, जैसे कि पिछले दिसंबर में तमिलनाडु के दक्षिणी डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़, पश्चिमी गुजरात में हाल ही में हुई भारी बारिश और केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन। कर हस्तांतरण पर सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशें अक्टूबर 2025 तक आने की उम्मीद है।

जबकि पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा भारत के गरीब क्षेत्रों के विकास के लिए कर हस्तांतरण को निर्धारित करने में राज्यों के बीच राज्य सकल घरेलू उत्पाद में अंतर को 45% का उच्चतम भार दिया गया है, इससे गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे शीर्ष कर राजस्व योगदान देने वाले राज्यों को काफी कम हस्तांतरण हुआ है। औद्योगिक और आर्थिक महाशक्तियों के रूप में, इन राज्यों को अपने विभिन्न क्षेत्रों की विशेष विकासात्मक, जलवायु और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित पूंजी और सामाजिक व्यय की आवश्यकता है।

जीएसटी ढांचे द्वारा कर संग्रह पर राज्यों पर प्रतिबंधों के अलावा, कम हस्तांतरण का मतलब यह भी है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सरकारें अपने आर्थिक और सामाजिक प्रक्षेपवक्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने हाथ बंधे हुए पा रही हैं। इसके अलावा, न तो जीएसटी और न ही वित्त आयोग ने आकस्मिक खर्चों को संबोधित किया है, जो अब पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं, ताकि चरम मौसम की घटनाओं को कम किया जा सके। भारत जैसे बड़े और जटिल देश में, जहाँ सामाजिक और आर्थिक संकेतक बहुत अलग-अलग हैं और प्राकृतिक संसाधनों और कमजोरियों का समान रूप से विविध प्रसार है, कर हस्तांतरण ढांचे में संशोधन के लिए तत्काल हस्तक्षेप का समय आ गया है जिससे राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी।

इससे वास्तविक संघीय एवं सहभागी शासन मॉडल संभव होगा।

# निकटदृष्टिता त्यागें, अंग्रेजी की प्रासंगिकता पर पुनः ध्यान केन्द्रित करें



रा. शिवा
एक अधिवक्ता
मद्रास उच्च न्यायालय और के संस्थापक
कानून और व्यवस्था के लिए नागरिक
डेमोक्रेसी (CLAD), विज्ञान को मजबूत करने के लिए एक शोध-
केंद्रित गैर-लाभकारी
संगठन
बच्चों के लिए शिक्षा



सबूर अली एम.
CLAD के सह-संस्थापक

टी अपने बच्चे/बच्चों को अंग्रेजी में बात करते देखना कई भारतीय माता-पिता का सपना है, जो बेहतर सामाजिक-आर्थिक अवसर सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं। इस व्यापक इच्छा के बावजूद, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने सात दशकों से अधिक समय तक अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को लगातार नजरअंदाज किया है।

भारत की स्वतंत्रता के बाद से, राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 जैसी शैक्षिक नीतियों का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा के प्रसार को प्रतिबंधित करना और विभिन्न क्षेत्रों में इसके महत्व को कम करना रहा है। फिर भी, अंग्रेजी की तटस्थ प्रकृति, जिसे भारत के संविधान द्वारा समानता के साधन के रूप में मान्यता दी गई है, इसकी स्थिति की रक्षा करती है, जिससे इसे राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखने की अनुमति मिलती है। प्रतिबंधात्मक नीतियों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच चल रहे इस टकराव ने आर्थिक रूप से वंचित लोगों की अंग्रेजी में दक्षता हासिल करने की क्षमता को काफी हद तक बाधित किया है, जिससे शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक नुकसान का एक चक्र जारी है। इस उपेक्षा ने सरकारी स्कूलों में हाशिए पर पड़े बच्चों को असमान रूप से प्रभावित किया है, जिससे शैक्षिक असमानताएँ गहरी हुई हैं। इसके विपरीत, अमीर परिवारों के बच्चों के पास अंग्रेजी में दक्षता हासिल करने के लिए संसाधन हैं, इस प्रकार उन लोगों के बीच की खाई चौड़ी हो गई है जो भाषा बोल सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं चिंताजनक बात यह है कि 2011 की भारतीय जनगणना से पता चलता है कि 90% आबादी अंग्रेजी नहीं बोलती है, जो एक स्पष्ट भाषाई विभाजन को उजागर करता है जो इस अंतर को पाटने में शिक्षा नीतियों की विफलता को रेखांकित करता है। हैरानी की बात यह है कि नीति में इस मुद्दे का उल्लेख नहीं है। न ही यह इसे संबोधित करने के लिए कोई उपाय प्रदान करता है।

एनईपी 2020 अंग्रेजी भाषा का अवमूल्यन जारी रखता है, इसे विदेशी भाषा करार देता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में संयोजक के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसमें आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए अंग्रेजी तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए एक परिभाषित रणनीति का भी अभाव है, जिससे इस महत्वपूर्ण शैक्षिक अंतर को पाटने की चुनौती और भी बदतर हो जाती है।

'विविधता' की आड़ में 'एजेंडा' एनईपी 2020 का त्रि-भाषा फॉर्मूला जाहिर तौर पर भाषाई विविधता को बढ़ावा देता है, लेकिन हिंदी-भारत की अवधारणा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक गहरे एजेंडे को छुपाता है, खासकर भारत में अंग्रेजी की भूमिका को कम करके। यह दृष्टिकोण न केवल उन लाखों लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत है जो अंग्रेजी को सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता की सीढ़ी के रूप में देखते हैं, बल्कि संविधान के साथ भी विरोधाभासी है, जो राष्ट्र पर किसी भी एक भाषा को थोपने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

संविधान में अंग्रेजी और हिंदी को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, तथा जानबूझकर किसी राष्ट्रीय भाषा को नियुक्त करने से परहेज किया गया है।

> सरकार को अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं के प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में बढ़ावा देने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

क्षेत्रीय भाषाओं की रक्षा करता है, जिससे एक महत्वपूर्ण संतुलन बना रहता है। यह ढांचा अंग्रेजी को एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में मान्यता देता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, व्यापार और वैश्विक संचार के लिए महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न जातीय समूहों के बीच तटस्थता सुनिश्चित करता है, जबकि यह क्षेत्रीय भाषाओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के वाहक के रूप में स्थान देता है। हालाँकि, NEP 2020 इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों की अनदेखी करके इस संतुलन को बिगाड़ने का जोखिम उठाता है।

यह कदम गलत दिशा में उठाया गया है और अंततः विफल होगा। बहुमूल्य समय और संसाधनों को बरबाद करना। यह राष्ट्र को अंग्रेजी को उस स्तर तक बढ़ावा देने के बजाय अपने अतीत की विवादास्पद भाषाई बहसों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करेगा जो क्षेत्रीय भाषाओं के सांस्कृतिक महत्व को पूरक बनाता है। इस संवैधानिक मतभेद को पहचानना भारत को ऐतिहासिक नुकसानों से दूर एक अधिक समावेशी और व्यावहारिक भाषा नीति की ओर ले जा सकता है।

1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद से, अंग्रेजी की मांग में उछाल आया है, जो वैश्विक कथन के साथ मेल खाता है कि "दुनिया कहाँ है"। इसका मतलब है कि अंग्रेजी में दक्षता न केवल वांछनीय है, बल्कि भारत के आर्थिक विकास में भाग लेने और अंतरराष्ट्रीय अवसरों को भुनाने के लिए भी आवश्यक है। विडंबना यह है कि लगातार सरकारों ने इस बदलाव को नजरअंदाज किया है, इसके बजाय क्षेत्रीय और राष्ट्रवादी भाषा नीतियों से चिपके रहना पसंद किया है।

एनईपी 2020 न केवल जारी है अंग्रेजी को हाशिए पर धकेलने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी अनुपातहीन महत्व दिया जा रहा है, जिससे अनजाने में क्षेत्रीय पहचान की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है। यह दृष्टिकोण यह पहचानने में विफल रहता है कि क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और अंग्रेजी को बढ़ावा देने के बीच कोई अंतर्निहित संघर्ष नहीं है। असली मुद्दा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयासों से उत्पन्न होता है, जो आम जनता के बीच अंग्रेजी के प्रसार को रोकता है।

अंग्रेजी विरोधी रुख कोई नई बात नहीं है। स्वतंत्रता के बाद, हिंदी को भारत की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिसके कारण अंग्रेजी की भूमिका को कम करने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए गए, जबकि अंग्रेजी एक सामाजिक भाषा है। यह इस विश्वास पर आधारित था कि अंग्रेजी के विपरीत, हिंदी भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य के बीच एक तटस्थ पुल नहीं हो सकती।

अतीत से सूत्र इस पूर्वाग्रह का पता स्वतंत्रता संग्राम से लगाया जा सकता है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से हिंदी भाषी नेताओं ने किया था, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद एक एकभाषी हिंदी भाषी भारत की कल्पना की थी। पाकिस्तान के साथ विभाजन, जिसने उर्दू को समीकरण से हटा दिया, ने हिंदी पर ध्यान केंद्रित करना और भी बढ़ा दिया। इसके बावजूद, भारत की बहुभाषी वास्तविकता और समानता और भाषाई विविधता के लिए संवैधानिक प्रावधानों ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को भी एक आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखना आवश्यक बना दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा फार्मूला प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का प्रसार करना था, जिससे राष्ट्र भाषायी रूप से एकीकृत हो सके।

हालांकि, इस फॉर्मूले का विरोध किया गया, खास तौर पर तमिलनाडु से, जिसने इसे हिंदी को थोपने और अंग्रेजी की भूमिका को कम करने के रूप में देखा। एनईपी 2020, भाषा के चयन में लचीलेपन का दावा करने के बावजूद, विकल्प चुनने की आड़ में इस एजेंडे को जारी रखता है, इस प्रकार भाषा थोपने के मूल मुद्दे को संबोधित नहीं करता है।

इस नीति का व्यावहारिक कार्यान्वयन इसकी कमियों को दर्शाता है। जबकि यह भाषाओं के चयन की अनुमति देता है, बुनियादी ढाँचा और संसाधन हिंदी के प्रति अत्यधिक पक्षपाती हैं। यह न केवल वास्तविक विकल्प को सीमित करता है बल्कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के नीति के लक्ष्य को भी कमजोर करता है। सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रेरणाओं के कारण हिंदी और संस्कृत पर जोर दिया जाता है, जिससे अंग्रेजी की उपेक्षा होती है, जो भारत में व्यावसायिक, शैक्षिक और कानूनी संदर्भों में महत्वपूर्ण बनी हुई है।

व्यावहारिक बनें इसकी तुलना में, चीन जैसे देशों ने अंग्रेजी के महत्व को पहचाना है, वैश्विक आर्थिक बदलावों और अपने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए इसके अध्ययन को अनिवार्य बनाया है। यह भारत के दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है, जहां केंद्रित अंग्रेजी भाषा नीति की कमी हमारी वैश्विक आर्थिक भागीदारी और सामाजिक गतिशीलता में बाधा डाल सकती है।

इसे सुधारने के लिए, भारत को एक व्यावहारिक भाषा नीति की आवश्यकता है जो अपने नागरिकों की व्यावहारिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए अपनी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करे। एक क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को मिलाकर दो-भाषा फॉर्मूला, भारतीयों की अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए वैश्विक नागरिक बनने की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करेगा।

ऐसी नीति वैश्विक आर्थिक अवसरों में व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी भारतीय जीवन के पेशेवर, शैक्षिक और कानूनी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।

सरकार को पदोन्नति को प्राथमिकता देनी चाहिए और अंग्रेजी का विकास भारतीय भाषाओं के प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण समानता और व्यक्तिगत अधिकारों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक भाषाई बाधाओं के बिना राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग ले सके।

एक उदार लोकतंत्र के रूप में भारत को अपने नागरिकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अब समय आ गया है कि इसकी भाषा नीति इस पर ध्यान दे, तथा एक संतुलित बहुभाषी ढांचे को बढ़ावा दे जो वास्तव में सभी भारतीयों की आकांक्षाओं का समर्थन करता हो। अंग्रेजी ही भारत का समाधान है।

# विलमिंग्टन में, तात्कालिकता और विरासत का मेल



हर्ष वी. पंत
उपाध्यक्ष
अध्ययन और विदेश ऑब्जर्वर पर नीति
अनुसंधान फाउंडेशन
(ओआरएफ), नई दिल्ली



विवेक मिश्रा
साथी, अमेरिका,
पर्यवेक्षक अनुसंधान
नींव

ए काफी प्रत्याशा के बाद, नेताओं ने क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) अपनी बैठक बुलाएंगे 21 सितंबर को विलमिंगटन, डेलावेयर, यू.एस. में चौथा शिखर सम्मेलन। यह बैठक 2021 में यू.एस. राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा आयोजित पहले व्यक्तिगत क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के बाद से एक पूर्ण चक्र को चिह्नित करती है, जो इस रणनीतिक साझेदारी के निरंतर विकास का प्रतीक है। यह शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) और भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ सदस्य देशों के बीच नेतृत्व में दबावपूर्ण वैश्विक चुनौतियों और बदलावों की पृष्ठभूमि में हो रहा है।

यह बैठक तत्काल महत्व रखती है, खासकर उच्चतम स्तर पर क्वाड शिखर सम्मेलनों के पिछले स्थगन को देखते हुए। श्री बिडेन और जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा दोनों नेतृत्व परिवर्तन का सामना कर रहे हैं; श्री बिडेन ने घोषणा की है कि वह फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और श्री किशिदा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापान में संभावित हार का सामना कर रही है। ये आसन्न परिवर्तन नए नेतृत्व की गतिशीलता के उभरने से पहले क्वाड की रणनीतिक दिशा और प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने की तात्कालिकता को रेखांकित करते हैं।

भारत, जिसे मूल रूप से इस वर्ष शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करनी थी, ने विनम्रतापूर्वक इसे अमेरिका के लिए स्थगित कर दिया, और अब अगली बैठक की मेज़बानी करेगा। यह निर्णय श्री बिडेन के लिए व्यावहारिक विचारों के अनुरूप है, जिन्होंने व्यस्त चुनावी चक्र के बीच, जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की अपनी हालिया यात्रा के बाद एक और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना चुनौतीपूर्ण पाया होगा।

इंडो-पैसिफिक एकीकरण इस शिखर सम्मेलन का एक प्राथमिक लक्ष्य समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) पर क्वाड के ढांचे को मजबूत करना होगा, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी पहलों को जोड़ने में तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है। जुलाई 2024 में टोक्यो में अपनी पिछली बैठक के दौरान, क्वाड विदेश मंत्रियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता (आईपीएमडीए) के लिए इंडो-पैसिफिक साझेदारी के विस्तार की घोषणा की, जो एक रणनीतिक प्रयास को दर्शाता है।

> चौथा क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन शांतिपूर्ण और स्थिर भारत सुनिश्चित करने में प्रगति का आकलन करने का एक अवसर होगा।
>
> इंडो-पैसिफिक

इस विशाल विस्तार को व्यापक इंडो-पैसिफिक आख्यान में एकीकृत करना। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय कानूनों को मानकीकृत करना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मानदंडों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही बढ़ाना है, जिससे नियम-आधारित व्यवस्था को और बढ़ावा मिले।

जुलाई की बैठक में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया, जो कि राष्ट्रों की नौवहन की स्वतंत्रता और परिचालन क्षमताओं के लिए आधार है। इसे ध्यान में रखते हुए, विलमिंगटन शिखर सम्मेलन में क्वाड समुद्री सुरक्षा कार्य समूह के तहत क्वाड समुद्री कानूनी वार्ता की संभावित शुरुआत की संभावना पर आगे विचार किए जाने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून में विशेषज्ञता को मजबूत करना है, जो न केवल क्वाड राष्ट्रों बल्कि क्षेत्र के अन्य देशों की भी सेवा कर सकता है।

इसका मुख्य ध्यान परिचालन पर होगा भारत में स्थित सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) के माध्यम से दक्षिण एशिया कार्यक्रम। यह कदम MDA में भारत की बढ़ती भूमिका और समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ वास्तविक समय की सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करके एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। IFC-IOR, जो वर्तमान में 12 अंतर्राष्ट्रीय संपर्क केंद्रों की मेज़बानी करता है, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समर्पित देशों के बढ़ते गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रगति पर नज़र रखना, अवसरों की तलाश करना क्वाड का व्यापक एजेंडा, जो 16 कार्य समूहों में फैला हुआ है, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, मानवीय सहायता, आपदा राहत, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने की इसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। विलमिंगटन शिखर सम्मेलन नेताओं के लिए इन मोर्चों पर प्रगति का आकलन करने और नई पहलों के लिए प्रतिबद्ध होने का अवसर प्रदान करता है। एजेंडे के प्रमुख विकासों में ओपन-रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) के कार्यान्वयन की समीक्षा होगी

पलाऊ में नेटवर्क, मॉरीशस में अंतरिक्ष-आधारित जलवायु चेतावनी प्रणाली की तैनाती, इंडो-पैसिफिक द्वीपों में ओ-ग्रिड सौर परियोजनाओं की प्रगति, और क्वाड विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) समूह के उद्घाटन के परिणाम।

क्वाड एक बेंचमार्क के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद-प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए ढांचा, विशेष रूप से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में। जैसे-जैसे क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं और बुनियादी ढांचा नेटवर्क अनुकूल होते हैं, क्वाड क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर महसूस करता है। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों, रूस-यूक्रेन युद्ध और एक विखंडित विश्व व्यवस्था के बीच हिंद-प्रशांत में शत्रुतापूर्ण अभिनेताओं से खतरे बढ़ गए हैं। चीन के मुखर व्यवहार, जो अक्सर स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के बाहर होता है, ने क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा दिया है, जिससे एक एकीकृत और सक्रिय क्वाड प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा, चीन से दूर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन ने क्षेत्रीय आर्थिक लचीलेपन और जोखिम कम करने की रणनीतियों की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। क्वाड के लिए, यह बदलती गतिशीलता क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है जबकि साथ ही विविध और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से सुरक्षा को बढ़ाती है।

विलमिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन भविष्य के शिखर सम्मेलन के उद्घाटन की प्रस्तावना के रूप में भी कार्य करता है, जिसका उद्देश्य सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करके वैश्विक शासन को नया रूप देना है। कई मामलों में, क्वाड पहले से ही इन व्यापक वैश्विक आकांक्षाओं के एक क्षेत्रीय सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करता है, जो इंडो-पैसिफिक में सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देता है।

चूंकि क्वाड लगातार परिपक्व हो रहा है, यह शिखर सम्मेलन समान मुद्दों पर वैश्विक आकांक्षात्मक मानदंडों के आधार पर इसकी प्रगति का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है, जिससे क्वाड को भविष्य की पहलों के लिए आधार तैयार करने में मदद मिल सकती है।

## संपादक के नाम चिठी

**केजरीवाल का जाना**

अरविंद केजरीवाल द्वारा नई दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और अपनी मंत्री आतिशी को अपना उत्तराधिकारी चुनने में कोई आश्चर्य नहीं है (पेज 1, सितंबर 18)। यह स्पष्ट था। सुश्री आतिशी ने कई मौकों पर श्री केजरीवाल के प्रति अपनी पूरी वफादारी साबित की है। आम आदमी पार्टी का यह कदम नई दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटने और अपनी मंत्री आतिशी को अपना उत्तराधिकारी चुनने में कोई आश्चर्य नहीं है (पेज 1, सितंबर 18)। यह स्पष्ट था। सुश्री आतिशी ने कई मौकों पर श्री केजरीवाल के प्रति अपनी पूरी वफादारी साबित की है।

इसे आत्म बलिदान के रूप में चित्रित करना हमारी आँखों में धूल झोंकने का एक प्रयास मात्र है। श्री केजरीवाल हमेशा से ही फैसले लेते रहे हैं और पूरे शो को कठपुतली की तरह चलाते रहे हैं।

वृंदा राजवंशी, नई दिल्ली

यह अजीब बात है कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कहती हैं कि उनकी 'प्राथमिकता' श्री केजरीवाल को वापस लाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री. केजरीवाल भले ही उनके गुरु हों, लेकिन बेहतर होगा कि वे दिल्लीवासियों की जरूरतों पर ध्यान दें। अगर दिल्लीवासी उनके कामकाज से खुश हैं, तो इससे उनकी 'इच्छा' पूरी होने का रास्ता साफ हो जाएगा। श्री केजरीवाल को नागरिकों से ज्यादा अदालतों से 'अपनी ईमानदारी का प्रमाणपत्र' चाहिए।

ए. जैनुलाब्दीन, चेन्नई

आम आदमी पार्टी को शासन में बढ़ावा देने की जरूरत है क्योंकि उसके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कमजोर पड़ गए हैं। क्या सुश्री आतिशी नौकरशाही में नई जान फूंक सकती हैं?

अंशू भारती, बेगुसराय, बिहार

वफ़ादारी के बयान हमारे लोकतंत्र का मज़ाक उड़ाते हैं। राजनेताओं की ईमानदारी मतदाताओं द्वारा तय नहीं की जाती।

ईमानदार हैं तो दूर रहें राजनीति। अब मुद्दा चुनावी सुधार सुनिश्चित करने का है ताकि ईमानदार लोगों के लिए राजनीति में प्रवेश करना और व्यवस्था को साफ करना संभव हो सके।

एमवी नागवेंद्र राव, हैदराबाद

**हुलुनबुइर में टीम इंडिया की जीत**

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप 2024 एक रोमांचक फाइनल था और ओलंपिक के बाद से टीम के सपनों का दौर सुनिश्चित करता है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जो शानदार फॉर्म में हैं, आगे से नेतृत्व करना जारी रखते हैं, हर जीत को और भी मीठा बनाता है ('स्पोर्ट' पेज, 18 सितंबर)। क्रिकेट के दीवाने देश के लिए, इस तरह के प्रदर्शन राष्ट्रीय खेल को पुनर्जीवित करने के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए।

बी. सुरेश कुमार, कोयंबटूर



अधिक जानकारी के लिए जुड़ें-https://telegram.me/DailyPressNation

## चिंतन

# ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की राह में कई चुनौतियां भी

जनगणना, जाति गणना, परिसीमन के संकेत के बाद अब पीएम मोदी की सरकार की ओर से ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की सिफारिश वाली पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट को मंजूरी प्रशासनिक सुधार की दिशा में सरकार के इरादे स्पष्ट कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि वह जल्द ही जनगणना कराएगी। यह वर्ष 2021 से लंबित है। कोविड के चलते टाल दी गई थी। वर्ष 2026 में परिसीमन होना है, इससे पहले सरकार जनगणना करवा लेना चाहती है, इससे परिसीमन करने में मदद मिलेगी। परिसीमन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। 31 अगस्त से दो सितंबर तक केरल में चली संघ (आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की बैठक में जाति जनगणना के पक्ष में लेकिन परंतु के साथ हामी मोदी सरकार को संकेत है कि वह जाति गणना पर आगे बढ़ सकती है। चूंकि इन दिनों कांग्रेस जातिगणना की रट लगाए बैठी है, तो भाजपा नीत राजग सरकार जनगणना के साथ जाति गणना करवाकर कांग्रेस के हौव्वा की हवा निकाल देना चाहेगी। परिसीमन के बाद भाजपा अपने कोर एजेंडे में से एक वन नेशन वन इलेक्शन को भी पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक राष्ट्र एक चुनाव का राग छेड़कर संकेत दे दिया था कि अगले लोकसभा चुनाव से पूर्व यह फैसला लागू कर सकती है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लेकर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना इसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। समिति ने लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है, इसके सौ दिन बाद स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की बात कही है। मंजूरी में सरकार के घटक दलों की भी हामी है। पीएम ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लोकतंत्र को अधिक जीवंत, सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना है। कोविंद समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। उम्मीद है, विधि आयोग भी 2029 तक सरकार के तीनों स्तरों, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में एकसाथ चुनाव प्रस्तावित करेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के कई फायदे हैं तो राह में कई चुनौतियां भी हैं। भाजपा इसे इसलिए जरूरी मानती है कि इससे जनता को बार-बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी। चुनावी खर्च बचेगा और मत प्रतिशत में इजाफा होगा। देश हमेशा चुनावी मोड में नहीं रहेगा। सरकारें बार-बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। चुनाव आचार संहिता बार-बार नहीं लगेगी। देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। चुनाव की वजह से बार-बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी। रेवड़ियों की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों का समय और ऊर्जा बचेगी। एक राष्ट एक चुनाव व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे दो तिहाई से अधिक राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। कई विधानसभाओं को समय पूर्व भंग करना होगा। लागू होने के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव के क्रम को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस के आक्रामक विरोध के बाद राजनीतिक सहमति बनाना टेढ़ी खीर होगा। क्षेत्रीय दल नुकसान के भय से इसके विरोध में रहेंगे। नए ईवीएम व वीवीपैट का इंतजाम करना होगा। एक मतदाता सूची व एक मतदाता पहचान पत्र बनाने होंगे। सुरक्षा बलों की अधिक जरूरत होगी। देश में 1952, 1957,1962 व 1967 में एक साथ चुनाव हुए थे। 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी सालाना रिपोर्ट में एक साथ चुनाव की सिफारिश की थी। 1999 में विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव करवाने की जरूरत याद दिलाई थी। विधि आयोग ने ही 2018 में एक मसौदा रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिस पर मोदी सरकार ने 2023 में कोविंद समिति का गठन किया था। 2024 के आम चुनाव में भाजपा ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया। देखने वाली बात होगी कि सरकार संवैधानिक, प्रशासनिक व राजनीतिक चुनौतियों को पार करती हुई इस एजेंडे को कब से लागू करती है।

## धर्म-कर्म

शकुन्तला देवी



# पितृ पक्ष की महत्ता मात्र श्राद्ध और तर्पण तक सीमित नहीं

सभी तरह के कर्तव्य-कर्मों को धर्म बताया गया है। श्राद्ध और तर्पण भी कर्तव्य-कर्म के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इससे पितर तृप्त या संतुष्ट (प्रसन्न) होते हैं। सनातन परंपरा में इंसान की कई श्रेणियां बताई गई हैं। जो बगैर किसी स्वार्थ से कार्य करता है, वह देवता कहलाता है। जो अपने स्वार्थ के साथ दूसरे के स्वार्थ को भी साधता चलता है, वह मानव है। इसी तरह जो अपने स्वार्थ की वजह से दूसरे के स्वार्थ का नाश करता है, वह राक्षस कहलाता है और जो बगैर किसी स्वार्थ के दूसरों को सताने में सुख का अनुभव करता है, वह पिचास कहलाता है। जो पितर के लिए अपना कर्तव्य करते हैं वे सच्चे मायने में इंसान हैं। इसलिए श्राद्ध और तर्पण महज कर्मकांड नहीं हैं। इसके पीछे पारिवारिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी लगे हुए हैं। पशु-पक्षियों, दीन-हीन, विधवा और अपंग को भोजन और दान करना इस उत्सव की पहचान है। दान उसे करना चाहिए जिसे देने से लेने वाले का हित हो और देने वाले का भी हित हो।

दरअसल, श्राद्ध और तर्पण के बारे में इने-गिने लोगों को वेद और शास्त्रों के विधान मालूम हैं। इसलिए लोग महज पंडित को दान देने और गया में जाकर पिंडदान करना ही इस कर्मकांड का हिस्सा समझते हैं। जबकि यह पौराणिक परंपरा है। वैदिक परंपरा में जिंदा माता-पिता और बड़ों की सेवा और उनकी जरूरतों को पूरा करना ही श्राद्ध और तर्पण कहा गया है। संस्कृत भाषा में पितृ शब्द है जिसका मायने पिता होता है। यानी पालन व रक्षण करने वाला। परिवार के उन लोगों के लिए यह नहीं है जो अब परिवार में सशरीर नहीं हैं। वक्त जैसे-जैसे गुजरता जाता है वैसे वैसे अच्छी और उपयोगी ज्ञान व परंपराएं भी कर्मकांड बन जाती हैं। ऐसा ही कर्मकांड पितृ पक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध और तर्पण हैं। यह कर्मकांड आज के दौर में पितृ पक्ष पर महज बाल बनवाने, पंडित को दान देने, हवन और पक्षियों को दाना या चारा देने तक सीमित हो गया है। पौराणिक परम्परा में क्वार (अश्विन माह) में श्राद्ध और तर्पण का विधान कर्मकांड के रूप में किए जाने की परम्परा है। इसमें दिए गए दान और भोजन का हिस्सा परलोक में जाकर भी मिलने की बात कही गई है। यह महज कल्पना ही है, इसमें कोई वैदिक विधान नहीं है। वैदिक और पौराणिक कर्मकांडों का मानव जीवन के साथ गहरा रिश्ता है। शास्त्र में पितरों के बारह स्थानों पर रहने का वर्णन है जिसमें वह स्थान जहां माता-पिता रहते हैं। वैदिक विचार के मुताबिक राष्ट्ररक्षा में उम्रदराज परिजनों की रक्षा व पालन-पोषण करने वाला विभाग पितृलोक कहा गया है। इससे भी यही साबित होता है कि जिन पूर्वजों की मौत हो गई है, उनके लिए परिजनों के लिए कोई क्रिया-कर्म वेद व शास्त्र सम्मत नहीं है।

शास्त्रीय विधान के अनुसार जिस कर्म या क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा और श्रद्धा के साथ जो कर्म किया जाए, उसे श्राद्ध कहते हैं। तर्पण के बारे में वेद का विचार है कि जिस-जिस कर्म से माता-पिता व गुरुजन सुखी या खुशहाल महसूस करें, उसे तर्पण कहा गया है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक भी पितर मरे हुए को नहीं कहते हैं और न उनके लिए कोई कर्म बाकी होता है। क्योंकि हर इंसान अपने कर्म का फल ही भोगता है। दूसरी बात, मरने के बाद क्या साल भर पितर भूखे रहते हैं जो पन्द्रह दिन भोग लगा देने से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। पौराणिक परंपरा में पितृ पक्ष में परिवारी जन जलांजलि देकर पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। वैदिक विचार से पता चलता है कि श्राद्ध और तर्पण का विधान जीवितों के लिए ही है। इसमें प्रकृति का जो पक्ष है, वह भी बहुत अच्छा है। कौओं, कुत्तों, गाय, चींटी और दूसरे जीवों के प्रति कर्तव्य निभाने का विधान इस तरह है कि सारी प्रकृति इन पन्द्रह दिनों में हमारे साथ एक हो जाती है। हमारी जो दूरी प्रकृति से बनी थी, श्राद्ध के आते ही वह दूरी खत्म हो गई।

(लेखिका धर्म चिंतन से जुड़ी हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

# क्या कमला रच पाएंगी इतिहास



अमेरिकी चुनाव
डॉ. एन.के. सोमानी

डिबेट के बाद हुए सर्वे में 63 फीसदी लोगों ने कहा कि कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर परफॉर्म किया जबकि 37 फीसदी लोग ही ट्रंप की परफॉर्मेंस से खुश दिखे। चुनाव का फैसला करने वाले सात राज्यों यानी स्विंग स्टेटस में भी कमला को ट्रंप के साथ या तो बराबरी की स्थिति में या उनसे थोड़ा आगे दिखाया गया है। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की दावेदारी पेश करने वाली कमला में लोगों को एक सभ्य और शालीन देश के राष्ट्रपति की छवि नजर आ रही हैं। इन बहसों के जरिए काफी हद तक यह तय हो जाता है कि व्हाइट हाउस में आने वाले नए अमेरिकी प्रमुख का नजरिया दुनिया के प्रति कैसा रहने वाला है। चुनाव 5 नवंबर को होने हैं।

अमेरिकी गणतंत्र के 47वें राष्ट्रपति के लिए चुनावी मुकाबला आहिस्ता-आहिस्ता अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है। चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कमला हैरिस मैदान में हैं। कमला भारतीय मूल की नेता हैं और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन की सरकार में उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच चुनाव को लेकर तल्खी इस कदर बढ़ चुकी है कि पिछले सप्ताह हुई दूसरी प्रेसिडेंसियल बहस में दोनों प्रत्याशियों ने एक-दूसरे पर जमकर निशाना साधा। फिलाडेल्फिया के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में रखी गई डिबेट में दोनों प्रत्याशियों ने गर्भपात, गन कंट्रोल, राष्ट्रीय कर्ज, स्वास्थ्य व सामाजिक लाभ, इमिग्रेशन, अर्थव्यवस्था व विदेश नीति से संबंधित अपने-अपने दृष्टिकोण से अमेरिकी जनता को परिचित कराया। डिबेट के बाद हुए सर्वे में 63 फीसदी लोगों ने कहा कि कमला ने ट्रंप से बेहतर परफॉर्म किया जबकि 37 फीसदी लोग ही ट्रंप की परफॉर्मेंस से खुश दिखे। चुनाव का फैसला करने वाले सात राज्यों यानी स्विंग स्टेटस में भी कमला को ट्रंप के साथ या तो बराबरी की स्थिति में या उनसे थोड़ा आगे दिखाया गया है। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की दावेदारी पेश करने वाली कमला में लोगों को एक सभ्य और शालीन देश के राष्ट्रपति की छवि नजर आ रही हैं।

चुनाव 5 नवंबर को होने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रेसिडेंसियल डिबेट की बड़ी अहम भूमिका होती है। चुनाव के दौरान होने वाली इस तरह की डिबेट में प्रत्याशी अपना चार वर्ष का एजेंडा व अमेरिका के प्रति अपना विजन मतदाताओं के समक्ष रखते हैं। चुनावी घोषणा-पत्र की तरह काम करने वाली इस तरह की डिबेट पर न केवल अमेरिकी मतदाता बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी टकटकी लगाए रखते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन बहसों के जरिए काफी हद तक यह तय हो जाता है कि व्हाइट हाउस में आने वाले नए अमेरिकी प्रमुख का नजरिया दुनिया के प्रति कैसा रहने वाला है। यह दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट थी।

इससे पहले 27 जून को मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन और ट्रंप के बीच पहली डिबेट हुई। इस डिबेट में जो बाइडन काफी कमजोर साबित हुए। बाइडन की नाम वापसी के बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर डिबेट में शामिल हुई कमला ने बेहतर परफॉर्म किया। उन्होंने ट्रंप को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश की। डिबेट के आरंभ में जब ट्रंप कमला पर भारी पड़ते दिखे तो कमला ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दो टूक कह दिया कि वह न तो बाइडेन है और न ही ट्रंप। वह कमला हैरिस है जिसके पास ऐसा प्लान है जो नए अमेरिका का रास्ता खोलेगा। हैरिस के इस आत्मविश्वास और बेबाकपन को दर्शकों ने खूब पंसद किया। कमला ने पूरी बहस पर अपना कंट्रोल बनाए रखा और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पूरे डिबेट के दौरान ट्रंप डिफेंसिव मोड़ में रहे। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बहस को 6.75 करोड़ लोगों ने देखा। भले ही बाइडन के खिलाफ बहस में ट्रंप हावी दिखे लेकिन दूसरी बहस में कमला ने ट्रंप पर बढ़त बना ली। बहस के दौरान अमेरिका के लोगों को कमला की बातें



अधिक पसंद आई। हालांकि, ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने मंगलवार को हैरिस के साथ बहस में जीत हासिल की है। उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा कि जब कोई पेशेवर पहलवान लड़ाई हार जाता है तो उसके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द होते हैं- मैं दोबारा मुकाबला चाहता हूं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने कट्टरपंथी वामपंथी उम्मीदवार कॉमरेड कमला हैरिस के खिलाफ बहस जीत ली है। इसलिए उन्होंने तुरंत दूसरी बहस की मांग की है। बहस के दौरान ट्रंप ने दावा किया है कि वह एक दिन में रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि युद्ध रोकने के लिए उनके पास कौन सी जादूई छड़ी है।

पश्चिम एशिया भी हिंसा की गिरफ्त में है। ताइवान पर चीन के आक्रमण के हालात में ट्रंप के पास क्या योजना है? यह कुछ ऐसे बिन्दू हैं जिस पर ट्रंप कन्फ्यूजन की स्थिति में दिखे। दूसरी ओर विदेश नीति से संबंधित तमाम मसलों पर कमला ने बाइडन की नीतियों को जारी रखने के संकेत दिए। यद्यपि विदेश नीति के मामले में ट्रंप के दृष्टिकोण से अमेरिकी सहमत हैं पर महिलाओं, अप्रवासियों व विस्थापितों के प्रति उनका नजरिया बेहद प्रतिक्रियात्मक रहा है जिसे अमेरिका जैसे मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष पद के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। कमला ने कई बार कहा कि ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। वह केवल अपनी और अमीरियत की बातें करते हैं। बहस के अंत में ट्रंप ने बाइडन को इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति और कमला को सबसे खराब उपराष्ट्रपति बताया। पूर्व राष्ट्रपति ने बाइडन-हैरिस प्रशासन पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने देश को नष्ट कर दिया है। लाखों अपराधी और मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग पूरी तरह से अनियंत्रित और बिना जांच के अमेरिका में घुस रहे हैं और मुद्रास्फीती ने हमारे मध्यम वर्ग को दिवालिया बना दिया है।

हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो गंभीर गिरावट में है। दुनियाभर में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। उधर, कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप देश में बेरोजगारी छोड़कर गए। हमने लोकतंत्र पर हमला होते देखा। हम कैपिटल हिल की घटना को याद कर सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था, जिसे बाइडन और उनके प्रशासन ने संभाला। कमला को बहस के बाद बने माहौल का भी फायदा मिला। कमला हैरिस ने कहा कि मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उनकी आर्थिक नीतियों से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और ट्रंप की योजना से अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी। गोल्डमैन सैक्स ने पिछले सप्ताह एक विश्लेषक में यही कहा था। ट्रंप ने चीनी वस्तुओं को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका में आयातित अधिकांश वस्तुओं पर 10% से 20% टैरिफ का प्रस्ताव दिया है।

पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अनुमान है कि इससे अमेरिकियों को प्रति वर्ष 2,600 डॉलर का नुकसान होगा। बहस के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चंदा मिला। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से यह उनकी अब तक की सबसे मजबूत फंडरेजिंग परफॉर्मेंस है। एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में जा सकते हैं। ट्रंप भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। लेकिन कमला हैरिस की मजबूत उम्मीदवारी के बाद उनकी जीत का अंतराल कम होता दिख रहा है। हालांकि चुनाव सर्वे में ट्रंप अभी भी आगे दिख रहे हैं। लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों की स्थिति ऐसी नहीं है कि भारी अंतराल से जीत की भविष्यवाणी की जा सके। चुनाव का परिणाम चाहे जो भी आए लेकिन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति वाले देश में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे दुनिया के लिए निर्णायक होंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

# मानव के लिए नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है?



संकलित
## दर्शन

नैतिक मूल्य मानव को परिपूर्णता प्रदान कर उसे ईश्वरीय रचनाओं में श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु आधुनिकता के नाम पर इन मूल्यों का निरंतर अवमूल्यन होता जा रहा है। बढ़ता भौतिकतावाद उन्हें लील रहा है। परिणामस्वरूप नैतिकता घुट-घुटकर ही सांस ले पा रही है। यह स्थिति तब है जब नैतिकता को मानव समाज के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता मिली है। नैतिकता के अभाव में मनुष्यता का आकलन संभव ही नहीं। नैतिकता व्यक्ति के विकास में एक सीढ़ी के समान है, जिसके सहारे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। नैतिक मूल्यों के अभाव में मनुष्य मानव जीवन को निरर्थक बना देता है। प्रख्यात विचारक अल्बेयर कामू ने भी कहा है कि नैतिकता के बिना एक व्यक्ति इस दुनिया में किसी पशु के समान है। हम जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय नैतिक कसौटी पर कसने के बाद ही करते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कई बार मनुष्य उसे अनदेखा कर फैसला करता है, जो नैतिक पतन का कारण बनता है। स्मरण रहे कि ईश्वर ने हमें सिर्फ सुख भोगने के लिए ही इस संसार में नहीं भेजा है। इसीलिए केवल भौतिक सुखों के लिए नैतिकता का परित्याग करना उचित नहीं। इसका एक कारण यही है कि अब हमने अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना करना आरंभ कर दिया है। हमें यह पता होता है कि अमुक कार्य नैतिक रूप से सही नहीं, लेकिन सुख के लिए वह कार्य करने से संकोच नहीं करते। इसमें अक्सर दूसरे के हितों की बलि चढ़ जाती है। स्वाभाविक है कि इससे टकराव बढ़ेगा।

# कद्दू का तीर्थ स्नान



संकलित
## प्रेरणा

एक बार तीर्थ यात्रा पे जाने वाले लोगों का संघ, संत तुकाराम जी के पास जाकर उनके साथ चलने की प्रार्थना की। तुकारामजी ने अपनी असमर्थता बताई। उन्होंने तीर्थयात्रियो को एक कड़वा कद्दू देते हुए कहाः मैं तो आप लोगों के साथ आ नहीं सकता लेकिन आप इस कद्दू को साथ ले जाईए और जहां-जहां भी स्नान करे, इसे भी पवित्र जल में स्नान करा लाए। लोगों ने उनके गूढ़ार्थ पे गौर किए बिना ही वह कद्दू ले लिया और जहां-जहां गए, स्नान किया वहां-वहां स्नान करवाया। मंदिर में जाकर दर्शन किया तो उसे भी दर्शन करवाया। ऐसे यात्रा पूरी होते सब वापस आए और उन लोगों ने वह कद्दू संतजी को दिया। तुकारामजी ने सभी यात्रियों को प्रीतिभोज पर आमंत्रित किया। तीर्थयात्रियों को विविध पकवान परोसे गए। तीर्थ में घूमकर आए हुए कद्दूकी सब्जी विशेष रूपसे बनवाई गई थी। सभी यात्रियों ने खाना शुरू किया और सबने कहा कि यह सब्जी कड़वी है। तुकारामजी ने आश्चर्य बताते कहा कि यह तो उसी कद्दू से बनी है, जो तीर्थ स्नान कर आया है। बेशक यह तीर्थाटन के पूर्व कड़वा था, मगर तीर्थ दर्शन तथा स्नान के बाद भी इसी में कड़वाहट है! यह सुन सभी यात्रिओ को बोध हो गया कि, हमने तीर्थाटन किया है लेकिन अपने मन को एवं स्वभाव को सुधारा नहीं तो तीर्थयात्रा का अधिक मूल्य नहीं है। हम भी एक कड़वे कद्दू जैसे कड़वे रहकर वापस आए हैं।

## अंतर्मन

## आज की पाती

### श्राद्ध के प्रति रूढ़िवादी सोच बदलें

पितृपक्ष शुरू हो चुका है। इस दौरान अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। हमारे देश में पत्थर को भी पूजा जाता है। नदियों की पूजा की जाती है। अपने पूर्वजों को याद करने के लिए हमारे देश में श्राद्धों का आयोजन किया जाता है। हमारे देश की महान संस्कृति हमेशा ही संदेश देती है कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। पूर्वजों का सम्मान करने से एक तो नैतिकता का संचार होता है, तो दूसरा उनके चलाए रास्तों पर चलने से कोई भी इनसान जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं होता है और न ही जिंदगी में कभी किसी काम में धोखा खाता है। कुछ लोग श्राद्धों को ढोंग या दिखावा बताते हैं, लेकिन उन लोगों को यह उत्तर देना चाहिए कि अगर आपके पूर्वज नहीं होते तो आपका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता। श्राद्धों के प्रति रूढ़िवादी सोच को बदलने की जरूरत है। – *प्रभाकर जोशी, राजनांदगांव*

## करंट अफेयर

# ब्रिटेन ने ई-वीजा परिवर्तन अभियान प्रारंभ किया

ब्रिटेन ने बुधवार को एक बड़ा अभियान शुरू किया और भारतीयों सहित देश भर में रह रहे सभी प्रवासियों से आग्रह किया गया कि वे आव्रजन दस्तावेज का उपयोग करने के बजाए ई-वीजा को अपनाएं। ब्रिटेन की सीमा एवं आव्रजन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की योजना के तहत भौतिक बायोमिट्रिक निवास परमिट (बीआरपी) या बायोमिट्रिक निवास कार्ड (बीआरसी) का इस्तेमाल करने वालों को अगले वर्ष तक पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। अधिकतर बीआरपी इस वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाएंगे। उन्हें कई चरण में ऑनलाइन प्रणाली में लाया जा रहा है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय में प्रवासन एवं नागरिकता मंत्री सीमा मल्होत्रा ने कहा, ‘जिन लोगों के पास आव्रजन दस्तावेज हैं, उनसे आग्रह है कि वे ई-वीजा अपनाने के लिए तत्काल कदम उठाएं और जिन लोगों को सलाह और सहायता की आवश्यकता है मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूं कि उन्हें सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी।’ गृह मंत्रालय ने कहा, ईवीजा अपनाना निशुल्क और बेहद सरल है। यह ग्राहकों को ज्यादा सुविधा प्रदान करता है, किफायती है और ब्रिटेन की सीमा एवं आव्रजन प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करता है।



## ऑफ बीट

# आनुवांशिक जानकारी से जान सकते हैं बहुत कुछ

कई वैज्ञानिक शोध अध्ययन एक विशिष्ट शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए डेटा एकत्र करते हैं। उदाहरण के लिए, मधुमेह की आनुवंशिकी का अध्ययन करने के लिए, शोधकर्ता आनुवंशिक डेटा के अलावा आपके रक्तचाप और लिपिड स्तर पर डेटा एकत्र कर सकते हैं। वैज्ञानिक बायोबैंक में रखने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र कर रहे हैं – ऐसे भंडार जो आनुवंशिक डेटा और रक्त, मूत्र या ट्यूमर ऊतक जैसे अन्य जैव नमूनों को भविष्य के अध्ययनों की एक विस्तृत संख्या में उपयोग करने के लिए संग्रहीत करते हैं। कुछ बायोबैंक, जैसे यूके बायोबैंक, बायोस्पेसिमेन डेटा को अन्य एकत्रित डेटा, जैसे यौन व्यवहार, चिकित्सा इतिहास, वजन, आहार और जीवन शैली से जोड़ते हैं। वे अक्सर आश्चर्यचकित होते हैं कि जिस आनुवंशिक डेटा को उन्होंने डीएनए परीक्षण किट का उपयोग करके या अपने स्थानीय क्लिनिक का दौरा करते समय एक निजी कंपनी में अनुसंधान के लिए उपयोग करने की सहमति दी थी, उसका उपयोग समलैंगिक यौन व्यवहार या जोखिम के आनुवंशिकी का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। बायोबैंक डेटा के साथ जो शोध किया जा सकता है वह डरावना लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।



## ट्रेंड

### लाभार्थियों से मिला



अपनी हालिया गुजरात यात्रा के दौरान, मैं जगशीभाई सुथार के घर गया। उन्हें और उनके परिवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लाभ हुआ है। मैं इस योजना के अन्य लाभार्थियों से भी मिला।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

### अधिकारों का हनन

देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का दर्जा छीन कर उसे केंद्र शासित बनाया गया हैश, ये जम्मू-कश्मीर वासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, अपमान है। ‘इंडिया’ को दिया गया आपका एक-एक वोट आपके अधिकार वापस लौटाएगा।
-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

### भारत में बदलाव आ रहा

सभी पुरुषों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों! मैं नहीं जानता कि आपमें से कितने लोग मुझसे सहमत होंगे। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो? क्या मैं अकेला हूं जो भारत में बदलाव देख रहा हूं?
-विराट कोहली, क्रिकेटर

### जो हुआ उससे सीखें

पूर्वजों से असहमत हो सकते हैं, उनकी भूलों का परिष्कार व परिमार्जन कर सकते हैं। किंतु उन्हें दिन-रात गरियाना कमजोर वर्तमान की निशानी होता है। जो हुआ उससे सीखकर वर्तमान व भविष्य के पथ पर प्रस्थान करना ही श्रेयस्कर होता है
-कुमार विश्वास, कवि व व्याख्याता

## अपने विचार

**हरिभूमि कार्यालय**

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaper

कल्पमेधा

*स्त्री, तूने अपने अथाह आंसुओं से संसार के हृदय को ऐसे घेर रखा है, जैसे समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए है।*

*– रवींद्रनाथ ठाकुर*

## अब न हो देर

देश में जनगणना लंबे समय से लंबित है। सरकार अब इसकी योजना बना रही है। विपक्षी दलों ने जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग उठाई है। धीरे-धीरे यह बड़ा मुद्दा बन गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसकी आवश्यकता जताई है। सरकार ने संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर काम हो रहा है। वर्ष 2011 में जनगणना कराई गई थी। तब से अब तक उसी समय के आंकड़ों से ही काम चलाने की मजबूरी है। हालांकि, उन आंकड़ों को सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के पलड़े में अप्रभावी, अधूरी और खराब प्रकृति का माना गया। जनगणना के आंकड़ें संवेदनशील माने जाते हैं और इनका व्यापक असर होता है। खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जैसी कई योजनाएं इनपर निर्भर होती हैं। आंकड़ों का उपयोग सरकारों के साथ उद्योग जगत और शोध संस्थाएं भी करती हैं। बदलते समय के साथ देश के सामने नई चुनौतियां हैं, जिन्हें लेकर नीति निर्धारण की जरूरत है। ऐसे में जरूरी है कि जनगणना को लेकर सरकार महापंजीयक और अन्य एजंसियों के लिए नए मानक दिशानिर्देश तैयार करे।

जून 2024 तक 233 देशों में से भारत उन 44 देशों में से एक था जिन्होंने इस दशक में जनगणना नहीं की थी। सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण यह कवायद नहीं की गई। हालांकि, 143 अन्य देशों ने इस काल में ही मार्च 2020 के बाद जनगणना की। संघर्ष, आर्थिक संकट एवं उथल-पुथल से प्रभावित यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमा, यूक्रेन, श्रीलंका और उप-सहारा अफ्रीका जैसे देशों ने जनगणना नहीं कराई। भारत में इस कवायद में देरी को लेकर सवाल उठे। यह तथ्य है कि वर्ष 1881 से 2011 तक बिना किसी बाधा के भारत में जनगणना कराई गई। सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) पहली बार वर्ष 1931 में कराई गई थी। इसका उद्देश्य अभाव के संकेतकों की पहचान करने के लिए ग्रामीण और शहरी- दोनों क्षेत्रों में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचनाएं जमा करना था। एसईसीसी में संग्रहित जानकारी सरकार द्वारा परिवारों को लाभ देने या लाभ से वंचित करने में फैसले के लिए आधार बनती है।

बहरहाल, जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर बहस जारी है। देश के कई हिस्सों में अभी भी जाति-आधारित भेदभाव है। ऐसे में विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर, सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिये पर रह रहे समुदायों के लिए लक्षित नीतियां बनाई जा सकती हैं। इसके विरोध में यह तर्क दिया जा रहा है कि जाति-आधारित भेदभाव बढ़ सकता है, जाति व्यवस्था के सबल होने की आशंका है। इसे रोकने के लिए जातिगत पहचान की जगह सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत में जातियों को परिभाषित करना जटिल मुद्दा है, क्योंकि यहां हजारों जातियां और उपजातियां हैं। जरूरी यह है कि मुद्दों में न उलझते हुए नीति निर्धारण पर ध्यान दिया जाए। निश्चित समय सीमा तय की जाए। जनगणना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। पहले ही काफी देर हो चुकी है। अब और देर उचित नहीं।

## दवा और मर्ज

लोगों में यह धारणा आम हो गई है कि कोई भी बीमारी रोग प्रतिरोधक दवाओं (एंटीबायोटिक) के बिना जल्दी ठीक नहीं हो सकती। खांसी-जुकाम और बुखार जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में भी रोग प्रतिरोधक दवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है। नतीजा यह कि रोग प्रतिरोधक दवाएं निष्प्रभावी हो रही हैं और यह वैश्विक स्तर पर गंभीर समस्या बन गई है। 'द लांसेट' पत्रिका में प्रकाशित नए अध्ययन में दावा किया गया है कि वर्ष 1990 से 2021 के बीच रोग प्रतिरोधक दवाओं के निष्प्रभावी हो जाने से दुनिया भर में हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। अगले 25 वर्षों में 3.9 करोड़ से अधिक लोगों की जान जा सकती है।

अध्ययन में कहा गया है कि रोग प्रतिरोधक दवाओं के निष्प्रभावी होने से भविष्य में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित दक्षिण एशिया में सर्वाधिक असर दिखने का अनुमान है। स्पष्ट है कि दक्षिण एशियाई देशों में रोग प्रतिरोधक दवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है। यह बात सही है कि गंभीर संक्रमण वाली बीमारियों के इलाज में रोग प्रतिरोधक दवाएं कारगर होती हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा और लंबे समय तक इन दवाओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है।

दरअसल, रोग प्रतिरोधक दवाओं के प्रति प्रतिरोध तब उत्पन्न होता है, जब संक्रामक रोगाणु को मारने के लिए बनाई गई ये दवाएं निष्प्रभावी हो जाती हैं, क्योंकि रोगाणु इन दवाओं का प्रतिरोध करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में रोग प्रतिरोधक दवाओं के निष्प्रभाव से होने वाली मौत में 80 फीसद से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बुजुर्ग ऐसी दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से ली जाने वाली ये दवाएं शरीर में फायदेमंद जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती हैं, जिससे और भी कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। विशेषज्ञों की राय है कि रोग प्रतिरोधक दवा चिकित्सक के परामर्श से ही लेनी चाहिए। साथ ही, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और नीति निर्माताओं को भी चाहिए कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल व बिक्री को लेकर नियमों को और सख्त करें।

# अतार्किक उपभोग और कचरे का बोझ

**हर आदमी अब मात्र उपभोग करने की एक इकाई बनकर रह गया है। 'इस्तेमाल करो और फेंको' की संस्कृति इसी उपभोक्तावाद की उपज है, जिसका व्यापक प्रभाव प्रकृति के अंधाधुंध दोहन और व्यापक प्रदूषण के रूप में आज हमारे सामने है।**

**कुशाग्र राजेंद्र**

मौजूदा दौर उपभोक्तावाद का है, जिसमें लोग बेतहाशा और बेतरतीब तरीके से दैनिक उपयोग का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें से अधिकांश को बहुत कम समय उपयोग करने के बाद सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। उपभोग की प्रवृत्ति के पीछे मानसिकता यह है कि हम जितना ज्यादा उपभोग करेंगे या जो हमारे अधिकार में होगा, हम उतना ही सुखी रहेंगे। आधुनिकता के दौर में अधिक से अधिक उपभोग सुख, समृद्धि और अच्छे जीवन स्तर का द्योतक है। भारत में उपभोग की प्रवृत्ति में क्रांतिकारी बदलाव नब्बे के दशक में आए आर्थिक उदारवाद के बाद हुआ, जिसका असर न सिर्फ बाजार पर पड़ा, बल्कि शहरीकरण के माध्यम से मध्यवर्ग के आर्थिक और सामाजिक ढांचे और प्रवृत्ति पर भी पड़ा। पिछले तीन दशक में बाजार ने उत्पादन और उपभोग को धीरे-धीरे अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसका नतीजा हुआ कि हमारी जरूरतें बाजार निर्धारित करने लगा है। इस प्रकार हम सब वस्तु के उपभोग की इकाई बनते चले गए, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बाजार को हुआ। तेजी से बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद के रूपों में आर्थिक प्रगति के नए प्रतिमान बने।

इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक उदारवाद ने कई जटिल, जड़ आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया, जिसमें गरीबी, संसाधनों का असमान वितरण, सर्वसुलभ शिक्षा, मंथर गति का आर्थिक विकास आदि प्रमुख हैं। साथ ही, गुजरते समय के साथ यह कई बड़ी समस्याएं भी लेकर आया। इन्हीं नकारात्मक प्रभावों में उपभोक्तावाद प्रमुख है। हर आदमी अब मात्र उपभोग करने की एक इकाई बनकर रह गया है। 'इस्तेमाल करो और फेंको' की संस्कृति इसी उपभोक्तावाद की उपज है, जिसका व्यापक प्रभाव प्रकृति के अंधाधुंध दोहन और व्यापक प्रदूषण के रूप में आज हमारे सामने है। इस प्रवृत्ति को लिखने की आदत में आए बदलाव से बखूबी समझा जा सकता है। आर्थिक उदारवाद के पहले लिखने के लिए निब वाला कलम होता था, जिसमें बार-बार स्याही भरी जाती थी और उसे वर्षों इस्तेमाल किया जाता था। तभी बाल पेन ने दस्तक दी, जिसमें सूखी स्याही वाले रिफिल का चलन था। इस्तेमाल के बाद रिफिल फेंक कर नया रिफिल डाला जाता था। कुछ दिनों बाद 'लिखो-फेंको' वाला कलम आ गया।

आज स्थिति यह है कि, एक आंकड़े के मुताबिक, मात्र दस फीसद लोग रिफिल खरीदते हैं। सब कलम खरीदते हैं, क्योंकि रिफिल और नए कलम का दाम लगभग बराबर हो चुका है। उसे इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक केवल अमेरिकी लोग साल भर में 1.6 अरब कलम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा दो अरब से अधिक है। नतीजतन, लाखों टन प्लास्टिक मिट्टी, नदी और समुद्र में जा मिलता है। जब बाजार और उपभोक्तावाद ने कुछ ही दशक में लिखने जैसी आदत को इस कदर प्रभावित किया है, तो इसके प्रभाव को बाकी दिनचर्या की वस्तुओं पर अंदाजा लगाना भी भयावह है।

फैशन, प्रकृति के दोहन का नया उपादान बन कर सामने आया है। वैश्विक स्तर पर हर वर्ष सौ अरब वस्त्र बनाए और इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी प्रति व्यक्ति बारह अलग-अलग कपड़े। यह तब है जब अधिकांश जनसंख्या बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पा रही है। सौ अरब कपड़े यानी वजन के हिसाब से लगभग नौ करोड़ टन कपड़ा सालाना कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है। कपड़ा बनाने में ढेर सारे पानी और उर्जा की खपत होती है, इस लिहाज से वैश्विक ताप का लगभग दस फीसद भार हमारे अलग-अलग 'मैचिंग' कपड़े पहनने और और दिखाने की प्रवृत्ति से पड़ता है। अगर फैशन की यही प्रवृत्ति जारी रही, तो 2030 के अंत तक कूड़े के ढलाव तेरह करोड़ टन इस्तेमाल किए गए कपड़ों से भर रहे होंगे।

> 'इस्तेमाल करो और फेंको' संस्कृति औद्योगिक क्रांति के आर्थिक संदर्भ की उपज है, जहां मूल उद्देश्य उत्पादन और उपभोक्ता के माध्यम से आर्थिक मुनाफे में उत्तरोतर बढ़ोतरी करना है। अगर उत्पाद टिकाऊ और मरम्मत के लायक होगा तो बहुत लंबे समय तक उपयोगी बना रहेगा और ऐसी वस्तुएं बाजार और मुनाफे के आड़े आएंगी, क्योंकि ऐसी वस्तुएं उपभोक्ता को लंबे समय तक के लिए बाजार से दूर कर देंगी। इसलिए कंपनियों ने न सिर्फ उत्पाद में तकनीकी परिवर्तन कर मरम्मत की संभावना को कम किया, बल्कि उसके इस्तेमाल की समय-सीमा को कम कर दिया।

हम प्रकृति का वैसे ही अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जैसे टिड्डी दल फसलों को सफाचट कर जाता है। रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान की मरम्मत की संस्कृति पूर्व आर्थिक उदारवाद के दौर की पहचान रही है, जो किसी भी सामान का अधिकतम और किफायती उपयोग सुनिश्चित करती थी। चप्पल-जूतों से लेकर, कपड़ों, बर्तन, रेडियो, टीवी, घड़ी, छाता, कृषि के सामान, यहां तक कि निब वाले पेन की मरम्मत करने वाले अर्थव्यवस्था में हिस्सेदार हुआ करते थे। 'इस्तेमाल करो और फेंको' संस्कृति औद्योगिक क्रांति के आर्थिक संदर्भ की उपज है, जहां मूल उद्देश्य उत्पादन और उपभोक्ता के माध्यम से आर्थिक मुनाफे में उत्तरोतर बढ़ोतरी करना है। अगर उत्पाद टिकाऊ और मरम्मत के लायक होगा तो बहुत लंबे समय तक उपयोगी बना रहेगा और ऐसी वस्तुएं बाजार और मुनाफे के आड़े आएंगी, क्योंकि ऐसी वस्तुएं उपभोक्ता को लंबे समय तक के लिए बाजार से दूर कर देंगी। इसलिए कंपनियों ने न सिर्फ उत्पाद में तकनीकी परिवर्तन कर मरम्मत की संभावना को कम किया, बल्कि उसके इस्तेमाल की समय-सीमा को कम कर दिया। अब हर महीने उत्पाद के माडल बदलने लगे, नई तकनीक का हवाला देकर विज्ञापन के माध्यम से उसे पहले माडल से बेहतर बताया जाने लगा। यहां तक निर्माता उत्पाद के उपयोग करने की समय सीमा भी निर्धारित करने लगे, ताकि निर्धारित समय के बाद उसे आवश्यक रूप से बदलना ही पड़े। इस तरह उपभोक्ता को बार-बार बाजार का रुख करना पड़ता है।

निर्माताओं ने भरसक प्रयास किया कि मरम्मत की संभावना खत्म हो जाए, पर जिस उत्पाद को मरम्मत से दरकिनार नहीं किया जा सकता, वहां भी दोहरे मुनाफे के लिए मरम्मत करने का अधिकार बौद्धिक संपदा संरक्षण के बहाने अपने पास ही रखा। निर्माताओं के मरम्मत की प्रवृत्ति को खत्म करने के गोरखधंधे को 'शमशेर कटारिया बनाम होंडा सील कार' के कानूनी मामले से समझा जा सकता है कि उत्पादक समूह किस स्तर तक न सिर्फ हमें एक अदद उपभोक्ता बना रहे हैं, बल्कि एक ही उत्पाद को नए-नए कलेवर के साथ एक खास अंतराल पर बेंच कर बार-बार मुनाफा कमाकर पृथ्वी को कूड़े का अंबार बना रहे हैं।

अब चूंकि चरम उपभोक्तावाद की हकीकत सामने आने लगी है, तो भारत सरकार सावधान और निर्माताओं के ऐसे गोरखधंधे पर लगाम लगाने को तत्पर हुई है। यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर उपभोक्ता के 'मरम्मत का अधिकार' सुनिश्चित करने की कवायद में जुट गई है। हालांकि यह तो अभी शुरुआत है, वैश्विक और भारत के स्तर पर सतत विकास के लक्ष्य के आधार पर उत्पाद तैयार करने से लेकर उसके उपयोग की समय-सीमा जैसे मुद्दों पर नकेल कसने की जरूरत है। अगर इस दिशा में सत्ता प्रतिष्ठान संज्ञान ले, तो न सिर्फ यह उपभोक्ता के लिए किफायती होगा, बल्कि पृथ्वी को कूड़े का ढेर बनने से बचा पाएंगे। टिकाऊ, मरम्मत योग्य और किफायती उत्पाद में ही सतत विकास निहित है, जिसके मूल में कम से कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा उपयोग या उपभोग है।

# छोटे पर्दे का परिवार

**बुलाकी शर्मा**

आजकल सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर जरूरत से ज्यादा सक्रियता की वजह से लोगों के समाज और परिवार से कटने की शिकायतें की जाती हैं और काफी हद तक यह सही भी है। मगर वाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, रील, एक्स जैसे सोशल मीडिया के माध्यमों की सक्रियता बढ़ने के बावजूद घर-परिवार के सदस्यों में आज भी छोटे पर्दे के प्रति रुझान बना हुआ है। सुबह और दोपहर पारिवारिक या व्यावसायिक व्यस्तता के कारण पहले के मुकाबले वे समय कम दे पाते हैं, लेकिन शाम के मुख्य समय या 'प्राइम टाइम' में परिवार के लोग, विशेष रूप से महिलाएं टेलीविजन के सामने बैठकर विभिन्न चैनलों पर आ रहे अपने पसंदीदा पारिवारिक धारावाहिक जरूर देखती हैं। ऐसे धारावाहिकों में दिखाए जा रहे संयुक्त परिवार और उनकी भव्यता, अरबों का कारोबार, शराब पार्टियां, आभिजात्य दर्प और रुतबा, अपनी जरूरतें भी सुगमता से पूरी करने में असमर्थ परिवारों को सपनों का संसार लगता है। वहीं संयुक्त परिवार पर एकछत्र राज करने के लिए किए जाते षड्यंत्र, भाई- भाई, बहन-भाई, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, सास-बहू, देवरानी-जेठानी जैसे आत्मीय रिश्तों के बीच संदेह और अविश्वास का भाव, सच्चे और खरे सदस्यों पर झूठे आरोप-प्रत्यारोप, उन्हें फंसाने की कोशिशें, समाज की स्वस्थ परंपराओं की अनदेखी, गैरजरूरी स्वच्छंदता जैसी स्थितियां उन्हें असहज करती हैं।

धारावाहिकों की ये कहानियां और उनके किरदार झुग्गी-झोपड़ियों से लेकर आभिजात्य वर्ग के घर, परिवार और उनके निजी कक्ष तक हर दिन पहुंच रहे हैं। लाखों-करोड़ों भारतीय परिवारों के लोग मनोरंजन के ध्येय से पर्दे के सामने बैठते हैं। उन धारावाहिकों के परिवारों में वर्चस्व के लिए रची जाती व्यूह रचना उत्सुकता का भाव बनाए रखती है। कई बार यह साफ दिखता है कि छोटे पर्दे के संयुक्त परिवार के कई सदस्य आर्थिक संपन्नता और असीम सुख-सुविधाओं के बावजूद संतोष और तृप्ति का अहसास नहीं करते, बल्कि वे मानसिक रूप से उद्वेलित दिखते हैं। वे अपने परिजनों के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी और षड्यंत्र करके और संपन्न बनने की सीमाहीन लालसा में आकंठ डूबे हुए लगते हैं। उनके लिए धन, संपदा और ऐश्वर्य प्रमुख हैं, पारिवारिक रिश्ते गौण।

छोटे पर्दे के ऐसे संयुक्त परिवार वास्तविकता और यथार्थ से दूर एक झूठा संसार रच रहे हैं। हो सकता है कि हमारे समाज में संयुक्त परिवार जैसी सामाजिक व्यवस्था कहीं से चरमरा रही है, जबकि संयुक्त परिवार में आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सभी सदस्य स्वयं को समृद्ध और सहज अनुभव करते हैं। सुख-दुख किसी एक का नहीं, सबका होता है और वे आपसी सौहार्द के साथ साझा करते हैं। परिवार का मुखिया समभाव रखता है और हरेक की जरूरतों को पूरा करता है। समय के साथ संयुक्त परिवारों की संख्या कम और एकल परिवारों की तादाद बढ़ती जा रही है। परिवार जनों की निजी महत्त्वाकांक्षाएं, आर्थिक रूप से मजबूत बनने की अभिलाषा, बच्चों का भविष्य बनाने की चिंता, आपसी टकराहट, स्वतंत्र रहने की भावना, रोजगार के लिए अन्यत्र रहने की विवशता समेत और भी कई कारक संयुक्त परिवार छोड़कर एकल परिवार के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। संयुक्त परिवार से अलग होने का मतलब परिवार से अलगाव नहीं होता। अलग-अलग रहते हुए भी परिवार से उनका गहरा रागात्मक जुड़ाव बना रहता है। इसीलिए राजस्थानी में एक कहावत प्रचलित है- जितने बेटे उतने घर। घर अलग-अलग होते हुए भी कुटुंब एक ही है, संयुक्त परिवार जैसा।

छोटे पर्दे पर दिखाए जाने वाले संयुक्त परिवार हमारे परंपरागत भारतीय संयुक्त परिवारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। भारतीय संयुक्त परिवारों में अपनत्व, आत्मीयता, समरसता, रागात्मकता और एक-दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण भाव की प्रधानता रहती है। रिश्तों को जीया जाता है, दिखावा नहीं किया जाता। सामान्य तकरार और रूठने-मनाने की स्वस्थ परंपरा के बीच आर्थिक आधार पर किसी सदस्य को महत्त्वपूर्ण या महत्त्वहीन मानने की मनोवृत्ति आमतौर पर नहीं होती। ऐसे संयुक्त परिवार आज भी मिल जाएंगे, जिनमें एक छत के नीचे प्रेम से चालीस-पचास परिजन रहते हैं, एक रसोई में खाना बनता है और सब हिलमिल कर भोजन करते हैं। अलग-अलग व्यवसाय और काम-धंधा होते हुए भी मुखिया के आदेशों की पालना होती है।

टीवी के कार्यक्रमों के परिवारों में ऐसा सुखद माहौल कहां दिखता है? भरे-पूरे परिवार में बमुश्किल एक-दो महिला सदस्य ही परिवार को एकसूत्र में बांधे रखने की कोशिश में दिखती हैं, वे भी हताश-निराश। इन कार्यक्रमों में अभिजात्य वर्ग की सुशिक्षित-अत्याधुनिक महिलाएं और पुरुष कूटनीतिक चालें चलने और परिवार के अन्य सदस्यों को शिकस्त देने में लगे दिखते हैं। ऐसे परिवार और ऐसे महिला-पुरुष किरदार भारतीय समाज के नहीं हो सकते। जबकि शहरों-कस्बों में ही नहीं, नगरों और महानगरों में आज भी ऐसे संयुक्त परिवार हैं, जहां रिश्तों की सोंधी महक लुभाती है। एकजुटता और इंसानियत का संदेश देती है। झोपड़पट्टियों में रहने को विवश दो वक्त का खाना जुटाने की जुगाड़ में लगे परिवार के सदस्य भी षड्यंत्रों से दूर रिश्तों के रेशमी धागे से बंधे हुए दिखते हैं।

भारतीय संस्कारों को आत्मसात किए हमारे समाज का संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार, उनमें जुड़ाव है, बिखराव नहीं। उनके संवेदनशील रिश्तों की नदी सूखी नहीं है, वह अनवरत-अबाध बह रही है। छोटे पर्दे के परिवारों की कहानियां हमारे सोच और संस्कारों से दूर, पता नहीं विश्व के किस छोर की कहानियां हैं।

**दुनिया मेरे आगे**

> सुख-दुख किसी एक का नहीं, सबका होता है और वे आपसी सौहार्द के साथ साझा करते हैं। परिवार का मुखिया समभाव रखता है और हरेक की जरूरतों को पूरा करता है। समय के साथ संयुक्त परिवारों की संख्या कम और एकल परिवारों की तादाद बढ़ती जा रही है।

## दागी नुमाइंदे

जब भी देश में लोकसभा के या किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अखबारों में किस राजनीतिक दल ने कितने दागियों को टिकट दिया, इसकी चर्चा होने लगती है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं के बावजूद देश की विधानसभाओं और संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि के सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है- चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक दल या आम नागरिक? पिछले कई दशकों से हम सुनते आ रहे हैं कि राजनीति अच्छे, ईमानदार लोगों के लिए नहीं है। जिस देश में यह सिखाया जाता हो और वहां की संसद या विधानसभाओं में दागी या अपराधी किस्म के लोग पहुंच जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा नुकसान है देश के लिए जो अच्छे लोग पहुंचाते हैं, क्योंकि वे अपराधियों के लिए जगह खाली करते हैं। साफ-सुथरी छवि के लोग राजनीति में आते भी हैं तो उन्हें बाद में पछतावा ही होता है, क्योंकि हमने कभी उनका सम्मान नहीं किया जो जीवन के संघर्ष में खड़े रहते हैं, जो हालात को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर हम अब भी नहीं जागे तो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग ही देश पर राज करते रहेंगे।

*– चरनजीत अरोड़ा, नरेला, दिल्ली*

## नई हवा

कश्मीर विधानसभा के चुनाव देश के अन्य राज्यों के चुनाव से कुछ अलग महत्त्व के हैं, क्योंकि वहां अनुच्छेद 370 हटाने के बाद एक नया वातावरण पैदा हुआ है। आतंकवादियों के जुल्म और वहां के कुछ नेताओं का अलगाववादी रवैया कश्मीरी जनता अच्छे से समझने लगी है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीरी उत्पादों से लेकर जमीन-जायदाद की कीमतों और पर्यटन में भारी वृद्धि और कई प्रकार के सकारात्मक अनुभव कश्मीरी जनता को प्राप्त हुए हैं। अब इन विधानसभा चुनाव के बाद जनता के अपने जनप्रतिनिधि चुनने का उन्हें नया अनुभव होगा और वह बिना किसी खौफ के पहली बार मतदान करेगी। इस बात की आशंका है कि चुनाव के दौरान पाकिस्तान और आतंकवादी कई तरह की परेशानियां खड़ी करने के प्रयास करेंगे। इस स्थिति को ध्यान में रखकर वहां अगले दौर में कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव कराए जाने चाहिए!

*– विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र*

## उम्मीद की राह

दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में नई घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। बेशक यह एक राजनीतिक दाव हो सकता है आम आदमी पार्टी का और विपक्षी नेताओं के द्वारा इसके समय पर सवाल किया जाना भी वाजिब है, लेकिन यह एक अच्छी खबर है कि नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रहा है। अब दिल्ली वाले उम्मीद लगा सकते है कि दिल्ली में रुके हुए काम तेज गति से होंगे और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। हालांकि पांच महीने की अवधि नाकाफी है नए मुख्यमंत्री के लिए। बारिश के दिनों में जिस तरह से दिल्ली में तबाही मची है, करंट लगने से और जल भराव से लोगों की जान गई है, यह सिलसिला हर हाल में रुकना चाहिए। आने वाले समय में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम में सुधारों के मसले पर काम करना बेहद आवश्यक है। दिल्ली की मलिन बस्तियों में बेहद तकलीफदेह और मुश्किल जीवन से कैसे निजात दिलाई जाए, यह नए मुख्यमंत्री के प्राथमिकता पर होना चाहिए।

*– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली*

## कर्ज का जाल

एक खबर के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार नया कर्ज लेने जा रही है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार की भी वित्तीय सेहत खराब है। मुफ्त की योजनाएं सरकार की वित्तीय स्थिति को पलीता लगा रही हैं। घोषित तौर पर पंजाब सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के भी लाले पड़े हुए हैं। चुनावों में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां देश को कर्ज के दलदल में धकेल रही हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और अन्य कई छोटे-मोटे देशों की कर्ज में डूबने के बाद क्या स्थिति हुई थी। कुछ मूलभूत योजनाओं को छोड़कर ऐसी सभी योजनाओं पर रोक लगना चाहिए, जिसमें कोई भी वस्तु मुफ्त देने का वादा किया गया हो। हालांकि जरूरतमंद लोगों को चिह्नित करके उन्हें सहायता जरूर पहुंचाई जानी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग को उसके औचित्य का संज्ञान लेना चाहिए।

*– ललित महालकरी, इंदौर*

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

अमर उजाला

# प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948



मानव समाज के लिए जो भी मूल्यवान है, वह व्यक्ति को दिए गए विकास के अवसर पर निर्भर करता है। -अल्बर्ट आइंस्टीन

**देश के व्यापार घाटे का दस महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचना एक गंभीर विषय है, जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे यह संकेत भी मिलता है कि देश विकास कर रहा है और उसकी मांगें बढ़ रही हैं। ऐसे में, दीर्घकालिक नीतियों के जरिये निर्यात बढ़ाते हुए इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए।**

## घाटे की चिंता



बीते अगस्त में देश के निर्यात में तेरह महीने की सबसे बड़ी गिरावट होने और आयात के बढ़ने से व्यापार घाटे का पिछले दस महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचना एक गंभीर विषय है, जो संकेत देता है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियां किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर रही हैं। यह इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि निर्यात में गिरावट आर्थिक विकास की रफ्तार को धीमा कर सकती है, साथ ही इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब दुनिया के तकरीबन सभी देश दो बड़े युद्धों और मंदी से जूझ रहे हैं, तब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी पुष्टि विश्व बैंक से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तक तमाम प्रतिष्ठित वैश्विक निकाय कर चुके हैं। दरअसल, फिलहाल निर्यात में जो गिरावट दिख रही है, उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार वैश्विक कारण ही हैं। अमेरिका व यूरोप पर मंदी का असर दिखने लगा है। चीन की अर्थव्यवस्था भी सुस्त दिख रही है। लिहाजा विदेशी बाजारों में मांग में कमी के अतिरिक्त अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोर स्थिति ने निर्यातकों पर दबाव डाला है। इसके अतिरिक्त, त्योहारों के समय को ध्यान में रखते हुए जुलाई में सोने पर आयात शुल्क पंद्रह से घटाकर छह फीसदी कर दिया गया था, जिससे अगस्त में इसका आयात बढ़कर रिकॉर्ड दस अरब डॉलर तक पहुंच गया। वस्तुओं के कुल आयात में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की यह एक बड़ी वजह रहा। हालांकि पेट्रोलियम, रत्न और आभूषणों को छोड़ दें, तो इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्युटिकल और टेक्सटाइल उत्पादों का निर्यात बढ़ना राहत के संकेत देता है। इसके अलावा, पेट्रोलियम की कीमतें गिरने से कच्चे तेल के आयात में भी एक-तिहाई कमी हुई है। नहीं भूलना चाहिए कि भारत का सूचना-तकनीकी और सेवा क्षेत्र वैश्विक निर्यात का बड़ा स्रोत है। बीते अगस्त में भी सेवाओं के निर्यात में करीब सात फीसदी वृद्धि हुई, जिसका मतलब यह है कि सेवाओं के व्यापार के मामले में भारत अधिशेष की स्थिति में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय सेवाओं की मांग बढ़ने से समग्र व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। बढ़ते व्यापार घाटे को नजर अंदाज बेशक नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का स्वाभाविक हिस्सा भी है, जो संकेत देता है कि देश विकास कर रहा है और उसकी मांगें बढ़ रही हैं। ऐसे में, दीर्घकालिक व सुनियोजित नीतियों के जरिये आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात को बढ़ावा देते हुए इसे आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि विकास के अवसर के रूप देखना चाहिए।

## विकास की राजनीति और मुफ्त की रेवड़ी

**विकास की राजनीति की राह में एक बड़ी समस्या राजनीति के तात्कालिक चुनावी हितों के फंदे में फंस जाने से पैदा होती है, जिसमें लोक लुभावन वादों को ही 'न्याय' एवं 'सामाजिक न्याय' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप एवं कांग्रेस के विकास मॉडल में यह समस्या देखी जा सकती है।**

भारत आज विकास की आकांक्षाओं वाला देश है। अतः भारत को आज 'विकास की राजनीति' चाहिए। देश में इसी विकास की बढ़ती आकांक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विकास की राजनीति' का जो व्याकरण 2005 के आसपास गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए गढ़ा था, उसे 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने सार्वदेशिक एवं सर्व-सामाजिक विस्तार देने की बार-बार कोशिश की है। यह जानना बेहद रोचक है कि जनता के बीच बढ़ती विकास की आकांक्षा एक तरफ राज्य एवं सत्ता की राजनीति से जुड़े राजनीतिक दलों को विकास की राजनीति की तरफ उन्मुख करती है, दूसरी तरफ विकास की राजनीति जब आगे बढ़ती है, तो वह जनता के मन में विकास की आकांक्षा को मजबूत करती है।



**बद्री नारायण**
*राजनीतिक विश्लेषक*

विकास की राजनीति का आर्थिक विकास के साथ नाभि-नाल संबंध होता है। आर्थिक विकास की तेज गति विकास की राजनीति के लिए फलक तैयार करती है। बाजार की बढ़ती विक्रय शक्ति एवं लोगों की बढ़ती क्रय शक्ति इस माहौल को रचने में बड़ी भूमिका निभाती है। पैसे के डिजिटल आदान-प्रदान ने समाज के विभिन्न वर्गों में पैसे की आवाजाही की गति को तेज किया है। इसने लोगों में विकास की आकांक्षा को प्रबल किया है।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकास के जो कार्य हुए हैं, तीर्थ, पर्यटन एवं बाजार का जो सम्मिश्रण यहां बना है, उसने न केवल बनारस में, बल्कि पूर्वांचल के एक बड़े भाग में पैसे की आवाजाही को तीव्र किया है। इस 'आवाजाही' ने इस क्षेत्र के गांवों में फैली जड़ता एवं आर्थिक आलस्य को तोड़ा है एवं लोगों में विकास की आकांक्षा तेज हुई है। इसके कारण इस क्षेत्र के लोगों में सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक गतिशीलता बढ़ी है।

विकास की राजनीति विकासमान देशों एवं अविकसित देशों का मुख्य नारा एवं मूल राजनीतिक एजेंडा होता है। भारत अत्यंत तीव्रगति



से विकास करने वाला देश है। इसने आगामी 2047 तक अपने लिए 'विकसित भारत का लक्ष्य' तय किया है। ऐसे में भारतीय राजनीति का मुख्य एजेंडा विकास की राजनीति ही होना चाहिए।

हमें यह समझना होगा कि विकास की राजनीति एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। विकास की प्रक्रिया की यह डगर बहुत मुश्किल एवं घुमावदार है। यह कई बार लोगों के कुछ वर्गों के निहित स्वार्थ को तोड़कर उन्हें बड़े परिवर्तनों के लिए बाध्य करती है। इस प्रक्रिया में कई बार लोगों का एक वर्ग नाराज भी होता है एवं चुनावों में नकारात्मक असर भी पैदा करता है। ऐसे में 'प्रबुद्ध जनमत' की बड़ी भूमिका होती है। प्रबुद्ध जनमत जनता के छितरे, अनेक तात्कालिक हितों एवं निहित स्वार्थों से जनमन को निकालकर उन्हें बड़े परिवर्तनों के लिए तैयार करता है। यह 'प्रबुद्ध जनमत' शिक्षित जन, लेखक, कवि, बौद्धिक वर्ग, पत्रकार एवं निष्पक्ष राजनीतिक विचारकों एवं एक्टिविस्ट्स से मिलकर बनता है। दुनिया के अन्य मुल्कों, यथा फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में 'प्रबुद्ध जनमत' राष्ट्र एवं समाज में परिवर्तन के लिए सकारात्मक माहौल बनाता है।

लेकिन भारत में यह समस्या है कि एक तो यहां 'प्रबुद्ध जनमत' का यह संवर्ग बहुत छोटा है, जबकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। दूसरा, उसका एक वर्ग जाति, धर्म एवं अनेक निहित राजनीतिक स्वार्थों में स्वयं बंधा हुआ है। अगर इस संवर्ग का विस्तार एवं विकास सम्यक ढंग से हो, यह संवर्ग अगर अपने छोटे-छोटे हितों एवं विभेदों से बाहर निकल कर 'विकास की राजनीति' के पक्ष में जनमत निर्माण के काम को आगे ले जा सके, तो इससे 'विकसित भारत' के मिशन को मदद मिलेगी। 'विकास की राजनीति' की इस प्रक्रिया में अनेक बाधाएं हैं। इसके रास्ते में पहली बाधा 'जाति की राजनीति' है। 'जाति की राजनीति' एक प्रतिगामी राजनीतिक प्रक्रिया है, जो विकास की राजनीतिक यात्रा को बार-बार बाधित करती रहती है। जिन राजनीतिक शक्तियों में विकास की दीर्घकालिक राजनीति करने का धैर्य नहीं है, वे इस 'शॉर्टकट' से चुनावी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करती हैं।

भारत में 'जाति की राजनीति' का व्याकरण बिल्कुल अलग होता है। वह विकास का अपना स्वप्न गढ़ता है, जो तुरत-फुरत, टकाटक एवं फटाफट आकर्षणों पर टिका होता है। 'जाति की राजनीति' को सामाजिक न्याय की राजनीति से जोड़कर राजनीतिक शक्तियां चमकदार शब्दावली, तात्कालिक स्वार्थों से स्वप्न गढ़ तो लेती हैं, किंतु ये स्वप्न मात्र मृगतृष्णा होते हैं, जिससे दमित एवं पिछड़े समूहों की जनता बार-बार ठगी जाती है। जाति भाव को अपने ढंग से गढ़कर चुनावी राजनीति करने वाली राजनीतिक शक्तियां अगर उसे संकुलित कर सामाजिक न्याय के बड़े हितों से जोड़ने का काम करती हैं, तो वह भी अंततः विकास की राजनीति की दिशा में ही आगे बढ़ता है।

विकास की राजनीति के लिए दूसरी समस्या राजनीति के तात्कालिक चुनावी हितों के फंदे में फंस जाने से पैदा होती है, जिसमें मुफ्त की रेवड़ी (फ्रीबीज), लोक-लुभावन वादों को ही 'न्याय' एवं 'सामाजिक न्याय' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के विकास मॉडल में यह समस्या देखी जा सकती है। इन दलों का विकास मॉडल यों भी तात्कालिक एवं जाति की राजनीति से बार-बार बाधित होता रहता है। इस नए संदर्भ में इन दलों को भी विकास के दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर देखना होगा। उन्हें यह भी समझना होगा कि सामाजिक कल्याण एवं गिफ्ट पॉलिटिक्स में फर्क होता है। इन्हें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में गिफ्ट पॉलिटिक्स की आर्थिक दुर्गति एवं पंजाब में ऐसी योजनाओं की क्षण-भंगुरता से सीखना होगा।

कुछ ही दिनों में हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखना यह होगा कि इन राज्यों में विकास की राजनीति कैसे जातीय, धार्मिक एवं क्षेत्रीय स्वार्थों से टकराती है। इस टकराहट में कौन कितना लहूलुहान होता है, यह भी देखना होगा।

edit@amarujala.com

## जीवन धारा



डेविड ह्यूम

*मन में पहले से मौजूद विचारों को नए विचारों में बदलना कठिन है। विचारों को नए पंख देने का एक ही रास्ता है शिक्षा। जीवन का सबसे मधुर मार्ग विज्ञान और शिक्षा के मार्गों से होकर गुजरता है।*

### आशा और खुशी की प्रवृत्ति वास्तविक धन है

*जीवन के रंगीन धागों को हर कोई एक जैसा नहीं देखता, सभी लोगों की अपनी अलग-अलग धारणाएं होती हैं। सुंदरता किसी भी वस्तु का गुण नहीं है, यह केवल उस मन में मौजूद है, जो उस पर विचार करता है। और प्रत्येक मन एक अलग सौंदर्य को देखता है। कोई वस्तु किसी को विकृत लग सकती है, तो दूसरे को उसमें सौंदर्य दिख सकता है। हमारा मस्तिष्क किसी को देखने के बाद जो धारणा बनाता है, वह हमारे पहले के अनुभव या मन में खुद से बनाए हुए विचारों की होती है। इसी वजह से हम कई बार दूसरों के बारे में गलत धारणा रखते हैं।*

*मानव जाति का अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से अपने विचारों में सकारात्मक और हठधर्मी होने के लिए प्रवृत्त होता है। और जब वे केवल एक पक्ष को देखते हैं, और दूसरे तर्क के बारे में कोई विचार नहीं रखते हैं, तो वे खुद को उन सिद्धांतों के प्रति समर्पित कर देते हैं, जिनके वे इच्छुक होते हैं। वे दूसरे लोगों के पक्ष को सुनते ही नहीं हैं। हमारे मन में पहले से मौजूद विचारों को नए विचारों में बदलना कठिन है। अपने विचारों को नए पंख देने का एक ही रास्ता है शिक्षा। जीवन का सबसे मधुर और सबसे अहानिकर मार्ग विज्ञान और शिक्षा के मार्गों से होकर गुजरता है। और जो कोई भी इस मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटा सकता है, या नई संभावना को खोल सकता है, उसे मानव जाति का हितचिंतक माना जाना चाहिए।*

*जब मनुष्य अपने एक ही विचारों तक सीमित रहता है, तो वह दर्द और कठिनाई के साथ रेंगता रहता है, जबकि नए विचार करने की शक्ति हमें एक पल में ब्रह्मांड के सबसे दूर क्षेत्रों में ले जा सकती है। मनुष्य का हृदय सबसे स्पष्ट विरोधाभासों को सुलझाने के लिए बना है। हर आनंद जल्द ही बेस्वाद और अरुचिकर हो जाता है। जब मैं बाहर की ओर देखता हूं, तो मुझे हर तरफ विवाद, विरोधाभास, क्रोध और बदनामी दिखाई देती है, जब मैं अपने भीतर देखता हूं, तो मुझे संदेह और अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं मिलता।*

*जब कोई राय हमें बेतुकी बातों की ओर ले जाती है, तो वह निश्चित रूप से गलत है। मानव जाति का अधिकांश हिस्सा बुराई और पुण्य के बीच झूलता रहता है। मानव स्वभाव में एक बहुत ही उल्लेखनीय प्रवृत्ति होती है कि वह बाह्य वस्तुओं पर वही भावनाएं बरसा देता है, जो वह स्वयं में देखता है, तथा हर जगह उन विचारों को ढूंढ लेता है, जो उसके लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं। आशा और खुशी की प्रवृत्ति वास्तविक धन है। भय और दुख की प्रवृत्ति वास्तविक गरीबी है। जब हम एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तब वास्तविक उपचार होता है। जब हम अपनी पिछली संवेदनाओं और भावनाओं के बारे में सोचते हैं, तो हमारा विचार एक विश्वसनीय दर्पण होता है, जो अपनी वस्तुओं की सही नकल करता है। लेकिन यह उन रंगों में होता है, जो हमारी मूल धारणाओं की तुलना में अधिक फीके और धुंधले होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बहस का विषय न हो, और जिसके बारे में विद्वानों के विचार विपरीत न हों।*

### दूसरों को भी सुनें

सूत्र

*अक्सर हम अपने विचारों के प्रति इतने दृढ़ और प्रतिबद्ध होते हैं कि दूसरों के विचारों को सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन अपने ही विचारों के किले में कैद रहने वाला व्यक्ति अक्सर कठिनाइयों से जूझता रहता है, जबकि नए विचारों का स्वागत करने वाला ब्रह्मांड के नए क्षितिजों तक पहुंच सकता है। इसलिए दूसरों के विचारों को भी सुनकर उन पर विचार करना चाहिए।*

## दूसरा पहलू

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने नई नीति के तहत खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर कंटेंट जारी करने की अनुमति दी है।

### खिलाड़ियों के मीम और पीछे की कहानियां

**पिछले** महीने संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक खेल इतिहास में सबसे ज्यादा सफल खेल आयोजन के लिए याद किए जाएंगे, जिस पर सबसे ज्यादा मीम बने। पारंपरिक रूप से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) का ध्यान ब्रॉडकास्ट मीडिया पर था। आईओसी ने पेरिस 2024 से पहले एथलीटों, कोचों और कर्मचारियों के लिए नई सोशल मीडिया नीति शुरू की, जिसमें एथलीटों को अपने प्रायोजकों के बारे में पोस्ट करने की अनुमति दी गई, ताकि उन्हें अपना ब्रांड बनाने और पैसा कमाने में मदद मिले। संकेत बताते हैं कि आईओसी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले क्षणों को प्रोत्साहित करती है, जिससे दर्शकों को ओलंपिक के नरम पक्षों की झलक मिलती है, जिसमें ओलंपिक के पर्दे के पीछे की गतिविधियां और एथलीटों के जीवन के क्षण भी शामिल होते हैं।



**नाओमी स्मिथ**

सोशल मीडिया नवोदित खिलाड़ियों को प्रसिद्धि दिलाने में अहम योगदान देता है, भले ही वे बाइल्स या बोल्ट जैसे खास खिलाड़ी न हों।

पहली बार टोक्यो ग्रीष्म ओलंपिक 2020 (जो 2021 में हुए) में देखा गया कि खिलाड़ियों ने कंटेंट बनाकर प्रशंसकों के लिए सोशल मीडिया पर जारी किया। अमेरिकी रग्बी सेवन टीम की सदस्य इलोना माहेर सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं, उनके टिकटॉक पर 23 लाख और इंस्टाग्राम पर 36 लाख फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया नवोदित खिलाड़ियों को प्रसिद्धि दिलाने में अहम योगदान देता है, भले ही वे सिमोना बाइल्स या उसेन बोल्ट जैसे खास खिलाड़ी न हों। पेरिस ओलंपिक 2024 ने भी इसे साबित किया है।




तुर्किये के 51 वर्षीय निशानेबाज यूसुफ डिक ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। उनके ऊपर कई मीम बने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी यूसुफ डिक पर मीम पोस्ट किया था।

नॉर्वे के तैराक हेनरिक क्रिस्टियनसेन खेल गांव में चॉकलेट खाने के तरीके, जिसे मफिन मैन कहा गया, को लेकर काफी प्रसिद्ध हुए। वहीं ऑस्ट्रेलियाई ब्रेकडांसर राचेल गुन ने मफिन मैन की नकल की। इसके अलावा, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के कई खिलाड़ियों पर भी मीम्स बने, जिनमें रचनात्मकता भी झलकती है। पेरिस ओलंपिक ने टोक्यो को पीछे छोड़ दिया था। 3.46 करोड़ दर्शकों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन खेल आयोजनों को देखा। तुर्किये के 51 वर्षीय निशानेबाज यूसुफ डिक ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। उनके ऊपर कई मीम्स बने। यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी यूसुफ डिक पर मीम पोस्ट किया था। आईओसी ने सोशल मीडिया को लेकर अपनी रणनीति इसलिए भी बदली है, क्योंकि ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा के लिए समिति की ओर से खिलाड़ियों को कोई भुगतान भी नहीं किया जाता है, जबकि सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों द्वारा पोस्ट डालने से उनकी अपनी पहचान तो बनती ही है, उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलता है। *(द कन्वर्सेशन)*

## आंकड़े

### एलपीजी खपत

दस वर्षों में भारत में घरेलू गैस एलपीजी की खपत 58 फीसदी बढ़ी है। यह वृद्धि उज्ज्वला योजना की वजह से भी है।

| | |
|---|---|
| 2015 | 1.80 |
| 2017 | 2.16 |
| 2019 | 2.49 |
| 2021 | 2.75 |
| 2023 | 2.85 |

गैस खपत के आंकड़े, करोड़ मीट्रिक टन में। | स्रोत : PPAC

**एक भक्त महिला को उसके पति ने कृष्ण के पास जाने से रोका और उसके हाथ-पैर बांध दिए। महिला ने कहा-आप शरीर को जाने से रोक सकते हो, आत्मा को नहीं।**

### मुरली मनोहर की भक्त

**एक** बार की बात है श्रीकृष्ण के सखा काफी भूखे थे। उन्होंने अपने सखाओं को वृंदावन में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों ने यज्ञ से पहले भोजन देने के लिए इन्कार कर दिया। यह बात जब उनकी पत्नियों को पता चली, तो वे श्यामसुंदर के लिए भोजन लेकर निकल पड़ीं। इन्हीं में एक ब्राह्मणी थी, वह मुरली मनोहर को मन से काफी प्रेम करती थी, लेकिन उसका पति बहुत ही क्रोधी था।

उसका पति भोजन कर रहा था, इसी बीच उसे पता चला कि पास की महिलाएं कृष्ण के बुलावे पर उनके लिए भोजन लेकर जा रही हैं। वह थाल सजाकर जाने लगी, तो उसके पति ने कहा, 'मैंने अभी भोजन नहीं किया है, तुम कहां जा रही हो।' ब्राह्मणी ने विनम्रता से कहा कि आपका भोजन लगभग समाप्त हो ही गया है। उसने जाने से रोका, तो ब्राह्मणी ने कहा कि वह अपने स्वामी से मिलने के लिए जरूर जाएगी। स्वामी शब्द सुनते ही उसका पति भड़क गया। उसने ब्राह्मणी के हाथ-पैर बांध दिए और कहा कि अब कैसे जाएगी? ब्राह्मणी ने पति से कहा, 'आप मेरे शरीर को बांध सकते हो, पर आत्मा को नहीं।' ब्राह्मणी आंखें बंद कर मुरली मनोहर के ध्यान में मग्न हो गई। वह इतनी मग्न हुई कि निढाल होकर गिर पड़ी और उसकी आत्मज्योति निकलकर परमात्मा से मिल गई। बाद में उसके पति को अपने किए पर काफी पछतावा हुआ।

अंतर्यात्रा
संकलित

## अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 18 जून, 1959

### प्रधानमंत्री की चेतावनी, अनाज संग्रह करने पर होगी कार्रवाई

अनाज का संग्रह रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जायेंगे
श्री नेहरू की व्यापारी वर्ग को चेतावनी
रोटी कपड़ा व मकान की समस्या को पहिले

**प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी है कि अनाज का संग्रह करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने आश्चर्य जताया कि अच्छे उत्पादन के बाद भी मंडियों में गल्ला नहीं आ रहा है।**

## परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त होना होगा

**कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देना होगा, पर इसके लिए व्यापक निवेश की जरूरत होगी।**

सीमा जावेद | मुद्दा

भारत का विनिर्माण क्षेत्र अग्रणी होने के साथ-साथ उल्लेखनीय रूप से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद ऑटोमोबाइल सेक्टर का योगदान करीब सात प्रतिशत है। भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और अब देश में संग्रहीत कुल जीएसटी में इसका योगदान 14-15 प्रतिशत है। हालांकि वर्ष 2016 में देश में ग्रीनहाउस गैसों के कुल उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का योगदान करीब 13 फीसदी रहा है। जाहिर है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देना होगा, लेकिन इसके लिए व्यापक निवेश की जरूरत होगी।

भारत का सड़क परिवहन क्षेत्र मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है और यह देश का सबसे बड़ा तेल उपयोगकर्ता क्षेत्र भी है। देश में पेट्रोलियम पदार्थों के कुल उपभोग में ऑटोमोबाइल सेक्टर की



हिस्सेदारी 44 प्रतिशत है। जहां तक वैकल्पिक ईंधन का सवाल है, तो उसकी भूमिका बहुत सीमित है। जाहिर है, उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र के भारी योगदान को देखते हुए इस क्षेत्र को डीकार्बनाइज करने के प्रयास नेट-जीरो लक्ष्यों को हासिल करने के लिहाज से अहम हैं। परिवहन क्षेत्र को डीकार्बनाइज किए बिना नेट-जीरो लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल साबित होगा।

जाहिर है, इसके लिए भारत को ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर रहना होगा। नतीजतन इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, नई टेक्नोलॉजी और अनुसंधान एवं विकास पर बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करना जरूरी हो गया है। क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी इनीशिएटिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक, परिवहन क्षेत्र को डीकार्बनाइज किए जाने से परिवहन उद्योग, खासकर इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में विकास के अवसर पैदा हो सकते हैं।

'इंडिया ऑटो इंडस्ट्री : मैपिंग कोर्स टू नेट जीरो 2070' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2070 तक देश में ऑटो सेक्टर का रूपांतरण होने से 197 खरब डॉलर का बाजार तैयार हो सकता है। इसमें 63 प्रतिशत हिस्सेदारी कारों की होगी और इनका योगदान 155 खरब डॉलर का होगा। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2070 तक करीब 263 अरब डॉलर का सबसे बड़ा निवेश चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी हो सकता है।

ट्रक निर्माताओं द्वारा वर्ष 2070 तक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 45 अरब डॉलर से अधिक के निवेश का अनुमान है। इसके अलावा, वर्ष 2020 से 2070 के बीच ऑटोमोबाइल क्षेत्र के रूपांतरण से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में 41 खरब डॉलर का राजस्व भी हासिल होने का अनुमान है।

बैटरी की सालाना 1,716 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने और पूरी तरह से घरेलू स्तर पर उत्पादन करने के लिए निर्माणकर्ताओं को वर्ष 2070 तक 196 अरब डॉलर का निवेश करना ही होगा। वर्ष 2070 तक भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को पूरी तरह से नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्यूफैक्चरर्स (ओईएम) इकाइयों को नई प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण पर 323 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश करने की जरूरत होगी।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में हो रही प्रगति की अगुवाई मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 के बीच के छह वर्षों में दोपहिया वाहनों की सालाना बिक्री 140 से 210 लाख इकाइयों तक रही है। इस दिशा में ऑटो या तीन-पहिया वाहनों का भी उल्लेखनीय योगदान है। वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 के बीच ऐसे 3-7 लाख वाहनों की बिक्री हुई। इस अवधि में ऑटो बाजार 180 से 260 लाख गाड़ियों की सालाना बिक्री के बीच रहा। वित्त वर्ष 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों ने कुल 12 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ दस लाख का आंकड़ा पार कर लिया।

वर्ष 2020 से 2070 के बीच इलेक्ट्रिक ट्रकों की भी बिक्री बढ़ने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि यह अनुमान कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री से संबंधित राजस्व में 834 अरब डॉलर से अधिक का योगदान देगा। बड़े-बड़े महानगरों की हवा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो चुकी है, इसके पीछे उद्योगों से निकलने वाला धुआं और विनिर्माण क्षेत्र के अलावा डीजल-पेट्रोल से चलने वाले वाहन भी हैं। इसलिए हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, इसके लिए मौजूदा परिदृश्य में इलेक्ट्रिक वाहन सबसे अच्छा विकल्प हैं।

संपादकीय जागरण

(12) गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 : आश्विन कृष्ण – 2 वि. 2081

धैर्य एक मौन प्रार्थना है

# जम्मू-कश्मीर का संदेश

जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के मतदान में लोगों ने जिस उत्साह के साथ अपने मताधिकार का उपयोग किया, वह न केवल यह बताता है कि यह केंद्र शासित प्रदेश शांति की राह पर बढ़ रहा है, बल्कि यह भी कि यहां के लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ी है। इसका प्रमाण यह है कि शाम पांच बजे तक 58 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हो चुका था। इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि उन क्षेत्रों में भी अच्छा-खासा मतदान हुआ, जो कभी आतंक के गढ़ के रूप में जाने जाते थे। महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान में भाग लिया, बल्कि यह भी है कि बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। इनमें वे भी हैं, जो पहले कभी आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक थे तथा पाकिस्तान की भाषा बोलते थे। स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर की चुनाव प्रक्रिया पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेरने और उसे इस दुष्प्रचार से वंचित करने वाली है कि इस भारतीय भू-भाग में लोकतंत्र की अनदेखी हो रही है। वास्तव में लोकतंत्र का दमन तो उसके कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हो रहा है। यह किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों के साथ किस तरह दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहा है। चूंकि जम्मू-कश्मीर में दस साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ये ऐसे चुनाव हैं, जो अनुच्छेद 370 और 35-ए हटने के बाद हो रहे हैं, इसलिए उन पर देश ही नहीं, दुनिया की भी नजर होना स्वाभाविक है। जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र की महत्ता और प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ यह भी रेखांकित कर रहे हैं कि अंततः घाटी की जनता को यह समझ आ गया कि लोकतांत्रिक तौर-तरीके ही उसकी समस्याओं के समाधान में सहायक होंगे, न कि आतंक और अलगाव का रास्ता। अभी यह कहना कठिन है कि जम्मू-कश्मीर की जनता सत्ता की बागडोर किसे सौंपेगी, लेकिन भावी सरकार को इसका आभास होना चाहिए कि लोग अपनी किन समस्याओं के समाधान की आस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं। वहां की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को भी सजग रहना होगा। उसे इसके प्रति भी सावधान रहना होगा कि कश्मीर में असर रखने वाले जो राजनीतिक दल लोगों से यह वादा करने में लगे हुए हैं कि अनुच्छेद 370 की वापसी हो सकती है, वे दिवास्वप्न दिखाने का ही काम कर रहे हैं। ऐसे दलों से घाटी की जनता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण अनुच्छेद की वापसी अब संभव नहीं। इसीलिए कांग्रेस ने इस पर मौन रहना उचित समझा। यह सही है कि स्थितियां अनुकूल होते ही जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, लेकिन स्थितियां पूरी तौर पर सामान्य होने के बाद ही और स्थितियों के सामान्य होने की पुष्टि तब होगी, जब कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौट सकेंगे।

# समाधान आवश्यक

बिजली कंपनी के उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों की कार्यालय में तय दिवस और समय पर उपस्थिति अच्छा कदम है। अधिकारी हर मंगलवार और शुक्रवार को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न एक बजे तक कार्यालय में बैठेंगे और उपभोक्ताओं की शिकायत सुनकर उसका निस्तारण करेंगे। उपभोक्ताओं की शिकायत सुनने और उनके निस्तारण के लिए यह प्रयास अच्छा है, लेकिन यह तब संतोषजनक निस्तारण के लिए मूर्त रूप ले पाएगा, जब निर्देश का भली प्रकार पालन हो व अधिकारी तय समय पर बैठकर शिकायतें सुनें। निस्तारण के प्रति गंभीरता दिखाएं। टरकाने वाली या चक्कर लगवाने वाली प्रवृत्ति का त्याग करना होगा। उपभोक्ताओं की समस्या को समझना होगा क्योंकि ऐसा नहीं होने पर उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए विवश होना पड़ेगा और जिस नीयत के साथ यह व्यवस्था बनाई गई है, वह धूमिल हो जाएगी। स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ी हैं। इन शिकायतों के बढ़ने का एक कारण स्मार्ट मीटर के प्रति उपभोक्ता के संशय को पूरी तरह दूर न कर पाना और उनकी शिकायतों का निस्तारण उचित प्रकार से नहीं होना भी है। डिफरमेंट चार्ज यानी स्वीकृत से अधिक भार क्षमता के विद्युत उपभोग पर कटने वाली राशि के बारे में भी उपभोक्ताओं को कई प्रकार के संशय हैं। इसके अतिरिक्त मीटर तेज चलने की शिकायतों के निस्तारण में समय लगने के कारण भी वे परेशान होते हैं। कार्यालय में तुरंत मीटर चेकिंग की व्यवस्था हो जाने से उपभोक्ताओं की शंका का समाधान उसी समय हो जाएगा और स्मार्ट मीटर के प्रति उनकी धारणा को बदलने में सहयोग भी मिलेगा।

**स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के बढ़ने का एक कारण उपभोक्ता की शिकायतों का उचित निस्तारण नहीं होना भी है।**

**कह के रहेंगे** — माधव जोशी

**जागरण जनमत** — कल का परिणाम

**क्या आतिशी अरविंद केजरीवाल की सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी हैं?**




**आज का सवाल**
क्या कांग्रेस का यह कहना सही है कि एक साथ चुनाव व्यावहारिक नहीं?

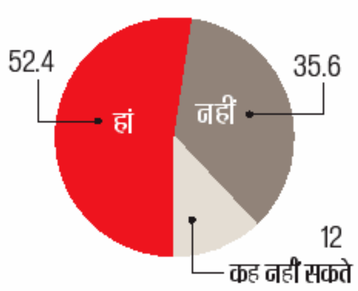

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

# आर्थिक सुधारों पर बने राजनीतिक सहमति

**जीएन वाजपेयी**

**भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के तीन कारकों में से भूमि और श्रम अब भी सुधारों की बाट जोह रहे हैं**

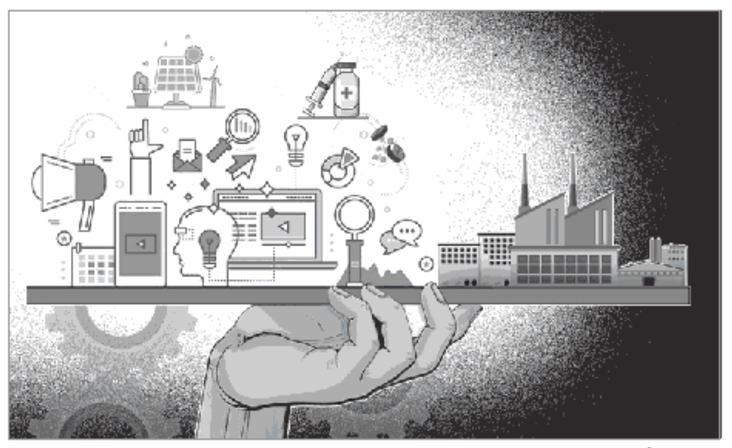

अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से वृद्धि कर रही है। इस समय वृद्धि की जो रफ्तार है, उसके आधार पर भारत 2030 तक सात ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की आर्थिकी बनकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वृहद आर्थिक स्थायित्व, युवा आबादी, गतिशील एवं जीवंत लोकतंत्र और तटस्थ भू-राजनीतिक दृष्टिकोण जैसे पहलुओं के चलते भारत विदेशी निवेशकों के लिए निवेश के पसंदीदा ठिकाने के रूप में उभरा है। इसके बावजूद निरंतर तेज वृद्धि के लिए भूमि, श्रम और कृषि के मोर्चे पर तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। तभी देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है। अच्छी बात है कि देश के कुछ राज्यों में विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा दिख रही है। इन राज्यों की सरकारें निवेशकों के प्रति उदारता दिखाने में कोताही नहीं कर रहीं। याद रहे कि उद्यमी अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए ही अपनी पूंजी और कौशल को दांव पर लगाकर प्रयास करते हैं। किसी उद्योग या इलाके में निवेश के फैसले पर पहुंचने के लिए कई पहलू प्रभावी होते हैं। इसमें उस इलाके तक पहुंच, उद्यम चलाने की लागत, मानव संसाधन उपलब्धता, निवेश, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के अलावा शासन एवं कर व्यवस्था, नियमन और कानून के स्तर पर निरंतरता जैसे पहलू बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर, न्यूनतम जोखिम के साथ अधिकतम लाभ ही निवेश का आधार मंत्र बनता है।

भारतीय राज्यों में आर्थिक स्तर पर कई असमानताएं दिखती हैं। गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी को देखें तो करीब 7,169 डालर के साथ यह राष्ट्रीय औसत से लगभग तीन गुना अधिक है। वहीं बिहार की जीएसडीपी 1,000 डालर से भी नीचे यानी राष्ट्रीय औसत से तीन गुना कम है। अप्रैल-जून, 2024 के शहरी युवा रोजगार स्थिति के आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार में पुरुषों की श्रम भागीदारी दर 32.9 प्रतिशत, जबकि महिलाओं की महज 5.3 प्रतिशत रही। यह देश में श्रम भागीदारी का सबसे निचला स्तर रहा। जबकि महाराष्ट्र में पुरुषों में यह दर 55.2 प्रतिशत तो महिलाओं में 22.9 प्रतिशत रही। रोजगार की दर राज्य की अर्थव्यवस्था की सेहत को दर्शाती है। अधिक संपन्न राज्य में यह दर काफी ऊंची है। ऐसी विषमता बड़े पैमाने पर आंतरिक पलायन और सामाजिक व्यग्रता बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय चिंता को बढ़ाती है। विषमता की यह स्थिति एकाएक नहीं बनी। इसके पीछे तत्कालीन सरकारों का वह रवैया मुख्य रूप से जिम्मेदार है कि उन्होंने उद्यमियों का भरोसा जीतने का प्रयास नहीं किया। शासन की गुणवत्ता, राजनीतिक अस्थिरता और कुछ मामलों में कानून एवं व्यवस्था की लचर स्थिति सबसे बड़े कारक रहे। राज्य को आर्थिक वृद्धि के पंख लगाकर ही विषमता को दूर किया जा सकता है। यह विषमता राजनीतिक स्तर पर भी मुद्दा बन जाती है। इस मोर्चे को दुरुस्त करने का दारोमदार भी राजनीतिक बिरादरी पर है।



अवधेश राजपूत

अफसोस है कि भारतीय समाज जाति, नस्ल और धर्म जैसे तमाम आधारों पर विभाजित है। लोकतंत्र में लोगों के फैसलों में अक्सर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे आर्थिक पहलुओं पर हावी हो जाते हैं। इन कारकों के संयुक्त प्रभाव का ही परिणाम है कि चुनावी सफलता के लिए मिश्रित समीकरणों को साधना पड़ता है। जीत का फार्मूला तैयार करने की मजबूरी में कुछ समझौते करने पड़ जाते हैं, जिससे हितों के टकराव और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में कुछ स्वयंभू सामाजिक संगठन सामने आ जाते हैं, जो अपने समर्थन की आड़ में वारे-न्यारे करने लगते हैं। भारतीयों ने कहने को तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति का तिरस्कार किया, लेकिन व्यवहार में कथित सामाजिक न्याय के नाम पर परत दर परत विभाजन को और महीन करते गए। इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता कि आर्थिक रूप से विपन्न लोगों की दुश्वारियों का अंत ही अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण जैसी किसी व्यवस्था के मूल में होना चाहिए। इसलिए अनुकूल नीतियों का बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, उन्हें लागू करने का क्या उपयुक्त तरीका हो सकता है और उनके संभावित परिणामों जैसे पहलुओं पर संसद एवं राज्य विधानमंडलों में व्यापक विमर्श होना चाहिए। तैयार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और संभावित परिणामों को लेकर सरकार को जवाबदेह बनाया जाना भी उतना ही आवश्यक है।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ कुछ मामलों में ऊंची आर्थिक वृद्धि के अनुकूल नहीं रह गई है। विरोधी को मात देने की लिए ऐसी लुभावनी घोषणाओं का दौर चल निकला है, जिसके चलते कुछ राज्य दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए हैं। सामाजिक न्याय रेवड़ियां बांटकर नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त बनने पर ही संभव है। याद रहे कि लोकलुभावनवाद वंचितों का भला करने के बजाय अक्सर नारेबाजी में सिमटकर राज्य के लिए आर्थिक मुश्किलों को आमंत्रण देने वाला साबित होता है। वैसे भी, अर्थव्यवस्था की ऊंची वृद्धि और आप्टिमल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में सीधा संबंध है। चूंकि भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के तीन कारकों में से भूमि और श्रम सुधारों की बाट जोह रहे हैं। भूमि और श्रम सुधारों को भावनात्मक रंग दिया जाता है और इसमें आम सहमति नहीं बन पा रही है। यह भी एक कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी क्षमताओं के अनुरूप तेजी नहीं पकड़ पा रही। स्थिति यह है कि चाहे जिसकी सरकार हो, विपक्ष में रहने वाला दल किसी भी सुधार का न केवल विरोध करता है, बल्कि उसकी आड़ में भावनात्मक राग अलापता है। इससे वंचितों का ही नुकसान हो रहा है। इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भारतीय मतदाता समझदार हो रहे हैं। तमाम उदाहरणों से जुड़े साक्ष्य दर्शाते हैं कि केवल 'अतिशय कल्याणवाद' ही वोट देने का प्रभावी आधार नहीं बनता। गरीबी के उन्मूलन और साझा समृद्धि के युग का प्रवर्तन करने के दृष्टिकोण से राजनीतिक परिपक्वता प्रदर्शित करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। यह केवल ऊंची आर्थिक वृद्धि की ओर उन्मुख करने वाली आम सहमति और सुधारों से जुड़े सभी संभावित कदमों के प्रभावी कार्यान्वयन से ही संभव हो सकता है।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

# जल निकासी के उपायों की अनदेखी

**प्रोफेसर मान सिंह**

**नदियों को जोड़ा जाए ताकि एक स्थान का पानी दूसरे स्थान का संरक्षित जल संसाधन बने, न कि ऐसे ही बहकर व्यर्थ हो जाए**

इस साल वर्षा ऋतु के दौरान देश के कई हिस्सों में अतिवृष्टि हो रही है। इस बार देश के पूर्वी तट वाले राज्य ही नहीं, बल्कि पश्चिमी तट के राज्य जैसे-गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में भी जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई है। असंख्य बांधों के फाटक लबालब भरे जलाशयों से पानी निकालने के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे सभी बांधों के निचले हिस्से में बाढ़ आ गई है। इससे खड़ी फसलों और संपत्ति की क्षति हो रही है। अब ऐसी स्थिति हर दूसरे-तीसरे साल पैदा होने लगी है, कभी इस राज्य में तो कभी उस राज्य में। परिणामस्वरूप शहरी संपत्ति तथा आधारभूत ढांचे की भारी क्षति हो रही है।

भारतीय किसान और खेतिहर मजदूर ग्रामीण आर्थिकी का हिस्सा हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते उनका सामना कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी चक्रवात से पड़ने लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में फसलें जलमग्न होकर नष्ट हो जा रही हैं। जो किसान गरीबी रेखा के ऊपर आ गए थे, जल के इस कहर से एक बार पुनः गरीबी रेखा को छूने या उसके नीचे जाने लगे हैं। प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना अब एक सालाना परंपरा बन गई है। किसानों और कृषि मजदूरों को स्थायी रूप से गरीबी के दायरे से बाहर निकालने के लिए नए उपायों के बारे में अब सोचना होगा। इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम को उन्नत बनाने और अतिवृष्टि के दुष्परिणामों से बचने के लिए जलनिकासी के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की आवश्यकता बढ़ गई है।

भारत विश्व के 2.4 प्रतिशत भौगोलिक भूभाग एवं चार प्रतिशत जल संसाधन की मदद से अपनी खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताएं पूरी करता है, लेकिन अतिवृष्टि से आई बाढ़ से दलहन और तिलहन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। देश पहले से ही दाल और खाद्य तेल की कमी से जूझ रहा है। दरअसल पानी की अधिकता दलहन और तिलहन की दुश्मन है। 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया था। उसी दौरान भारत विश्व बाजार से दाल आयात करने के लिए मजबूर हुआ। घरेलू मांग की पूर्ति के लिए भारत ने कनाडा, बर्मा, तंजानिया, मोजांबिक आदि देशों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनके पास भी दलहन की कमी थी। लिहाजा ऊंचे दाम पर दूसरे देशों से भारत दाल आयात के लिए मजबूर हुआ। तभी से देश में दलहन की कीमत बहुत बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति इस साल भी पैदा होने की आशंका है।



बरसात में आम हो गए हैं ऐसे दृश्य ● प्रेट्र

आज भारत की आबादी चीन से अधिक हो गई है। हमारे देश के नागरिक प्रोटीन की अपनी आवश्यकता मुख्य रूप से दाल से ही पूरी करते हैं। ऐसे में हमें फिर से विश्व बाजार की ओर देखना होगा। इस वर्ष आए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन कम रहने वाला है। लिहाजा आगे भी देश में दलहन और तिलहन की कमी रहने वाली है। वास्तव में दुनिया में कहीं भी इतनी अधिक दाल पैदा नहीं होती कि वहां से आयात कर भारत अपनी मांग पूरी कर सके। दाल के आयात पर भारी खर्च और घरेलू बाजार में इसकी कमी देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ लोगों के पोषण को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए देश में बेहतर जलनिकासी का प्रबंध हो जाए तो बरसात से हो रही जगह-जगह जलमग्नता और बाढ़ पर कारगर नियंत्रण किया जा सकता है।

अब जलवायु परिवर्तन जगजाहिर है। जलवायु परिवर्तन वायु और जल से संबंधित है। इसके चलते तूफान-चक्रवात, अतिवृष्टि या बादल का फटना, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं अब बार-बार होंगी। इससे देशव्यापी दलहन और तिलहन फसलों की हानि के अलावा मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्टर जैसे-रेल, सड़क, बिजली, पुल और दूरसंचार नेटवर्क आदि की भारी क्षति होती रहेगी। परिणामस्वरूप राष्ट्र को जानमाल की क्षति भी उठानी पड़ी। इससे बचने के लिए हमें जल्द ही कुछ दीर्घकालिक समाधान करने चाहिए। इस पर राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श करना समय की मांग है। इसके लिए सबसे पहले बाढ़, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का एक वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित विभागों और मंत्रालयों के सहयोग से किया जाना चाहिए। इसके विश्लेषण के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुंच कर एक राष्ट्रव्यापी नीति बनानी चाहिए।

यह अच्छी बात है कि जल संरक्षण के लिए इन दिनों देश में आठवें जल सप्ताह का आयोजन हो रहा है। उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ठीक कहा कि जल स्रोत सीमित हैं और उनके सक्षम उपयोग से ही सभी के लिए जल की आपूर्ति संभव है। उन्होंने जल की हर एक बूंद को बेशकीमती बताते हुए देश के प्रत्येक नागरिक से जल योद्धा के रूप में कार्य करने का आह्वान किया। अनेक वैज्ञानिक अध्ययन समाज को यह बताते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में प्राकृतिक आपदाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और कहर बरपाएंगी। फलस्वरूप बड़ी संख्या में जलवायु परिवर्तन शरणार्थी सामने आएंगे। आगे जल प्रलय का प्रारूप क्या होगा, यह सिर्फ प्रकृति को ही पता है। इससे निपटने के लिए 142 करोड़ जनसंख्या वाले भारत को एक आपदा प्रबंधन और निवारण तंत्र बनाकर रखना होगा। इसके लिए गांवों और शहरों में जल निकासी के लिए व्यापक जल इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। इन्फ्रास्ट्रक्टर को इस तरह बनाना चाहिए कि वे भारी बारिश को भी झेल सकें। साथ ही सभी नदियों को आपस में जल्द से जल्द जोड़ा जाना चाहिए ताकि एक स्थान के बाढ़ का पानी दूसरे स्थान का संरक्षित जल संसाधन बने, न कि ऐसे ही व्यर्थ में बह जाए। इस मद में भारी निवेश करना होगा। यह भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहायक होगा।

(लेखक नई दिल्ली स्थित आइसीएआर-आइएआरआइ के जल प्रौद्योगिकी केंद्र के पूर्व परियोजना निदेशक हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### धर्म

धर्म क्या है? यह गूढ़ सवाल है। हर व्यक्ति स्वविवेक के आधार पर धर्म की व्याख्या करता आया है। भूखे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धर्म रोटी है। अपने पेट की क्षुधा को शांत करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। संकट में फंसे हुए व्यक्ति को संकट मुक्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन मनीषियों ने धर्म की और भी परिभाषाएं दी हैं। धर्मज्ञ व्याख्याकारों ने बताया कि धैर्य, क्षमा, अस्तेय, पवित्रता, आत्मसंयम, बुद्धि, विद्या, सत्य एवं अक्रोध आदि को हर तरह से अंगीकार करना धर्म है। उन्होंने इसमें जोड़ा-स्वयं को रुचिकर न हो, वह व्यवहार दूसरों के साथ मत करो।'

व्यास जी ने धर्म की लंबी व्याख्या की। राजा, प्रजा, साधु-संन्यासी के धर्मों को विभाजित किया और धर्म का उल्लंघन करने की मनाही की। वात्स्यायन ने बताया कि मानव के लिए धर्म मनसा, वाचा, कर्मणा होता है। यह केवल क्रिया या कर्मों से संबंधित नहीं है, बल्कि धर्म चिंतन और वाणी से भी संबंधित है। सप्त ऋषियों में से एक गौतम ऋषि की मानें तो उन्होंने बताया है कि जिस काम के करने से अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है। वहीं कबीरदास का कहना है कि 'कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानिअइ सो काफिर बेपीर।' तुलसीदास भी कबीर की बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि 'परहित सरिस धर्म नहीं भाई।' यानी दूसरों का भला करना ही धर्म है। प्रयाग से जल भर कर रामेश्वरम चढ़ाने निकले एकनाथ बाबा रामेश्वरम मंदिर के बाहर पड़े गधे को जल पिला देना धर्म समझते हैं।

इन सब विचारों को व्यवहार की कसौटी पर कसा गया तो निष्कर्ष निकलता है कि जब तक परपीर के लिए संवेदना न जागे, जब तक परहित के लिए अंदर से भावों के धक्के न लगें तब तक सारा कर्मकांड, समस्त धर्मज्ञान व्यर्थ है। धर्मपरायण वही है, जो रोते हुए इंसान को हंसा दे। धार्मिक वही है, जो दुखीजनों के दुख बांट सके। यही सच्ची पूजा है और यही असली धर्म भी।

पुष्पेंद्र दीक्षित

## पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

### संभव है एक देश-एक चुनाव

'एक साथ चुनाव की तैयारी' संपादकीय में सही कहा गया है कि ऐसा होने पर बार-बार होने वाले चुनावों से मुक्ति मिलेगी। यदि ऐसा होता है तो हमारे प्रशासन को जनहित के अन्य मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। अभी तो साल भर देश के किसी न किसी हिस्से में चुनावों की दुंदुभी बज रही होती है। देश के अमूल्य स्रोत इसमें लगते हैं। बस अब हमारे राजनीतिक दलों को थोड़ी फुरसत निकालकर इस मुद्दे पर देशहित को सर्वोपरि मानकर विचार करना चाहिए। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में पंचायत/नगर निगम से लेकर विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए। यह संभव है। दीर्घकालिक हित में अल्पकालिक स्वार्थ त्यागकर विपक्षी दल इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। हमारा चुनाव आयोग एकदम सक्षम है और वह यह कार्य करवा सकता है। हां, एकबारगी कुछ विधानसभाओं को समयपूर्व भंग करना होगा, कुछ का थोड़ा समय बढ़ाना होगा। यही प्रक्रिया स्थानीय निकायों के लिए अपनाई जाएगी। इससे संघीय संरचना मजबूत होगी। हमारा विशाल लोकतंत्र बहुत अनुभवी हो गया है। ऐसा होने पर जहां राजनीतिक विमर्श बदलेगा, वहीं दीर्घकालिक देशहित की नीतियों पर बल दिया जाएगा। राजनीतिक कटुता कम होगी। खर्चीले चुनावों से मुक्ति मिलेगी। प्रशासनिक प्राधिकारी लोकहित के कार्यों को अधिक समय दे पाएंगे। राष्ट्रीय स्रोतों को अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया जा सकेगा। राजनीतिक दल सकारात्मक राजनीति करेंगे। एक देश-एक चुनाव की स्थिति में राजनीतिक दल सोच-समझकर प्रत्याशियों का चयन करेंगे, जिससे अंततः जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

### जल्द हो जनगणना

जनगणना को लेकर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उसमें न केवल देरी होगी, बल्कि वह 2027 से पहले संभव नहीं होगी। मेरी समझ से जनगणना में देर होने की आशंका उभरने का एक कारण यह भी है कि इस बार बजट में उसके लिए कोई प्रविधान नहीं किया गया। अब यदि अगले बजट में उसके लिए प्रविधान किया जाता है तो 2025-26 में ही जनगणना का काम शुरू हो सकता है। जनगणना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है और उसके पूरा होते-होते यदि 2027 बीत जाए तो हैरानी नहीं। 2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण स्थगित की गई थी। जनगणना में देरी होने का मतलब है सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और योजनाओं के निर्माण में 2011 के आंकड़ों से ही काम चलाने की मजबूरी। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग सरकारों के साथ उद्योग जगत और शोध संस्थाएं भी करती हैं। इसके अतिरिक्त संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भी जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। यदि प्रस्तावित जनगणना के आंकड़े सामने आने में देरी होती है तो फिर महिला आरक्षण लागू करने में भी विलंब हो सकता है। संसद व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करना तब संभव होगा, जब निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन होगा और इसके लिए जनगणना के अद्यतन आंकड़े चाहिए होंगे।

अविनाश, आरा

### विदेश में बयान से बिगड़ती छवि

विदेशी धरती पर बेलगाम राहुल गांधी आलेख पढ़ा। राहुल गांधी अब नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वह जब भी विदेश जाते हैं तो ऐसे बयान देते हैं, जिनसे देशविरोधी मुद्दों को हवा मिलती दिखती है। गत दिनों अमेरिका दौरे पर गए राहुल ने कहा, 'आज भारत में लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें पगड़ी या कड़ा धारण करने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जाने में सक्षम होंगे। यही लड़ाई है और सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए है।' इस बयान के जरिये राहुल गांधी विदेशी धरती पर यह जताने की कोशिश करते नजर आए कि भारत में सिख असुरक्षित हैं। सवाल यह है कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने या गुरुद्वारा जाने से रोका जा रहा है? निश्चित तौर पर इसका जवाब न में है। ऐसे में राहुल गांधी के बयान को अगर उनके विरोधी खालिस्तानी आंदोलन से जोड़कर देखें तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विदेशी धरती पर राहुल गांधी की बयानबाजी को वैश्विक प्रचार जरूर मिलता है, लेकिन इससे भारत की छवि लोकतंत्रहीन और तानाशाही वाले देश की बनती है। पिछले साल अमेरिका में ही राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इसके पहले 2022 में लंदन में कहा था कि भारत के आत्मा पर हमले हो रहे हैं और बिना आत्मा के देश कुछ भी नहीं होता। इस पर वरीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी को विचार करना चाहिए।

–पवन कुमार, पटना

## पोस्ट

लेबनान में पेजर विस्फोट की कहानी का सार यही है कि आने वाले समय में युद्ध हथियारों से नहीं लड़े जाएंगे। टेक्नोलाजी ही सबसे बड़ा हथियार होगी।

अरविंद चोटिया@arvindchotia

भारत को जातिगत जनगणना की नहीं, बल्कि वंचित वर्ग के बच्चों के लिए बेहतर सरकारी स्कूलों की दरकार है, ताकि बेहतर नौकरियों के लिए उनकी बढ़िया तैयारी हो सके और उनका जीवन संवर सके।

तवलीन सिंह@tavleen_singh

दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं, मगर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही कराने की मांग करके बड़ा दांव खेला है। इस पर भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को सावधान रहना होगा।

पंकज शर्मा@Pankaj__Sharma

हाल में लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। क्या वह गैर-संवैधानिक था। क्या उससे भारत का संघीय ढांचा टूट गया? एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा को समझे बिना ही विरोध की बीन बजाने वाले लोग समझ नहीं रहे कि निरंतर अंतराल पर होते रहने वाले चुनावों से विकास संबंधी एवं प्रशासनिक कामकाज कितना अधिक प्रभावित होता है।

संजय निरुपम@sanjaynirupam

## जनपथ

लंबी-लंबी लाइनें लोगों में उत्साह,
देखि आज कश्मीर को मुंह से निकले वाह!
मुंह से निकले वाह वोट में जगा भरोसा,
दिखे न अब आतंक पाक का पाला-पोसा।
यह परिवर्तन देख दंग हैं नेता दंभी,
बदल रहीं कश्मीर लाइनें लंबी-लंबी।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 158

********

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 19 सितंबर, 2024

दैनिक जागरण

धैर्य एक मौन प्रार्थना है

## जम्मू-कश्मीर का संदेश

जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के मतदान में लोगों ने जिस उत्साह के साथ अपने मताधिकार का उपयोग किया, वह न केवल यह बताता है कि यह केंद्र शासित प्रदेश शांति की राह पर बढ़ रहा है, बल्कि यह भी कि यहां के लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ी है। इसका प्रमाण यह है कि शाम पांच बजे तक 58 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हो चुका था। इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि उन क्षेत्रों में भी अच्छा-खासा मतदान हुआ, जो कभी आतंक के गढ़ के रूप में जाने जाते थे। महत्वपूर्ण केवल यह नहीं है कि लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान में भाग लिया, बल्कि यह भी है कि बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। इनमें वे भी हैं, जो पहले कभी आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक थे तथा पाकिस्तान की भाषा बोलते थे। स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर की चुनाव प्रक्रिया पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेरने और उसे इस दुष्प्रचार से वंचित करने वाली है कि इस भारतीय भू-भाग में लोकतंत्र की अनदेखी हो रही है। वास्तव में लोकतंत्र का दमन तो उसके कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हो रहा है। यह किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों के साथ किस तरह दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहा है।

चूंकि जम्मू-कश्मीर में दस साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ये ऐसे चुनाव हैं, जो अनुच्छेद 370 और 35-ए हटने के बाद हो रहे हैं, इसलिए उन पर देश ही नहीं, दुनिया की भी नजर होना स्वाभाविक है। जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र की महत्ता और प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ यह भी रेखांकित कर रहे हैं कि अंततः घाटी की जनता को यह समझ आ गया कि लोकतांत्रिक तौर-तरीके ही उसकी समस्याओं के समाधान में सहायक होंगे, न कि आतंक और अलगाव का रास्ता। अभी यह कहना कठिन है कि जम्मू-कश्मीर की जनता सत्ता की बागडोर किसे सौंपेगी, लेकिन भावी सरकार को इसका आभास होना चाहिए कि लोग अपनी किन समस्याओं के समाधान की आस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं। वहां की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को भी सजग रहना होगा। उसे इसके प्रति भी सावधान रहना होगा कि कश्मीर में असर रखने वाले जो राजनीतिक दल लोगों से यह वादा करने में लगे हुए हैं कि अनुच्छेद 370 की वापसी हो सकती है, वे दिवास्वप्न दिखाने का ही काम कर रहे हैं। ऐसे दलों से घाटी की जनता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण अनुच्छेद की वापसी अब संभव नहीं। इसीलिए कांग्रेस ने इस पर मौन रहना उचित समझा। यह सही है कि स्थितियां अनुकूल होते ही जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, लेकिन स्थितियां पूरी तौर पर सामान्य होने के बाद ही और स्थितियों के सामान्य होने की पुष्टि तब होगी, जब कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौट सकेंगे।

## गरीबों की चिंता

उत्तराखंड सरकार गरीबों के उत्थान के साथ ही उनको हर स्तर पर सहयोग एवं सुविधाएं प्रदान करने की नीति पर आगे बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार समेत अनेक क्षेत्रों में गरीबों के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। अब बिजली पर होने वाले खर्च में भी गरीबों को सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के निर्धन विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब 100 यूनिट तक विद्युत खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। एक किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ता इस सुविधा के पात्र होंगे। प्रदेश के लगभग 11.50 लाख उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे। सरकार ने हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित लक्ष्मी आवास योजना के 101 लाभार्थियों को कब्जा पत्र और चाबी भी सौंपी है। ऊर्जा राज्य होने के नाते बिजली के खर्च में सब्सिडी देकर सरकार ने यह संदेश दिया है कि गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। पहाड़ी एवं मैदानी भूभाग वाले राज्य की विकास को लेकर चुनौतियां अलग हैं। बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ होना शेष है। पर्वतीय जनपदों में सड़कों का जाल बिछाने पर काम होना है। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों तक प्रभावी शिक्षा व्यवस्था कैसे बन सके, इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना की आवश्यकता है। पहाड़ी शहरों में पेयजल सुविधा का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की चुनौती बनी है। ऐसे में सतत एवं सर्वांगीण विकास के लिए सरकार को हर क्षेत्र में तेजी से कार्य करना होगा। यदि राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से शुरुआत करनी होगी। सरकार को योजनाएं भी इसी सोच को केंद्र में रखकर तैयार करनी होंगी।

# आर्थिक सुधारों पर बने राजनीतिक सहमति

जीएन वाजपेयी

**भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के तीन कारकों में से भूमि और श्रम अब भी सुधारों की बाट जोह रहे हैं**

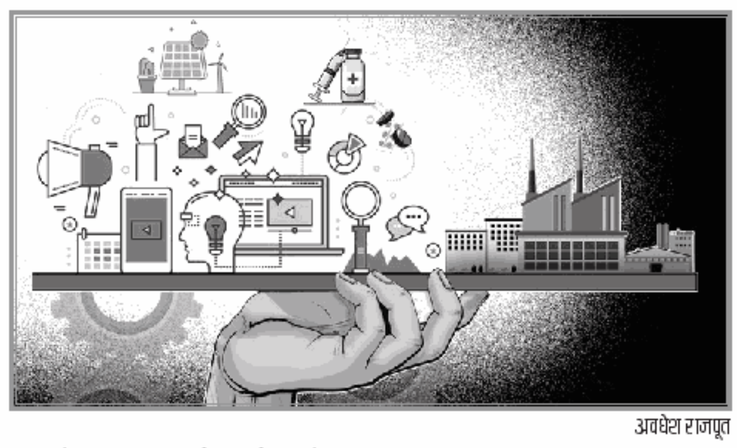

अवधेश राजपूत

अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से वृद्धि कर रही है। इस समय वृद्धि की जो रफ्तार है, उसके आधार पर भारत 2030 तक सात ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की आर्थिकी बनकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वृहद आर्थिक स्थायित्व, युवा आबादी, गतिशील एवं जीवंत लोकतंत्र और तटस्थ भू-राजनीतिक दृष्टिकोण जैसे पहलुओं के चलते भारत विदेशी निवेशकों के लिए निवेश के पसंदीदा ठिकाने के रूप में उभरा है। इसके बावजूद निरंतर तेज वृद्धि के लिए भूमि, श्रम और कृषि के मोर्चे पर तत्काल सुधारों की आवश्यकता है। तभी देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है। अच्छी बात है कि देश के कुछ राज्यों में विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा दिख रही है। इन राज्यों की सरकारें निवेशकों के प्रति उदारता दिखाने में कोताही नहीं कर रहीं। याद रहे कि उद्यमी अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए ही अपनी पूंजी और कौशल को दांव पर लगाकर प्रयास करते हैं। किसी उद्योग या इलाके में निवेश के फैसले पर पहुंचने के लिए कई पहलू प्रभावी होते हैं। इसमें उस इलाके तक पहुंच, उद्यम चलाने की लागत, मानव संसाधन उपलब्धता, निवेश, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के अलावा शासन एवं कर व्यवस्था, नियमन और कानून के स्तर पर निरंतरता जैसे पहलू बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर, न्यूनतम जोखिम के साथ अधिकतम लाभ ही निवेश का आधार मंत्र बनता है।

भारतीय राज्यों में आर्थिक स्तर पर कई असमानताएं दिखती हैं। गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी को देखें तो करीब 7,169 डालर के साथ यह राष्ट्रीय औसत से लगभग तीन गुना अधिक है। वहीं बिहार की जीएसडीपी 1,000 डालर से भी नीचे यानी राष्ट्रीय औसत से तीन गुना कम है। अप्रैल-जून, 2024 के शहरी युवा रोजगार स्थिति के आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार में पुरुषों की श्रम भागीदारी दर 32.9 प्रतिशत, जबकि महिलाओं की महज 5.3 प्रतिशत रही। यह देश में श्रम भागीदारी का सबसे निचला स्तर रहा। जबकि महाराष्ट्र में पुरुषों में यह दर 55.2 प्रतिशत तो महिलाओं में 22.9 प्रतिशत रही। रोजगार की दर राज्य की अर्थव्यवस्था की सेहत को दर्शाती है। अधिक संपन्न राज्य में यह दर काफी ऊंची है। ऐसी विषमता बड़े पैमाने पर आंतरिक पलायन और सामाजिक व्यग्रता बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय चिंता को बढ़ाती है। विषमता की यह स्थिति एकाएक नहीं बनी। इसके पीछे तत्कालीन सरकारों का वह रवैया मुख्य रूप से जिम्मेदार है कि उन्होंने उद्यमियों का भरोसा जीतने का प्रयास नहीं किया। शासन की गुणवत्ता, राजनीतिक अस्थिरता और कुछ मामलों में कानून एवं व्यवस्था की लचर स्थिति सबसे बड़े कारक रहे। राज्य को आर्थिक वृद्धि के पंख लगाकर ही विषमता को दूर किया जा सकता है।

अफसोस है कि भारतीय समाज जाति, नस्ल और धर्म जैसे तमाम आधारों पर विभाजित है। लोकतंत्र में लोगों के फैसलों में अक्सर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे आर्थिक पहलुओं पर हावी हो जाते हैं। इन कारकों के संयुक्त प्रभाव का ही परिणाम है कि चुनावी सफलता के लिए मिश्रित समीकरणों को साधना पड़ता है। जीत का फार्मूला तैयार करने की मजबूरी में कुछ समझौते करने पड़ जाते हैं, जिससे हितों के टकराव और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में कुछ स्वयंभू सामाजिक संगठन सामने आ जाते हैं, जो अपने समर्थन की आड़ में बारे-न्यारे करने लगते हैं। भारतीयों ने कहने को तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति का तिरस्कार किया, लेकिन व्यवहार में कथित सामाजिक न्याय के नाम पर परत दर पर विभाजन को और महीन करते गए। इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता कि आर्थिक रूप से विपन्न लोगों की दुश्वारियों का अंत ही अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण जैसी किसी व्यवस्था के मूल में होना चाहिए। इसलिए अनुकूल नीतियों का बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, उन्हें लागू करने का क्या उपयुक्त तरीका हो सकता है और उनके संभावित परिणामों जैसे पहलुओं पर संसद एवं राज्य विधानमंडलों में व्यापक विमर्श होना चाहिए। तैयार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और संभावित परिणामों को लेकर सरकार को जवाबदेह बनाया जाना भी उतना ही आवश्यक है।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ कुछ मामलों में ऊंची आर्थिक वृद्धि के अनुकूल नहीं रह गई है। विरोधी को मात देने की लिए ऐसी लुभावनी घोषणाओं का दौर चल निकला है, जिसके चलते कुछ राज्य दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए हैं। सामाजिक न्याय रेवड़ियां बांटकर नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त बनने पर ही संभव है। याद रहे कि लोकलुभावनवाद वंचितों का भला करने के बजाय अक्सर नारेबाजी में सिमटकर राज्य के लिए आर्थिक मुश्किलों को आमंत्रण देने वाला साबित होता है। वैसे भी, अर्थव्यवस्था की ऊंची वृद्धि और आप्टिमल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में सीधा संबंध है। चूंकि भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के तीन कारकों में से भूमि और श्रम सुधारों की बाट जोह रहे हैं। भूमि और श्रम सुधारों को भावनात्मक रंग दिया जाता है और इसमें आम सहमति नहीं बन पा रही है। यह भी एक कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी क्षमताओं के अनुरूप तेजी नहीं पकड़ पा रही। स्थिति यह है कि चाहे जिसकी सरकार हो, विपक्ष में रहने वाला दल किसी भी सुधार का न केवल विरोध करता है, बल्कि उसकी आड़ में भावनात्मक राग अलापता है। इससे वंचितों का ही नुकसान हो रहा है। इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भारतीय मतदाता समझदार हो रहे हैं। तमाम उदाहरणों से जुड़े साक्ष्य दर्शाते हैं कि केवल 'अतिशय कल्याणवाद' ही वोट देने का प्रभावी आधार नहीं बनता। गरीबी के उन्मूलन और साझा समृद्धि के युग का प्रवर्तन करने के दृष्टिकोण से राजनीतिक परिपक्वता प्रदर्शित करने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। यह केवल ऊंची आर्थिक वृद्धि की ओर उन्मुख करने वाली आम सहमति और सुधारों से जुड़े सभी संभावित कदमों के प्रभावी कार्यान्वयन से ही संभव हो सकता है।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)
response@jagran.com

# जल निकासी के उपायों की अनदेखी

प्रोफेसर मानसिंह

**नदियों को जोड़ा जाए ताकि एक स्थान का पानी दूसरे स्थान का जल संसाधन बने, न कि ऐसे ही बहकर व्यर्थ हो जाए**

बरसात में आमहो गए हैं ऐसे दृश्य। प्रेट्र

इस साल वर्षा ऋतु के दौरान देश के कई हिस्सों में अतिवृष्टि हो रही है। इस बार देश के पूर्वी तट वाले राज्य ही नहीं, बल्कि पश्चिमी तट के राज्य जैसे-गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में भी जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई है। असंख्य बांधों के फाटक लबालब भरे जलाशयों से पानी निकालने के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे सभी बांधों के निचले हिस्से में बाढ़ आ गई है। इससे खड़ी फसलों और संपत्ति की क्षति हो रही है। अब ऐसी स्थिति हर दूसरे-तीसरे साल पैदा होने लगी है, कभी इस राज्य में तो कभी उस राज्य में। परिणामस्वरूप शहरी संपत्ति तथा आधारभूत ढांचे की भारी क्षति हो रही है।

भारतीय किसान और खेतिहर मजदूर ग्रामीण आर्थिकी का हिस्सा हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते उनका सामना कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी चक्रवात से पड़ने लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में फसलें जलमग्न होकर नष्ट हो जा रही हैं। जो किसान गरीबी रेखा के ऊपर आ गए थे, जल के इस कहर से एक बार पुनः गरीबी रेखा को छूने या उसके नीचे जाने लगे हैं। प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना अब एक सालाना परंपरा बन गई है। किसानों और कृषि मजदूरों को स्थायी रूप से गरीबी के दायरे से बाहर निकालने के लिए नए उपायों के बारे में अब सोचना होगा। इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम को उन्नत बनाने और अतिवृष्टि के दुष्परिणामों से बचने के लिए जलनिकासी के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की आवश्यकता बढ़ गई है।

भारत विश्व के 2.4 प्रतिशत भौगोलिक भूभाग एवं चार प्रतिशत जल संसाधन की मदद से अपनी खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताएं पूरी करता है, लेकिन अतिवृष्टि से आई बाढ़ से दलहन और तिलहन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। देश पहले से ही दाल और खाद्य तेल की कमी से जूझ रहा है। दरअसल पानी की अधिकता दलहन और तिलहन की दुश्मन है। 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया था। उसी दौरान भारत विश्व बाजार से दाल आयात करने के लिए मजबूर हुआ। घरेलू मांग की पूर्ति के लिए भारत ने कनाडा, बर्मा, तंजानिया, मोजांबिक आदि देशों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनके पास भी दलहन की कमी थी। लिहाजा ऊंचे दाम पर दूसरे देशों से भारत दाल आयात के लिए मजबूर हुआ। तभी से देश में दलहन की कीमत बहुत बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति इस साल भी पैदा होने की आशंका है।

आज भारत की आबादी चीन से अधिक हो गई है। हमारे देश के नागरिक प्रोटीन की अपनी आवश्यकता मुख्य रूप से दाल से ही पूरी करते हैं। ऐसे में हमें फिर से विश्व बाजार की ओर देखना होगा। इस वर्ष आए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में दलहन और तिलहन का उत्पादन कम रहने वाला है। लिहाजा आगे भी देश में दलहन और तिलहन की कमी रहने वाली है। वास्तव में दुनिया में कहीं भी इतनी अधिक दाल पैदा नहीं होती कि वहां से आयात कर भारत अपनी मांग पूरी कर सके। दाल के आयात पर भारी खर्च और घरेलू बाजार में इसकी कमी देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ लोगों के पोषण को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए देश में बेहतर जलनिकासी का प्रबंध हो जाए तो बरसात से हो रही जगह-जगह जलमग्नता और बाढ़ पर कारगर नियंत्रण किया जा सकता है।

अब जलवायु परिवर्तन जगजाहिर है। इसके चलते तूफान-चक्रवात, अतिवृष्टि या बादल का फटना, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं अब बार-बार होंगी। इससे देशव्यापी दलहन और तिलहन फसलों की हानि के अलावा मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्टर जैसे-रेल, सड़क, बिजली, पुल और दूरसंचार नेटवर्क आदि की भारी क्षति होती रहेगी। इससे बचने के लिए हमें जल्द ही कुछ दीर्घकालिक समाधान करने चाहिए। इस पर राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श करना समय की मांग है। इसके लिए सबसे पहले बाढ़, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का एक वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित विभागों और मंत्रालयों के सहयोग से किया जाना चाहिए। इसके विश्लेषण के उपरांत किसी निष्कर्ष पर पहुंच कर एक राष्ट्रव्यापी नीति बनानी चाहिए।

यह अच्छी बात है कि जल संरक्षण के लिए इन दिनों देश में आठवें जल सप्ताह का आयोजन हो रहा है। उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ठीक कहा कि जल स्रोत सीमित हैं और उनके सक्षम उपयोग से ही सभी के लिए जल की आपूर्ति संभव है। उन्होंने जल की हर एक बूंद को बेशकीमती बताते हुए देश के प्रत्येक नागरिक से जल योद्धा के रूप में कार्य करने का आह्वान किया। अनेक वैज्ञानिक अध्ययन समाज को यह बताते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में प्राकृतिक आपदाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और कहर बरपाएंगी। फलस्वरूप बड़ी संख्या में जलवायु परिवर्तन शरणार्थी सामने आएंगे। आगे जल प्रलय का प्रारूप क्या होगा, यह सिर्फ प्रकृति को ही पता है। इससे निपटने के लिए भारत को एक आपदा प्रबंधन और निवारण तंत्र बनाकर रखना होगा। इसके लिए गांवों और शहरों में जल निकासी के लिए व्यापक जल इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। इन्फ्रास्ट्रक्टर को इस तरह बनाना चाहिए कि वे भारी बारिश को भी झेल सकें। साथ ही सभी नदियों को आपस में जल्द से जल्द जोड़ा जाना चाहिए ताकि एक स्थान के बाढ़ का पानी दूसरे स्थान का संरक्षित जल संसाधन बने, न कि ऐसे ही व्यर्थ में बह जाए। इस मद में भारी निवेश करना होगा। यह भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहायक होगा।

(लेखक नई दिल्ली स्थित आइसीएआर-आइएआरआइ के जल प्रौद्योगिकी केंद्र के पूर्व परियोजना निदेशक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

## धर्म

धर्म क्या है? यह गूढ़ सवाल है। हर व्यक्ति स्वविवेक के आधार पर धर्म की व्याख्या करता आया है। भूखे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धर्म रोटी है। अपने पेट की क्षुधा को शांत करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। संकट में फंसे हुए व्यक्ति को संकट मुक्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन मनीषियों ने धर्म की और भी परिभाषाएं दी हैं। धर्मज्ञ व्याख्याकारों ने बताया कि धैर्य, क्षमा, अस्तेय, पवित्रता, आत्मसंयम, बुद्धि, विद्या, सत्य एवं अक्रोध आदि को हर तरह से अंगीकार करना धर्म है। उन्होंने इसमें जोड़ा-स्वयं को रुचिकर न हो, वह व्यवहार दूसरों के साथ मत करो।'

व्यास जी ने धर्म की लंबी व्याख्या की। राजा, प्रजा, साधु-संन्यासी के धर्मों को विभाजित किया और धर्म का उल्लंघन करने की मनाही की। वात्स्यायन ने बताया कि मानव के लिए धर्म मनसा, वाचा, कर्मणा होता है। यह केवल क्रिया या कर्मों से संबंधित नहीं है, बल्कि धर्म चिंतन और वाणी से भी संबंधित है। सप्त ऋषियों में से एक गौतम ऋषि की मानें तो उन्होंने बताया है कि जिस काम के करने से अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है। वहीं कबीरदास का कहना है कि 'कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानिअइ सो काफिर बेपीर।' तुलसीदास भी कहते हैं कि दूसरों का भला करना ही धर्म है। प्रयाग से जल भर कर रामेश्वरम चढ़ाने निकले एकनाथ बाबा रामेश्वरम मंदिर के बाहर पड़े गधे को जल पिला देना धर्म समझते हैं।

इन सब विचारों को व्यवहार की कसौटी पर कसा गया तो निष्कर्ष निकलता है कि जब तक परपीर के लिए संवेदना न जागे, जब तक परहित के लिए अंदर से भावों के धक्के न लगें तब तक सारा कर्मकांड, समस्त धर्मज्ञान व्यर्थ है। धर्मपरायण वही है, जो रोते हुए इंसान को हंसा दे। धार्मिक वही है, जो दुखीजनों के दुख बांट सके। यही सच्ची पूजा है और यही असली धर्म भी।

पुष्पेंद्र दीक्षित

# रील बनाने की बढ़ती सनक

डा. कुमारेंद्र सिंह सेंगर

**भीड़ से अलग दिखने की मानसिकता ने आज लोगों को एक तरह से मशीन बना दिया है**

मोबाइल फोन ने एक साधे, सब सधे की अवधारणा को पूरा किया है। बातचीत के लिए बनाए गए इस यंत्र ने अपने तंत्र में इतना कुछ समेट लिया है कि कई बार तो समझ ही नहीं आता है कि इसका उपयोग किसके लिए प्रमुखता से किया जाता है? खुद मोबाइल कंपनियां भी अब बातचीत को प्राथमिकता में रखने के बजाय कैमरे को प्राथमिकता में रख रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि तब मोबाइल का नशा न था। मोबाइल से रील बनाने का फैशन न था। जरा-जरा सी बात पर सेल्फी लेने का चलन न था।

समाज में रील्स बनाने की बढ़ती सनक ने व्यक्तियों की जीवनशैली को एकदम ही बदल दिया है। हालत ये हैं कि कहीं भी, कुछ भी किया जा रहा हो तो पहले सेल्फी ले लो, रील बना लो। किसी पर्यटन स्थल पर घूमने गए हों तो रील डाल दो। बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, साइकिल में, पैदल कहीं भी किसी रूप में हो प्राथमिकता में रील बनाकर उसे अपलोड करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। सेल्फी लेना अथवा रील बनाकर उसे इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करना गलत नहीं है, मगर जैसा कि कहा जाता है कि अति हर चीज की बुरी होती है, बस उसी अति ने आज सेल्फी लेने के चलन को, रील बनाने, अपलोड करने के कदम को जानलेवा स्थिति तक पहुंचा दिया है। मोबाइल हाथ में हो तो कई बार ऐसे दिमागी असंतुलन वाले लोग भूल जाते हैं कि कहां सेल्फी लेनी है कहां नहीं। कहां वीडियो बनाना सुरक्षित है, कहां नहीं। उनको ध्यान भी नहीं रहता है कि अपने इस नशे के चक्कर में वे अपनी और अपने साथ के लोगों की जान खतरे में नहीं डाल रहे। कभी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर, कभी बीच नदी की धार में, कभी बाइक पर स्टंट करते हुए, कभी ट्रेन से होड़ करते हुए, कभी खतरनाक जीव-जंतुओं के साथ लोग रील बनाते नजर आते हैं।

दरअसल बाजार के बढ़ते प्रभाव ने जिंदगी को विज्ञापन की तरह से चकाचौंध से भरा हुआ साबित करने का प्रयास किया है। भीड़ से अलग दिखने की मानसिकता ने, किसी भी क्षेत्र में सबसे ऊपर रहने की दौड़ ने, इंटरनेट मीडिया के आभासी लाइक-शेयर के नंबर-गेम ने व्यक्तियों को एक तरह से मशीन बना दिया है। दो-चार रील के द्वारा, कुछ हजार-लाख लाइक, शेयर की चाह में एक झटके में प्रसिद्धि पाने की तृष्णा आखिर किसलिए? इस मनोविकार के चलते रियल लाइफ पर रील लाइफ हावी होकर लोगों की जान लेती जा रही है। इस तरह की जानलेवा हरकतों को सिवाय पागलपन के कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस पागलपन को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। मोबाइल जिस काम के लिए बना है उसके लिए ही अधिकाधिक उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में यह पागलपन लगातार घरों के चिरागों को बुझाता रहेगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### संभव है एक देश-एक चुनाव

'एक साथ चुनाव की तैयारी' संपादकीय में सही कहा गया है कि ऐसा होने पर बार-बार होने वाले चुनावों से मुक्ति मिलेगी। यदि ऐसा होता है तो हमारे प्रशासन को जनहित के अन्य मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। अभी तो साल भर देश के किसी न किसी हिस्से में चुनावों की दुंदुभी बज रही होती है। देश के अमूल्य स्रोत इसमें लगते हैं। बस अब हमारे राजनीतिक दलों को थोड़ी फुरसत निकालकर इस मुद्दे पर देशहित को सर्वोपरि मानकर विचार करना चाहिए। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में पंचायत/नगर निगम से लेकर विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए। यह संभव है। दीर्घकालिक हित में अल्पकालिक स्वार्थ त्यागकर विपक्षी दल इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। हमारा चुनाव आयोग एकदम सक्षम है और वह यह कार्य करवा सकता है। हां, एकबारगी कुछ विधानसभाओं को समयपूर्व भंग करना होगा, कुछ का थोड़ा समय बढ़ाना होगा। यही प्रक्रिया स्थानीय निकायों के लिए अपनाई जाएगी। इससे संघीय संरचना मजबूत होगी। हमारा विशाल लोकतंत्र बहुत अनुभवी हो गया है। ऐसा होने पर जहां राजनीतिक विमर्श बदलेगा, वहीं दीर्घकालिक देशहित की नीतियों पर बल दिया जाएगा। राजनीतिक कटुता कम होगी। खर्चीले चुनावों से मुक्ति मिलेगी। प्रशासनिक प्राधिकारी लोकहित के कार्यों को अधिक समय दे पाएंगे। राष्ट्रीय स्रोतों को अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया जा सकेगा। राजनीतिक दल सकारात्मक राजनीति करेंगे। एक देश-एक चुनाव की स्थिति में राजनीतिक दल सोच-समझकर प्रत्याशियों का चयन करेंगे, जिससे अंततः जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

### हाकी का सिरमौर भारत

भारतीय हाकी टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एशियाई चैंपियंस ट्राफी के फाइनल में चीन को हरा कर देश को एशिया हाकी का सिरमौर बना दिया है। इस शानदार उपलब्धि के पीछे खिलाड़ियों की एकजुटता और उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन है। जिसने पांचवीं बार भारत को यह खिताब दिलाया है। भारत इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है। टीम की उपलब्धि इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि टोक्यो और पेरिस ओलिंपिक में भारतीय हाकी टीम ने कांस्य पदक जीता है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

### सामाजिक गैरबराबरी

'उनकी भी सुनें, जिनकी सुनवाई नहीं' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने एससी-एसटी वर्ग के जरिये जातिगत वास्तविकता को सामने रखने का प्रयास किया है। बड़ी दिलचस्प बात है कि जो एससी-एसटी वर्ग कथित अन्य वर्गों द्वारा भेदभाव को रेखांकित कर क्रीमी लेयर का विरोध कर रहा है वह एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध पर उतारू है जबकि वास्तव में यह निर्णय सामाजिक गैरबराबरी को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है। दुखद है, दो-तीन पार्टियों को छोड़कर सभी इस निर्णय के विरोध में हैं या चुप्पी साधे हुए हैं। इससे भी दुखद बात है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में से वंचित जातियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए आयोजित किए गए धरना-प्रदर्शन की खबर मुख्य धारा के मीडिया की सुर्खियां नहीं बटोर पाईं। आखिर जो वर्ग समग्र भेदभाव को लेकर चिंतित नजर आता है। उसे खुद के भीतर भेदभाव क्यों नहीं नजर आता है? वे यह क्यों मान बैठे हैं कि उपवर्गीकरण से उनके हितों को आघात पहुंचेगा? क्या उन्हें आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए, जिनकी स्थिति सामान्य वर्ग की उच्च संपन्न जातियों सरीखे हो गई है? वास्तव में यह नए तरह की जातीयता का द्योतक है। जिसे खत्म करने का संकल्प अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संख्या बल के बूते प्रभावी जातियों को लेने चाहिए अन्यथा यह सच्चाई समाज के सामने उजागर होगी कि एससी-एसटी समाज की वंचित जातियों से इन वर्गों की वे जातियां भी दूरी बनाकर रखती हैं जिनकी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और जो राजनीतिक रूप से प्रभावी हैं। mukeshkr.m7542@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

********

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

# एक साथ चुनाव

पूरे विचार-विमर्श के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश-एक चुनाव का फैसला कर लिया। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चौंकाता है। देश जब आजाद हुआ था, तब एक साथ सारे चुनाव हुए थे, पर बाद में राज्यों में राजनीतिक उठापटक की वजह से मध्यावधि चुनाव होने लगे और एक साथ चुनाव का क्रम टूट गया। अब बुधवार को कैबिनेट ने फैसला किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव पूरे देश में एक साथ होंगे। लोग यह भूले नहीं हैं कि यह एनडीए सरकार का एक प्रिय विषय रहा है और इसके लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति ने विभिन्न पक्षों से पूरे विचार-विमर्श के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसे अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी है। अब पहली नजर में आकलन करें, तो एक देश एक चुनाव के लिए यहां से जमीनी कवायद शुरू हो गई है। मगर क्या यह काम आसान है? क्या सभी दल और नेता इस फैसले को मान लेंगे? जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सत्ता है, वहां तो इस फैसले का खूब विरोध होगा। क्या चुनाव आयोग विरोध का सही उत्तर दे पाएगा?

ध्यान देने की बात है कि पूर्व राष्ट्रपति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कैसे कराया जाएगा, इसकी व्यापक रूपरेखा दी गई है। पहले लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होंगे। उसके बाद 100 दिनों के अंदर हर जगह स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। ऐसा कब होगा, यह तो तय नहीं है, पर इस फैसले को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने पड़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव के लिए संविधान में कम से कम पांच या 18 छोटे-बड़े संशोधन करने पड़ेंगे। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठान लिया है कि देश में चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे। वैसे तो एक देश-एक चुनाव का विषय पुराना है, मगर पहली बार कोई सरकार इस योजना के साथ इस मुकाम तक पहुंची है। प्रधानमंत्री ने एकाधिक बार इस बात को दोहराया है कि बार-बार चुनाव की वजह से देश के विकास में बाधा आती है। देश में लगभग हर चार-छह महीने पर कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। आचार संहिता लागू रहती है। अतः यह कहना सही है कि एक साथ चुनाव होने पर देश को हर स्तर पर लाभ होगा। राजनीतिक सुविधा भी बढ़ेगी, आर्थिक विकास की रफ्तार बनी रहेगी और देश में सामान्य कामकाज भी बेहतर हो सकेगा। ध्यान रहे, एक साथ चुनाव भाजपा का चुनावी वादा भी है, पर यह देखना होगा कि विपक्षी दल इस फैसले को कैसे स्वीकार करते हैं। वैसे, कुछ ही फैसले या संशोधन ऐसे हैं, जहां विधानसभाओं से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी।

**वैसे तो अपने देश में एक देश-एक चुनाव का विषय पुराना है, मगर पहली बार कोई केंद्र सरकार इस विषय पर एक ठोस फैसले के साथ सामने आई है।**

चूंकि फैसला बड़ा है, अतः किसी पर थोपने के बजाय सहमत करने पर ज्यादा जोर होना चाहिए। जो व्यावहारिक अड़चनें हैं, उन्हें दूर करना जरूरी है। शंकाओं का बाजार भी गर्म है। बीते लोकसभा चुनाव में सौ से भी ज्यादा दिन खर्च हुए हैं। सात चरणों में मतदान कराने में 44 दिन खर्च हुए हैं। चुनाव आयोग कितना सक्षम है? क्या वह लोकसभा चुनाव के साथ ही, तमाम विधानसभाओं के चुनाव करा पाएगा? कितने लोगों की सेवा लगेगी और कितने सुरक्षाकर्मियों का इंतजाम करना पड़ेगा? इतने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोजित करने में आने वाली तमाम अड़चनों का क्या अनुमान लगा लिया गया है? चुनाव आयोग के साथ ही केंद्र सरकार को भी सभी राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर एक देश एक चुनाव को संभव बनाना चाहिए।

## हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 19 सितंबर, 1949

### इंडिया अथवा भारत

नई दिल्ली, १८ सितम्बर। विधान परिषद ने आज देश का नाम 'इण्डिया अथवा भारत' स्वीकार कर लिया। आज सवेरे दो घण्टे की बैठक हुई, जिसमें देश के नाम के संबंध में एक धारा स्वीकृत की गई। इसके पश्चात अध्यक्ष ने वर्तमान अधिवेशन को स्थगित करने की घोषणा की और कहा कि आगामी अधिवेशन सम्भवतः ६ अक्तूबर से प्रारम्भ होगा। धारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात सदस्यों ने 'भारतमाता की जय' के नारे से इस निश्चय का स्वागत किया।

कुछ सदस्यों ने, जिनमें पंडित कमलापति त्रिपाठी, श्री एच.बी. कामथ और श्री राम सहाय के नाम उल्लेखनीय हैं, इस धारा के शब्दों की आलोचना की और कहा कि इण्डिया अथवा भारत के बजाय भारत अथवा इण्डिया होना चाहिये; क्योंकि इण्डिया अथवा भारत कहने से भारत को गौण स्थान प्राप्त होता है। श्री कामथ के इस संशोधन के पक्ष में ३८ और विरोध में ५१ मत आये।

मौलाना हसरत मोहानी ने संशोधन पेश करते हुए कहा कि भारत प्रांतों का संघ नहीं बल्कि सार्वभौमिक जनतन्त्र प्रांतों का संघ होना चाहिये। उन्होंने स्मरण दिलाया कि नेहरूजी ने उद्देश्य प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे देश का नाम सार्वभौमिक जनतन्त्र भारत होगा, लेकिन अब इस उद्देश्य प्रस्ताव से क्यों पीछे हटा जा रहा है। श्री एच.बी. कामथ ने अपना संशोधन पेश करते हुए कहा कि देश का नाम 'इण्डिया अथवा भारत के बजाय भारत अथवा इण्डिया होना चाहिये, क्योंकि इससे भारत नाम को वह स्थान नहीं मिलता, जैसा देश के गौरव के लिए होना चाहिये।' पंडित कमलापति त्रिपाठी ने संशोधन पर हृदय का उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि मसविदा समिति ने देश के नामकरण के संबंध में जो संशोधन उपस्थित किया है, उसके शब्द यदि दूसरे प्रकार के होते, तो वह देश के गौरव और परम्परा के अनुसार होता। श्री कामथ ने जो संशोधन पेश किया है कि देश का नाम 'भारत अथवा इण्डिया हो, न कि इण्डिया अथवा भारत' उसे स्वीकार करने से हमारे देश का गौरव बढ़ता है। उन्होंने कहा कि फिर भी मसविदा समिति ने जो संशोधन पेश किया है, उसे हम पसन्द करते हैं। जब देश पराधीन हुआ तब उसने अपनी संस्कृति खो दी, मनुष्यता खो दी, गौरव खो दिया, अपना स्वरूप और नाम भी खो दिया। लुप्त हुई संज्ञा को प्राप्त करने के पश्चात अब वह उस गौरव को प्राप्त कर सकेगा।

# रिटायर करने की उम्र बढ़ाई जाए

**सेवानिवृत्ति जहां व्यक्ति की शारीरिक-मानसिक क्षमता पर निर्भर करती है, तो वहीं वेतन की तुलना में उसकी उत्पादकता पर भी। इसी आधार पर व्यक्ति को रिटायर करना चाहिए।**



यहां स्कैन करें

**रवि एस श्रीवास्तव** | अर्थशास्त्री व श्रम विशेषज्ञ

अपने देश में नौकरी से सेवानिवृत्ति की उम्र (रिटायरमेंट एज) बढ़ाने की बहस नई नहीं है। इन दिनों इस पर नए सिरे से इसलिए चर्चा हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की घोषणा की है, जिसमें पूरी पेंशन पाने के लिए सेवा की न्यूनतम अवधि का जो प्रावधान किया गया है, वह पहले की योजना से अधिक है। पहले की पेंशन योजनाओं में पूरी पेंशन-राशि पाने के लिए न्यूनतम सेवा-अवधि 33 वर्ष होती थी, जिसे निरंतर घटाते हुए 20 साल कर दिया गया था, लेकिन यूपीएस में इसे बढ़ाकर 25 साल किया गया है।

सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग अन्य क्षेत्रों के अलावा अर्द्धसैनिक बलों की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि सेवा की उनकी अवधि दूसरों की तुलना में कम होती है। मगर उनको रियायत मिलने की संभावना कम है, क्योंकि उनकी नौकरी काफी हद तक उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता पर निर्भर करती है। हां, अन्य क्षेत्रों में सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने का सवाल इसलिए जोर पकड़ रहा है, क्योंकि वहां कई अभ्यर्थी किसी-न-किसी कारण देर से सेवा में शामिल होते हैं।

बहरहाल, इस बहस को हमें इस सवाल के संदर्भ में भी देखना चाहिए कि सेवानिवृत्ति की उम्र आखिर तय क्यों की जाती है? एक धड़ा मानता है कि जब तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पर काम करने के लायक है, उसे नौकरी में रखा जाना चाहिए। जबकि, दूसरा तर्क कुछ जटिल है, लेकिन इसे यूं समझना चाहिए कि अपने यहां लोगों को उनके अनुभव के आधार पर भुगतान किया जाता है। चूंकि श्रम बाजार अनुभव को तवज्जो देता है, इसलिए किसी व्यक्ति की नौकरी के दौरान आमदनी कम नहीं होती, बल्कि निरंतर बढ़ती ही जाती है। इसकी पीछे की सोच यह है कि अनुभव अर्जित करने के कारण व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ती जाती है। मगर एक समय में, जब उसकी उत्पादकता बढ़े हुए वेतन के



अनुपात में कम हो जाए, तो उसे सेवा से बाहर कर देना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि सेवानिवृत्ति एक तरफ जहां व्यक्ति की शारीरिक-मानसिक क्षमता पर निर्भर करती है, तो दूसरी तरफ वेतन की तुलना में उसकी उत्पादकता पर भी।

चूंकि लोगों की जीवन-प्रत्याशा बढ़ी है और वे अधिक उम्र तक सक्रिय रहने लगे हैं, इसलिए सरकारी और अर्द्ध-सरकारी क्षेत्रों में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जाती रही है। पहले यह 55 साल होती थी, जिसे 58 साल और फिर 60 वर्ष कर दिया गया। शिक्षकों के लिए तो सेवानिवृत्ति की आयु पहले 62 साल और फिर 65 साल तय की गई, क्योंकि माना जाता है कि उन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता और देश में उनकी कमी भी रही है। इसी तरह, जजों की रिटायरमेंट एज भी बढ़ाई गई है, जो राज्यों की अदालतों में 62 साल और सर्वोच्च न्यायालय में 65 साल है। मगर कई जगह सेवानिवृत्ति की आयु अब भी 55 साल है, विशेषकर केरल में, जबकि वहां जीवन-प्रत्याशा अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। वहां माना जाता है कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से नए लोगों को श्रम बाजार में आने का मौका कम हो जाएगा। दरअसल, किसी जमाने में पश्चिम बंगाल केंद्रित सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (एसयूसीआई) जैसी पार्टी रोजाना चार घंटे काम करने पर जोर देती थी, ताकि हर दिन दो पाली में काम होने से दोगुने लोग श्रम बाजार का हिस्सा बन सकें। इस तर्क पर कोई सहमत हो सकता है और कोई असहमत भी, पर ऐसी ही सोच के कारण शायद केरल ने अपने यहां अब तक सेवानिवृत्ति की उम्र नहीं बढ़ाई है।

हालांकि, दुनिया में सेवानिवृत्ति को लेकर अमूमन दो तरह की प्रवृत्तियां दिखती हैं। एक तरफ, यूरोप और अमेरिका के कुछ देश हैं, जहां सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई गई है, तो दूसरी तरफ, उत्तरी अमेरिकी देश व कनाडा हैं, जहां इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वहां रोजगार के कई क्षेत्रों में व्यक्ति जब तक चाहे, काम कर सकता है, पर उसकी तनख्वाह को एक उम्र के बाद सीमित कर दिया जाता है। मतलब यह कि उसके हाथ में बेशक पूरे पैसे आते हैं, लेकिन उसमें एक हिस्सा उसकी पेंशन का भी होता है, यानी तकनीकी रूप से वह पहले की तुलना में सरकारी खजाने से कम वेतन पाता है। सोच यह होती है कि चूंकि पेंशन की राशि व्यक्ति के जीवन-काल की अर्जित रकम है, इसलिए सरकारी खजाने पर उसके वेतन का नाममात्र बोझ पड़ता है। यूरोप और अमेरिका के कुछ देशों में भी ऐसा संशोधन किया गया है कि लोग खुद यह तय कर सकें कि एक तय उम्र के बाद वे कितना काम करेंगे? और फिर, काम के घंटे के अनुपात में उनका वेतन तय किया जाता है, जिसमें एक हिस्सा पेंशन का होता है। इस तरह, व्यक्ति की उत्पादकता का हरसंभव इस्तेमाल किया जाता है और जब व्यक्ति को खुद लगता है कि वह काम के लायक नहीं रहा, तो वह सेवा से बाहर हो जाता है। जाहिर है, पश्चिमी दुनिया सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने को उत्सुक रही है। कई जगहों पर तो इसे खत्म भी कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत के संदर्भ में व्यावहारिक रास्ता क्या है? हमारे यहां अमूमन उत्पादकता से सेवानिवृत्ति जुड़ी है। लिहाजा, जिस उम्र तक व्यक्ति बतौर उत्पादक योगदान कर सकता है और उसे जो वेतन दिया जा रहा है, वह उस लायक काम कर रहा है, तो उसकी सेवा जारी रहनी चाहिए। अब तक सेवानिवृत्ति की उम्र में जो थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसका आधार भी मुख्यतः यही सोच है।

यहां इस तर्क का कोई अर्थ नहीं है कि श्रम बाजार में नए लोगों को अवसर देने के लिए सेवानिवृत्ति-आयु घटा देनी चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि किसी भी वक्त यदि अधिक उत्पादक लोगों को हटाकर कम उत्पादक लोगों को श्रम बाजार का हिस्सा बनाया जाएगा, तो राष्ट्रीय आय पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसे इस तरह समझिए कि यदि 58 या 60 साल का व्यक्ति 20 साल वाले व्यक्ति से कहीं अधिक उत्पादक है, तो उसे सेवा से हटाने का कोई तुक नहीं है। हां, यदि श्रम बाजार में 20 साल वाले व्यक्ति की संख्या बढ़ानी है, तो हमें रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। इसके बजाय उत्पादक लोगों को घर पर बैठाना कोई अच्छी सोच नहीं होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# हमारे विकास का इंजन बनेंगे खास बारह औद्योगिक शहर



यहां स्कैन करें

**सुभ्रकांत पांडा** | पूर्व अध्यक्ष, फिक्की

विकसित भारत की राह बेशक विनिर्माण क्षेत्र से होकर गुजरती है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और ऐसा करना एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप है। जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनमें व्यापार को आसान बनाने और व्यापार की लागत घटाने के उपाय शामिल हैं। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

फिलहाल, देश भर में 4,400 से अधिक औद्योगिक पार्क/क्षेत्र हैं, जिनमें से 64 प्रतिशत मिश्रित उपयोग वाले हैं। वैसे, हाल ही में क्षेत्र-विशेष आधारित पार्कों की ओर रुझान बढ़ा है। गौर करने की बात है कि देश में कुल औद्योगिक पार्क या क्षेत्र का 75 प्रतिशत हिस्सा पांच राज्यों में ही है। जाहिर है, विशेष औद्योगिक क्षेत्रों ने इन राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, यानी एनआईसीडीपी के तहत 12 नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे। इस काम के लिए केंद्र ने 28,602 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। ये शहर देश के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाएंगे। 40 लाख प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार पैदा करेंगे और 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश को आकर्षित कर आर्थिक विकास के इंजन के रूप में काम करेंगे।

**ये शहर देश में करीब 40 लाख रोजगार पैदा करेंगे और 1.5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा के निवेश को आकर्षित करेंगे।**

उद्योग के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम देश की जरूरत है। यह बात अक्सर चर्चा में आती है कि यह भारत का समय है। भारत को एक वैश्विक उत्पादन केंद्र बनना होगा। तमाम तरह की वस्तुओं के उत्पादन व विश्व स्तर पर आपूर्ति में भी उसे आगे आना होगा। भू-राजनीतिक वजहों से भी उसके लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का समय आ गया है। औद्योगिक शहरों के बनने से निवेश को जमीन पर साकार करने का समय कम हो जाएगा। अब ऐसा परिवेश देना जरूरी है कि निवेशकों का समूह विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग तंत्र का तेजी से विकास कर सके। ध्यान रहे, 2030 तक निर्यात में दो ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को पाने के लिए विशेष औद्योगिक शहर चाहिए।

भारत की उच्च लॉजिस्टिक्स लागत चिंता का विषय रही है। उत्पादों के परिवहन का खर्च ज्यादा हो जाता है। जब औद्योगिक शहरों का विकास होगा, तो उत्पादों की परिवहन सुविधा बढ़ेगी और लागत घट जाएगी। उत्पादन या सामान परिवहन के मामले में भारत अपनी स्थिति सुधारने के प्रयासों में लगा है। इस मोर्चे पर रैंकिंग सुधारने के लिए 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) की घोषणा की गई थी। जब एक ही औद्योगिक शहर में सभी जरूरी उत्पाद उपलब्ध होंगे, तो किसी भी वस्तु की निर्माण लागत में कमी आएगी। भारतीय उत्पादों को किफायती या विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए लागत को हर स्तर पर घटाना होगा, ताकि ग्राहकों को वाजिब मूल्य पर सामान उपलब्ध हो सकें।

शहरीकरण विकास की ही एक शाखा है। भारत में शहरी नियोजन में सुधार होना चाहिए। नए स्मार्ट शहर विकसित करके और 'वॉक टु वर्क' अवधारणा को बढ़ावा देकर हमें अपना नजरिया बदलना होगा। सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन शहरों में हरित टेक्नोलॉजी का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। ऐसे शहरों का विकास केंद्र बनना जरूरी है, ताकि उनके आसपास जरूरी उत्पादन व सेवा के उद्यम स्थापित हो सकें। जब नौकरियां बनेंगी। आजीविका का सृजन होगा, तो देश का सामाजिक-आर्थिक उत्थान भी होगा।

औद्योगिक पार्क भारत के लिए नए नहीं हैं, पर उन्हें लेकर जो नई दृष्टि है, वह व्यापक है। मजबूत टिकाऊ ढांचे के लिए यह जरूरी है, तभी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी। ताजा घोषणा से अनेक पहलू जुड़े हैं, पर हर पहलू में क्रियान्वयन सबसे अहम होगा। चार परियोजनाओं का पूरा होना व अन्य चार पर तेजी से काम होना शुभ संकेत है। यह काम देश में पहले ही हो जाना चाहिए था। खैर, भारत के औद्योगिक क्षेत्र को बदलने के प्रयासों को अब बढ़ावा मिलने लगा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

## मनसा वाचा कर्मणा

# यह पूरा संसार ही ईश्वर

प्रश्न यह है कि ईश्वर की आराधना करनी है, तो मंदिर कौन होगा? यहां शास्त्रों ने साफ बताया, पूरा संसार ही मंदिर है। संसार क्यों मंदिर है? यह भी सुनिए, जिन धागों से यह वस्त्र बना है, धागे कारण हैं। इनको कारण कहते हैं, इनसे कार्य उत्पन्न होता है। वस्त्र में धागे हर जगह होते हैं, कारण व्यापक होता है। जहां-जहां तक कार्य का अस्तित्व है, कारण जरूर होगा। हमारे यहां दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि जो कार्य के पहले रहे, वह कारण कहलाता है। चावल पहले होगा, तो ही भात बनेगा। यह संसार किससे बना है बताइए? यह आपको पता होना चाहिए। संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले, तीनों भगवान ही हैं। पटाखे और बम छोड़ने से संसार का कुछ नहीं होगा।

कुछ वर्ष पहले अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा को निशाना बनाया, वह प्रतिमा विस्फोट से उड़ा दी गई। लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी प्रतिमा थी और नष्ट हो गई, यह कितना बड़ा अत्याचार है, पर समझिए, सनातन धर्म का ईश्वर केवल मूर्ति में नहीं रहता है। आप मूर्ति तोड़कर सोच रहे हैं कि सनातन धर्म नष्ट हो गया, वह तो आकाश में भी है। वह कण-कण में है, आप कितना भी बम मारोगे, बम समाप्त हो जाएंगे, आप भी समाप्त हो जाओगे, पर आकाश नष्ट नहीं होगा। ईश्वर संसार को बनाते हैं, यह तो आपको बार-बार पढ़ाया जाता है, पर आज से आप याद कर लीजिए, ईश्वर ही संसार बन जाते हैं। जैसे धागा ही कपड़ा बन गया, जैसे आटा ही रोटी बन गया, जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट मिलकर मकान बन गए, वैसे ही ईश्वर ने केवल संसार बनाया ही नहीं, बल्कि वह स्वयं संसार बन गए। हर जगह ईश्वर हैं। कारण व्यापक होता है, इसलिए एक वाक्य पढ़ाया जाता है- *सर्वंखल्विदं ब्रह्मं।* सब ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

तभी तो तुलसीदास जी ने कहा, *सीय राममय सब जग जानी। करउं प्रनाम जोरि जुग पानी।।* सिया राममय पूरा संसार है, उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब ईश्वर हर जगह है, तो आपको किसी धर्मस्थल में जाने की जरूरत नहीं है। कहा गया है- *ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्/ तेन त्यक्तेन भुंञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥* जड़-चेतन प्राणियों वाली यह सृष्टि सर्वत्र परमात्मा से व्याप्त है। इसके पदार्थों का आवश्यकता के अनुसार ही भोग करें, उनका संग्रह न करें। इसी अभिप्राय को गीताकार ने भी स्पष्ट किया है कि जिससे पूरे संसार की उत्पत्ति होती है, जिसने जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि सब ले लिया, जिस ईश्वर द्वारा संसार प्रकट होता है, जिसमें पूरा संसार व्याप्त है। ऐसे ईश्वर की आराधना अपने कर्मों द्वारा करनी चाहिए, तभी सिद्धि प्राप्त होती है।

**जैसे धागा ही कपड़ा बन गया, आटा ही रोटी बन गया, जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट मिलकर मकान बन गए, वैसे ही ईश्वर ने केवल संसार बनाया ही नहीं, बल्कि वह स्वयं संसार बन गए।**

**रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य**

**द्रौपदी मुर्मु** | राष्ट्रपति, भारत



**जन-शक्ति के बल पर ही जल-शक्ति का समुचित संग्रह और उपयोग किया जा सकता है। जल-शक्ति के समुचित संचय तथा उपयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी नागरिकों को जल-योद्धा की भूमिका निभानी होगी।**

# बुलडोजर न्याय मौजूदा वक्त की जरूरत

सड़कों, सार्वजनिक फुटपाथों, रेल लाइनों जैसी जगहों से अतिक्रमण हटाने के अलावा किसी अन्य जगह पर बने घर को तोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आपत्ति जताई है और 1 अक्तूबर तक देश भर में 'बुलडोजर न्याय' पर रोक लगा दी है। मगर क्या यह सच नहीं है कि जिन आरोपियों के घरों को तोड़ा गया था, उनकी करतूतों से न जाने कितने अन्य घर तबाह और बर्बाद हो गए थे? बुलडोजर से घरों का टूटना भौतिक क्षति है, जिसे आसानी से देखा जा रहा है, पर जब किसी घर का कोई सदस्य किसी आपराधिक घटना का शिकार हो जाता है, तब वह घर ही नहीं, उसमें रहने वाले लोगों के दिल भी टूट जाते हैं। इसको कौन देखेगा? जिन घरों ने अपनी बहन-बेटियों की अस्मत लुटने का दर्द सहा है, जिनके परिजनों की हत्या कर दी गई है, क्या उनके आरोपी के घर सही-सलामत रहने चाहिए? क्या उनके घर नहीं टूटने चाहिए? दुख की बात है कि ऐसे पीड़ित लोगों की संख्या काफी अधिक है।

यह सही है कि ऐसी याचिकाओं पर अदालत द्वारा फैसला लेना आसान नहीं होता। उसे कई किंतु-परंतु सोचने होते हैं। लेकिन अदालत का तो काम ही है, अपनी न्याय-प्रक्रिया से जख्मों पर मरहम लगाना। अगर आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, तो जो नुकसान आरोपी ने किया है, उसकी भरपायी भला कैसे हो सकेगी? बुलडोजर न्याय की इसलिए भी तारीफ की जाती रही है, क्योंकि यह त्वरित असर डालता है। 'तारीख पर तारीख' जैसी शब्दावलियां इसके लिए इस्तेमाल नहीं की जातीं। ऐसे में, देर से मिलने वाला न्याय वास्तव में न्याय नहीं होता, जैसी बातें भी बेमानी हो जाती हैं।

बुलडोजर कार्रवाई से इतना तो जरूर हुआ है कि पीड़ित लोगों के दिलों को सुकून मिला है, साथ ही अपराधियों और बुरी प्रवृत्ति रखने वालों में यह डर पैदा हुआ है कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया, तो उन्हें बख्शा नहीं ही जाएगा, परिवार को भी उनके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। यह डर अपराधियों में होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से उनके मनोबल को तोड़ा जा सकता है और अपराध की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता अपनी जगह जायज है, लेकिन मौजूदा वक्त में बुलडोजर न्याय की सख्त जरूरत है। इस संदर्भ में खाड़ी के देशों की स्थिति गौर करने लायक है। सख्त और त्वरित सजा देने संबंधी चलन का ही नतीजा है कि वहां जघन्य अपराध का ग्राफ बहुत कम है। हमें इन तथ्यों पर भी गौर करना चाहिए।

**प्रत्यूष आनंद, टिप्पणीकार**

## अनुलोम-विलोम
### बुलडोजर न्याय



# यह कार्रवाई सांविधानिक मूल्यों के खिलाफ

करीब एक सप्ताह पहले सर्वोच्च अदालत ने यह संकेत दे दिया था कि वह बुलडोजर वाला त्वरित न्याय को लेकर उत्सुक नहीं है और इसको बहुत जरूरी नहीं मानती। उस समय न्यायालय ने यह भी मंशा जताई थी कि वह राज्यों को बुलडोजर न्याय का सहारा लेने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। आखिरकार 17 सितंबर को वह दिन आ ही गया, जब अदालत ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी। बुलडोजर के जरिये संपत्ति को ध्वस्त करने से रोकने संबंधी दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने इस किस्म के ध्वंस पर 1 अक्तूबर तक रोक लगा दी है। दो सदस्यीय पीठ ने कहा है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों और जलाशयों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा, लेकिन यदि अवैध ध्वस्तीकरण की एक भी घटना देश में कहीं भी होती है, तो वह संविधान की प्रकृति के विरुद्ध मानी जाएगी। बेशक, यह रोक अभी 15 दिनों के लिए है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तो शीर्ष अदालत अपने इस आदेश को स्थायी बना देगी और बुलडोजर न्याय को नियमित तौर पर खत्म कर दिया जाएगा।

भले ही सुनवाई के दौरान इसके समर्थन में कहा गया कि वैधानिक अधिकारों के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते, पर सच यही है कि यदि हम देश में त्वरित न्याय का यह सिलसिला शुरू कर देंगे, तो हममें और तालिबान या आईएस में शायद ही कोई फर्क रह जाएगा। हमारे लिए सजा अपराधी को सुधारने का एक माध्यम है, न कि उसे हर हाल में दंडित करने का इरादा। भारतीय लोकतंत्र की इसीलिए तारीफ भी की जाती है, क्योंकि यहां सबके हितों का ध्यान रखा जाता है और हमारा यही मानना है कि भले 100 अपराधी जेल से छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। न्याय के बारे में हमारी यह मान्यता बुलडोजर न्याय से खंडित होती है। त्वरित न्याय जैसी व्यवस्था में गलती होने की आशंका अधिक होती है और इस तरह तो हमारा लोकतंत्र भी धवल नहीं रह सकेगा।

अब जब 15 दिनों के लिए ही सही, इस बुलडोजर संस्कृति पर रोक लग गई है, तो यह उम्मीद करनी चाहिए कि इस पर स्थायी रोक लग सकेगी और लोगों को राहत मिलेगी। वैसे भी, जिसने अपराध किया हो, सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। अपराधियों के घर गिराने या ध्वस्त करने से सजा उसके माता-पिता, पत्नी-बच्चे या अन्य परिजनों को भी मिलती है, जो हमारी न्यायपालिका की बुनियादी अवधारणा के खिलाफ है। अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का है।

**जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार**

https://t.me/AllNewsPaperPaid

## सेना में महिलाएं

वायु सेना की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं. यह युद्धक देश में ही विकसित किया गया है. स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी के साथ मोहना सिंह भारतीय वायु सेना में शामिल होने वाली प्रारंभिक महिला युद्धक पायलटों में हैं. कंठ और चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान की पायलट हैं. अभी तक मोहना सिंह मिग युद्धक उड़ाती थीं. इन महिला सैन्य अधिकारियों की उपलब्धियां इसलिए ऐतिहासिक हैं कि ये भविष्य के लिए ऐसा ठोस आधार तैयार कर रही हैं, जिसके कारण भविष्य में सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी में बड़ी बढ़ोतरी होगी तथा अन्य क्षेत्रों में भी लड़कियों एवं महिलाओं का मनोबल बढ़ाने में योगदान मिलेगा. वर्ष 2016 में महिलाओं को लड़ाकू विमान पायलट बनाने का निर्णय लिया गया था. वर्तमान में इन पायलटों की संख्या लगभग 20 है. देश की स्वतंत्रता के बाद 1958 में महिलाओं को सैन्य सेवा में नियमित कमीशन के तौर पर शामिल करने का सिलसिला शुरू हुआ था, पर प्रारंभ में उनकी भूमिका चिकित्सा सेवा तक सीमित थी. लंबे अंतराल के बाद 1992 में उन्हें शॉर्ट सेवा का अवसर हासिल हुआ. फिर भी, आज तक की उनकी यात्रा आसान नहीं रही है. जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह सशस्त्र सेना में भी अपनी पुख्ता जगह बनाने के लिए महिलाओं को बड़ा संघर्ष करना पड़ा है. आज भी सेना में उनकी तादाद चार प्रतिशत के आसपास ही है. साल 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि शॉर्ट सेवा की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन पाने का अधिकार है. वर्तमान में महिलाएं मेडिकल सेवा के अलावा सेना के दस विभागों में कार्य कर सकती हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, सिग्नल, सेना वायु सुरक्षा, सेना सेवा कोर, आयुध, सेना उड्डयन कोर, इंटेलिजेंस कोर, शिक्षा एवं न्याय विभाग शामिल हैं. थल और वायु सेनाओं के साथ-साथ नौसेना में भी महिलाओं के लिए सेवा क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है. साल 2019 में शुभांगी स्वरूप को नौसेना के लिए डोर्नियर निगरानी हवाई जहाज उड़ाने का पहली बार मौका मिला था. एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के द्वार खोले जाने के बाद से महिला भर्ती बढ़ी है, पर इसकी गति धीमी है. इस वर्ष मार्च में सेवा में शामिल हुए 2,630 अग्निवीर सैनिकों के तीसरे बैच में 396 महिलाएं भी थीं. मिलिटरी पुलिस में महिलाओं के उत्साहजनक प्रदर्शन को देखते हुए थल सेना ने अधिक से अधिक महिला जवानों की भर्ती का निर्णय लिया है. महिलाओं को लेकर जो सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव है, उसमें बदलाव के बाद ही राह आसान हो पायेगी.

**जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह सशस्त्र सेना में भी अपनी पुख्ता जगह बनाने के लिए महिलाओं को बड़ा संघर्ष करना पड़ा है.**

# संशोधित बीजों पर नीति बनाना मुश्किल

**डॉ अश्विनी महाजन**
राष्ट्रीय सह-संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच
ashwanimahajan@rediffmail.com

**यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसने देश और दुनिया में बीते ढाई दशक से भी अधिक समय से भारी बहस पैदा की है, जहां विशेषज्ञ विभाजित हैं और लोग चिंतित हैं, जहां एक मजबूत नियामक तंत्र का अभाव है और इसके कारण न्यायालय जीएम के पक्ष में निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है, जीएम फसलों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के भी सबूत नहीं हैं, कई देशों ने पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआ है. ऐसे में बहुत कम संभावना है कि सरकार चार माह में राष्ट्रीय नीति तैयार करने का कार्य पूरा कर पायेगी.**

हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जेनेटिकली मोडीफाइड- जीएम) सरसों की व्यावसायिक खेती के संबंध में एक विभाजित निर्णय दिया है. न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अनुमोदन प्रक्रिया में खामियों तथा पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों पर पर्याप्त विचार की कमी का हवाला देते हुए जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री और पर्यावरण रिलीज के खिलाफ फैसला सुनाया, तो न्यायमूर्ति करोल ने फील्ड ट्रायल जारी रखने का समर्थन किया, पर, यह जोर दिया कि सख्त सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना चाहिए. जीएम फसलों की व्यावसायिक खेती के संबंध में यह मामला (सुमन सहाय और अरुणा रोड्रिग्स और अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) 2004 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन जीएम फसलों के पैरोकार व्यावसायिक रिलीज के लिए अदालती मंजूरी अभी तक नहीं ले पाये. इस मामले से कई विवादास्पद मुद्दे जुड़े हैं, जिन पर अदालत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पायी है. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीते 23 जुलाई को दिया गया विभाजित निर्णय एक बार फिर मामले की जटिलताओं को दर्शाता है.

न्यायालय ने सरकार को विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद चार माह के भीतर जीएम पर नीति तैयार करने का निर्देश दिया है. यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसने देश और दुनिया में बीते ढाई दशक से भी अधिक समय से भारी बहस पैदा की है, जहां विशेषज्ञ विभाजित हैं और लोग चिंतित हैं, जहां एक मजबूत नियामक तंत्र का अभाव है और इसके कारण न्यायालय जीएम के पक्ष में निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है, जीएम फसलों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के भी सबूत नहीं हैं, कई देशों ने पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआ है. ऐसे में बहुत कम संभावना है कि सरकार चार माह में राष्ट्रीय नीति तैयार करने का कार्य पूरा कर पायेगी. यह पहली बार नहीं है कि जीएम फसलों के लिए परामर्श तंत्र अपनाया जा रहा है. यूपीए सरकार के दौरान बीटी बैंगन के वाणिज्यिक विमोचन के संबंध में तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश के साथ सार्वजनिक सुनवाई हुई थी. सुनवाई के अंत में उन्होंने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बीटी बैंगन के वाणिज्यिक रिलीज पर रोक लगा दी थी. न्यायालय ने सरकार को परामर्श आयोजित करने का निर्देश दिया है, इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि इन परामर्शों की संरचना क्या हो सकती है. सर्वोच्च न्यायालय की तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने कई विवादास्पद मुद्दों को लंबे समय से सूचीबद्ध किया है, जो परामर्श प्रक्रिया का आधार बन सकते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकते हैं.

सबसे पहला मुद्दा, जिस पर विशेषज्ञों में सहमति का अभाव है, जीएम फसलों की उच्च उत्पादकता का दावा है. सरकार और जीएम समर्थकों का तर्क है कि देश बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात कर रहा है, जिनमें से अधिकांश जीएम तेल हैं. सरकार का दावा है कि डीएमएच 11 को अपनाने से आयात पर निर्भरता कम करने और अधिक उत्पादकता के कारण किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है. लेकिन डीएमएच 11 के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार भी इसकी उत्पादकता 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं है. देश में सरसों की कई अन्य संकर किस्मों की अपेक्षित उपज 2500 से 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक है. भारतीय सरसों और रेपसीड संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ धीरज सिंह के एक शोध पत्र के अनुसार, राजस्थान में किसानों द्वारा उगायी गयीं किस्मों- आरएस 1706, आरएच 1424 और आरएच 725 की उत्पादकता (जैसा सरकार ने खुद घोषित किया है) क्रमशः 2613, 2604 और 2642 किलोग्राम है. विवाद का दूसरा मुद्दा बौद्धिक संपदा अधिकारों का है. किसान संगठनों को चिंता है कि एक बार अपनाने के बाद बीज पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार हो जायेगा और किसानों पर बीजों पर रॉयल्टी के रूप में बोझ बढ़ जायेगा. ये आशंकाएं बेवजह नहीं हैं. किसानों को असफल बीटी कपास के बीज के लिए बहुत अधिक कीमत (लगभग 8000 करोड़ रुपये) चुकानी पड़ी थी, क्योंकि उस बीज की कीमत का एक बड़ा हिस्सा विशेषता शुल्क था. डीएमएच 11 बीज को स्वदेशी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, पर उसमें भी बायर कंपनी की प्रौद्योगिकी के कुछ गुणों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण बौद्धिक संपदा का विषय किसान हितों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव का है. जीएम समर्थक बिना किसी वैध तर्क के दावा करते हैं कि इससे आयातित खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता कम हो जायेगी, तथ्य यह है कि खाद्य फसलों में जीएम अपनाने के बाद हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी अपना लाभ खो सकते हैं. आज हम गैर-जीएम टैग के कारण लगभग 54 अरब डॉलर मूल्य के खाद्य उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं. जब खाद्य पदार्थों में जीएम की अनुमति दे दी जायेगी, तो हम इस महत्वपूर्ण लाभ को खो देंगे, क्योंकि आयात करने वाले देश, जहां जीएम की अनुमति नहीं है, भारतीय खाद्य आयातों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. चौथा विवादास्पद मुद्दा जीएम बीजों के भारतीय खाद्य और आयुर्वेद पर प्रभाव के बारे में है. जीएम फसलें खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बदल देती हैं, जो हमारे भोजन का आवश्यक हिस्सा हैं, मसलन- सरसों का साग. भारतीय सरसों के आयुर्वेद में कई औषधीय उपयोग हैं, जिन्हें हम खो सकते हैं. पांचवां मुद्दा शाकनाशी सहिष्णुता है. लगभग 88 प्रतिशत जीएम फसलों को शाकनाशी (हरबिसाइड) सहनशील बनाया गया है. इसका मतलब है, ये फसलें शाकनाशियों के उपयोग को बढ़ाती हैं, जिससे विषाक्तता बढ़ जाती है. लगभग सभी प्रमुख शाकनाशी कैंसरकारी साबित हुए हैं. यह खेद की बात है कि जीएम सरसों के शाकनाशी सहनशील होने के तथ्य को शुरू में छुपाया गया था. डीएमएच11 के परीक्षण के दौरान इसकी शाकनाशी सहिष्णुता के बारे में कोई परीक्षण नहीं किया गया था. जब यह कृत्य उजागर हुआ, तो समिति ने हास्यास्पद शर्त लगा दी कि किसी भी स्थिति में किसान खरपतवारनाशकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे.

विवादास्पद मुद्दों की सूची में कई अन्य बिंदु शामिल हैं, जैसे- बीज संप्रभुता, जैव विविधता, उपभोक्ता संरक्षण व विकल्पों, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और पोषण सुरक्षा पर प्रभाव, हितों के टकराव का मुद्दा, स्वतंत्र परीक्षण का अभाव और खरपतवारनाशकों के प्रति सहनशील जीएमओ के उपयोग से संबंधित सामाजिक-आर्थिक विचार और मधुमक्खियों पर इनके दुष्प्रभाव. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

# मणिपुर पर देश में सन्नाटा पसरा है

**योगेंद्र यादव**
राजनीतिक विश्लेषक
https://x.com/_YogendraYadav

**यह खबर मणिपुर के बारे में नहीं है, दिल्ली की निष्ठुरता के बारे में है, देश में पसरे सन्नाटे के बारे में है, हमारे दिल में फैले अंधेरे के बारे में है. खबर यह है कि जो जल कर राख हो रहा है, वह मणिपुर नहीं है, वह भारत का सपना है, उस गीत की इबारत है, जो बचपन में सुना था- 'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा!'**

मणिपुर जल रहा है. यह कोई खबर नहीं है. 'न्यूज' में कुछ 'न्यू' तो होना चाहिए भाई! रोजमर्रा की सामान्य बात खबर नहीं बन सकती. यह कोई खबर नहीं है कि 17 महीने से जातीय हिंसा की आग में झुलसते मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गयी, कि नयी घटनाओं में दस और बेगुनाह मारे गये, कि अब शायद मृतकों की संख्या दो सौ से पार हो चली है, कि राज्य के अधिकतर इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयीं, कि कई जगह कर्फ्यू लगा, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई, कि फिर भी सरकारी सूत्रों ने स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया है कि अब भी कोई साठ हजार मणिपुरी अपने घर को छोड़ कर शरणार्थी शिविरों में दूसरी सर्दी बिताने पर मजबूर हैं, कि सुरक्षा अधिकारियों ने दो समुदायों के बीच चली जा रही हिंसा को रोकने में लाचारी जतायी, कि मणिपुर में तैनात असम राइफल के पूर्व प्रमुख ने कहा कि मणिपुर की पुलिस अब मितेई पुलिस और कुकी पुलिस में बंट चुकी है, कि मणिपुर के भीतर ही एक अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसा बॉर्डर बना हुआ है, जिसमें सुरक्षा बल नहीं, बल्कि जातीय सेनाओं के सिपाही मितेई या कुकी होने की शिनाख्त करने के बाद प्रवेश करने देते हैं, कि दोनों तरफ बंकर बने हुए हैं, कि दूसरे पक्ष के व्यक्ति की बॉर्डर के उस पार जाने पर गोली मार दी जाती है, कि मुख्यमंत्री अपने ही राज्य के कुकी बाहुल्य जिलों में प्रवेश भी नहीं कर सकते, कि कुकी समुदाय के विधायक विधानसभा के नजदीक भी फटक नहीं सकते, कि कोई नहीं जानता कि इस राज्य में राज कौन कर रहा है, कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं भी और नहीं भी हैं, कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन मणिपुर में उनका दौरा होने की कोई सूचना नहीं है.

'देखिए, यह है मणिपुर का मामला. हमें इससे क्या लेना देना? कोई मुंबई तो है नहीं, जहां हुई कार एक्सीडेंट की भी खबर बन जाए! अब यह मितेई और कुकी वाला क्या झगड़ा है? कोई हिंदू-मुसलमान वाला मसाला हो, तो बताइए कि उसकी खबर चलायें. और, ऊपर से वहां सरकार भी भाजपा की है. अगर विपक्षी दलों की किसी सरकार में जंगलराज की खबर होती, तो चल भी जाती. तो, कुछ ऐसी खबर लाइए, जिसमें कुछ रस हो, हमारे रीडर्स के लिए दिलचस्पी हो.' चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ-कुछ सनसनीखेज खबर सुनाऊं आपको.

खबर यह है कि मणिपुर में अब कुकी और मितेई समुदाय के सिपाही एक-दूसरे पर सिर्फ बंदूक से हमला नहीं कर रहे है. मामला अब ऑटोमेटिक राइफल तक भी सीमित नहीं रहा. कुछ दिन पहले ही मणिपुर में ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर से लड़ाई की खबर आयी है. यह कोई अफवाह या आरोप नहीं है, खुद मणिपुर पुलिस ने इसकी पुष्टि की है. अब तो बस टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की कसर बची है. क्या तब खबर बनेगा मणिपुर?

खबर यह है कि अब मणिपुर की बहुसंख्यक हिंदू धर्मावलंबी, यानी मितेई समुदाय के लोगों ने ही मुख्यमंत्री बीरेन सिंह में अविश्वास व्यक्त कर दिया है. पहले कुकी समुदाय ने मुख्यमंत्री पर खुल्लम-खुल्ला मितेई समर्थक होने का आरोप लगाकर उनका बहिष्कार किया था. इसका फायदा उठाकर बीरेन सिंह मितेई हृदय सम्राट बने थे. लेकिन फूट डालने की राजनीति का यही अंत होता है कि पहले आप जिनके हितैषी बनते हैं, वही बाद में आपका खेल पहचान जाते हैं. अब मुख्यमंत्री को उनकी कुर्सी से मुक्त करने वाली खबर के लिए किस बात का इंतजार है? खबर यह है कि मणिपुर में कब राष्ट्रपति शासन लग जाता है और कब हट जाता है, इसकी किसी को कानों-कान खबर भी नहीं होती है. इस राज्य का मुख्यमंत्री खुद राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर यह मांगता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की कमान उसे सौंप दी जाए, यानी कि जो अधिकार उसे संविधान ने मुख्यमंत्री होने के नाते दिया है, वह अधिकार व्यवहार में उसे दे दिया जाए. प्रदेश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सुरक्षा सलाहकार के हाथ में दे गयी है. सोचिए, अगर विपक्षी दल की सरकार होती, तो क्या यह खबर बनती? क्या केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा में गफलत की खबर बन सकती है?

एक अच्छी खबर यह है कि मणिपुर अब बोलने लगा है. मणिपुर घाटी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद बिमोल अकोइजाम ने संसद में आधी रात को एक ऐतिहासिक भाषण दिया है. सदन में प्रधानमंत्री मोदी के पूरे भाषण के दौरान विपक्ष 'मणिपुर-मणिपुर' की रट लगाते रहता है. क्या यह पॉजिटिव स्टोरी की तरह खबर बनेगी? एक और खबर बताऊं? यह खबर मणिपुर के बारे में नहीं है, दिल्ली की निष्ठुरता के बारे में है, देश में पसरे सन्नाटे के बारे में है, हमारे दिल में फैले अंधेरे के बारे में है. खबर यह है कि जो जल कर राख हो रहा है, वह मणिपुर नहीं है, वह भारत का सपना है, उस गीत की इबारत है, जो बचपन में सुना था- 'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा!'

**(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

## एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी की बढ़ती उपस्थिति का अर्थ

हाल के दिनों में जर्मन नौसैनिक युद्धपोत द्वारा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में खतरनाक युद्धाभ्यास करने से क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम बढ़ रहा है और क्षेत्र में उन बलों को गलत संकेत जा रहा है जो गैर-क्षेत्रीय शक्तियों पर भरोसा करते हैं. विदित हो कि दो जर्मन युद्धपोत- फ्रिगेट बाडेन-वुर्टेमबर्ग और आपूर्ति जहाज फ्रैंकफर्ट एम मेन- ताइवान जलडमरूमध्य से गुजरने के बाद सोमवार को मनीला पहुंचे. वे गुरुवार तक बंदरगाह पर रहेंगे. यह 20 वर्षों में जर्मन युद्धपोतों की फिलीपींस की पहली यात्रा है. फिलीपींस मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मनीला में अपने प्रवास के दौरान जर्मन युद्धपोत फिलीपीनी नौसेना के साथ अभ्यास करेंगे. जिसका उद्देश्य जर्मन और फिलीपीनी सशस्त्र बलों के बीच दीर्घकालिक संबंध बनाना और मजबूत करना है. विशेषज्ञों का मानना है कि फिलीपींस के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करने सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से जर्मनी की गतिविधियां, वास्तव में अमेरिका के लिए जर्मनी के सुरक्षा संरक्षण रैकेट का हिस्सा है. वाशिंगटन के लिए अपने महत्व को साबित करने के लिए बर्लिन स्वयं को अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति के साथ अधिक निकटता से जोड़ रहा है और इसी क्रम में वह निरंतर इस क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता बनाये रखने की अमेरिकी बयानबाजी का आह्वान भी कर रहा है. जर्मनी घरेलू स्तर पर कठिन स्थिति का सामना कर रहा है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही वह सुदूर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. यूरोपीय सुरक्षा की वर्तमान में जो स्थिति है, उसमें भी जर्मनी ने बहुत कम प्रगति की है, वह केवल अमेरिका का अनुसरण कर रहा है. उसने ताइवान जलडमरूमध्य से लेकर दक्षिण चीन सागर तक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है. इससे स्पष्ट होता है कि जर्मनी प्रासंगिकता की तलाश में रास्ता भटक चुका है और तथाकथित सुरक्षा गारंटी के बदले स्वयं को अधिक जोखिम में डाल रहा है.

GLOBAL TIMES

चैंपियंस ट्रॉफी

# एशियाई हॉकी में भारतीय हॉकी की बादशाहत बरकरार

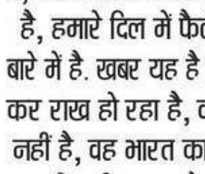

**मनोज चतुर्वेदी**
वरिष्ठ खेल पत्रकार
chaturvedi.manoj23@gmail.com

भारत ने बीते कुछ वर्षों में एशियाई हॉकी में अपनी बादशाहत कायम की है. चीन में हुई एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप में भारत के लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के दौरान भी कोई टीम उसकी बादशाहत को चुनौती देती नहीं दिखी. पेरिस ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम ने दिखाया कि वह अब बिग लीग वाली टीम है और उसे रोक पाना आसान नहीं है. यह जरूर है कि फाइनल में चीन ने हारने से पहले भारतीय टीम की अच्छी परख की, पर वह भारतीय दबदबे को तोड़ने में सफल नहीं हो सकी. यह सही है कि चीन के लिए भारत को मैच के तीन क्वार्टरों में गोल जमाने से रोके रखना जीत पाने की तरह ही है. पर भारत के लिए खुशी की बात यह है कि वह रिकॉर्ड पांचवीं बार खिताब जीतने में सफल हुई है.

भारतीय कोच क्रेग फुल्टोन ने कहा, 'हमने सातों मैच में अच्छी हॉकी खेली. पेरिस ओलिंपिक के बाद सिर्फ आठ दिन का ब्रेक मिलने की वजह से खिलाड़ी थके हुए भी महसूस कर रहे थे. हम कुछ युवाओं को भी साथ लाये हैं. पर हम जीते, यह अच्छी टीम की निशानी है.' इस चैंपियनशिप में चीन ने फाइनल में दमदार प्रदर्शन से सभी को चौंकाया. पाकिस्तान भले ही फाइनल में स्थान नहीं बना सका, पर उसने भारत के विरुद्ध बेहतरीन प्रदर्शन किया. उसने यदि यही क्षमता बाकी मैचों में दिखाई होती, तो फाइनल में चीन की जगह वह मुकाबला कर रहा होता. भारतीय हॉकी ने 2019 में ग्राहम रीड के मुख्य कोच बनने के बाद से ही प्रगति पथ पर चलना शुरू कर दिया था और उनके कार्यकाल में ही भारत ने 41 वर्षों बाद टोक्यो ओलिंपिक में हॉकी का पदक जीता था. परंतु 2023 में विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद उनकी विदाई होने पर दक्षिण अफ्रीकी कोच क्रेग फुल्टोन के मुख्य कोच बनने के बाद से भारतीय टीम ने नयी ऊंचाइयों को छुआ है. क्रेग फुल्टोन का कार्यकाल 2028 के लॉस एंजिल्स ओलिंपिक तक बढ़ाया जाना अच्छा कदम है.

भारतीय हॉकी में ऐसा दौर भी आया था, जब धड़ाधड़ कोच बदले जा रहे थे. इससे खिलाड़ी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें करना क्या है. पर अब लगता है कि इसमें सुधार आया है. यह वही दौर था, जब भारत 2008 के बीजिंग ओलिंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सका था. वर्ष 2012 के लंदन ओलिंपिक में वह अंतिम स्थान पर रहा था. यह वह दौर था जब खराब प्रदर्शन होते ही कोच की छुट्टी करने के साथ दो-चार खिलाड़ियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था. वहीं इन सबके लिए जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी कुर्सी पर जमे रहते

थे. परंतु बीते आठ-दस वर्षों में भारतीय हॉकी में बदलाव आया है. सही मायनों में अब तैयारियों को प्रमुखता दी जाती है. इसी का परिणाम है कि हम आज विश्व स्तर पर चमक बिखेर रहे हैं. भारतीय टीम में स्थायित्व आया है. फुल्टोन के समय में एक बात अच्छी दिख रही है कि टीम में एक तरफ जहां मनप्रीत सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, वहीं उत्तम सिंह और आराइजीत सिंह जैसे युवा भी हैं. इससे भारत जरूरी दूसरी पंक्ति को तैयार करने में सफल हो रहा है.

भारत को यदि ओलिंपिक और विश्व कप जैसी प्रतिष्ठित चैंपियनशिपों में स्वर्ण पदक जीतना है, तो और तैयारियों की जरूरत होगी. इसके लिए सप्लाई लाइन को और मजबूत करना होगा. मौजूदा समय में देश में क्लब हॉकी लगभग खत्म सी है, इससे सुदूर इलाकों के युवाओं के लिए खेलना अभी भी मुश्किल है. इसलिए हॉकी सुविधाओं को गांव-गांव तक ले जाना जरूरी है. हाल के समय में भारतीय सफलताओं में ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह की भूमिका अहम रही है. इस चैंपियनशिप में भी वह सात गोल दागकर चीन के यांग जी हुन (नौ) के बाद दूसरे स्थान पर रहे. पर इस बार भारतीय फॉरवर्डों ने मैदानी गोलों से दिखाया कि जीत में उनकी भूमिका भी अहम है. यह भारतीय हॉकी के लिए अच्छा संकेत है. भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 26 गोल दागे, जिनमें से 18 मैदानी गोल हुए. मैदानी गोलों की संख्या बढ़ने से टीम की हरमनप्रीत सिंह पर निर्भरता कम होगी. पर फिर भी हमें हरमनप्रीत जैसी क्षमता वाले दो-तीन और ड्रैग फ्लिकर तैयार करने की जरूरत है. भारत ने जुगराज को तैयार किया है, पर उनमें भी हरमनप्रीत जैसी क्षमता नहीं है.

भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब गोलकीपर श्रीजेश के बिना जीता है. श्रीजेश के संन्यास के बाद यह भारत का यह पहला टूर्नामेंट था. पर उनकी अनुपस्थिति में कृष्ण बहादुर पाठक और सूरज करकेरा, दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है. बेहतर होगा कि श्रीजेश को भारतीय टीम में गोलकीपिंग कोच की भूमिका दी जाए, साथ ही जूनियर गोलकीपरों को तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाए. इससे ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

आपके पत्र

### चिकित्सा सेवा से वंचित गांव

आज सरकार द्वारा अनगिनत योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं भी शामिल हैं. परंतु गांवों में आज भी चिकित्सा सेवा की स्थिति दयनीय है. आंकड़े बताते हैं कि गांव में एलोपैथ ही नहीं, होम्योपैथी और आयुर्वेद चिकित्सकों की भी कमी है. स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकों की कमी के चलते रोजाना अनेक ग्रामीण असमय दम तोड़ देते हैं. बीते कुछ वर्षों से स्थिति बेहतर हुई है, परंतु अभी और सुधार की जरूरत है. सरकार से अनुरोध है कि वह गांवों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराये.

**रितेश कुमार,** रांची

### भारत-बांग्लादेश टेस्ट सीरीज

भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाने वाली है. पाकिस्तान को उसी की धरती पर हराने से बांग्लादेश का मनोबल ऊंचा है. ऐसी हालत में बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहिए. इस बार भारत अपने सभी प्रमुख खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहा है. अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के सम्मिश्रण से बांग्लादेश की टीम भी काफी संतुलित नजर आ रही है. दोनों टीमों के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है. ऐसे में दो टेस्ट मैचों की इस शृंखला के रोमांचक होने की उम्मीद है.

**अनित कुमार राय,** धनबाद

**पोस्ट करें :** प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

Thursday, September 19, 2024
Ranchi-City
https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/66eb306ea5cca038520b7bd5

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

# युद्ध का बदलता स्वरूप

**युद्ध** के लिए अति उत्तम हथियारों को बनाने के लिए हमेशा ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता रहा है। मानव हजारों साल पहले टेक्नोलॉजी शब्द से परिचित नहीं था लेकिन जिस दिन उसने पहली बार किसी जानवर का शिकार किया था तो उसने शायद पत्थर का उपयोग किया होगा। बाद में उसने पत्थरों को नोकीला बना, धनुष बना और तलवारें बनाकर हथियार बना लिए। धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई। फिर बनी तोपें, बंदूकें, टैंक, लड़ाकू विमान, रॉकेट मिसाइल और यहां तक कि अति विध्वंसक परमाणु बम भी बना लिए। बाबर ने भी अपने समय में तोप का इस्तेमाल कर राणा सांगा की सेना पर विजय प्राप्त की थी। 1991 में लड़ा गया खाड़ी युद्ध बहुत विध्वंस माना गया। इस युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व वाली सेना ने अति आधुनिक मारक हथियारों का इस्तेमाल कर इराक को पराजित कर दिया था। वर्तमान दौर में इजराइल के पास विमान, टैंक, पनडुब्बी और परमाणु बम तो हैं ही साथ ही उन्नत मिसाइलें, लड़ाकू विमान और युद्ध पोत भी हैं। यह सब होने के साथ इजराइल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली दुनियाभर में चर्चित है। उसकी शक्ति के मुकाबले उसके दुश्मन देश कहीं नहीं टिकते।

इजराइल की खुफिया एजैंसी मोसाद दुनियाभर में इसलिए कुख्यात है कि वह अपने दुश्मनों को चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों उनको ढूंढ कर मारने में सिद्धहस्त है। तकनीकी विकास में इजराइल का मुकाबला बड़ी शक्तियां भी नहीं कर पा रहीं। 21वीं सदी में युद्ध जमीन, हवा, समुद्र और साइबर क्षेत्रों तक फैल गए हैं। युद्धों का स्वरूप बदल चुका है। अब तो एआई से लैस ड्रोन और रोबोटिक्स जैसे आटोमैटिक विध्वंसकारी हथियार जन्म ले चुके हैं। आज तो एआई सक्षम उपकरणों से बिना मनुष्य की मदद लिए कहीं भी हमला किया जा सकता है। मंगलवार की शाम टीवी चैनलों पर लेबनान में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को पेजर धमाकों से निशाना बनते देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। पेजर धमाकों में दर्जनों लोगों की मौत है गई जबकि 3 हजार से अधिक लोग घायल बताए जाते हैं। पेजर का इस्तेमाल मोबाइल फोन आने से पहले किया जाता था। अब इनका इस्तेमाल न के बराबर हो चुका है। हालांकि सुरक्षित मैसेज सेवा के लिए आज भी आतंकवादी संगठन इनका इस्तेमाल करते हैं। रेडियो बम, प्रेशर कुकर बम, ट्वाय बम या अन्य डिवाइसों से धमाके तो पहले भी होते रहे हैं लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए इस सुरक्षित तकनीक को ही घातक बना दिया गया। यह काम इजराइल के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। यह एक कल्पना से परे हमला है कि एक साथ हजारों पेजर फट जाएं। ऐसे हमले सीरिया के क्षेत्र में भी हुए। पेजर में धमाके कैसे सम्भव हुए यह सब नवीनतम टैक्नीक से ही सम्भव है। हिजबुल्लाह के लिए यह वर्षों से सबसे खतरनाक हमला है।

**वर्तमान दौर में इजराइल के पास विमान, टैंक, पनडुब्बी और परमाणु बम तो हैं ही साथ ही उन्नत मिसाइलें, लड़ाकू विमान और युद्ध पोत भी हैं। यह सब होने के साथ इजराइल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली दुनियाभर में चर्चित है। उसकी शक्ति के मुकाबले उसके दुश्मन देश कहीं नहीं टिकते। इजराइल की खुफिया एजैंसी मोसाद दुनियाभर में इसलिए कुख्यात है कि वह अपने दुश्मनों को चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों उनको ढूंढ कर मारने में सिद्धहस्त है। तकनीकी विकास में इजराइल का मुकाबला बड़ी शक्तियां भी नहीं कर पा रहीं। 21वीं सदी में युद्ध जमीन, हवा, समुद्र और साइबर क्षेत्रों तक फैल गए हैं। युद्धों का स्वरूप बदल चुका है।**

इजराइल-हमास संघर्ष शुरू होने से एक साल के भीतर यह हमला युद्ध से भी ज्यादा गम्भीर है। इजराइल-हमास युद्ध में हिजबुल्लाह भी कूदा हुआ है। क्योंकि इजराइल के पास हमले की वो क्षमताएं और खुफिया तंत्र है जो इंसान के सोचने के दायरे को भी पार कर देता है। हिजबुल्लाह पिछले कुछ दिनों से इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा था। यह इजराइल की ही ताकत है कि वह इन रॉकेट हमलों को आसानी से विफल करता आ रहा है। हिजबुल्लाह पर जबर्दस्त हमला एक तरह से ईरान को भी चुनौती है। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। आशंका इस बात की है कि इजराइल-हमास युद्ध का कहीं और विस्तार न हो जाए। अगर युद्ध का विस्तार फैलता है तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। यह जग जाहिर है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि वह खुद को काबू में रखे।

तकनीक और स्वचालन में तेज उन्नति संघर्ष और युद्ध के भविष्य को गढ़ना जारी रखेगी, जो देश इन तकनीकों को आगे बढ़ा रहे हैं उनका एकमात्र लक्ष्य इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करना और जल्द से जल्द तैनात करना है। युद्ध क्षेत्र में एक-दूसरे के आमने-सामने रोबोट और दूसरी स्वायत्त प्रणालियों के होने की संभावना और मानव क्षति का कोई डर नहीं होने से सैन्य योजनाकार लड़ाई में पूरे दमखम से कूद सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। युद्ध के लिए इस तकनीकी विकास का यह सबसे गंभीर नतीजों वाला प्रभाव है। यह युद्ध लड़ने के राजनीतिक नतीजों तथा शत्रुता ख़त्म करने के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ़ने की नैतिक आवश्यकता को समाप्त कर देगा। अराजकता की ओर बढ़ने की यह स्पष्ट संभावना घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का नियमन अनिवार्य बनाती है।

भविष्य में होने वाले युद्ध तकनीक पर आधारित होंगे। इस लिए भारत के सशस्त्र बलों को भी ऐसे युद्धों के लिए तैयार रहना होगा। भविष्य के युद्धों में केवल वीरता ही पर्याप्त नहीं, हमें कल्पना से परे जाकर खुले दिमाग से काम लेना होगा। भारत महाशक्ति तब बनेगा जब वह नई तकनीक, ऊर्जा और नए जोश और नई सोच के साथ काम करेगा।

**आदित्य नारायण चोपड़ा**
Adityachopra@punjabkesari.com

## सुर्खियां पाना चाहते हैं...

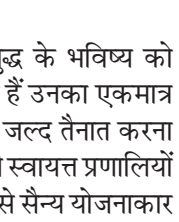

"कैसे उम्मीद रखें उनसे कि
वो संविधान का गौरव बढ़ाना चाहते हैं,
और हमारे चुने हुए नुमाइंदे के रूप में
सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना चाहते हैं,,
वो तो अपने तालिबानी फरमानों से केवल सुर्खियां पाना चाहते हैं
और समाज में सिर्फ अशांति और हिंसा का बीज लगाना चाहते हैं...।"

**गीता पाढा**

# हरियाणा : शासन विरोधी भावना में फंसी भाजपा

मर्यादाएं

**चन्द्रमोहन**
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

**हरियाणा** और जम्मू-कश्मीर के चुनावों और उनके बाद होने वाले महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनावों का राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा। यह बताएंगे कि हवा किस तरफ़ बह रही है। वैसे तो महाराष्ट्र के चुनाव भी साथ होने चाहिए थे पर चुनाव आयोग ने किन्हीं कारणों से इन्हें साथ करवाने से इंकार कर दिया। यह दिलचस्प है कि सरकार देश में एक साथ चुनाव करवाने की बात करती है। प्रधानमंत्री कई बार 'वन नेशन वन इलेक्शन' की बात कर चुके हैं पर जिस चुनाव आयोग से तीन प्रदेशों के चुनाव इकट्ठे नहीं करवाए जा सकते वह सारे देश में कैसे एक साथ चुनाव करवाएंगे ? भाजपा के लिए बेहतर होता कि महाराष्ट्र के चुनाव भी साथ करवा लिए जाते क्योंकि रुझान लग रहा है कि दस वर्ष के बाद शासन विरोधी भावना हरियाणा में भाजपा को परेशान करने जा रही है। फ़ायदा कांग्रेस को होगा।

अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आप में जान पड़ गई है। उनके इस्तीफ़े का दिल्ली पर असर हो सकता है, हरियाणा पर बहुत असर नहीं होगा। उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिल्ली के वोटर को प्रभावित करने के लिए दिया है। उन्होंने कहा भी है कि "दिल्लीवालों, अगर आप को लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना और अगर लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो मुझे वोट मत देना"। अरविंद केजरीवाल ने भावनात्मक जुआ खेला है कि वह पीड़ित है। ऐसा कर वह 10 साल की शासन विरोधी भावना से भी बचना चाहते हैं। वह नैतिक पहल छीनना चाहतें हैं। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने दिल्लीवालों से खुद को जेल से बाहर रखने के लिए वोट मांगा था, दिल्ली की प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। हरियाणा में वह 'हरियाणा के लाल' के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ऐसा वह पहले भी कर चुके हैं पर कुछ मिला नहीं था। इस समय हमारी राजनीति दो हिस्सों में बंट गई लगती है। जो भाजपा को जीताना चाहते हैं और जो उसे हराना चाहते हैं।

हरियाणा में भाजपा ने सीएम बदल कर बचने की कोशिश की है। मनोहर लाल खट्टर की जगह उनके वफ़ादार नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया है पर सैनी खट्टर की छाया से निकल नहीं पा रहे। उनकी घोषणा के बावजूद की वह करनाल से चुनाव लड़ेंगे उन्हें लाडवा से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। सैनी वैसे भी बार-बार चुनाव क्षेत्र बदलने के लिए मशहूर हैं। नई सरदर्द वरिष्ठ नेता अनिल विज ने खड़ी कर दी है जिन्होंने भाजपा की जीत की स्थिति में सीएम पद के लिए अपना दावा रख दिया है। भाजपा में यह अभूतपूर्व घटना है क्योंकि भाजपा में कोई खुलेआम अपना दावा नहीं ठोकता। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन आशा से बहुत कम रहा और वह पांच सीटें कांग्रेस को खो बैठे। भाजपा के लिए असली चिन्ता यह है कि जिस कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में 28.51 प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे वह 2024 में 43.68 प्रतिशत वोट जीतने में सफल रही जबकि उसने नौ सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। पांच साल में15 प्रतिशत की कांग्रेस के वोट में विशाल वृद्धि हरियाणा की जनता का बहुत बड़ा संदेश है। भाजपा का अपना वोट 46.1 प्रतिशत थापर यह पिछले लोकसभा चुनाव से 12 प्रतिशत गिरा है। प्रदेश चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर नरेन्द्र मोदी नहीं है।

लोकसभा के चुनाव में भाजपा के दलित समर्थन में भी भारी गिरावट देखी गंई है। कांग्रेस मज़बूत नज़र आ रही है। जैसे पंजाब विश्वविद्यालय के प्रो. अशुतोष कुमार ने कहा है, "गति कांग्रेस के साथ है। लोकसभा चुनाव के

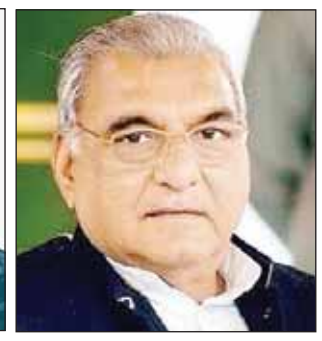

तीन महीने के बाद भी कुछ नहीं बदला"। उनके अनुसार मज़बूत शासन विरोधी भावना, नेतृत्व का मामला, भाजपा में आंतरिक कलह, किसानों की समस्या, सब भाजपा को परेशान करेंगे। एक बात जो उन्होंने नहीं कही वह कांग्रेस का मजबूत स्थानीय नेतृत्व है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा में कांग्रेस के पास अनुभवी नेता हैं जिन्हें विशेष तौर पर प्रभावशाली जाट समुदाय का समर्थन हासिल है। भाजपा नए नए चेहरों का एक्सपेरिमेंट करती है। ज़रूरी नहीं वह सफल रहे। मध्य प्रदेश और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अब तक जम नहीं सके। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का स्तर और स्वीकार्यता नायब सिंह सैनी से बहुत अधिक है। कांग्रेस ने भी हुड्डा को खुला हाथ दे दिया लगता है। टिकटों के बंटवारे में उनकी ही चली है, कुमारी सैलजा जैसों को अधिक महत्व नहीं दिया गया। हुड्डा के दबाव में आप के साथ समझौता भी नहीं हो सका।

हरियाणा में भाजपा की बड़ी समस्या मनोहर लाल खट्टर की विरासत से उभरना है। उन्हें सीएम बना कर भाजपा ने ग़ैर- जाट समुदाय को साधने की कोशिश की थी। 2014 में पार्टी 90 में से 47 सीटें जीतने में सफल रही थी। उस समय नरेन्द्र मोदी की आभा भी शिखर पर थी। 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को केवल 40 सीटें मिली थी। जिन मतदाताओं ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को जीत दिलवाई थी उन्होंने ही विधानसभा चुनाव में पूरा समर्थन नहीं दिया और सरकार बनाने के लिए मनोहर लाल खट्टर को दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पर निर्भर होना पड़ा। समर्थन में यह गिरावट रूकी नहीं लगती। नायब सिंह सैनी ने नीतियों को सही करने की कोशिश की है और युवाओं और महिलाओं को रेवड़ियाँ बाँटना शुरू कर दिया है पर यह देर से उठाया गया कदम है। अनुभव है कि लोग चुनाव से बहुत पहले मन बना लेते हैं।

भाजपा ने अपनी सूची में कई दलबदलू शामिल किए हैं। किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने के कुछ ही दिनों के बाद उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया। पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का कहना है कि जीतने की क्षमता एक मात्र मानदंड है। अर्थात पार्टी कह रही है कि विचारधारा अब बहुत महत्व नहीं रखती और सत्ता प्राप्त करने के लिए वह भी कांग्रेस के रास्ते पर चल रहे है। इसका कायकर्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। टिकट बंटवारे को लेकर एक समय तो बग़ावत की स्थिति पैदा हो गई थी। कांग्रेस में भी असंतोष था पर उसे सम्भाल लिया गया है, वहां कोई अनिल विज नहीं उठा। एक और मामले में कांग्रेस का अनुकरण किया गया है। देश भर में भाजपा वंशवादी राजनीति का विरोध कर रही है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर में भाजपा ने तीन परिवारों के वंशजों को खूब रगड़ा लगाया है पर हरियाणा में इसी भाजपा ने बंसी लाल, भजनलाल, विनोद शर्मा, राव इन्द्रजीत सिंह, देवीलाल, सब के परिवार के सदस्यों को या तो टिकट दिए या प्रदेश मंत्रिमंडल में रखा।

हरियाणा में बड़ी समस्या बेरोज़गारी है। मार्च 2023 में हरियाणा की बेरोज़गारी की दर देश में सबसे अधिक 26.77 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय बेरोज़गारी औसत 9 प्रतिशत के लगभग थी। लगभग दो लाख सरकारी नौकरियां भरी नहीं गईं। बेरोज़गार युवा इस सरकार और भावी सरकारों को परेशान करते रहेंगे। बेचैन और आक्रामक किसान जत्थेबंदियों ने भी वहां सरकार की नाक में दम कर रखा है। जिस कठोरता के साथ सरकार पंजाब सीमा पर किसानों से निबटी है उससे किसानों में भाजपा के प्रति ग़ुस्सा है। कई गांवों में भाजपा के लोगों को घुसने नहीं दिया गया। 'संयुक्त किसान मोर्चा', (एसकेएम) ने तो भाजपा को सजा देने का आह्वान कर दिया है। अग्निपथ योजना के कारण प्रदेश का यूथ नाराज़ है। हरियाणा के युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा आकर्षण था। रोज़गार भी मिलता था और इज्जत भी। लेकिन जबसे चार साल वाली अग्निपथ योजना शुरू हुई है यह आकर्षण ख़त्म हो गया है। पहले 5000 के क़रीब युवा भर्ती होते थे अब यह संख्या कम हो कर 1000 के क़रीब रह गई है।

प्रभावशाली जाट समुदाय भी एंटी है। 2014 से पहले मुख्यमंत्री देवीलाल, बंसी लाल, ओम प्रकाश चौटाला और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सब जाट थे। केवल एक बार भजनलाल मज़बूत ग़ैर जाट मुख्यमंत्री रहे हैं। 2014 के बाद भाजपा ने ग़ैर-जाट,मनोहर लाल खट्टर को सीएम बना दिया। अपनी हैसियत कम होने को जाट भूले नहीं। चाहे वह 26-28 प्रतिशत ही हैं पर राजनीतिक और सामाजिक दबदबा कहीं अधिक है। सारा किसान आन्दोलन इन्हीं ने चलाया था। जिस तरह केन्द्र की सरकार हरियाणा की महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न की शिकायत से बेरुख़ी से निबटी है उसका भी असर हुआ है।

विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहीं हैं। इस जांबाज़ महिला पहलवान के प्रति हरियाणा में बहुत सहानुभूति है। पेरिस से लौटने के बाद भाजपा का विनेश के प्रति रवैया उदासीन रहा है। खट्टर के सीएम बनने के बाद सरकार में जाटों का प्रभाव कम हो गया। अब वह समझते हैं कि शायद समय आ गया है कि ग़ैर जाटों से वह सत्ता छीन सकते हैं इसीलिए वह भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के पीछे एकजुट हो रहे हैं। इसका एक और प्रभाव यह हो रहा है कि जो प्रादेशिक पार्टियां जाटों के समर्थन पर निर्भर थी वह ख़त्म होने के कगार पर है। लोकसभा चुनाव में दोनों जाट आधारित आईएनएलडी और जेजेपी को लोगों ने नकार दिया। पहली को 1.74 प्रतिशत वोट मिले तो दूसरी को एक प्रतिशत और नोटा से भी कम।

पर अभी चुनाव में कुछ दिन बाक़ी हैं। भाजपा खूब ज़ोर लगाएगी। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भुनाने का पूरा प्रयास होगा। यह भी देखने की बात होगी कि आप किसका वोट काटती है? अरविंद केजरीवाल की पार्टी शहरी है पर जहां वह भाजपा विरोधी वोट को बांटेगी वहां वह भाजपा के शहरी वोट पर भी सेंध लगा सकती है। पर यह भी हो सकता है कि हरियाणा में आप का वही हाल हो जो 2019 में हुआ था, जब नोटा से भी कम वोट मिले थे। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का प्रभाव नहीं होगा। वह कह ही चुकीं हैं कि उनका काम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। हरियाणा में किसी तीसरे की गुंजायश नहीं है। अफ्रीकी मुहावरा है कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास रौंद दी जाती है।

# एजुकेशन लंगर सिख कौम की प्राथमिकता होनी चाहिए

सिख सियासत

**सुदीप सिंह**
newsreporter.2008@gmail.com

**गुरु** नानक देव जी से लेकर सभी दस गुरु साहिबान ने सिखों को जरुरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। गुरु साहिबान द्वारा दी गई शिक्षा के मुताबिक हर सिख को ''गुरु की गोलक - गरीब का मुंह'' भाव गुरु की गोलक में आने वाले धन को जरुरतमंदों पर खर्च करना चाहिए पर अफसोस कि आज सिख कौम केवल लंगर लगाने और गुरुद्वारा साहिबान की इमारतों को आलीशान बनाने में लगी हुई है। वहीं आज भी सिखों के अनेक परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई सिर्फ इसलिए बीच में ही रुकवा देते हैं क्योंकि उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। मगर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इन्हीं पैसों को अगर जरुरतमंद परिवारों के बच्चों की एजुकेशन पर खर्च किया जाए तो ना जाने कितने लोगों का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है।

उच्च पदों से सिख गायब होने का दुख सबको है, मगर क्या किसी ने इस बात की चिन्ता की है कि सिख बच्चों को आईपीएस, आईएएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाए ताकि सिख बच्चे इन पदों पर आसीन हो सकें। ऐसा भी देखा जा रहा है कि गुरुपर्व के मौके पर करोड़ों रुपयों के

फूलों से सजावट की जाती है जो देखने में बहुत ही सुन्दर भी दिखती है मगर इन लोगों को भी चाहिए कि सजावट में कुछ खर्च कम करके एजुकेशन में लगाये जाएं।

कुछ संस्थाएं ऐसी जरुर हैं जो जरुरतमंद बच्चों की पढ़ाई पर अपनी दसवंद के पैसे खर्च करने को प्राथमिकता दे रहे हैं, उन्हीं में से एक है फरीदाबाद के बलविन्दर सिंह। जिनके द्वारा अपने पारिवारिक सदस्यों की मदद से सिख बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जा रही है। अभी हाल ही में इन्होंने दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में सिख बच्चों के लिए

जागरुकता कैंप लगाया और भाग लेने वाले बच्चों में से उन बच्चों का चयन किया गया जिनमें ऐसी क्षमता पाई गई जो कि आगे चलकर निश्चित तौर पर उच्च पदों पर आसीन होकर अपने साथ साथ कौम का भविष्य भी उज्जवल बना सकते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, महासचिव जगदीप सिंह काहलो के द्वारा भी इनके कार्यों की सराहना की गई और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इसी प्रकार समाजसेवी डा. गुरमीत सिंह सूरा जैसे भी कई लोग हैं जो निजी तौर पर हर वर्ष कई सिख बच्चों की पूर्ण एजुकेशन का खर्च उठाकर उनका भविष्य सुधारने में लगे हैं।

**सारागढ़ी का इतिहास स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए**

सारागढ़ी का युद्ध सिखों की बहादुरी का प्रतीक है जिसमें मात्र 21 सिख सैनिकों ने हवलदार ईश्वर सिंह के नेतृत्व में 10 हजार अफगान सैनिकों का डटकर ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि 600 के करीब अफगानियों को मौत के घाट उतारने के बाद अन्त में वीरगति को प्राप्त हो गये। संसार के 5 महान युद्धों में इसकी गिनती आती है। इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजी हकूमत अफगानिस्तान पर कब्जा करने की मंशा लिए हुए थी जिसके चलते 1897 तक अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमले करना भी शुरू कर दिए थे। अफगानिस्तान की सीमा पर ब्रिटिश सेना के कब्जे में दो किले गुलिस्तान और लॉकहार्ट थे। ओराक्जई जनजाति के लोग गुलिस्तान और लॉकहाट के किलों पर अपना कब्जा चाहते थे जिसके पास ही सारागढ़ी के नाम से एक चौकी मौजूद थी जो दोनों किलों के बीच संचार का जरिया थी। इस चौकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी 36वीं सिख रेजिमेंट के पास थी जिसमें 21 सैनिक तैनात थे। 10 हजार अफगान पश्तूनों ने 12 सितम्बर 1897 की सुबह 9 बजे सारागढ़ी पोस्ट पर आक्रमण शुरू कर दिया। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या अपनी तरफ आता देख सैनिकों के नेता हवलदार ईश्वर सिंह ने सिग्नल मैन गुरमुख सिंह को आदेश दिया कि पास के फोर्ट लॉकहार्ट में तैनात अंग्रेज अफसरों को तुरंत हालात से अवगत कराने के साथ मदद मांगी जाए। सिग्नल मिलने के बाद कर्नल हौथटन ने पोजिशन होल्ड रखने और तुरन्त सहायता नहीं भेज पाने की बात कही। यह जानकारी मिलने के बाद ईश्वर सिंह ने निर्णय लिया कि वे मरने से पूर्व इस चौकी को नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर सिंह का साथ उनके सैनिकों ने भी दिया और अन्तिम सांस तक लड़ने का निर्णय लिया।

पंजाब की भगवंत मान सरकार के द्वारा सारागढ़ी के इतिहास की याद ताजा रखने हेतु फिरोजपुर में सारागढ़ी स्मारक तैयार करवाया है जिसके लिए राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने अपने फण्ड से 50 लाख रुपये की अनुदान राशि दी है बीते दिनों इसका विधिवत उद्घाटन कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर के द्वारा किया गया । डॉ. साहनी ने कहा कि सारागढ़ी की लड़ाई वीरता, पराक्रम और बलिदान का प्रतीक है, जो देशभक्ति और साहस की भावना को जगाता है। उन्होंने केन्द्र और राज्य की सरकार से मांग की कि वह स्कूली पाठ्य पुस्तकों में सारागढ़ी की लड़ाई पर एक अध्याय शुरू करे ताकि छात्रों को "अद्वितीय और अनुकरणीय लड़ाई" के बारे में पढ़ाया जा सके। गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल लोनी रोड में भी चेयरमैन परविन्दर सिंह लक्की और प्रिंसीपल सतबीर सिंह के द्वारा एक कार्यशाला करवाई गई ताकि बच्चों को इतिहास के प्रति जागरुक किया जा सके।

**सिख पंथ में अरदास की महत्वता**

सिख कौम में अरदास की बहुत महत्वता है, सच्चे मन से की हुई हर अरदास पूरी होती है। सिख कौम अरदास में अपने साथ-साथ समूची मानवता की भलाई भी मांगती है। वैसे तो हर सिख को अपनी अरदास स्वयं करनी चाहिए पर ऐसा ना करते हुए वह गुरुद्वारा साहिब के ग्रन्थी, सेवादार से भी अरदास करवा सकते हैं। आमतौर पर ग्रन्थी, सेवादार से अरदास करवाते समय लोग उन्हें अरदास भेंट अर्पण करते हैं। एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आपने जो भी भेंट देनी है वह अरदास शुरू होने से पहले या फिर समाप्ति के बाद दी जानी चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि जब ग्रन्थी सिंह अरदास कर रहे होते हैं तो बीच में ही संगत अरदास भेंट अर्पण करती रहती है जिससे अरदास करने वाले का ध्यान भटकना स्वभाविक सी बात है। सिख कौम को अरदास से ही शक्त भी मिलती है, कई बड़े युद्ध केवल अरदास से ही जीते गए हैं। हाल ही में पंजाबी फिल्म निर्माता जिप्पी ग्रेवाल ने ''अरदास सरबत के भले की'' मूवी बनाई है जिसमें अरदास की महत्वता और उसे करने के तरीके को दर्षाया गया है जिसकी भरपूर प्रशंसा की जा रही है।

हालांकि जब फिल्म का टेलर जारी हुआ था तो इसमें गुरबाणी की पंक्तियों से छेड़छाड़ किये जाने की बात सामने आई थी जिसकी हजूर साहिब से जुड़े परमजीत सिंह वीरजी के द्वारा एतराज जताया गया जिस पर फिल्म निर्माता ने तुरन्त ध्यान देते हुए गलतियों में सुधार के पश्चात फिल्म को रिलीज किया। दिल्ली में फिल्म के प्रिमियर के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके, समाजसेवी एम एम पाल सिंह गोल्डी आदि ने फिल्म को देखने के पश्चात् बताया कि जो भी व्यक्ति फिल्म को देख रहा है उनकी आंखें नम हो जाती है। इससे पहले भी फिल्में जिप्पी ग्रेवाल के द्वारा बनाई जा चुकी हैं। जिप्पी ग्रेवाल की तारीफ की जानी चाहिए जिन्होंने इतनी भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक मूवी तैयार की है।

# नशा तस्कर कॉरिडोर को ध्वस्त करने के सीएम के सख्त निर्देश

**नई दिल्ली,** (पंजाब केसरी) : छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त तेवर अपनाए हैं। उनके निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है और कई बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने प्रदेश भर में कई सफल कार्रवाइयां की हैं, जिनमें रायपुर रेंज में हजारों क्विंटल गांजा जलाया गया और बिलासपुर जिले में साढ़े 12 लाख रुपये के नशीली इंजेक्शन के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इसके अलावा, जीपीएम पुलिस ने 21 लाख रुपये के गांजे के साथ तीन अंतरराज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। रायपुर में आयोजित एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में नशाखोरी एक गंभीर समस्या बन चुकी है, और इसे जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस को अवैध व्यापार के इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा। साथ ही उन्होंने अवैध शराब की बिक्री को लेकर भी सख्त हिदायत दी, जिसमें पुलिस पर संरक्षण के आरोप लगते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों से पुलिस की छवि धूमिल होती है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, छत्तीसगढ़ अब तस्करों के लिए गांजा, अफीम और अन्य मादक

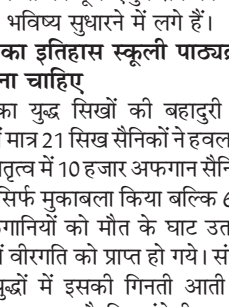

पदार्थों की सप्लाई का एक अहम कॉरिडोर बन चुका है, जिसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, और 15 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। प्रदेश से गुजरने वाले इस कॉरिडोर के माध्यम से बड़ी मात्रा में नशे की सामग्री अन्य राज्यों तक पहुंचाई जा रही है। रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का उद्घाटन करते समय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह चिंता जताई थी कि छत्तीसगढ़ में गांजे की तस्करी एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि राज्य में गांजे की खपत राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है और इससे कमाए गए पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद और नक्सलवाद को फंडिंग देने में किया जाता है। सरकार ने हर जिले में ड्रग नेटवर्क चार्ट बनाने की योजना बनाई है, जो तस्करी के गतिविधियों में वृद्धि और गिरावट को रंगों के माध्यम से इंगित करेगा। इससे तस्करों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और अधिकारियों की सक्रियता या निष्क्रियता उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही, तस्करों द्वारा अपनाए जा रहे नए-नए तरीकों को लेकर भी सरकार सतर्क है और उनके खिलाफ भी अभियान चलाए जा रहे हैं।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 19 सितम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com



## अनमोल वचन

*भोग में रोग का, उच्च-कुल में पतन का, धन में राजा का, मान में अपमान का, बल में शत्रु का, रूप में बुढ़ापे का और शास्त्र में विवाद का डर है। भयरहित तो केवल वैराग्य ही है* -भगवान महावीर

# आत्ममंथन का समय

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी समझ से जोरदार राजनीतिक चाल चली है, लेकिन लगता नहीं कि उनको बहुत ज्यादा राजनीतिक लाभ होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि केजरीवाल ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर जनता से फैसला मांगा है। अगर इस बार दिल्ली की जनता उनकी पार्टी के पक्ष में जनादेश देती है तो इसका मतलब होगा कि वे ईमानदार हैं। यह बयान चालाकीपूर्ण है। वास्तव में उनकी ईमानदारी का फैसला अदालत करेगी। जनता ही फैसला करने लग जाए तो जेल से चुनाव जीतने वाले अपराधी बेदाग और ईमानदार हो जाएंगे। दूसरी बात आबकारी नीति के मामले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत उनकी पार्टी सवालों के घेरे में हैं। लेकिन पूरे मामले में केजरीवाल आज तक खुलकर



यह नहीं बता पाए कि नई आबकारी नीति क्यों लाए और क्यों इसे वापस ले लिया। केजरीवाल की चुप्पी साबित करती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तीसरी बात आम आदमी पार्टी (आप) की ही नेता रहीं स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर केजरीवाल के करीबी विभव कुमार द्वारा मारपीट के समय स्वयं केजरीवाल और उनकी पत्नी, दोनों मौजूद थे लेकिन आज तक दोनों ने इस मामले में मुंह नहीं खोला जबकि जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के धरने पर केजरीवाल ने पहुंच कर उनका समर्थन किया था। कहा था कि दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ी हमारी बेटियां हैं, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वस्तुतः स्वाति मालीवाल के मामले में केजरीवाल और उनकी पार्टी को अधिक नुकसान हुआ है। जनता इन सब चीजों को देखती और परखती है। केजरीवाल और उनकी पार्टी की पहले जैसी छवि नहीं रही है। फिर एक दशक के शासन में आप के विरुद्ध सत्ता विरोधी लहर भी है। अब आतिशी मार्लेना सिंह को आप के विधायक दल का नेता चुना गया है। आतिशी ने बहुत सक्षम नेत्री के रूप में अपने को स्थापित किया है। वह केजरीवाल के प्रति वफादार हैं और घोषणा कर चुकी हैं कि अपने राजनीतिक गुरु के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रही हूं और उन्हें वापस लाने के लिए काम करूंगी। यह ठीक है कि आप में केजरीवाल को कोई चुनौती देने वाला नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी गलती-कमियों पर आत्ममंथन करना चाहिए और जनता के सामने सचमुच ईमानदार बन कर रहना चाहिए अन्यथा बदलावकारी राजनीति के लिए उनका आगमन एक दुर्घटना के रूप में दर्ज किया जाएगा।

# ममता की रणनीति

कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को डॉक्टरों की मांगों के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने पुलिस कमीश्नर, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के निदेशक को उनके पदों से हटा दिया। प्रदर्शनकारी चिकित्सकों से मिलने के बाद ममता ने कहा कि सरकार ने उनकी चार में से तीन मांगें मान ली हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को हटाने को वह राजी नहीं हुईं। उक्त तीनों को पद से हटाने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा जांच पूरी करने और पीड़िता को न्याय दिलाने में हर संभव मदद की बात भी की। अस्पताल में सीसीटीवी, पेशाबघर आदि सुविधाओं के लिए सौ करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी। प्रदर्शनकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई न करने पर भी सहमति जताई। इस बातचीत और मांगों को मानने को ममता के पांव पीछे खींचने के तौर पर देखा जा रहा है। अपने करीबी अधिकारियों को लेकर उनका रुख



हमेशा अड़ियल रहा है। केंद्र से इस मसले में ममता की कई बार तकरार भी हो चुकी है। हालांकि कुछ रोज पहले ही उन्होंने स्पष्ट किया था कि पुलिस कमीश्नर दुर्गा पूजा तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसे ममता के रणनीतिक दांव के तौर पर भी आंका जा रहा है। दरअसल, इस घटना पर पूरे देश की निगाहें अटकी हुई हैं। दूसरे, यह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों और जनाक्रोश का असर महिला मतदाताओं पर पड़ने से आशंकित ममता ने दूरगामी रणनीति अपनाई। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदाराना रुख दिखाते हुए ही ममता ने इसी महीने की शुरुआत में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक आनन-फानन में पारित किया। बहरहाल, इस आंदोलन को खत्म कराने को उनकी मजबूरी के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए कि अपनी असफलताओं और विवादों को सुलटाने में उन्हें कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। सीबीआई पहले ही राज्य में शिक्षा से जुड़े कथित घोटाले की जांच कर रही है जिसके नतीजे ममता की सरकार के पक्ष में न होने का भी खमियाजा चुकाना पड़ सकता है। समय और जनता के रुख को भांपते हुए ममता द्वारा उठाया गया यह कदम दूरदर्शितापूर्ण और न्यायप्रियता भरा माना जा सकता है। चिकित्सकों के काम पर लौटने से रोगियों और उनके परिजनों को भी खासी राहत मिलेगी।

कटाक्ष/ सहीराम

# नई व्याख्या

मंडल-कमंडल की नई व्याख्या सामने आ गई है जी! अभी तक तो इसकी यही व्याख्या चल रही थी और सर्वस्वीकृत तथा सर्वमान्य भी थी कि कमंडल को मंडल की काट के लिए ही लाया गया था। लेकिन अब नई व्याख्या सामने आई है कि वास्तव में कमंडल तो मंडल की मदद के लिए आया था। नई व्याख्या किसी और ने नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने की है। राजनीतिक विश्लेषक, टिप्पणीकार सावधान हो जाएं कि अब जब कभी भी वे किसी राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक विषय के दाव-पेंच की मनमानी व्याख्या करेंगे तो उन्हें इस सर्वोच्च व्याख्याकार की ओर से न सिर्फ समुचित जवाब दिया जाएगा, बल्कि दुरुस्त भी किया जाएगा, वैसे ही जैसे वे गणेश जी की सर्जरी या कौरवों के स्टेम सेल टाइप के जन्म जैसे मिथकों की वैज्ञानिक व्याख्या करते रहे हैं। वैसे यह तो कुछ-कुछ हल्दी घाटी के युद्ध की नई संघी व्याख्या का सा मामला हो गया जी कि यह युद्ध तो वास्तव में महाराणा प्रताप ने ही जीता था। खैर, अभी तक तो इतिहास की ही पुनर्व्याख्या हो रही थी, पुनर्लेखन हो रहा था और यह काम संघ के जिम्मे था। लेकिन समसामयिक राजनीतिक मुद्दों और विषयों की भी पुनर्व्याख्या होने लगी है, और जिम्मा स्वयं प्रधानमंत्री ने ले लिया है।

पिछले दिनों उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा कि मंडल तो वीपी सिंह की वही सरकार लेकर आई थी, जिसका भाजपा समर्थन कर रही थी। हालांकि इधर भाजपा और उधर वाम मोर्चा, दोनों ही बाहर से उसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया। यह भी नहीं बताया कि आडवाणी जी की रथयात्रा आयोजित करने की योजना इसके बाद ही बनाई गई थी। वैसे, वे यह बताने से चूकते नहीं हैं कि मोदी ने यह किया, वह किया। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि रथ यात्रा का सारथी मैं ही था, माने मोदी ही था। यह भी नहीं बताया कि वीपी सिंह सरकार से भाजपा ने इसीलिए समर्थन वापस लिया था कि उसने मंडल रिपोर्ट लागू की थी। जबकि दूसरी ओर वाम मोर्चा तो उसे समर्थन देता रहा था। इसीलिए विद्वानों, विचारकों, संपादकों, समाचार पत्रों-पत्रिकाओं, सबने इस पूरे प्रकरण को मंडल बनाम कमंडल के रूप में ही पेश किया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इसकी नई व्याख्या पेश कर दी है कि वास्तव में कमंडल तो मंडल की मदद के लिए आया था।

# ग्रामीण विकास का नया अध्याय

कृषि उन्नयन
डॉ. जयंतीलाल भंडारी



यकीनन इस समय सरकार द्वारा खाद्य कीमतों पर सतर्कता, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए एक के बाद एक जो रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं, उनसे देश की आर्थिकी बढ़ने का परिदृश्य निर्मित हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में 17 सितम्बर को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 100 दिनों में कृषि एवं ग्रामीण विकास उन्नयन के प्रयास इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर हैं, और इनसे जहां किसान लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं ग्रामीण विकास का एक नया अध्याय भी लिखा जा रहा है।

गौरतलब है कि हाल में केंद्र सरकार ने जहां बासमती चावल और प्याज निर्यात पर राहत दी है, वहीं खाद्य तेलों के आयात शुल्क में भी कुछ वृद्धि की है, ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिल सके और मुद्रास्फीति भी नियंत्रित रहे। ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने खाद्य वस्तुओं के निर्यात के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय लिए हैं, उनके तहत बासमती चावल पर लागू 950 डॉलर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) और प्याज के निर्यात पर लागू 550 डॉलर न्यूनतम एमईपी को हटाने के साथ ही प्याज पर निर्यात शुल्क 40 फीसद से घटाकर 20 फीसद करना शामिल है। खाद्य वस्तुओं के आयात संबंधी फैसले के तहत सरकार ने शून्य आयात शुल्क पर पीली मटर के आयात की अवधि 31 सितम्बर से बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दी है। इसके साथ-साथ कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर प्रभावी आयात शुल्क 12.5 फीसद से बढ़ाकर 32.5 फीसद कर दिया गया है। रिफाइंड तेल पर प्रभावी आयात शुल्क अब 13.75 फीसद से बढ़ा कर 35.75 फीसद किया गया है।

इसी तरह पिछले दिनों 2 सितम्बर को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें कृषि क्षेत्र के विकास की सात बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन पर कुल 14000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें से 2,817 करोड़ रुपये डिजिटल कृषि मिशन के लिए दिए जाएंगे। वहीं, फसल विज्ञान पर 3,979 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कृषि शिक्षा और प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। पशुधन के स्थायी स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई है।

गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के अभियान के तहत 11 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) परिसर के खेतों में जाकर 61 फसलों की 109



नई एवं उन्नत किस्में जारी करते हुए कहा कि इनसे देश में कम जमीन में अधिक पैदावार लेने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इससे महंगाई से भी बचाव होगा। किसानों को फायदा पहुंचाने के इन प्रयासों के साथ एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी रेखांकित हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां 18 जून को किसानों को 'पीएम किसान सम्मान निधि' की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किए और कहा कि इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और लगभग 20 हजार करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में वितरित किए जा रहे हैं। वहीं 19 जून को 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 के बजट के तहत किसानों के कल्याण और कृषि को विकास का इंजन बनाने की रणनीति के तहत किसानों के हित में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की क्षमता के दोहन के जो अभूतपूर्व कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी जा सकेगी। निस्संदेह सरकार ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। कृषि और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इसी के मद्देनजर इन दिनों प्रकाशित हो रहीं वैश्विक आर्थिक संगठनों और वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्टों में भारत में कृषि सेक्टर में सुधार और ग्रामीण खपत में वृद्धि के मद्देनजर भारत की विकास दर के अनुमान बढ़ाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि तीन सितम्बर को विश्व बैंक द्वारा जारी 'इंडिया डवलपमेंट अपडेट' रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण मांग में तेजी के चलते भारत की विकास दर 7 फीसद के स्तर पर पहुंचते हुए दिखाई देगी।

निश्चित रूप से सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने की डगर पर आगे बढ़ते हुए कई अहम बातों पर ध्यान दिया जाना होगा। सरकार के सामने खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर सतर्कता रखने के साथ-साथ घटी हुई कृषि विकास दर, गेहूं भंडारण में कमी, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने तथा खाद्य उत्पादों की बर्बादी रोकने तथा किसानों के असंतोष की चुनौतियों का सामाधान करने की चुनौतियां हैं। जहां वित्त वर्ष 2023-24 में देश की विकास दर 8.2 फीसद रही, वहीं कृषि विकास दर महज 1.4 फीसद ही रही। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भी जीडीपी में कृषि योगदान बढ़ाने की चुनौती दिखाई दे रही है।

हम उम्मीद करें कि सरकार ने पिछले 100 दिनों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली जिन योजनाओं की पहल की है, उनके लाभों और प्रयोगों के बारे में किसानों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। हम उम्मीद करें कि सरकार द्वारा नई कृषि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, जलवायु अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणाली अपनाए जाने, अधिक से अधिक ग्रामीण कच्ची सड़कों को मंडियों से जोड़ने जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के साथ-साथ वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट के तहत कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन की डगर पर लगातार आगे बढ़ा जाएगा। हम उम्मीद करें कि सरकार कृषि एवं ग्रामीण विकास के सामने विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला तत्परता से करेगी और इससे छोटे किसानों और ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों को अधिक खुशियां मिलते दिखाई देंगी।

*(लेखक के निजी विचार हैं)*

> 2024-25 के बजट में किसानों के कल्याण और कृषि को विकास का इंजन बनाने की रणनीति के तहत किसानों के हित में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की क्षमता के दोहन के जो अभूतपूर्व कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी जा सकेगी। निस्संदेह सरकार ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। कृषि और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है






लेबनॉन में हिज्बुल्लाह को निशाना बनाते हुए विस्फोट करके किए गए भीषण हमलों में मासूम लोग मारे जा रहे हैं, सैकड़ों घायल हो रहे हैं। इस्राइल और हिज्बुल्लाह, दोनों के तरफ के इस प्राणघाती उन्मादी टकराव को आखिर, रोकेगा कौन?

**राजदीप सरदेसाई, पत्रकार**
**@sardesairajdeep**

# घुल रहा आर्सेनिक का जहर



गंगा जल | सुरेश भाई

गंगाजल का महत्त्व है कि लंबे समय तक घर में रखने के बाद भी प्रदूषित नहीं होता लेकिन अब स्थिति बदल गई है क्योंकि गंगा के किनारे बसे गांवों में हैंडपंप, पाइपलाइन आदि से जो लाखों लोग पानी पी रहे हैं, उसमें आर्सेनिक की मात्रा काफी बढ़ चुकी है जिसके कारण वे त्वचा में घाव, किडनी, लीवर, दिल की बीमारियां, न्यूरो संबंधी विकार, तनाव और कैंसर से पीड़ित हैं।

गंगा के मैदानी इलाकों में पटना सहित बिहार के 20 जिले इस समय आर्सेनिक पानी पीने के दुष्प्रभाव से कैंसर का सामना कर रहे हैं। यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 10 प्रतिशत से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। महावीर कैंसर संस्थान एवं रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक जापान के साथ मिल कर इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए डॉ. अशोक कुमार घोष और डॉ. अरुण कुमार टोक्यो रवाना भी हो गए हैं। बिहार के बक्सर, सारन, समस्तीपुर, वैशाली, किशनगंज भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, पटना आदि स्थानों में गॉल ब्लैडर कैंसर रोगियों की गंभीर स्थिति है। इस बाबत शोध 14 मार्च, 2023 को नेचर जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ जिससे पता चलता है कि आर्सेनिक, प्रभावित आबादी के मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करके पित्ताशय थैली तक पहुंचता है। लंबे समय तक इलाज के अभाव में कैंसर का रूप ले लेता है जिसमें हर साल होने वाली मृत्यु दर में 33 प्रतिशत का इजाफा हो जाता है। 1980 के दशक में सबसे पहले पश्चिम बंगाल के भूजल में उच्च स्तर के आर्सेनिक पाए जाने की बात सामने आई थी। उस समय मानवाधिकार आयोग ने सरकार का ध्यान आकर्षित भी किया था लेकिन इसको कम करने के उपाय की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि कई गैर-सरकारी संगठन इस विषय पर बार-बार अपने शोध कार्यों की चर्चा करते रहे हैं, और इन संगठनों ने अनेक उदाहरण भी अपनी-अपनी रिपोर्टिंग में प्रस्तुत किए हैं।

'इनर वायस फाउंडेशन'(आईवीएफ) के अनुसार 2020 तक 10 लाख से अधिक लोगों की मौत आर्सेनिक वाला पानी पीने से हुई। आर्सेनिक औद्योगिक प्रदूषण, खनन से पैदा होता है। अकेले भारत में 5 करोड़ लोगों के इससे प्रभावित होने का अनुमान है। बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत के



कुछ भागों में भी लोग आर्सेनिक के जहर से प्रभावित हैं। देश में कुछ स्थानों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित मानकों से 300 गुना अधिक आर्सेनिक बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के अनेक जिले ऐसे हैं, जहां आर्सेनिक पानी पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और यहां लोगों को बचाने के प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्सेनिक न्यूरोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जब उनका सिस्टम आर्सेनिक जहर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो उनके आंतरिक अंग बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान बच्चों के वजन में कमी, नवजात की मृत्यु 6 गुना अधिक बढ़ने की आशंका रहती है।

मनुष्य ने अपने चारों ओर इतना प्रदूषण पैदा कर दिया है कि अंधाधुंध औद्योगिक अपशिष्टों के माध्यम से भूजल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। इस तरह के दूषित जल का प्रयोग भोजन बनाने में भी हो रहा है जिससे आर्सेनिक विषाक्तता बढ़ती जा रही है। अधिकांश फसलों की सिंचाई भी दूषित पानी से हो रही है। कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है जो भोजन के माध्यम से मनुष्य के शरीर तक पहुंच रहा है। चिकन, चावल, फलों के रस और कुछ मछलियों में भी आर्सेनिक की मात्रा काफी होती है जिसके अधिक से अधिक खाने में उपयोग होने से मानव जीवन खतरे में पड़ गया है। प्राकृतिक रूप से देखें तो मिट्टी और चट्टानों में आर्सेनिक पाया जाता है, जो भूजल में प्रवेश करता है। खनिज अयस्कों के विघटन से भी पानी में विषाक्त तत्व प्रवेश करते हैं। लेकिन विषाक्त तत्वों की मात्रा तभी बढ़ती है जब धरती के पेट में जहरीले रसायन प्रवेश करते हैं।

वैज्ञानिकों ने भोजन और भूजल के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के बीच संबंध पाया है, जिसका संबंध कीटनाशक पदार्थों के उपयोग से भी है। कह सकते हैं कि जीवन शैली में प्रदूषणकारी तत्वों का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसने आर्सेनिक की मात्रा को पानी में बहुत अधिक बढ़ा दिया है जबकि गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता और स्वच्छता के लिए वर्षों से किए जा रहे प्रयास धरती के पेट में पानी के साथ पहुंचने वाले जहरीले तत्वों को रोकने में असफल हैं। अरबों लीटर गंदा जल गंगा में हर रोज उड़ेला जा रहा है। जब तक इसको रोकने का कोई उपाय नहीं होता है, तब तक निर्धारित मानकों से अधिक आर्सेनिक जैसा जहरीला पदार्थ पानी में घुलता रहेगा जिससे कैंसर जैसी बीमारियों से बचना मुश्किल होगा।

देहभाव | डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी



मम्मी! मैं स्कूल नहीं जाना चाहता,' पांचवीं कक्षा में पढ़ते दिव्यांग बालक ने कहा। 'क्यों? तुम तो क्लास में सबसे होशियार हो,' मम्मी ने कहा। 'क्या आप लोग नहीं जानते कि मेरी नाक कितना बड़ी है? क्लास में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं।' बच्चा रोते हुए बोला। यह केवल एक बच्चे की बात नहीं है, शरीर की एक छोटी-सी विकृति बड़े से लेकर छोटे तक, सभी को परेशान करती है। हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं, जहां बाह्य शरीर का मूल्यांकन ही व्यक्तित्व का वास्तविक मूल्यांकन बन गया है। एक बच्चा जब समझदारी की पहली सांस लेता है, तो वह यही सब इस संसार से सीखता है। यही कारण है कि शरीर की छोटी सी खामी या विकृति उसे किसी सदमे से कम नहीं लगती। पूरा दिन इस कमी को सोच कर एक बालक या युवा अपनी सर्जनात्मक शक्ति को खोता जा रहा है। 'मैं कैसा दिखता हूं?' हमें हमेशा दूसरों की तुलना में अपने शरीर में खामियां नजर आती हैं। फिर इन कमियों को दूर करने के लिए लोग बड़े-बड़े विज्ञापनों की चमकती दुनिया का सहारा लेते हैं :'आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है...सिक्स पैक बॉडी नहीं है...', 'वजन बढ़ाएं..., तुरंत वजन कम करें...,अपना चेहरा चमकदार बनाए रखें...', 'ये पहनो... वो पहनो...', ऐसे साबुन और शैंपू, दवा और चूर्ण, क्रीम और कपड़े, जीन्स और जुएलरी के विज्ञापनों के जाल में फंस कर लोग अपनी असली पहचान छिपा कर अपने शरीर को सुंदर बनाने की होड़ में अपना जीवन व्यतीत ही नहीं बर्बाद भी कर देते हैं। देह के दोषों को दूर करने के प्रयास में लोग अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को इस देह की चिंता से मुक्त करने के लिए कहते हैं, 'यह देह नाशवंत है और आत्मा अविनाशी है। आत्मा मुख्य है, देह नहीं।' जी हां, आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। महंतस्वामी महाराज समझाते हैं कि आत्मा में अनंत शक्ति है किंतु देहभाव (केवल शरीर का विचार) के कारण व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश संपूर्ण विश्व का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश इस भौतिक शरीर का पोषण करता है।

## रीडर्स मेल

### खेल संस्कृति को बढ़ावा मिले

हमारे देश के हॉकी खिलाड़ियों ने चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार फिर से शानदार जीत हासिल की। जीत की यह पांचवी बार जीत थी। सरकारों को हाकी में देश को फिर से नम्बर एक बनाने के लिए भरपूर प्रयास करने चाहिए। इस खेल के खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएं देनी चाहिए। भारत ही वरन विश्व में हॉकी के जाने-माने खिलाड़ी ध्यानचंद, जिन्होंने हॉकी में अच्छा प्रदर्शन किया था और भारत को कई बार जीत दिलवाई थी, को आज तक भारत रत्न नहीं मिलना भी सरकारों के हाकी के प्रति उदासीन रवैये को दर्शाता है? देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्राइमरी स्कूलों से लेकर कॉलेज तक के विद्यार्थियों का खेलों में भाग लेना अनिवार्य करे और खेलों को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। अगर हमारे देश की राज्य और केंद्र सरकार, सभी खेलों के खिलाड़ियों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और देश के विभिन्न स्थानों से ऐसे खिलाड़ियों को चुनने का अभियान चलाएं, जो विभिन्न खेलों में रुचि रखते हैं और उनमें माहिर हैं, तो आने वाले ओलंपिक और अन्य विश्वस्तरीय खेलों में हमारे देश का और भी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है।

**राजेश कुमार चौहान, जालंधर**

### केजरीवाल का आतिशी दांव

केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने शेष बचे कार्यकाल के लिए आतिश को मुख्यमंत्री बनाकर एक ही तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया है जिनमें सबसे खास तो दिल्ली विधानसभा का आगामी चुनाव फिर से जीतना है। मगर इस बार यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि लोक सभा चुनाव में उनकी पार्टी का सफाया हो चुका है। दूसरा, जनता अच्छे-से केजरीवाल की महा-ईमानदार छवि को पहचान गई है, और अब ऐसी नौटंकीबाजी से कतई प्रभावित होने वाली नहीं है। हरियाणा चुनाव में भी सभी सीटों पर अकेले अपने उम्मीदवार खड़े करके आप 'हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे' वाला मुहावरा सार्थक करने जा रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद ही केजरीवाल के इस आतिशी दांव का नफा-नुकसान सामने आ जाएगा!

**सुभाष बुडावन वाला, रतलाम, मप्र**

### निंदा से बचें राहुल

व्यक्ति अपने हुनर और योग्यता से बहुत कुछ हासिल करता है। यह उसकी बौद्धिक संपत्ति है। कुछ व्यक्ति कमियां देखते हैं। उनकी बस कमियां निकालने की आदत होती है। ऐसे व्यक्ति किसी की बराबरी करने से रहे। जब-तब दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी भारत में बेरोजगारी का कारण चीनी सामान मानते हैं। अभी उनके आरक्षण वाले बयान पर जीभ काट कर लाने वाले को पुरस्कृत करने को कहा गया। क्या आप उनकी बातों को हल्के में लेते हैं। ऐसा व्यक्ति बस परनिंदा देखता है। उसकी बराबरी नहीं कर पाता। यहां की बेरोजगारी का कारण चीनी माल बेचने वाली, आरक्षण को नये सिरे से लागू करने वाली उनकी बातों में बेशक, कुछ दम है। उनकी लोकप्रियता में इससे बराबर वृद्धि हो रही है और कमियां देखने वाली प्रवृत्ति भी कायम हैं।

**दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली**

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 36
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 19 सितंबर 2024

# कश्मीर में नई शुरुआत

**जम्मू-कश्मीर** के सात जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुई पहले चरण की वोटिंग को आधार बनाया जाए तो ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं। शांति, सुव्यवस्था और लोगों की भागीदारी की दृष्टि से ये चुनाव उन तमाम नैरेटिव के लिए पूर्णविराम साबित हो सकते हैं जो बाहरी शक्तियां कश्मीर को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चलाती रहती हैं।


वोटरों की भागीदारी

**370 और राज्य का दर्जा |** जम्मू-कश्मीर में पिछले एक दशक में यह पहला विधानसभा चुनाव है। ये दस साल जम्मू-कश्मीर के लिए इस मायने में भी खास रहे कि इस दौरान न केवल संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसे हासिल विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया बल्कि वह राज्य से केंद्रशासित क्षेत्र में तब्दील हो गया। स्वाभाविक रूप से इन बड़े कदमों को लेकर वहां के लोगों की राय बंटी हुई है और कुछ हलकों में इसे लेकर गहरा असंतोष भी है।

**लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति |** ध्यान देने वाली बात यह है कि इस असंतोष ने भी लोगों को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इन चुनावों में अनुच्छेद 370 की वापसी और राज्य का दर्जा प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने आए हैं। रोजगार एक और बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। लेकिन लोगों की इन भावनाओं को देश के अन्य हिस्सों में मतदाताओं की आकांक्षाओं और उनके असंतोष से अलग नहीं कहा जा सकता।

**लंबी कतारें |** पिछले तीन-चार दशकों के अनुभव की रोशनी में देखें तो यह बड़ा महत्वपूर्ण फर्क है। चुनावों के बहिष्कार की अपीलों, धमकियों और चेतावनियों के बीच लोगों के ऐसे ही असंतोष अलगाववाद और उग्रवाद के समर्थन में इस्तेमाल कर लिए जाते थे। इस बार मतदाताओं की लंबी कतारों ने ऐसी गुंजाइश नहीं रहने दी। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के वोटिंग आंकड़ों का पीछे छूटना बेहद अहम है। लोकसभा चुनावों में 58.46 फीसदी वोटिंग हुई थी जो पिछले 35 साल का रेकॉर्ड था।

**कोई हिंसा नहीं |** ये चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे। इसका श्रेय सुरक्षा बलों और प्रशासनिक तंत्र को देना पड़ेगा। आतंकवाद के आकाओं ने तो अपनी तरफ से इन चुनावों को बाधित करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी थी। चुनाव की घोषणा होने के बाद न केवल सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ीं बल्कि आतंकी हमलों के भी काफी प्रयास हुए। मगर आतंकी तत्व आम लोगों की सोच को बदलने में कामयाब नहीं हो सके। यह चुनाव जम्मू-कश्मीर की आतंकवाद से मुक्ति का निर्णायक बिंदु साबित हो तो आश्चर्य नहीं।

## साड्डी दिल्ली

# आतिशी की रजनी मैडम

विवेक शुक्ला

**आतिशी को** दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनके सेंट स्टीफंस कॉलेज और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में बिताए समय की बातें होने लगी हैं। पर, उनके स्प्रिंगडेल्स स्कूल, पूसा रोड और वहां की संस्थापक प्रिंसिपल रजनी कुमार मैडम को नजरअंदाज किया जाना समझ से परे है। मूल रूप से ब्रिटिश नागरिक रजनी कुमार ने अपने स्कूल को धर्मनिरपेक्षता और विश्वबंधुत्व के आधार पर खड़ा किया था। राजधानी में न जाने कितने श्रेष्ठ स्कूल खुलते रहे हैं, पर रजनी कुमार के स्प्रिंगडेल्स स्कूल ने श्रेष्ठता की नई इबारत लिखी। रजनी कुमार और उनके पति युधिष्ठर कुमार वामपंथी विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने अपने स्कूल में मेहनतकश परिवारों के बच्चों को भी दाखिले दिए। आप समझ सकते हैं कि रजनी कुमार मैडम की छत्रछाया में रहते हुए आतिशी ने बेहतर समाज बनाने का सपना जरूर देखा होगा।

जोयस मारग्रेट जोनस सन 1948 में डॉ. युधिष्ठर कुमार से शादी करने के बाद हो गई थीं रजनी कुमार। उनकी शादी उस दिन हुई, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। मतलब 30 जनवरी 1948 को। दोनों लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में साथ-साथ पढ़ते थे। शादी के बाद दिल्ली आ गए। ईस्ट पटेल नगर में रहने लगे। कुछ वर्षों के बाद रजनी कुमार ने अपने पति और ससुर के सहयोग से ईस्ट पटेल नगर के अपने घर में स्कूल खोला। स्कूल का नाम रखा स्प्रिंगडेल्स स्कूल। रजनी कुमार ने करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, पूसा रोड, रामजस रोड वगैरह में घर-घर जाकर लोगों से कहा कि वे अपने बच्चे उनके स्कूल में भेजें। फिर उन्होंने पूसा रोड में स्प्रिंगडेल्स स्कूल खोला।

रजनी कुमार का दो साल पहले 99 साल की उम्र में निधन हो गया। वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक सक्रिय रहीं। वह लड़कियों की शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर रहा करती थीं। आसपास रहने वाले शरणार्थी परिवारों की बेटियों को अपने स्कूल में तुरंत दाखिला देती थीं। रजनी मैडम देश के विभाजन के बाद राजधानी में आए शरणार्थी परिवारों के दर्द से अपने को जोड़ती थीं। वह न जाने कितने शरणार्थी परिवारों की बेटियों की संरक्षक बन गई थीं। उन्होंने स्प्रिंगडेल्स स्कूल में 1971 में अफ्रीका क्लब की स्थापना की थी। वह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की अमानवीय नीति का जमकर विरोध करती थीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रफेसर डॉ. अनिरुद्ध देशपांडे बताते हैं कि जब उनके स्कूल में अफ्रीका क्लब से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। रजनी कुमार मैडम ने स्कूल में कुछ अफ्रीकी शिक्षक भी नियुक्त किए थे। जाहिर है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाते हुए आतिशी को अपनी रजनी मैडम की याद आती होगी।

## एकदा

# गांधीजी के हस्ताक्षर

**महात्मा गांधी** की जिंदगी का एक बड़ा पहलू उनका मजाकिया अंदाज भी था। कभी-कभी किसी सहज या गंभीर बात पर भी ऐसा मजाक कर डालते कि वहां का माहौल खुशनुमा हो जाता था। 1928 की एक घटना है। तब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पं. मोतीलाल नेहरू थे। वहां महात्मा गांधी को एक खादी भंडार का उद्घाटन करना था। उनके साथ आचार्य कृपलानी भी पधारे थे। यह खबर लोगों में फैल गई थी कि खादी भंडार के उद्घाटन पर खरीदारी करने वालों के बिलों पर गांधीजी हस्ताक्षर भी करेंगे। फिर क्या था, बड़ी संख्या में खरीदार उमड़ पड़े। महात्मा गांधी खरीदारों की भीड़ देखकर खुशी से खिल गए। लेकिन, सभी के बिलों पर हस्ताक्षर करना आसान नहीं था। उन्होंने मौके की नजाकत को भांपकर कहा, 'मैं आप सबका बड़ा आभारी हूं। जितनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हो रहे हैं, उतनी संख्या में बिल तैयार करने में बहुत समय लग जाएगा। समय बचाने के लिए एक रास्ता मेरी समझ में आ रहा है। आप लोगों को जितने-जितने रुपये की खरीदारी करनी है, मैं उतने रुपयों के बिलों पर लिखकर हस्ताक्षर किए देता हूं, खादी के सामान का विवरण बाद में आप भरते रहिएगा।' लोगों को यह बात पसंद आई और कुछ ही घंटों में महात्मा गांधी के हाथ में ढाई हजार रुपये आ गए। आचार्य कृपलानी ने गांधीजी को सुनाते हुए फबती कसी, 'लोगों ने अभी सामान लिया भी नहीं और बनिये ने जनता से ढाई हजार रुपये ऐंठ लिए।' बापू तपाक से बोले, 'प्रफेसर कृपलानी, यह बनिये के ही वश की बात है, किसी प्रफेसर की नहीं।' बापू के विनोद ने वातावरण को सहज बना दिया।


Subrata Dhar

संकलन : दीनदयाल मुरारका

## चाहे निर्भया कांड हो या कठुआ मामला, इसके बाद क़ानूनों में सज़ा के कठोर प्रावधान किए गए

# सिर्फ़ क़ानून कड़े करने से नहीं बनेगी बात


राजेश चौधरी

**हाल ही** में कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला सामने आने के बाद सड़क से लेकर सदन और अदालत से लेकर मीडिया तक में इस पर काफी बहस चल रही है। इस कांड के बाद रेपिस्ट को सख्त सजा की मांग दोबारा उठी और पश्चिम बंगाल सरकार ने रेप कानून को सख्त बनाने के लिए विधानसभा में बिल पेश किया, जिसे विपक्षी दलों की सम्मति से पास भी कर दिया गया।

**निर्भया से कठुआ कांड तक |** यह पहली बार नहीं है कि देश महिला के साथ रेप को लेकर उबल रहा हो। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुआ निर्भया कांड किसे याद नहीं होगा। उस वक्त भी रेप कानून में बदलाव के लिए लोगों ने आवाज उठाई थी। तब कानून में सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया। उसके बाद कठुआ रेप का मामला सामने आया था और उस समय भी रेप कानून में फिर बदलाव हुए। इस बार कोलकाता में दरिंदगी की गई तो फिर रेप लॉ में उम्रकैद और फांसी की सजा का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है।

**रेप पर कानूनी प्रावधान |** IPC की धारा-375 में बताया गया है कि अगर किसी महिला से कोई पुरुष जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो वह रेप होगा। महिला के साथ किया गया यौनाचार या दुराचार दोनों ही रेप के दायरे में होगा। इसके अलावा महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में अगर पुरुष अपना प्राइवेट पार्ट डालता है तो वह भी रेप के दायरे में माना जाएगा। महिला के प्राइवेट पार्ट में पुरुष कोई भी ऑब्जेक्ट डालता है तो वह रेप होगा। महिला की उम्र अगर 18 साल से कम है तो उसकी सहमति का भी कोई अर्थ नहीं होगा। उसके साथ सहमित से बनाए गए संबंध को भी रेप ही माना जाएगा। अब यही प्रावधान भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-63 में रखे गए हैं।

**कानून में निर्धारित सजा |** IPC की धारा-376 के तहत रेप के लिए कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया था। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा-64 में कहा गया है कि रेप मामले में कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा होगी। IPC की धारा-376 A के तहत प्रावधान किया गया कि अगर रेप के कारण महिला वेजिटेटिव स्टेज (मरने जैसी स्थिति) में चली जाए तो दोषी को अधिकतम फांसी की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा-66 में कहा गया है कि अगर महिला रेप के कारण वेजिटेटिव स्टेज में पहुंच जाए तो कम से कम 20 साल या ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद (मरते दम तक कैद) या फिर फांसी तक की सजा हो सकती है।



**गैंगरेप का मामला |** गैंगरेप के लिए 376 D के तहत कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रभर के लिए जेल (नैचरल लाइफ तक के लिए जेल) का प्रावधान किया गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा-70 के तहत इसे परिभाषित किया गया है। 376 E के तहत प्रावधान किया गया कि अगर कोई शख्स रेप के लिए पहले दोषी करार दिया गया हो और वह दोबारा रेप या गैंगरेप के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे उम्रकैद (नैचरल लाइफ) से लेकर फांसी तक की सजा दी जा सकती है। इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा-71 में परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा-65 (1) में प्रावधान है कि अगर किसी लड़की की उम्र 16 साल से कम है तो उसके साथ रेप के मामले में कम से कम 20 साल और अधिकतम उम्रकैद (नैचरल लाइफ) हो सकती है। साथ ही 65 (2) में प्रावधान किया गया है कि अगर लड़की की उम्र 12 साल से कम है तो रेप के दोषी को कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद (मरते दम तक कैद) या फिर फांसी की सजा हो सकती है। CRPC की धारा-309 में भी बदलाव किया गया था। इसके तहत प्रावधान किया गया कि रेप से संबंधित मामले का ट्रायल दो महीने में पूरा किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-346 में भी ऐसा ही प्रावधान है।

**लंबी कानूनी प्रक्रिया**
- अदालतों में लंबित हैं करीब 5 करोड़ केस
- ऊपरी अदालतों में अपील में जाता है वक्त
- कानून को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं

**अपराजिता बिल |** हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाए गए अपराजिता बिल में रेप के दोषी के लिए उम्रकैद से फांसी तक की सजा का प्रावधान है। अगर पीड़ित मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाए या उसकी मौत हो जाए तो अपराजिता कानून के तहत फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। गैंगरेप मामले में उम्रकैद (नैचरल लाइफ) या फिर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें गिरफ्तारी के 21 दिन के भीतर चार्जशीट दायर किए जाने और ट्रायल एक महीने में पूरा किए जाने का प्रावधान है।

**कानून का असर |** इन सख्त कानूनों का जैसा असर होना चाहिए, वह नहीं दिख रहा। जानकार बताते हैं कि सख्त कानून तो बन गया लेकिन उस बारे में लोगों के बीच जागरुकता नहीं है। जब तक लोगों को कानून के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, उनमें कानून का डर नहीं होगा। ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते भी आया। इस याचिका में गुहार है कि स्कूल लेवल पर एंटी रेप लॉ और POCSO के बारे में बताया जाए जिससे आम लोगों के बीच कानून के बारे में जागरूकता पैदा हो।

**अदालतों में लंबित मामले |** निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करीब पांच करोड़ केस पेंडिंग हैं। निचली अदालत में जजों की भारी कमी है। निर्भया केस में निचली अदालत और हाईकोर्ट से मामला जल्दी निपटाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में मामले की अपील के बाद लिस्ट होने में ही दो साल लग गए थे। ऐसे में सिर्फ सजा सख्त करने के बजाय कानून के प्रति जागरूकता फैलाने और जुडिशल इन्फ्रास्ट्रक्चर को पुख्ता करने की भी जरूरत है।

# हिमाचल में क्या कमज़ोर हुआ भाईचारा


दयाशंकर शुक्ल सागर

**शिमला में** मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद फौरी रूप से भले थम गया हो, लेकिन इसकी चिंगारी हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। तमाम इलाकों में लोग सड़क पर उतर कर मस्जिदों को हटाने और बाहर से आए लोगों का पंजीकरण कराने की मांग कर रहे हैं।

**बाहरियों का विवाद |** हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी देखें तो यहां मुस्लिम आबादी 3% से भी कम है। ज्यादातर मुसलमान बाहरी राज्यों से यहां काम की तलाश में आए और बस गए। इनमें भी बड़ी संख्या कश्मीरी मुसलमानों की है, जो दशकों से कंधे पर भारी सामान ढोने का काम करते हैं। इन्हें यहां 'खान' कहकर पुकारा जाता है। ये 'खान' हमेशा से शिमला के व्यापारी वर्ग की लाइफलाइन रहे हैं। ये स्वभाव से इतने सीधे और सरल हैं कि शायद ही कभी इनका किसी से कोई विवाद हुआ हो। विवाद का कारण पश्चिमी यूपी और बिहार से रोजगार के लिए आए मुस्लिम युवा बन रहे हैं, जो हिमाचल की संस्कृति से वाकिफ नहीं।

**बड़ी होती गईं मस्जिद |** 60 और 70 के दशक में मुसलमानों ने नमाज पढ़ने के लिए छोटी-छोटी कच्ची मस्जिदें बनाई थीं। ज्यादातर का निर्माण निजी जमीनों पर हुआ और इस पर कभी किसी ने एतराज नहीं किया। मुसलमानों को इबादत के लिए कुछ जमीनें दान में भी दी गईं। जैसे मंडी के राजा ने एक मुसलमान बुनकर से खुश होकर उसे जगह दी, जहां छोटी-सी मस्जिद बन गई। आगे चलकर बंदोबस्त रिकॉर्ड में यह भूमि मस्जिद के रूप में दर्ज हो गई। इसी तरह, 1960 में शिमला के संजौली में वक्फ बोर्ड की जमीन पर एक छोटी-सी मस्जिद बनी थी। शुरुआत में आसपास के चुनिंदा मुसलमान यहां आकर नमाज पढ़ते थे। कुल्लू की जामा मस्जिद भी कभी केवल एक मंजिला थी। बाद में इसे तोड़कर मस्जिद का नया भवन बनाया गया।

**अवैध निर्माण |** हाल के बरसों में बाहर से आए मुस्लिमों की संख्या बढ़ी। यूपी और बिहार से आए ज्यादातर मुसलमान पेशे से बढ़ई, नाई, दर्जी थे, जिनके काम की बहुत मांग है यहां। बाद में ये अपने रिश्तेदारों को भी ले आए, जो पटरी पर दुकानदारी करने लगे। फिर इन्होंने दुकानें खरीद लीं। आबादी बढ़ने के साथ पिछले 10 बरसों में मस्जिदों का आकार भी बढ़ने लगा। पुनर्निर्माण के नाम पर इनकी मंजिलें बढ़ने लगीं। संजौली की विवादित मस्जिद भी पांच मंजिल की हो गई। जाहिर है, इसके लिए किसी स्थानीय निकाय से इजाजत नहीं ली गई। ऐसा कमोबेश हिमाचल के सभी जिलों में हुआ। इसे किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया।



कॉमन रूम

**ऐसे बढ़ा विवाद |** शिमला में पिछले दिनों दो दुकानदारों के बीच हुए मामूली झगड़े ने सब कुछ बदल दिया। इनमें एक दुकानदार की कहानी इतनी-सी है कि वह 10 साल पहले शिमला आया था। देखते-देखते उसने तीन दुकानें खरीद लीं। उसने अपना कोई हिंदू नाम रखा था और एक हिंदू लड़की से शादी की थी। इस झगड़े में कुछ मुस्लिम लड़कों का एक स्थानीय व्यापारी से विवाद हुआ। ये लड़के बाद में करीब की संजौली मस्जिद में जा छुपे। सोशल मीडिया पर ताकाझांकी और छेड़छाड़ से जुड़े अनगिनत आरोप लगाए जाने लगे कि बाहर से आए लोग स्थानीय लोगों से किस कदर बेअदबी से पेश आते हैं।

**राजनीति का दखल |** यह मामला फिर भी दब जाता अगर सियासी रंग न चढ़ा होता। विपक्ष में बैठी BJP को बड़ा मुद्दा मिल गया। दिलचस्प यह हुआ कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के मंत्री-विधायकों ने भी इसका समर्थन किया और अपनी ही सरकार के प्रति हमलावर हो गए। हिमाचल प्रदेश में 97% आबादी हिंदुओं की है, इसलिए कोई भी सियासी दल बहुसंख्यक वर्ग को नाराज करने की स्थिति में नहीं। हिंदुत्ववादी ताकतों के उभार ने 'मुस्लिम तुष्टीकरण' के मिथक को तोड़ दिया है। विपक्षी दलों ने भी धीरे-धीरे खुद को मुसलमानों से जुड़े मुद्दों से दूर कर लिया है ताकि उन पर तुष्टीकरण का ठप्पा न लगे। कुल मिलाकर हुआ यह कि जिस छोटे मसले को बातचीत से सुलझाया जा सकता था, उसने इतना बड़ा रूप ले लिया। यह शुभ संकेत नहीं, खासकर उस राज्य में जहां सांप्रदायिक वैमनस्य का कोई इतिहास नहीं।

# भारी पड़े उस रानी के अग्निबाण

सुविज्ञा जैन

**बात 500** साल पहले की है। पुर्तगाल के व्यापारी हिंद महासागर के समुद्री रास्तों पर कब्जा कर चुके थे। इसके बाद वे कोशिश में थे भारत पर राज करने की। लेकिन, उन्होंने सोचा नही होगा कि उनका सामना हो जाएगा उल्लाल के सिहासन पर बैठी तुलुव रानी अब्बक्का से। महारानी लक्ष्मीबाई से भी कोई 300 साल पहले रानी अब्बक्का पुर्तगालियो से युद्ध कर रही थी। उन्होने दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर धनधान्य से भरपूर एक रियासत उल्लाल पर कई दशको तक राज किया। उल्लाल उस समय विजयनगर साम्राज्य की एक रियासत थी। इस क्षेत्र को कहते है तुलुनाडू।

AI Image



**विदेशियों की घुसपैठ |** 16वीं सदी में उल्लाल पर चौटा वंश का राज था। मातृवंशीय परंपरा के चलते सिंहासन पर अब्बक्का को बैठाया गया। उनके शासनकाल में समुद्र के रास्ते उल्लाल से मध्य पूर्व के देशों को मसाले, चावल और कपड़ों का निर्यात होता। उल्लाल में व्यापार की अपार संभावनाओं ने ही पुर्तगालियों को इस नगर की तरफ आकर्षित किया होगा। पुर्तगाली उस समय तक गोवा पर कब्जा कर चुके थे। दक्षिण भारत के कई क्षेत्र प्रभाव में थे उनके। ऐसे दौर में ही सन 1525 में पुर्तगाली बेड़ा उल्लाल पहुंचा। विदेशी वहां के उत्पादों के दाम अपनी मनमर्जी से तय करने लगे और व्यापारियों पर सस्ते दाम पर माल बेचने का बेजा दबाव बनाने लगे।

**पहला टकराव |** यह बात अब्बक्का को पता चली, तो उन्होंने व्यापारियों को पुर्तगालियों को सामान बेचने से मना कर दिया। विदेशियों के इरादे भांपते हुए अब्बक्का ने केलादी के राजकुमार वेंकटप्पा नायक की मदद से पुर्तगालियों को उल्लाल से बाहर खदेड़ भेजा। भारत में अपना दबदबा बढ़ा रहे पुर्तगालियों से उल्लाल के संघर्ष की यह शुरुआत थी। इसके बाद भी उन्होंने कई बार उल्लाल पर हमला बोला और हर बार अब्बक्का ढाल बनकर खड़ी रहीं।

**पड़ोसियों से एकता |** रानी अब्बक्का ने पुर्तगाली व्यापारियों की सेना को कई दशकों तक उल्लाल में घुसने नहीं दिया। एक रोमांचक तथ्य है कि भारत के ज्ञात इतिहास में वह ऐसी अंतिम योद्धा थीं, जिसे अग्निबाण चलाने में निपुणता हासिल थी। इन्हीं अग्निबाणों के हमले से पुर्तगाली तिलमिला गए थे। युद्ध में अब्बक्का का राजनयिक कौशल भी बहुत काम आया। उल्लाल ने अपने पड़ोसी रियासतों से बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखे थे। इस एकता की वजह से ही पुर्तगालियों के कब्जे के बावजूद अब्बक्का समुद्री रास्तों से अरब देशों को अपने उत्पाद निर्यात करती रहीं।

## टाइम मशीन

**मस्जिद में ली शरण |** सन 1555 में अब्बक्का ने एक बड़े समुद्री बेड़े के साथ आए एडमिरल डॉन अल्वारो डा सिल्वीयरा को मात दी। अब्बक्का की सेना में मोगावीरा समुदाय के सैनिकों की बहुलता थी। यह समुदाय समुद्री युद्ध कौशल में माहिर था। हालांकि एक मौका जरूर आया, जब पुर्तगाली हमले में अब्बक्का का महल उनके हाथ से चला गया था। सन 1568 में जनरल जोआओ पिक्सोटो के नेतृत्व में पुर्तगाली सैनिक अब्बक्का के महल के अंदर जा घुसे। रानी को एक मस्जिद में शरण लेनी पड़ी।

**अभय रानी |** अब्बक्का के पति ने उनसे विश्वासघात करते हुए पुर्तगालियों की मदद की थी। बहरहाल, अब्बक्का ने 200 जांबाज सिपाहियों को तैयार किया और रात के अंधेरे में पुर्तगालियों पर धावा बोल अपनी राजधानी वापस पा ली। इसी वीरता की वजह से प्रजा ने रानी अब्बक्का को अभय रानी का नाम दिया था।

# सहूलियतें मिलेंगी

प्रणव प्रियदर्शी

**देश में** वर्कफोर्स में महिलाओं की कम भागीदारी एक बड़ा मसला है, जिसकी तरफ सरकार का फोकस बढ़ा है। लेबर सेक्रेटरी की अगुआई में एक टास्क फोर्स इस मसले पर गंभीरता से काम कर रहा है। जल्द ही सरकार की ओर से कुछ ऐसे कदम सुझाए जा सकते हैं, जिनसे कामकाजी महिलाओं की दिक्कतें दूर होने की उम्मीद है। देखा गया है कि कामकाजी महिलाओं को घर-परिवार की जिम्मेदारियों के चलते काम छोड़ना तक पड़ जाता है। एक बार काम छूट जाए तो वापसी इस वजह से भी मुश्किल होती है कि काम के शेड्यूल को मैनेज करने में पारिवारिक जिम्मेदारियां आड़े आती हैं। इसलिए टास्क फोर्स कुछ ऐसे फ्लेक्सी अरेंजमेंट का फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, जिससे खासकर असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को फिक्स्ड शेड्यूल से कुछ राहत मिल जाए। उनके लिए रोज या सप्ताह में काम के कुछ घंटे इस तरह से निर्धारित किए जा सकते हैं, जिनसे उन्हें सहूलियत हो। उम्मीद की जा रही है कि ऐसे कदम पहले केयर इकॉनमी जैसे उन सेक्टरों में उठाए जा सकते हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी अन्य सेक्टरों के मुकाबले ज्यादा है। जानकारों के मुताबिक, ये कदम कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं होंगे, शुरू में इनका स्वरूप अडवाइजरी ही रखा जाएगा ताकि इन सेक्टरों में धीरे-धीरे और व्यावहारिक दिक्कतों से निपटते हुए इन्हें लागू किया जा सके। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत में वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का ग्लोबल एवरेज जहां 50% (पुरुषों का 80%) है, वहीं भारत में यह महज 37% । इस मुकाबले पुरुषों का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भारत में 77.2% है। नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि आबादी का 48% होने के बावजूद यहां महिलाओं का GDP में योगदान महज 18% है। अगर रोजगार में इस जेंडर गैप को दूर किया जा सके तो GDP में महिलाओं का योगदान 30% तक बढ़ सकता है।

AI Image



## आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

# बस लेनदेन नहीं, अहसान चुकाने का अवसर है दान

निर्मल जैन

**हममें से** कोई भी बिल्कुल अलग और अकेले नहीं रह सकता। जिस जीवन को हम देह, मन, भावनाएं और आसपास के परिवेश के रूप में जानते हैं उसमें परस्पर लेन-देन को नकार नहीं सकते। कोई भी इससे बच नहीं सकता। अगर कोई इससे बचता है, तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा अनुभव करने लगेंगे, मानो अपनी कब्र पर जी रहे हैं। कब किसको देना है और कब किससे लेना है, यह कोई बताने नहीं आएगा। हम सबको अच्छी तरह पता है कि जीवन के साथ क्या लेन-देन करना है।

जन्म से लेकर अंत तक हम अनगिनत लोगों से अलग-अलग रूपों में सहयोग प्राप्त करते हैं। कभी-कभी तो बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति से भी सहायता लेनी पड़ जाती है। ज्ञानार्जन से लेकर संपत्ति उपार्जन तक, हम सामाजिक संपर्क और समाज के सहयोग से ही कुछ प्राप्त कर पाते हैं। अपने मित्र, बंधु-बांधव से ही नहीं, हम पशुओं से नाना प्रकार की सेवाओं के साथ दूध, वनस्पतियों से साग-भाजी-फल, औषधियां लेते हैं। वायु से सांस न लें तो तो जीना असंभव, सागर और बादल हमें जल देकर हमारी प्यास बुझाते हैं, पृथ्वी से सहयोग कर अन्न उपजाते हैं। अग्नि भोजन पकाती है और सूर्य की ऊर्जा हमारे लिए नितांत आवश्यक है।

जब हम दूसरों की इतनी उदारता का उपभोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में उन सबके लिए भी कुछ करने का भाव पैदा होना मानवीय गुण है। इसे ही हमारी संस्कृति में दान कहा गया है। दान न उपकार है, न किसी पर एहसान है। जिसे हम दान कहकर बड़ा गर्वित अनुभव करते हैं, वह समाज से भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न रूप में ली गई सहायता का भुगतान भर है। अगर हम लेते ही रहें, वापस न दें तो यह एक प्रकार से हमारी कृतघ्नता होगी। दान ही एक ऐसा विकल्प है, जिससे समाज में अमीर की दौलत गरीब की आंखों में न खटके। जगत से आत्मीयता बढ़ाने और विश्वबंधुत्व स्थापित करने के लिए दान ही श्रेष्ठ सोपान है।

किसी की मदद करने की भावना से नहीं, बल्कि पुण्य प्राप्ति, वाहवाही, प्रतिष्ठा के लिए या देने के पीछे यह सोच हो कि यहां दे रहे हैं तो कहीं और इससे ज्यादा और बेहतर मिलेगा, सुख-शांति मिलेगी। यह सोच देने का सामर्थ्य ला देती है। किसी को कुछ दे देना दान नहीं है। यह दान के नाम पर एक सौदा है। प्रसन्नता और शांति भीतर की वस्तु है। किसी को कुछ देकर शांति पाने का यह सौदा अनुचित है। देने और लेने का यह विचार इंसान के जीवन में मानवता के विकल्प के तौर पर लाया गया है। मानवता से मतलब एक मानवीय गुण से है। दान भी एक मानवीय गुण है, कर्तव्य है, आत्म शुद्धि का प्रवेश द्वार है, उदारता का अंतर्नाद है।

उदारता यह नहीं है कि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है वह किसी को दे दें, बल्कि उदारता यह है कि जिस चीज की हमें भी जरूरत है उसके उपभोग की मात्रा में कमी करके किसी और ज्यादा जरूरतमंद को दे दें। दान मालिकाना हक की सोच मिटाने वाली वैसी ही गुप्त प्रक्रिया है जैसे प्रकृति बिना किसी विज्ञापन और किसी को बताए हमें इतना सब कुछ देती है। देना आत्म विकास का सुनहरा अवसर है। दान से हम कुछ खोते नहीं हैं, उल्टा पाते हैं, कर्तव्य पालन का आनंद।

# रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

### फिर भी है उम्मीद

**18 सितंबर** के संपादकीय 'अधिक नहीं है समय' में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी की चुनौतियों को उजागर किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चयन एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण निर्णय है। यह निर्णय आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की तरह है। पिछले दो वर्षों में AAP को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें कई प्रमुख नेताओं का जेल जाना शामिल है। ऐसे में, आतिशी के पास सीमित समय है। उम्मीद है कि वह इस समय का सदुपयोग करते हुए कुछ नई पहल कर सकेंगी, ताकि उनकी पार्टी आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी के साथ उतर सके। AAP के सामने चुनौती केवल BJP नहीं, बल्कि कांग्रेस की भी होगी, जो अपनी खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश में है।

**सुधांशु मिश्र,** ईमेल से

### 100 दिन पूरे हुए

**यह पत्र** 18 सितंबर के लेख 'विकसित भारत का पूरा होगा संकल्प' से संबंधित है। पीएम नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद उनकी तीसरी पारी के 100 दिन पूरे हुए हैं। विपक्षी दलों को मोदी सरकार के जल्दी गिर जाने का भ्रम था, पर उन्होंने बिना किसी दबाव के काम जारी रखा है। पीएम मोदी का हर एजेंडा पूरा होने की उम्मीद है। बेशक, BJP को कुछ समझौते करने पड़े, लेकिन वह सहयोगी दलों के दबाव में आए बिना देश के लिए हितकारी निर्णय लेते रहे हैं।

**सुभाष बुडावन वाला,** ईमेल से

### PM की पहल

**रूस की** सेना में धोखे से भर्ती किए गए भारतीयों को मुक्त कराने की मोदी सरकार की कोशिशों को अब एक बड़ी सफलता मिली है। सरकार के प्रयासों के चलते 45 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना ने मुक्त कर दिया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में रूसी यात्रा के दौरान इनकी रिहाई का मुद्दा उठाया था। अब भी 50 भारतीयों की मुक्ति के प्रयास जारी हैं, जिन्हें रूसी सेना में भर्ती किया गया था।

**एम.एम. राजावतराज,** ईमेल से

**nbtedit@timesofindia.com** पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

### अंतिम पत्र

**रूस में** पूतिन ने दी आबादी बढ़ाने की सलाह - एक खबर
- युद्ध बंद हो जाए तो शायद इस सलाह की जरूरत न रहे!

**सीमा अग्रवाल**

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 184

# निर्यात को मिले प्राथमिकता

भारत खुशकिस्मत है कि हमारे यहां उपभोक्ताओं का एक बड़ा आधार है जो कुछ हद तक अर्थव्यवस्था को वैश्विक मांग की लहरों से बचाता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वृद्धि और आर्थिक सुरक्षा को बिना निर्यात पर ध्यान दिए हासिल किया जा सकता है। दुर्भाग्य की बात है कि आंकड़ों से संकेत मिलता है कि फिलहाल देश में यह प्रक्रिया नहीं चल रही है। वास्तव में अगर कुछ हुआ है तो वह यह कि हालात विपरीत दिशा में चले गए हैं। निजी कारोबारी क्षेत्र में मोबाइल हैंडसेट निर्माण, जैसे कुछ क्षेत्रों की उल्लेखनीय सफलता के अलावा निर्यात के बजाय उसके उलट रुख देखने को मिला है। जैसा कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, वित्त वर्ष 2012-13 में जहां 18 फीसदी से अधिक विनिर्माण बिक्री का निर्यात हुआ था, वहीं 2022-23 में यह घटकर 7 फीसदी से कम हो गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकॉनमी के आंकड़ों के मुताबिक तो चालू वित्त वर्ष में इसमें और गिरावट आ सकती है।

विनिर्माण अर्थव्यवस्था में निर्यात पर कम ध्यान केंद्रित होने का प्रभाव भी स्पष्ट हैं। सेवा निर्यात जहां स्वस्थ बना हुआ है, वहीं भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है। अगस्त में यह 30 अरब डॉलर के साथ 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसकी कुछ वजहें अस्थायी हैं। बीते सालों में चीन की वृद्धि धीमी पड़ी है और आखिरकार वह विकास के उस दौर में पहुंच गया है जहां उसे बचत और निवेश आधारित वृद्धि से नए सिरे से संतुलन कायम करते हुए खपत बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। ऐसा करने से स्वाभाविक तौर पर जिंस जैसी चीजों की मांग कम होगी। इसका यह अर्थ भी है कि ऐसी अतिरिक्त क्षमता मौजूद है जो व्यापक वैश्विक मांग को पूरा कर सके। इस्पात क्षेत्र चीन में अधिक क्षमता के असर को उजागर करता है। भारत इस वर्ष इस्पात के शुद्ध निर्यातक के बजाय आयातक बन गया क्योंकि चीन में इस्पात की घटती मांग के कारण उसे बाहर इसकी खपत करनी है।

दूसरा मसला है आपूर्ति श्रृंखला में उथलपुथल। पश्चिम एशिया में अस्थिरता के कारण बीमा तथा अन्य क्षेत्रों की लागत बढ़ गई है। समुद्री रास्ते से मालढुलाई को लेकर अलग तरह के जोखिम हैं। कुछ निर्यातकों का कहना है कि चुनिंदा पोत ही भारतीय बंदरगाहों पर आ रहे हैं और बाहर जाने वाले पोतों में अधिक प्रतिस्पर्धा है। इन समस्याओं को हल करने की जरूरत है लेकिन इसके साथ ही निर्यात पर ढांचागत रूप से ध्यान देने को लेकर भी गहरे सवाल किए जाने की जरूरत है। भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बहुत मजबूत हैसियत नहीं रखता है और वैश्विक निकायों की 'चीन प्लस वन' की रणनीति को बहुत अधिक कामयाबी नहीं मिली है। भारत का आकार उसके लिए लाभदायक है लेकिन यह उसके लिए अभिशाप भी बन सकता है। आंतरिक मांग की भरपाई पर ध्यान केंद्रित करना किसी एक कंपनी को तो बाजार में बनाए रख सकता है लेकिन यह पूरी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। किसी भी देश ने आंतरिक मांग पर ध्यान केंद्रित करके कभी भी टिकाऊ वृद्धि हासिल नहीं की है।

आर्थिक विकास में कोई व्यक्ति अपने बूते पर खुद को आगे नहीं ले जा सकता है। वैश्विक मांग और निवेश हमेशा नई परियोजनाओं के लिए गुंजाइश बनाने, वृद्धि के लिए क्षमता निर्माण आदि में अहम भूमिका निभाते हैं।

व्यापक विनिर्माण के लिए यह खासतौर पर महत्त्वपूर्ण है। विश्व स्तर पर चीन का मुकाबला करने के लिए देश के नियामकीय और पर्यावरण माहौल में बदलाव लाना लंबे समय से टलता रहा है और इसकी वजह देश के घरेलू बाजारों का दबाव रहा है। नतीजा स्पष्ट है: विनिर्माण क्षेत्र तेजी से वैश्विक मांग के बजाय घरेलू क्षेत्र पर निर्भर होता जा रहा है और आने वाले दिनों में वह लाजिमी तौर पर दरों में संरक्षण की मांग करेगा। यह भारतीय उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं होगा। उपभोक्ता कल्याण, अहम आर्थिक मजबूती, स्थिर व्यापार घाटा और टिकाऊ वृद्धि के लिए भारत को नए बाजारों की ओर देखना होगा।

अजय मोहंती

# चीन की जनांकिकी गिरावट और हमारे लिए सबक

**चीन की स्थिति को देखकर पता चलता है कि हमारा अपना जनांकिकी लाभांश हमेशा बरकरार रहने वाला नहीं है। ऐसे में हालात का भरपूर फायदा उठाने की आवश्यकता है। बता रहे हैं आकाश प्रकाश**

ज्यादातर लोगों को पता है कि चीन जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा है। इसकी जड़ में एक संतान वाली नीति और बदलते सामाजिक सांस्कृतिक मानक हैं और देश के सामने बड़ी जनांकिकी चुनौतियां खड़ी हैं। परंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे चुनौतियां कितनी गंभीर हैं, दशक भर में उनका क्या असर होगा और हर संशोधन के बाद आंकड़े खराब क्यों होते जा रहे हैं?

कुछ कठोर तथ्यों के साथ शुरुआत करते हैं: चीन में आबादी की वृद्धि ऋणात्मक हो चुकी है। 2022 और 2023 में उसकी आबादी में कमी आई। 2019 में इस बात पर सहमति थी कि चीन 2031 में 1.45 की उच्चतम आबादी के स्तर पर पहुंचेगा। बहरहाल, वह 2021 में ही 1.4 अरब के साथ आबादी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, यानी एक दशक पहले। हालांकि कुछ टीकाकारों ने 1.4 अरब के इस आंकड़े पर भी संदेह जताया है। उनका कहना है कि वास्तविक आबादी आधिकारिक आंकड़ों से करीब 10 करोड़ कम है।

चीन की प्रजनन दर एक है जो अब अमेरिका (1.6) और जापान (1.2) से भी कम है। क्या आपने कभी सोचा था कि चीन की प्रजनन दर जापान से भी कम होगी? एक संतान नीति को 2016 में त्यागने के बावजूद चीन की प्रजनन दर लगातार कम होती रही। 2016 के बाद जन्म दर में अचानक नाटकीय गिरावट आई। इससे यह संकेत मिलता है कि मसला केवल एक संतान वाली नीति का नहीं था। चीन में कुछ ही महिलाएं शादी और बच्चे पैदा करना चाहती हैं और ज्यादातर करियर पर ध्यान देना चाहती हैं। शादी को लेकर बदलते सामाजिक मानकों के अलावा चीन में फिलहाल महिलाओं की तुलना में तीन करोड़ ज्यादा पुरुष हैं। इसकी वजह एक संतान वाली नीति और लैंगिक पूर्वग्रह है।

आज चीन की श्रम योग्य आबादी में करीब एक अरब लोग शामिल हैं। अब से आगे हर दशक इनमें करीब 10 करोड़ की कमी आएगी। उदाहरण से समझें तो ये 10 करोड़ की आबादी जर्मनी की कामगार आयु की आबादी की दोगुनी है। आगामी 20 साल में चीन में 20 करोड़ श्रमिक कम होंगे जबकि भारत में 17.5 करोड़ बढ़ेंगे। चीन में अगले एक दशक में 60 से अधिक आयु तथा 15-59 की आयु के लोगों की का अनुपात यानी निर्भरता अनुपात 30 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। 2001 में यह अनुपात केवल 15 फीसदी था। 2031-32 तक चीन की आबादी में 60 से अधिक उम्र के लोग, अमेरिका से अधिक होंगे। 2036 तक चीन में उम्रदराजों का निर्भरता अनुपात अमेरिका से अधिक होगा। बढ़ता निर्भरता अनुपात गिरती उत्पादकता और बढ़ती राजकोषीय चुनौतियों का प्रतीक होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक 2100 तक चीन की आबादी 46 फीसदी घटकर 77 करोड़ रह जाएगी। वहीं माध्य अनुमान के मुताबिक उस समय तक चीन की आबादी गिरकर मात्र 63 करोड़ रह जाएगी। यह भी तथ्य है कि यह आंकड़ा निरंतर गिर रहा है। उदाहरण के लिए 2010 में ऐसे ही अनुमान में कहा गया था कि 2100 तक चीन की श्रम योग्य आबादी वर्तमान अनुमान से 12.5 करोड़ अधिक होगी।

बिगड़ती जनांकिकी को आव्रजन संतुलित करता है। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देश ऐसा करके ही अपने जनांकिकी संबंधी गिरावट को धीमा करेंगे। चीन की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए वहां आव्रजन समस्या का हल नहीं हो सकता। सवाल यह है कि इन आंकड़ों का बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा भारत पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव होगा?

एक स्पष्ट नतीजा तो यही है कि चीन उच्च वृद्धि के पथ पर वापस नहीं जाएगा। अगर श्रम योग्य आबादी में गिरावट आएगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? यह ध्यान रखना होगा कि चीन में सरकार ने निजी क्षेत्र से काफी हद तक मुंह मोड़ रखा है और वह अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से में जबरदस्त हस्तक्षेप करती है। अगर निजी उद्यमी भयभीत हैं तो उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? उनकी गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना को देखते हुए उत्पादकता में तेजी लाना आसान नहीं है। अगर उत्पादकता में इजाफा नहीं हुआ तो चीन वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भों में 2-3 फीसदी से तेज विकास कैसे हासिल करेगा? क्या घटती आबादी वाला कोई देश तीन फीसदी की दर से वृद्धि हासिल कर सका है? दुनिया को घटती आबादी वाले देशों का अधिक अनुभव नहीं है, खासकर जब मामला चीन जैसे विशाल देश का हो। इसके अनचाहे परिणाम होंगे।

हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में नकदी बहुत अधिक है। हालांकि कर्ज अधिकतर घरेलू पूंजी में है। क्या धीमी वृद्धि, संभावित अपस्फीति और बुजुर्गों पर खर्च की सामाजिक लागत के साथ यह स्थिति बनी रह सकती है। नॉमिनल जीडीपी वृद्धि में कमी आने के साथ ही कर्ज चुकाने की क्षमता सवालों के घेरे में आ जाएगी। कर्ज के जाल में फंसने से बचने के लिए नॉमिनल जीडीपी वृद्धि का कर्ज की लागत से अधिक होना जरूरी है।

अगर वृद्धि घटकर 2-3 फीसदी रह जाती है तो चीन को विभिन्न क्षेत्रों की अधिशेष क्षमता का इस्तेमाल करना होगा और वह वैश्विक मुद्रास्फीति का एक कारक बनेगा। घरेलू स्तर पर अधिक बिक्री नहीं कर पाने के कारण चीन विदेशों में सामान भेजेगा और कीमतें कम करेगा। विभिन्न देशों को यह तय करना होगा कि कम लागत वाले आयात का लाभ उठाना है या अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए व्यापार गतिरोध का इस्तेमाल करना है। कई उत्पादों के मामले में चीन बढ़ती मांग के बीच मुख्य स्रोत नहीं रह जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत को और अधिक गंभीरता से लेना होगा क्योंकि यह बढ़ती मांग का मुख्य स्रोत होगा।

वैश्विक जिंस कीमतों पर पड़ने वाले असर के बारे में भी सोचना होगा। वैश्विक जिंस खपत में चीन का योगदान 50 फीसदी है। इसमें धीमापन आने पर भारत समेत कोई देश भरपाई नहीं कर पाएगा। ऐसे में जिंस कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। यह भारत जैसे जिंस आयातक के लिए फायदे का सौदा होगा। हमारा अधोसंरचना विकास जारी है और जिंस कीमतों में कमी हमारे लिए मददगार होगी।

हम सभी चीन प्लस वन के अवसर को लेकर उत्साहित हैं लेकिन तथ्य यह है कि उसकी श्रम योग्य आबादी में सालाना 10 करोड़ की गिरावट के साथ चीन को विनिर्माण रोजगार भी कम करने होंगे। श्रमिक या तो उपलब्ध नहीं होंगे या बहुत महंगे होंगे। यह भारत के लिए बेहतरीन अवसर होगा।

मौजूदा सरकार ने भारत को विनिर्माण के लिए आकर्षक बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। परंतु हमें कम कुशलता वाले विनिर्माण पर जोर देना होगा। अभी भी कपड़ा, खिलौने, फुटवियर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत चीन का स्वाभाविक विकल्प नहीं बन सका है।

अगर चीन आज अपनी क्षमताओं के शिखर पर है और उसकी जनांकिकी संबंधी चुनौतियां सामने हैं तो इसका भूराजनीति के लिए क्या अर्थ है? क्या आसन्न गिरावट को देखते हुए वह अपने दीर्घकालिक क्षेत्रीय हितों को तत्काल बढ़ावा देगा?

यह स्पष्ट है कि चीन के तेज विकास के दिन बीत गए। भारत अब उभरते बाजारों में नया अग्रणी देश है। परंतु हमें इतने से आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है। चीन का धीमापन हमारे लिए बड़ा अवसर है। हमें उसे दोनों हाथों से लपकना चाहिए और अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए। हमें इस जनांकिकीय बदलाव के परिणामों पर विचार करते हुए इसका पूरा फायदा उठाने की योजना बनाकर काम करना चाहिए। भारत फिलहाल इस मामले में बेहतरीन स्थिति में है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। जैसा कि चीन को देखकर पता चलता है, जनांकिकी का लाभ हमेशा नहीं रहेगा।

*(लेखक अमांसा कैपिटल से जुड़े हैं)*

# टिकाऊ कपास क्रांति के लिए उपाय जरूरी

**पिछले** दशक में कपास उत्पादन में लगातार गिरावट आने से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वर्ष 2002 में जीन संवर्द्धित और कीट प्रतिरोधी बीटी-कपास संकर किस्मों के साथ शुरू हुई कपास क्रांति के दिन अब लदने लगे हैं। हालांकि इसके लिए कई कारकों विशेष तौर पर नए कीटों और रोगों के उभार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मुख्य कारण अनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों के संबंध में सरकार की अविवेक भरी नीति है, जिसकी वजह से पुराने बीजों की जगह लेने वाले नए और उन्नत बीजों की नियमित आवक में बाधाएं बनी हैं।

शुरुआत में आए अधिकतर जीएम हाइब्रिड कपास में कीट-मारक जीन होता है, जो मिट्टी में रहने वाले बेक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस (बीटी) से निकला होता है। लेकिन अब ये किस्में लगातार रूप बदलते कीटों और रोगाणुओं के खतरों तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता खो चुकी हैं। ऐसे में अब उनके प्रभावी और बेहतर विकल्प तलाशने का वक्त आ गया है।

बहुराष्ट्रीय बायोसाइंसेज कंपनी मॉन्सैंटो ने बीटी-कपास हाइब्रिड के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी लेकिन व्यावसायिक कार्यों के प्रति सरकार के दुर्भावनापूर्ण नजरिये के कारण कंपनी बहुत पहले ही भारत से बाहर चली गई। उसके बाद से ही मॉन्सैंटो अस्तित्व में नहीं है क्योंकि वर्ष 2018 में बेयर ने इसे खरीद लिया। निजी क्षेत्र में बीज तैयार करने वाली अधिकांश कंपनियां भी ज्यादा लागत वाली इस जीन संवर्द्धित तकनीक में निवेश करने से हिचकिचा रही हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके उत्पादों को व्यवसायीकरण के लिए मंजूरी मिलने में हमेशा अनिश्चितता रहेगी।

हालांकि जीन में बदलाव वाली कपास की कुछ किस्मों ने खरपतवारों और कीटों दोनों को नियंत्रित करने का खर्च कम करने में मदद की है। इनमें खरपतवार नष्ट करने वाली बीटी कपास हाइब्रिड शामिल हैं और ये हाल में उपलब्ध हुई हैं। सरकार ने इसके लिए औपचारिक मंजूरी नहीं दी है, जिसके कारण अवैध माध्यमों से बड़े पैमाने पर ये उपबल्ध हो रही हैं। इस तरह भारत उन्नत जीएम कपास बीजों के इस्तेमाल के लिहाज से अन्य देशों की तुलना में पांच से छह पीढ़ी पीछे है।

खेती बाड़ी
सुरिंदर सूद

इसलि हैरत नहीं होनी चाहिए कि 2001 में भारत में जिस कपास की औसत पैदावार 278 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और 2013-14 में बढ़कर 566 किलो हो गई थी, उसकी पैदावार हाल में घटकर 440-445 किलो ही रह गई है। यह 800 किलो प्रति हेक्टेयर की वैश्विक औसत उत्पादकता से काफी कम है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चीन जैसे देशों के किसान आम तौर पर 1,800 से 2,000 किलोग्राम तक की पैदावार कर लेते हैं। औसत उत्पादकता से लिहाज से भारत कपास उगाने वाले 30 अन्य देशों से नीचे है।

हालांकि भारत का वार्षिक कपास उत्पादन चीन के बराबर है जो कपास उत्पादन में मान्यता प्राप्त प्रमुख देश है लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फसल की बोआई यहां बहुत बड़े क्षेत्रों में होती है। वास्तव में भारत में कपास का रकबा लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है और चीन के लगभग चार गुना है। लेकिन प्रति हेक्टेयर औसत उपज चीन की तुलना में एक-चौथाई से भी कम है।

भारत इकलौता देश है, जहां कपास की सभी चार किस्में गॉसिपियम अर्बोरियम, जी हर्बेसियम (दोनों को एशियाई कपास या देसी कपास माना जाता है), जी बारबेडेंस (मिस्र कपास) और जी हिरसुटम (अमेरिकी कपास) उगाता है। लेकिन भारत में ज्यादातर कपास यानी करीब 90 फीसदी अमेरिकी किस्म की कपास है। देसी कपास की नरमी और अवशोषण गुण के कारण इसे सर्जरी आदि से जुड़ी प्रक्रिया के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा देसी कपास स्थानीय कृषि व्यवस्था के लिए बेहतर अनुकूल है और कीटों, रोगों तथा मौसम की अनियमितताओं के लिहाज से भी मजबूत है, जिसकी खेती सदियों से होती आ रही है।

कपास उत्पादन को बरकरार रखना कपड़ा क्षेत्र की आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत जरूरी है। कपड़ा उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत और निर्यात में 11 प्रतिशत का योगदान देता है। करीब 60 लाख कपास किसानों के अलावा कई लाख लोग प्राकृतिक धागे और इससे जुड़े उत्पादों जैसे धागा, कपड़ा, परिधान और अन्य तरह के कपड़ों के उत्पादन, प्रसंस्करण और कारोबार में जुड़े हुए हैं। कपड़ा उद्योग से करीब 4.5 करोड़ लोगों की आजीविका चलती है। भारत का कपड़ा बाजार करीब 240 अरब डॉलर का है और 6.8 प्रतिशत सालाना चक्रवृद्धि दर से यह वर्ष 2033 तक 475 अरब डॉलर का आंकड़ा छू सकता है। अच्छे बीजों का इस्तेमाल कर इस वृद्धि को और तेज किया जा सकता है।

कपास वास्तव में एक बहु-उपयोगी फसल है, जो प्रमुख रेशे के अलावा भोजन और चारा भी मुहैया करा सकती है। कपास का उपयोग धागे और विभिन्न प्रकार के कपड़े के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा और घरेलू क्षेत्रों में विभिन्न प्रयोगों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके बीज खाद्य तेल तैयार करने और पशुओं तथा मुर्गियों के लिए पौष्टिक चारा तैयार करने के काम भी आते हैं। कपास की खेती के लिए नए आधुनिक तरीके और बीजों का इस्तेमाल करना ही कपास क्रांति फिर से लाने के तत्काल उपाय हैं।

नई अधिक उपज वाली और कीट-प्रतिरोधी कपास किस्मों के विकास की सुविधा के लिए जीएम बीज नीति की समीक्षा के साथ-साथ फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बेहतर कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। इससे न केवल देश में कपास की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि किसानों की आय में वृद्धि होगी, निर्यात संभावनाओं में सुधार होगा और कपास-आधारित उद्योग को लाभ होगा।

https://www.BusinessStandard

## आपका पक्ष

### आरोपियों के घर ध्वस्त करना गलत

किसी मामले में आरोपी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त करना कानूनन और संवैधानिक रूप से गलत है। एक व्यक्ति घर बनाने में अपनी जीवन की जमा पूंजी लगा देता है। अगर किसी आरोप में वह गिरफ्तार होता है और राज्य सरकार द्वारा उनकी संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाता है तो यह कहीं से भी उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में 'बुलडोजर न्याय' देखने को मिला है। आरोपियों के घर व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा है। उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसे मामले में कड़ी टिप्पणी की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति समेत अन्य संपत्तियों को ध्वस्त करना संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मामलों में ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। हालांकि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध

पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामले के आरोपियों के घर ध्वस्त करने पर रोक लगाई है

निर्माण पर रोक लागू नहीं होगी। आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त करने का मकसद उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करना हो सकता है। लेकिन ऐसा करना गैरकानूनी है। घर गिराए जाने के बाद अगर आरोपी का परिवार है तो वह कहां जाएगा। आरोपी के परिवार का क्या दोष कि उनके घर को तोड़ कर बेघर कर दिया जाए। अतः ऐसे गैरकानूनी कृत्यों पर रोक जरूरी है।

*मोहित कुमार, नई दिल्ली*

### खाद्य पदार्थों के दाम स्थिर रहे

देश निरंतर तरक्की के पथ पर अग्रसर है। देश में तकनीक, बुनियादी ढांचा का विकास हो रहा है। लेकिन बारिश के दिनों में खाद्य पदार्थों के दाम में इजाफा होना सभी तकनीक को मात देने जैसा लगता है। बारिश के कारण सब्जियों के दाम बढ़ना आम बात हो गई है। इसकी वजह परिवहन में देरी या फिर उत्पादन में कमी या फिर कालाबाजारी भी हो सकती है। लेकिन देश में तकनीक के बढ़ते चलन से इस पर काबू पाया जा सकता है। कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार तकनीक का उचित इस्तेमाल कर सकती है। किसी मंडी में कितना माल आया इसका हिसाब लगाने से ही कालाबाजारी पकड़ में आ सकता है। मगर अधिकारियों की उदासीनता के कारण आम लोगों को ज्यादा कीमत देकर खाद्य पदार्थ खरीदने पड़ते हैं। खाद्य पदार्थ के दाम हर दिन स्थिर रहे इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

*केडी दुबे, नोएडा*

### छोटी फर्मों के लिए अनुपालन सरल बनाने की दरकार

बिजली, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए एक रोडमैप की आवश्यकता है। छोटी फर्मों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के साथ-साथ सभी व्यवसायों के लिए प्रणाली को सरल बनाने की गुंजाइश है। जिसमें बड़े व्यवसाय भी शामिल हैं, जिन्हें प्रत्येक राज्य में पंजीकरण करने के लिए बाध्य किया जाता है और अलग-अलग अनुपालन आदेशों का सामना करना पड़ता है। इन सभी पर एक बार में चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए जीएसटी परिषद की ज्यादा बैठक होनी चाहिए।

*धीरेंदु सोमानी, बेंगलूरु*

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

## देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

एक भारतीय सैनिक के हाथ पर बैठे बाज के सिर पर कैमरा लगा हुआ है। राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत तथा अमेरिकी थल सेना के जवानों ने बुधवार को 20वां संयुक्त युद्ध अभ्यास किया।

संपादकीय

# सड़ता अनाज जिम्मेदारी तय हो

एक तरफ गरीबों को अन्न के लाले हैं तो दूसरी तरफ सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज रखा-रखा सड़ रहा है। यह स्थिति मप्र के सरकारी अनाज गोदामों की है। जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक राज्य के गोदामों में रखा 58 हजार टन (5.76 लाख क्विंटल) गेहूं, ज्वार और बाजरा फिर बर्बाद हो गया। इसका बाजार मूल्य करीब पौने 2 सौ करोड़ रू. होता है। यह अनाज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रमुख जिलों में रखा था, जो अब इंसानों के खाने लायक नहीं बचा। अब यह जानवरों, मुर्गे (पोल्ट्री के उपयोग) को खिलाया जाएगा। कुछ अनाज तो सिर्फ औद्योगिक इस्तेमाल में ही आने की स्थिति में पहुंच चुका है। यह स्थिति तब है जब मप्र कुपोषण के मामले में देश पर कलंक की तरह है। अधिकृत पोषण ट्रैकर के जून 2024 के आंकड़ों के मुताबिक मप्र में 27 प्रतिशत बच्चे कम वजन के मिले हैं। यह देश में सर्वाधिक है। फिर भी मप्र में गोदामों में रखा अनाज सड़ रहा है और किसी के माथे पर कोई शिकन नहीं है। यह मामला भी इसलिए उजागर हुआ, क्योंकि हाल में खाद्य विभाग ने प्रदेश का खराब अनाज बेचने के लिए टेंडर जारी किया है। ये वो अनाज है जो किसानों पर समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। इसके अलावा गेहूं के परिवहन व भंडारण का खर्च अलग है। इस हिसाब से सरकार को यह गेहूं 30 रू. प्रति किलो पड़ा। उसी गेहूं को अब मात्र 2 से 16 रू. किलो के भाव से बेचा जाएगा। प्रदेश में अनाज भंडारण को लेकर लापरवाही का आलम यह है कि घटिया क्वालिटी का होने से प्रदेश का 16 लाख टन गेहूं रखने से एफसीआई ने भी इंकार कर दिया है। ये खराब गेहूं वर्ष कि 2020-21 से लेकर 2023-24 के बीच खरीदा गया है। पिछले साल चार मई को 6628.93 टन खराब अनाज बेचा गया। इसी तरह 3 अगस्त 2023 को जारी टेंडर से भी 10 हजार 986 टन अनाज बेचा गया। चिंता की बात यह है कि सरकारी अनाज की सर्वाधिक बर्बादी वाले जिलों में प्रदेश की राजधानी भोपाल भी शामिल है। यहां सर्वाधिक 9 लाख 84 हजार टन अनाज की बर्बादी राजधानी भोपाल के साथ पूरे संभाग में हुई है। दूसरे नंबर पर जबलपुर है, जहां 3.74 लाख टन और उज्जैन में 1.21 लाख टन अनाज खराब हुआ है। इंदौर में 19,913 टन, सतना में 92,276 टन, सागर में 11 हजार 547 टन और ग्वालियर में 30 हजार 764 टन अनाज खराब हुआ है। भोपाल संभाग के ही बुधनी, आष्टा, रेहटी, नसरुल्लागंज, दिवटिया के कुछ गोदामों में रखा अनाज जानवरों के खाने लायक बचा है। चावल भी खराब होने की खबर है। भोपाल में लापरवाही का आलम कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां तो पूरी सरकार बैठी है। उसके बाद भी अनाज गोदामों में सड़ रहा है, लेकिन कहीं कोई चिंता नहीं है। इस लापरवाही के लिए किसी अफसर को जिम्मेदार नहीं माना गया। पिछले दो साल में कार्रवाई के नाम पर करीब 25 गोदाम सहायक सस्पेंड हुए। एक-दो क्वालिटी कंट्रोलरों से जवाब-तलब हुआ, लेकिन जिम्मेदार अफसरों पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है कि जो हो रहा है, वह अफसरों, व्यापारियों की मिली भगत का नतीजा है। वैसे भी सड़ा गेहूं शराब लॉबी बेहद सस्ते में खरीद लेती है, क्योंकि शराब बनाने के लिए अनाज को सड़ाना ही पड़ता है। सरकारी गोदाम यह काम लगभग मुफ्त में कर देते हैं। लेकिन अनाज सड़ने के पीछे पैसा तो जनता का ही बर्बाद हुआ है। इतने बड़े पैमाने अनाज खराब होने के लिए शीर्ष स्तर पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय हानि है।

# नादानी के बांध, बैराज और तटबंध

**सन् 1975 में बनकर तैयार हुए फरक्का-बैराज का मकसद था कि इसके जरिए 40 हजार क्यूसेक पानी का रुख बदला जाये, ताकि कोलकाता बंदरगाह बाढ़ से बच सके, लेकिन ये मंसूबे बांधते समय नदी में आने वाली तलछट का अनुमान नहीं लगाया गया। परिणामस्वरूप, जरूरत के मुताबिक पानी का रुख नहीं बदला जा सका। आज बैराज का जलाशय तलछट से ऊपर तक भरा है। पीछे से आने वाली विशाल जलराशि पलटकर साल में कई-कई बार विनाश लाती है। ऊंची भूमि भी डूब का शिकार होने को विवश है। हजारों वर्ग किलोमीटर की फसलें इससे नष्ट हो जाती हैं। फरक्का-बैराज बनने के बाद धारा के विपरीत ऊपर की ओर आने वाली ढाई हजार रुपये प्रति किलो मूल्य वाली कीमती 'हिल्सा मछली' की बड़ी मात्रा हम हर साल खो रहे हैं।**

**कुमार कृष्णन**

गंगा मुक्ति आंदोलन' के प्रमुख अनिल प्रकाश ने बिहार की नदियों पर बैराजों के निर्माण पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि – 'बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नदियों पर बैराज बनाने की हड़बडी से पहले गंगा पर बने फरक्का-बैराज से उपजी विनाशकारी बाढ़, कटाव, जल-जमाव, भूमि के ऊसर होने, मछलियों के अकाल आदि भीषण स्थितियों का वैज्ञानिक आकलन अवश्य करा लेना चाहिए।' बैराज एक प्रकार का लो-हैड, डायवर्सन बांध है जिसमें कई बड़े गेट होते हैं जिन्हें पानी की मात्रा और दिशा को नियंत्रित करने के लिए खोला या बंद किया जा सकता है। सन् 1975 में बनकर तैयार हुए फरक्का-बैराज का मकसद था कि इसके जरिए 40 हजार क्यूसेक पानी का रुख बदला जाये, ताकि कोलकोता बंदरगाह बाढ़ से बच सके, लेकिन ये मंसूबे बांधते समय नदी में आने वाली तलछट का अनुमान नहीं लगाया गया। परिणामस्वरूप, जरूरत के मुताबिक पानी का रुख नहीं बदला जा सका। आज बैराज का जलाशय तलछट से ऊपर तक भरा है। पीछेसे आने वाली विशाल जलराशि पलटकर साल में कई-कई बार विनाश लाती है। ऊंची भूमि भी डूब का शिकार होने को विवश है। हजारों वर्ग किलोमीटर की फसलें इससे नष्ट हो जाती हैं। फरक्का-बैराज बनने के बाद धारा के विपरीत ऊपर की ओर आने वाली ढाई हजार रुपये प्रति किलो मूल्य वाली कीमती 'हिल्सा मछली' की बडी मात्रा हम हर साल खो रहे हैं।

ऐसे में बिहार को बैराज की क्या जरूरत है? बिहार के 'जल संसाधन विभाग' के मंत्री विजय चौधरी के अनुसार नेपाल में बांध बनाने का प्रस्ताव कई सालों से है, लेकिन फिलहाल इसकी उम्मीद नहीं दिख रही। नतीजे में बिहार सरकार को नेपाल से आने वाली चार नदियों पर चार बैराज बनाने का फैसला लेना पडा। ये बैराज कोसी नदी पर डगमारा में, गंडक नदी पर अरेराज में, महानंदा नदी पर मसान में और बागमती नदी पर डिंग में बनाए जाएंगे। इनकी 'डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट' (डीपीआर) तैयार की जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में, प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से संबंधित आपदाओं से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। इस राशि से नेपाल से आने वाली बाढ़ के नुकसान को रोकने के लिए बैराज बनाए जाएंगे। इसके लिए विश्वबैंक से 4400 करोड़ रुपये की सहायता भी ली जा रही है।

दूसरी तरफ, बैराज बनाने के बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ व्यापक आंदोलन की तैयारी आरंभ हो गयी है। आंदोलन के प्रथम चरण में बिहार, बंगाल और उत्तरप्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके उपरांत साथी संगठनों की बैठक कर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। इसके पहले नेपाल सरकार से भारत सरकार की ऊंचा बांध बनाने को लेकर बातचीत हुई थी। वर्ष 2004 में विराटनगर में संयुक्त कार्यालय भी खोले गए थे, लेकिन जहां भी सर्वे करने जाते, लोग बांध के विरोध में हंगामा करने लगते। यही कारण है कि नेपाल में बांध बनाना मुश्किल हो गया।

जानकार मानते हैं कि बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करने वाली तटबंध आधारित नीति ने बाढ़ के संकट को बढ़ाने का काम किया है। उत्तर बिहार की नदियों के जानकार दिनेश कुमार मिश्र के अनुसार आजादी के वक्त जब राज्य में तटबंधों की कुल लंबाई 160 किलोमीटर थी तब राज्य का सिर्फ 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ पीड़ित था। अब, जब तटबंधों की लंबाई 3760 किलोमीटर हो गयी है तो राज्य की लगभग तीन चौथाई जमीन, यानी 72.95 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है। यानी जैसे-जैसे तटबंध बढ़े बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल भी बढ़ता चला गया।

सरकार का भी रवैया विचित्र है। एक ओर तो बिहार की बाढ़ के लिए फरक्का-बैराज को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो दूसरी तरफ नए की वकालत भी करते हैं। अनिल प्रकाश के अनुसार फरक्का-बैराज के अनुभवों से ही समझ लेना चाहिए था कि नदियों को रोककर बाढ़ का मुकाबला नहीं किया जा सकता। 'वैसे तो नदियों पर बांध मुख्यतः बिजली बनाने के लिए बनाये जाते हैं, बाढ़ रोकने के लिए नहीं। इसके बावजूद बांध बनाना एक पुराना तरीका साबित हो रहा है। आजकल कई वजहों से दुनिया भर में बांधों को तोड़ा जा रहा है। अमेरिका की मिसिसिपी नदी पर बने बांधों को वहां की सरकार ही तोड़ रही है। चीन में ह्वांगहो नदी पर बने तटबंध को बम से उड़ा दिया गया।'

वर्ष 1870-75 से पहले बिहार में बाढ़ का जिक्र नहीं मिलता। जबसे यहां रेलवे की शुरुआत हुई और नदियों के स्वतंत्र बहाव में बाधा उत्पन्न होने लगी, बाढ़ की समस्या सामने आने लगी। इसके बावजूद उत्तर बिहार में नदियों का अपना बेहतरीन तंत्र विकसित था। बड़ी नदियां, छोटी नदियों और 'चौरों' से जुड़ी थीं और पूरे इलाके में 'पोखरों' का जाल बिछा था। बारिश के दिनों में बड़ी नदियों में जब अधिक पानी होता था तो वे अपना अतिरिक्त पानी छोटी नदियों, 'चौरों' और तालाबों में बांट देती थीं। इससे बाढ़ की समस्या नहीं होती थी। फिर जब गर्मियों में बड़ी नदियों में पानी घटने लगता, तो छोटी नदियां और 'चौरे' इन्हें अपना पानी वापस कर देतीं। इससे ये नदियां सदानीरा बनी रहती थीं।

बिहार की 76 प्रतिशत आबादी और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। वहीं आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश के कुल बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का 16.5 प्रतिशत बिहार में पड़ता है और कुल बाढ़ पीड़ित आबादी का 22.1 प्रतिशत इसी राज्य के लोग हैं। 'एएन सिन्हा इंस्टीच्यूट' के विशेषज्ञ डॉ. विद्यार्थी का कहना है कि बिहार में तटबंधों का निर्माण पिछले 50 सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है और बाढ़ का इलाका भी उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। पहले 25 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित इलाका था, लेकिन आज 70 लाख हेक्टेयर से अधिक इलाका बाढ़ प्रभावित है।

साठ और 70 के दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बांधों का निर्माण हुआ, लेकिन हाल के वर्षों में बांधों के निर्माण की वैश्विक स्तर पर आलोचना हो रही है। बांधों से होने वाले फायदों के लिए भारी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में नदियों की अविरल धारा के लिए मुहीम चल रही है। साल 2016 से ही बांध तोड़े जा रहे हैं। अकेले 2022 में यूरोपीय नदियों पर बने 325 बांध तोड़ दिए गए, जो 2021 से 36 प्रतिशत ज्यादा थे। खास बात यह है कि जिन नदियों पर बांध तोड़े गए वहां का जलीय जीवन बदलने लगा। मछलियों का लौटना इस बात की निशानी है कि नदी का इकोसिस्टम खुद को ठीक कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, भारत में बड़े बांधों, बैराजों द्वारा उपजाऊ धरती, जंगल सहित जैव-विविधता से भरी प्रकृति और नदी से जुड़ी संस्कृति स्वाहा कर विकास का यज्ञ चलाया जा रहा है।

(सप्रेस)

अध्यात्म

# सूरदास जी की गुरु भक्ति

आखिर सूर के जीवन की शाम ढल आई। सूर गोवर्धन से नीचे उतरकर घाटी मे आ गए और आखिरी साँसे लेने लगे। उधर श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र गोस्वामी विटठलनाथ जी ने अपने सभी गुरू-भाइयो और शिष्यो के बीच डुगडुगी बजवा दीः भगवद मार्ग का जहाज अब जाना चाहता है। जिसने आखिरी बार दर्शन करना है, कर लो। समाचार मिलते ही जनसमूह सूर की कुटिया तक उमड़ पडा। जिसने अपने कंठ की वीणा को झनका-झनका कर प्रभु-मिलन के गीत सुनाए, आज उसी से बिछुडने की बेला थी। भक्त-हर्दय भावुक हो उठे थे। बहुत संभालने पर भी सैकडो आंखो से रुलाइयाँ फूट रही थी। इसी बीच गुरूभाई चतुर्भुजदास जी ने सूर से एक प्रश्न कियाः देव, एक जिज्ञासा है। शमन करे।

सूरदास जीः कहो भाई। चतुर्भुजदास जीः देव, आप जीवन भर कृष्ण-माधुरी छलकाते रहे। कृष्ण प्रेम मे पद रचे, कृष्ण-धुन मे ही मंजीरे खनकाए। कृष्ण-कृष्ण करते-करते आप कृष्णमय हो गए। परन्तु... सूरदास जीः परन्तु क्या, चतुर्भुज..? चतुर्भुजदास जीः ..परन्तु आपने अपने और हम सबके गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी के विषय मे तो कुछ कहा ही नही। गुरू-महिमा मे तो पद ही नही रचे। यह सुनकर सूर सरसीली सी आवाज मे बोलेः अलग पद तो मै तब रचता, जब मै गुरुवर और कृष्ण मे कोई भेद मानता। मेरी दृष्टि मे तो स्वयं कृष्ण ही मुझे कृष्ण से मिलाने ÷वल्लभ÷ बनकर आए थे। ऐसा कहते ही सूर ने आखिरी सांस भरी और जीवन का आखिरी पद गुना। उनकी आंखे वल्लभ-मूर्ति के चरणो मे गडी थी और वे कह रहे थे। भरोसो द्रढ इन चरनन केरौ, श्री वल्लभ नखचन्द्र छटा बिनु-सब जग मांझ अन्धेरो । साधन और नहीं या कलि मे जासो होत निबेरौ । सूर कहा कहै द्विविध आंधरौ बिना मोल के चेरौ ।। मुझे केवल एक आस, एक विश्वास, एक द्रढ भरोसा रहा-और वह इन(गुरू) चरणों का ही रहा। श्री वल्लभ न आते, तो सूर सूर न होता। उनके श्री नखो की चाँदनी छटा के बिना मेरा सारा संसार घोर अंधेरे मे समाया रहता।मेरे भाइयो, इस कलीकाल मे पूर्ण गुरू के बिना कोई साधन, कोई चारा नही, जिसके द्वारा जीवन-नौका पार लग सके।

सूर आज अंतिम घडी में कहता है कि, मेरे जीवन का बाहरी और भीतरी दोनो तरह का अंधेरा मेरे गुरू वल्लभ ने ही हरा। वरना मेरी क्या बिसात थी। मै तो उनका बिना मोल का चेरा भर रहा।

# एनपीएस वात्सल्यः भावी पीढ़ी के लिए एक बुद्धिमानी भरा निवेश

**श्रीराम अय्यर**

आज की दुनिया में, एक स्थिर व सुरक्षित आर्थिक भविष्य सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है। ÷एनपीएस वात्सल्य योजना÷ बच्चों को जन्म से ही एक सेवानिवृत्ति कोष बनाने का अनूठा अवसर प्रदान करते हुए, उन्हें आर्थिक आजादी की राह पर आगे बढ़ाती है। नाबालिगों के लिए लक्षित, यह योजना माता-पिता को बिल्कुल शुरुआत से ही योगदान करने में समर्थ बनाते हुए उनके बच्चे के आर्थिक भविष्य की एक ठोस शुरुआत सुनिश्चित करती है। 18 वर्ष के होने पर, बच्चे निवेश करना जारी रख सकते हैं जिससे उनकी संपत्ति चक्रवृद्धि आधार पर बढ़ सकती है- जो उन्हें एक सफल वयस्क जिंदगी जीने के लिए तैयार करेगी।

## भावी पीढ़ी का सशक्तिकरण

'एनपीएस वात्सल्य' महज निवेश का एक विकल्प ही नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। यह योजना युवाओं को आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए सशक्त बनाती है। माता-पिता और अभिभावकों को जल्दी शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करके, यह योजना भावी पीढ़ियों के आर्थिक कल्याण की दिशा में एक अहम भूमिका निभाती है। यह योजना आर्थिक रूप से एक सुरक्षित राष्ट्र बनाने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस वर्ष के बजट भाषण में इस योजना की घोषणा के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा था, *÷नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की एक योजना, एनपीएस वात्सल्य शुरू की जाएगी। बच्चों के 18 वर्ष के हो जाने पर, यह योजना निर्बाध रूप से एक नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो सकती है।÷*

## एनपीएस वात्सल्य क्या है?

'एनपीएस वात्सल्य' नाबालिगों के लिए डिजाइन किया गया राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का एक अनुकूलित संस्करण है। यह योजना माता-पिता या अभिभावकों को नियमित योगदान के साथ अपने बच्चों के लिए एक निवेश खाता खोलने की अनुमति देती है। जैसे ही बच्चा 18 वर्ष का होता है, यह निवेश खाता एक मानक एनपीएस में रूपांतरित हो जाता है। इससे उक्त युवा को अपने निवेश संबंधी निर्णयों के मामले में पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है।

## 18 वर्ष की आयु के बाद के लाभ

एकबारगी बच्चे के वयस्क होते ही, 'एनपीएस वात्सल्य' एक नियमित एनपीएस खाते में बदल जाता है। यह सुविधा वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देते हुए निरंतर योगदान को प्रोत्साहित करती है। यह योजना बचत की आदत पैदा करती है, जो आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## यह योजना कैसे काम करती है?

'एनपीएस वात्सल्य' योजना पारंपरिक एनपीएस के जैसी संरचना का ही अनुसरण करती है। यह योजना स्थिरता एवं विकास की संभावनाओं को सुनिश्चित करते हुए इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉन्ड का एक समुचित व संतुलित पोर्टफोलियो मिश्रण प्रदान करती है। इसके पीछे का मुख्य विचार जल्दी निवेश शुरू करना है ताकि दीर्घकालिक अवधि में चक्रवृद्धि आधार पर लाभ मिले। जीवन के अहम पड़ावों पर बच्चों की सहायता के उद्देश्य से डिजाइन की गई यह योजना माता-पिता को अपने निवेश के मामले में लचीलापन प्रदान करती है, जिससे उन्हें एक विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलती है। 18 वर्ष का होने पर, बच्चा वयस्क एनपीएस की तरह ही यह तय कर सकता है कि उसे कैसे निवेश करना है और अपनी निधि को कैसे और बढ़ाना है।

**चक्रवृद्धिकरण (कंपाउंडिंग) की शक्ति-एक परिवर्तनकारी पहलूः** 'एनपीएस वात्सल्य' का सबसे महत्वपूर्ण लाभ चक्रवृद्धिकरण (कंपाउंडिंग) की शक्ति है। जल्दी शुरुआत करने से, ग्राहकों को 18 अतिरिक्त वर्षों की चक्रवृद्धि का लाभ मिलता है। इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त धन संचय हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे के माता-पिता उसके जन्म से शुरू करके सालाना 50,000 रुपये का योगदान करते हैं, तो 10 प्रतिशत के वार्षिक रिटर्न के साथ, बच्चे के 18 वर्ष का होने तक धनराशि बढ़कर लगभग 25 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। यदि उक्त युवा के कमाई शुरू करने तक, उसके लिए निवेश जारी रहता है, तो उक्त निधि 25 साल की आयु तक बढ़कर 40 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। यदि वे 60 साल की आयु तक अपनी आय में से 50,000 रुपये का वार्षिक योगदान करते हैं, तो यह निधि बढ़कर लगभग 12.5 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। 'एनपीएस वात्सल्य' के माध्यम से शुरुआती योगदान के बिना, यह आंकड़ा सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये तक ही पहुंचेगा॒ लगभग आठ गुना का अंतर, जो धन सृजन की गति को जबरदस्त तेज करने की इस योजना की क्षमता को दर्शाता है। इस योजना के तहत सभी गणनाएं जीवनकाल में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत के सीमित रिटर्न को मानकर की गई हैं।

## निवेश संबंधी विकल्प

मानक एनपीएस की तरह ही, 'एनपीएस वात्सल्य' इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉन्ड का मिश्रण प्रदान करता है। ग्राहक अपने लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर 'ऑटो चॉइस' (एलसी25, एलसी50 और एलसी75 जैसे जीवन चक्र निधि) या 'एक्टिव चॉइस' का विकल्प चुन सकते हैं। एनपीएस की सफलता, 'एनपीएस वात्सल्य' के लिए एक ठोस मिसाल कायम करती है। एनपीएस के बारे में यह दावा है कि अगस्त 2024 तक उसके प्रबंधन के तहत 13 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है।

## एनपीएस वात्सल्य क्यों चुनें?

हर माता-पिता अपने बच्चों को आर्थिक एवं भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने का निरंतर प्रयास करते हैं। 'एनपीएस वात्सल्य' योजना एक समर्पित निवेश खाते, जो समय के साथ बढ़ती जाती है, की पेशकश करके इस प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। यह योजना न केवल शिक्षा जैसे जीवन के प्रमुख लक्ष्यों के मामले में सहायता करती है, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए पर्याप्त धन अर्जित करने के लिए चक्रवृद्धिकरण की शक्ति का भी लाभ प्रदान करती है। इसके अलावा, यह कम आयु में बच्चों में बचत संबंधी अनुशासन पैदा करती है और उन्हें अपनी वित्तीय योजना बनाने व धन प्रबंधन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

## निष्कर्ष

'एनपीएस वात्सल्य' एक रचनात्मक आर्थिक उपकरण है, जिसे माता-पिता को अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने हेतु सशक्त बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। बचत के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर और दीर्घकालिक अवधि में धन सृजन का एक उपाय पेश करके, यह योजना अगली पीढ़ी के लिए निवेश का एक बुद्धिमानी भरा विकल्प प्रदान करती है। चक्रवृद्धिकरण और शुरुआत से ही आर्थिक योजना बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करके, 'एनपीएस वात्सल्य' यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे की आर्थिक सुरक्षा की यात्रा उसके जन्म के साथ ही शुरू हो जाए।

**(लेखक एमडी एवं सीईओ, एचडीएफसी पेंशन फंड हैं)**

## आज का कार्टून

## राशिफल

**मेष**

आज दिनचर्या काफी अच्छी रहेगी। आप किसी विचार में खोये हो सकते हैं। अपनी प्रतिभा और क्षमता को व्यर्थ न जानें दें बल्कि उसका सार्थक उपयोग करें।

**वृषभ**

आपके अपने सम्मान की चिन्ता रहेगी। इसके कारण आप लोगों से झगड़ भी सकते हैं। आपको कुछ समय आत्मचिन्तन में लगाना चाहिये।

**मिथुन**

आपको अतिआत्मविश्वास से बचना चाहिये। घुटनों और कूल्हों में दर्द हो सकता है। जल्दबाजी में आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं।

**कर्क**

रुके हुये कार्यों में अचानक गति आ सकती है। अल्प मेहनत से ही आपको धन लाभ होगा। किसी महँगे उत्पाद की खरीदारी कर सकते हैं।

**सिंह**

आज आपको सैद्धान्तिक होने के बजाय व्यवहारिक होना चाहिये। लेन-देन की समस्या का समाधान होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर सावधान रहें।

**कन्या**

उच्च शिक्षा के मार्ग में बाधा आ सकती है। नजदीकी सम्बन्धियों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहेंगे। आलस्य और मौजमस्ती में समय बर्बाद न करें।

**तुला**

व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। कठिन विषयों का आप अध्ययन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मीटिंग्स को लेकर लापरवाही न करें।

**वृश्चिक**

आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। कन्सल्टिंग से जुड़े प्रोफेशन में सफलता मिलेगी। आपकी इच्छा के अनुसार सभी काम समय पर हो जायेंगे।

**धनु**

अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करें। मुँह का स्वाद बिगड़ सकता है। कुण्ठित विचारों वाले मित्रों से दूरी बनाकर रखें। किसी गम्भीर विषय को लेकर तनाव हो सकता है।

**मकर**

कार्यक्षेत्र की परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आपके पक्ष में आ रही है। मित्रों का साथ और सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होगा। बच्चे आपसे जिद कर सकते हैं।

**कुंभ**

कार्यक्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर कुछ तनाव रहेगा। अधेड़ उम्र की महिलाओं को हार्मोनल असन्तुलन जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।

**मीन**

आपके सामाजिक सम्पर्कों में वृद्धि होगी। दोपहर के बाद आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अचानक धन लाभ होने से उत्साहित रहेंगे।

देशप्राण स्वतंत्र हिन्दी दैनिक



# केजरीवाल का आतिशी दांव

एक बार फिर साबित हुआ कि अरविंद केजरीवाल राजनीति के चतुर सुजान हैं। वे भी आपदा को अवसर में बदलने का हुनर जानते हैं। शीर्ष अदालत से सशर्त जमानत मिलने से खुद को बंधा महसूस करते हुए उन्होंने इस्तीफे का दांव चलाकर राजनीतिक जगत में एक हलचल पैदा कर दी। वहीं पार्टी में वरिष्ठता क्रम में निचले पायदान पर खड़ी आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल ने एक बार फिर से चौंकाया है। कयास लगे थे कि अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं उनकी पत्नी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कहा जा रहा था। दरअसल, क्षेत्रीय दलों में एक परंपरा रही है कि किसी राजनीतिक या कानूनी संकट के चलते परिवार के ही किसी सदस्य को सत्ता की बागडोर सौंप दी जाती थी। ताकि स्थितियां सामान्य होने पर फिर मुख्यमंत्री की गद्दी आसानी से वापस ली जा सके। जैसे बिहार में चारा घोटाले में घिरने के बाद लालू यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता की बागडोर सौंपी थी। विगत के ऐसे प्रसंग भी हैं जब कानूनी बाध्यताओं के चलते पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री का पद दिया गया तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे लेने लगी। विगत में बिहार और झारखंड में ऐसे प्रसंग सामने आए। बहरहाल, केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही अपने तरकश से जो तीर चले हैं, वे कुल मिलाकर निशाने पर लगते नजर आए हैं। हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव समेत अन्य राष्ट्रीय मुद्दों में उलझी भाजपा व कांग्रेस पर केजरीवाल ने मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना दिया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के साथ कराने की मांग करके आप ने दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। लेकिन यदि केजरीवाल शराब घोटाले में नाम आने व गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस्तीफा दे देते तो शायद उन्हें इसका ज्यादा लाभ मिलता, जैसे कि लालकृष्ण आडवाणी ने कतिपय राजनीतिक आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल, केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सोची-समझी रणनीति के तहत ही दिया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को अपनी ईमानदारी के जनमत संग्रह के रूप में दर्शा सकें। उनका मकसद भाजपा सरकार द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकाबला करने तथा खुद को राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार के रूप में दिखा जनता की सहानुभूति अर्जित करना भी है। निस्संदेह, जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र हासिल करने की योजना उनकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा जान पड़ती है। वहीं तय समय से तीन माह पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने की मांग करके उन्होंने जता दिया है कि आप चुनाव अभियान के लिये तैयार है। दरअसल, केजरीवाल वर्ष 2014 के इस्तीफे के दांव को दोहराना चाहते हैं, जिसके बाद 2015 में आम आदमी पार्टी को भारी जीत मिली थी। लेकिन इस बार की स्थितियां खासी चुनौतीपूर्ण व जोखिम भरी हैं। निस्संदेह, यह जुआ मुश्किल भी पैदा कर सकता है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। जिसे विपक्ष ने पार्टी की घटती लोकप्रियता के रूप में दशार्या था। दरअसल, बुनियादी प्रशासनिक ढांचे की खामियां व भाजपा के लगातार हमलों ने आप को बचाव की मुद्रा में ला खड़ा कर दिया था। वहीं दूसरी ओर आप सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अभी भी मतदाताओं को पसंद आ रही हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस्तीफे का पैंतरा आप को राजनीतिक रूप से कितना रास आता है। वहीं दूसरी ओर कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल के इस पैंतरे से तेज हुई राजनीतिक सरगर्मियों का असर पड़ोसी राज्य हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी दिख सकता है। चुनाव में इंडिया गठबंधन से मुक्त आप राज्य की सभी सीटों पर ताल ठोक रही है। जिसका कुछ लाभ भाजपा को भी हो सकता है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि चुनौतियों से जूझती पार्टी अपना जनाधार किस हद तक मजबूत कर पाती है। वहीं दूसरी ओर जनता की अदालत में दिल्ली सरकार की फ्री पानी-बिजली व सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा कराने की नीति की भी परीक्षा होनी है।

# पश्चिमी देशों की भारत और पीएम मोदी से बढ़ती उम्मीदें

अशोक भाटिया

लेखक वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले देश की सत्ता की कमान संभाली। इन बीते 10 सालों में वह न केवल मजबूत वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं बल्कि मौजूदा समय में वह सबसे बड़े संघर्ष के समाप्ति की उम्मीद भी बन गए हैं।ढाई साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध के खात्मे को लेकर पश्चिमी देश भी अब भारत और प्रधानमंत्री मोदी की ओर उम्मीद लगाकर देख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है युद्ध में शामिल दोनों पक्षों का भारत पर भरोसा। प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों का दौरा किया। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर साफ कर दिया है कि उन्हें शांति समझौते को लेकर भारत की मध्यस्थता मंजूर है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद कहा था कि अगली शांति वार्ता भारत में आयोजित होनी चाहिए।

बताया जाता है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भरोसा है कि अगर भारत शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है तो यह युद्ध रुक सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया था प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि वह शांति के पक्ष में खड़ा है। यह संदेश न केवल रूस-यूक्रेन के लिए था बल्कि यह पूरी दुनिया को यह बताने के लिए है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका क्या होगी?रूस-यूक्रेन के अलावा अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को भी रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन-पोलैंड यात्रा से लौटे तो 26 अगस्त को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर उनसे बात की। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर चर्चा हो चुकी है।अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि भारत और रूस के बीच संबंध कितने मजबूत हैं, पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने इस संघर्ष की शुरूआत से लेकर अब तक मजबूती से रूस का साथ निभाया है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार शांति की अपील भी करते रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने साफ-साफ कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है।

पिछले हफ्ते रूस दौरे पर गए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत युद्ध रुकवाने के प्लान पर अब तेजी से जुट गया है। माना जा रहा था कि डोभाल, राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का ह्यपीस प्लानह्ण साझा कर सकते हैं। वहीं अगर पुतिन की ओर से सहमति बन जाती है तो फिर आने वाले दिनों में इसे लेकर कोई बड़ी कवायद शुरू होती नजर आ सकती है।खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए मॉस्को जा सकते हैं। एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव भी रखा है, लिहाजा सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री मोदी वाकई इस जंग को रुकवाने में बड़ी और सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध के अलावा भारत मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयासों में भी अहम भूमिका निभा सकता है। मिडिल ईस्ट के कई इस्लामिक मुल्कों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। यूएई, कतर, सऊदी अरब और ईरान जैसे इस्लामिक मुल्क हों या इजराइल सभी के साथ भारत के रिश्ते समय के साथ बेहतर और मजबूत होते जा रहे हैं।पिछले साल नवंबर में दिल्ली पहुंचे अरब देशों के राजदूतों ने मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण माना था, तो वहीं सोमवार को इजराइल के नए राजदूत रिवेन अजार ने बड़ा बयान दिया है, निजी अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यह भारत पर निर्भर करता है कि वह गाजा युद्ध के समाधान के लिए किस हद तक शामिल होना चाहता है।

दरअसल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजरायल पर हमला किया, तो भारत उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले इस आतंकी हमले की निंदा की थी। हमले के ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल के लिए भारत कितना अहम है। वहीं पिछले महीने नेतन्याहू के साथ फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष को खत्म करने लिए बातचीत और कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील की।फिलिस्तीन के नजरिए से देखा जाए तो भारत ने फिलिस्तीन-इजरायल विवाद में हमेशा से ह्यटू स्टेटह्ण समाधान का समर्थन किया है। भारत आजाद फिलिस्तीन का समर्थक रहा है और वर्षों से इसके फिलिस्तीन के साथ राजनयिक संबंध हैं। करीब एक हफ्ते पहले भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अबू अल-हैजा ने भी शांति के लिए भारत पर भरोसा जताया, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन भी मध्यस्थता के लिए भारत जैसे दोस्त की तलाश में है।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति में काफी बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने इन 10 सालों में कई ऐसे देशों की यात्रा की जहां कभी कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था, इससे एक ओर भारत के उन देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए तो वहीं दूसरी ओर विश्व पटल पर भारत की छवि विश्वबंधु वाली बनकर उभरी है।पिछले साल अगस्त में प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत को लेकर 23 देशों में सर्वे किया। भारत को लेकर इन देशों का रुख सकारात्मक रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल समेत 9 देशों में 50 फीसदी से ज्यादा लोग भारत को लेकर अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 11 साल के कार्यकाल के दौरान भारत ने अपनी विदेश नीति को काफी हद तक नया रूप दिया है। उनके कार्यकाल की पहचान अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रति दृढ़ और रणनीतिक दृष्टिकोण से रही है। भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना, भारत के वैश्विक कद को बढ़ाना और आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना उनकी विदेश नीति के कुछ हिट्स में से एक हैं।

पिछले एक दशक में चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहीं हों, लेकिन भारत सरकार ने कई देशों से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने में सफलता हासिल की। सीरिया और यमन में युद्ध जैसे हालातों के बीच से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाया गया है, वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा के जरिए भारतीय छात्रों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि किसी भी नागरिक को हम पीछे नहीं छोड़ सकते।कोरोना महामारी के दौरान विकसित देशों ने छोटे और गरीब देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया था लेकिन भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए करीब 100 देशों को वैक्सीन मैत्री पहल के जरिए 200 मिलियन (20 करोड़) वैक्सीन की डोज इन देशों को भेजा। इस पहल में साउथ एशिया के देश, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश शामिल रहे। भारत की इस पहल से न केवल इन देशों में वैक्सीन की कमी को पूरा हुई बल्कि इन तमाम देशों के साथ भारत के डिप्लोमेटिक संबंध मजबूत हुए। साथ ही साथ इससे विश्व पटल पर भारत की ग्लोबल लीडर की छवि मजबूत हुई, जो सिर्फ बड़े और विकसित देशों की नहीं बल्कि छोटे और गरीब देशों की भी चिंता और मदद करता है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और ग्लोबल लीडरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला रूस-यूक्रेन युद्ध में, जब भारत ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस से रियायती दरों पर क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान मोदी सरकार ने देश के आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए जटिल जिओ-पॉलिटिकल परिदृश्यों को कुशलता से संभाला। भारत के इस कदम से न केवल घरेलू ऊर्जा डिमांड पूरी हुई बल्कि बदलते वैश्विक वातावरण में कूटनीतिक संवेदनशीलता और भारत की आर्थिक प्राथमिकता के बीच संतुलन बनाने की क्षमता को भी दिखाया है।

# आसमान को कूड़ाघर बनने से बचाएं



वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

जब भी साफ हवा, नीला आसमान, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस जैसे अवसर आते हैं, तो हम पृथ्वी के हित में अपने दायित्वों की बात करते हैं। भाषणबाजी से अलग, पृथ्वी के हित में हम सबसे महत्वपूर्ण कदम यह उठा सकते हैं कि आसमान को कूड़ा घर न बनाएं। जगह-जगह विशाल कूड़े के पहाड़, लैंडफिल्स में आग लगना और कई दिनों तक घुटन भरा धुआं उगलना यह दशार्ता है कि कूड़ा सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में भी अपनी जगह बना रहा है। प्लास्टिक इस संदर्भ में एक बड़ा खलनायक है। जलने के साथ-साथ माइक्रो-प्लास्टिक के छोटे कण भी वायुमंडल में पहुंचते हैं।

हाल ही में एक आम दृश्य यह देखा जा रहा है कि लोग सड़कों पर पत्तियां इकट्ठा करके उन्हें जलाते हैं। चुनावी सामग्री का कूड़ा भी सड़कों पर फैल जाता है और उसे भी जला दिया जाता है। इस धुएं का आसमान में फैलना, हमें यह बताता है कि हम अपने कूड़े को सीधे आसमान में भेज रहे हैं।

देशभर में विकास की दौड़ में वायु गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। निर्माण कार्यों, कोयला बिजली उत्पादन, और ईंट-भट्ठों से उड़ने वाली धूल और कणीय प्रदूषक वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। जब वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो धूल और कणीय प्रदूषकों को रोकने के लिए जाली व कपड़े की दीवारें लगाई जाती हैं। नगरों में कूड़ा जलाने वाले संयंत्र और सड़क सफाई की मशीनें भी वायु में प्रदूषकों का अम्बार छोड़ देती हैं।

वातावरण में धूल और कणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन्स का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारें विशेषकर ठंड के मौसम में इन प्रदूषणों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ रहती हैं। अंततः स्कूलों और कार्यालयों को बंद करना पड़ता है। राजनीतिक कारणों से निर्माण कार्यों और कूड़े के ढेर की अनदेखी होती है, जिससे प्रदूषण और बढ़ जाता है।

वायु में कणीय प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। इससे बीमारियों में वृद्धि होती है। ये कण पानी में भी जमते हैं और वहां से मिट्टी और घास में पहुंच जाते हैं, जो जानवरों के भोजन में भी शामिल हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर 90 प्रतिशत लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं और हर साल वायु प्रदूषण के कारण लगभग 7.9 मिलियन लोग समय से पहले मर जाते हैं, खासकर कम और मध्यम आय वाले देशों में। अत्यंत महीन कणीय प्रदूषकों को नियंत्रित करना अति आवश्यक है।

7 अक्टूबर, 2019 को यूरोप और अमेरिका के देशों ने एक साझा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और अमोनिया जैसे प्रदूषकों के अलावा पीएम 2.5 कणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन को भी तय सीमा में बांधने का फैसला किया गया। हालांकि, कणीय प्रदूषण केवल भौतिक परिमाण से नहीं मापा जाता, उसकी रासायनिक प्रकृति भी महत्वपूर्ण होती है। प्लास्टिक, कागज और रबर जलने पर उनके कणीय प्रदूषक भी हवा में चले जाते हैं।

भारत में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण उच्चतम है, और इसके कारण तेजाबी बारिश होती है। पेड़ों की पत्तियों पर प्रदूषण बैठ जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। आसमान को कूड़ाघर बनने से बचाने के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर सुधार आवश्यक हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, वाहन ठीक रखना, और कूड़ा जलाने से बचना ये सभी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं।

दुनियाभर में बढ़ते ऊर्जा की मांग के कारण बड़े प्रदूषणकारी देश जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। भारत, जिसमें दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहर शामिल हैं, भी कोयले के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रहा है। इससे कणीय प्रदूषण और बढ़ेगा। नवीनतम खतरा माइक्रो-प्लास्टिक के वायुमंडल में पहुंचने का है। प्लास्टिक पर पाबंदी और इसके कम उपयोग से माइक्रो-प्लास्टिक भी कम होगा। हमें हताशा से बाहर निकलना होगा और अपनी आदतों में सुधार करना होगा। कूड़ा जलाने, पटाखे जलाने, धुआं छोड़ते वाहनों का उपयोग करने से बचना होगा। छोटे-छोटे बदलाव भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कूड़ा जलाने पर रोक और उचित कूड़ा प्रबंधन। प्राकृतिक कारणों से भी कणीय प्रदूषण बढ़ता है, जैसे आंधी-तूफान, खनन और ज्वालामुखी विस्फोट। पेड़ों की संख्या बढ़ाकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है।

अंततः, यदि हम कूड़ा करते रहें और सरकारों पर आरोप लगाते रहें कि वे प्रदूषण कम करने में असफल हैं, तो यह हमारे लिए हानिकारक होगा। हर व्यक्ति का जिम्मेदारी समझना जरूरी है ताकि प्रदूषित हवा की समस्या कम की जा सके। जैसे हम अपने जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करना चाहते, वैसे ही आसमान को भी प्रदूषण से बचाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण केवल एक राजनीतिक या सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालता है।

हाल ही में एक आम दृश्य यह देखा जा रहा है कि लोग सड़कों पर पत्तियां इकट्ठा करके उन्हें जलाते हैं। चुनावी सामग्री का कूड़ा भी सड़कों पर फैल जाता है और उसे भी जला दिया जाता है। इस धुएं का आसमान में फैलना, हमें यह बताता है कि हम अपने कूड़े को सीधे आसमान में भेज रहे हैं। देशभर में विकास की दौड़ में वायु गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। निर्माण कार्यों, कोयला बिजली उत्पादन, और ईंट-भट्ठों से उड़ने वाली धूल और कणीय प्रदूषक वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। जब वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो धूल और कणीय प्रदूषकों को रोकने के लिए जाली व कपड़े की दीवारें लगाई जाती हैं। नगरों में कूड़ा जलाने वाले संयंत्र और सड़क सफाई की मशीनें भी वायु में प्रदूषकों का अम्बार छोड़ देती हैं। वातावरण में धूल और कणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन्स का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारें विशेषकर ठंड के मौसम में इन प्रदूषणों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ रहती हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आचार्य चाणक्य के अनुसार, आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं।

चाणक्य

सन्मार्ग
पटना, गुरुवार 19 सितंबर 2024
www.live7tv.com

# आतंकी साजिशों से संकट में भारतीय रेल: यह राजनीति नहीं बल्कि एकजुटता का समय

विनोद पाठक

सा 12 सितंबर को यानी की ठीक 187 वर्ष पहले साल 1837 में भारतीय रेल की नींव पड़ी थी। मद्रास (अब चेन्नई) में भाप इंजन संचालित ट्रेन चली थी। हालांकि, पहली सवारी गाड़ी साल 1853 में बॉम्बे-ठाणे के बीच चली। तब से लेकर आज तक भारतीय रेल ने सैकड़ों गुणा तरक्की की है। आज भारतीय रेल देश की लाइफ लाइन कही जाती है, जिसमें 22 हजार ट्रेनों में पौने तीन करोड़ से अधिक लोग रोजाना सफर करते हैं। भारतीय रेल देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जोड़ती है। भारतीयों का अटूट विश्वास अपने रेल नेटवर्क पर है, लेकिन इन दोनों भारतीय रेल अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। यह संकट तकनीकी नहीं, बल्कि एक साजिश है। कुछ असामाजिक या कहें आतंकी तत्व भारत की लाइफ लाइन को डिरेल करने की खतरनाक साजिश रच रहे हैं।

भारतीय रेलवे के खिलाफ साजिश : विगत 40 दिनों में 18 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें अलग-अलग राज्यों में रेलवे ट्रैक पर भारी वस्तु रखकर ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश हुई। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर ओडिशा तक कई स्थानों पर रेल ट्रैक पर सिलेंडर, भारी सीमेंट स्लैब, लोहा आदि रखा मिला। ऐसी घटनाओं से यह आशंका और गहरी हो जाती है कि पिछले दिनों ट्रेनों के पटरियों से उतरने के पीछे तकनीकी कारण नहीं, बल्कि साजिश थी। देश में रेल नेटवर्क की बात करें तो 1,32,310 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक भारत में बिछा है। यह भारत का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बनाता है। इतने विशाल रेल नेटवर्क की सुरक्षा के लिए अलग से फोर्स है, लेकिन एक-एक स्थान की चौकसी करना दुनिया के किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। बीते कुछ वर्षों में भारतीय रेल ने बहुत तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ी है। पिछले 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाया गया है। केंद्र सरकार के अनुसार वर्तमान में 4 किलोमीटर प्रतिदिन का ट्रैक देश में बिछाया जा रहा है। रेलवे का विद्युतीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। 95 प्रतिशत ब्रॉड गेज रूट्स का विद्युतीकरण कर दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में भारतीय रेल की अहम भूमिका है। जब भारतीय रेल इस तेजी से विकास कर रही है तो वो कौन से तत्व हैं? जो इस पर गिद्ध निगाह गड़ाए हुए हैं। कुछ विदेशी एजेंसियों और आतंकी संगठनों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए यह असामाजिक और आतंकी तत्व आम भारतीयों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं होंगी तो जनता के मन में भय आना स्वाभाविक है। हालांकि, सरकार अब पहले से ज्यादा सतर्कता बरत रही है। ट्रेनों को बेपटरी करने की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने एआई संचालित 75 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। ये सीसीटीवी कैमरे कोच के अलावा लोको पायलट को सतर्क करने के लिए लोकोमोटिव (इंजन) में भी लगाए जाएंगे, जो पटरी पर संदिग्ध वस्तुओं का पता लगाकर ड्राइवर को आपातकालीन ब्रेक लगाने के लिए सचेत करेंगे। कुल मिलाकर रेलवे 40,000 कोच, 14000 लोकोमोटिव और 6000 ईएमयू को एआई संचालित सीसीटीवी कैमरों से लैस करने की योजना बना रही है। निश्चित रूप से यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश करने वाले आतंकी तत्वों को चिन्हित कर कड़ी सजा दे। हालांकि, इतने बड़े नेटवर्क पर हर एक स्थान पर नजर बनाए रखना सरकार या सुरक्षा एजेंसी के लिए संभव नहीं है। यहां जिम्मेदारी समाज की भी है। रेलवे ट्रैक के आसपास रहे लोगों का दायित्व है कि वो ऐसे तत्वों को लेकर सतर्क रहें। अपने बीच ऐसे तत्वों को पहचानें, जो देश की संपत्ति और लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे संकट के समय में राजनीतिक दलों को भी एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। तकनीकी कारणों से दुर्घटनाओं पर सरकार की आलोचना सही है, लेकिन जानबूझकर ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश पर विपक्ष का मौन सही नहीं है। आखिर भारतीय रेल किसी सरकार या पार्टी विशेष की न होकर देश की आन-बान-शान है। राष्ट्रीय धरोहर है।

**(यह लेखक के निजी विचार हैं।)**

# इस्तीफे का दांव

दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अरविंद केजरीवाल के फैसले ने एक स्तर पर लोगों को चौंकाया जरूर, लेकिन इसने प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीति के कई तात्कालिक और कुछ दूरगामी पहलुओं की ओर भी ध्यान खींचा है। केजरीवाल के जेल में रहते हुए उन पर इस्तीफे का दबाव बनाने में विरोधियों ने कोई कसर उठा नहीं रखी। उस पूरी अवधि में सभी दबावों की अनदेखी करते हुए वह अड़े रहे। अब जब केंद्रीय एजेंसी सीबीआई पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और पूरी पार्टी इसे केजरीवाल की जीत बता रही है, तब उन्होंने इस्तीफे का एलान कर दिया। इसी बिंदु पर चुनावी राजनीति की रणनीतिक बारीकियां अपनी ओर ध्यान खींचती हैं। दिलचस्प है कि इस मामले में चाहे बीजेपी हो या आप दोनों में हमलावर तेवर बनाए रखने की जैसे होड़ लगी हुई है। दोनों ही दल इस बात को लेकर काफी सतर्क नजर आते हैं कि वे बचाव की मुद्रा में न दिखने लग जाएं। आप नेता चाहें या न चाहें केजरीवाल की छवि दिल्ली में बड़ा चुनावी मुद्दा बनने ही वाली है। ऐसे में इस्तीफे के जरिए इस सवाल को केंद्र में लाकर आप ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि वह इस सवाल से किसी भी रूप में कतरा नहीं रही। महत्वपूर्ण यह भी है कि केजरीवाल ने पहले इस्तीफा न देने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए पूरे इंडिया ब्लॉक को इस दायरे में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि चाहे कर्नाटक में सिद्धारमैया हों या केरल में पी विजयन या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी- बीजेपी ने इन सबके खिलाफ मामला दर्ज कर इनकी सरकार गिराने की साजिश तैयार रखी थी। इस बड़ी साजिश को नाकाम करने के लिए ही वह अब तक इस्तीफा न देने की बात पर अड़े रहे। साफ है कि खुद को इंडिया ब्लॉक में मजबूती से बनाए रखना अभी उनकी प्राथमिकता में है। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से आखिरी पलों में तालमेल के कोई संकेत अभी तक नहीं हैं। चाहे अन्ना आंदोलन हो या एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर आने के बाद का, आप लीडरशिप ईमानदारी को कानून-व्यवस्था की नजरों से ही देखती थी। इसीलिए शुरू में उसका स्टैंड यह था कि जिस नेता पर भी कोई मामला दर्ज हो या उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बार पार्टी के नेता पद छोड़ने का फैसला करते हुए भी जनता की अदालत में खुद को बेकसूर साबित करने पर जोर दे रहे हैं। यह पार्टी के नजरिए में आए बदलाव का सबूत है। यह भारत में राजनीति की जीवंतता की एक निशानी तो है ही।

# जम्मू के प्रति आश्वस्त नहीं रह सकती भाजपा

ज्योति मल्होत्रा

ज म्मू से कठुआ तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाजपा के चुनावी होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिनपर लिखे एक पंक्ति वाले नारे का मकसद है मतदाता के मानस में 2014 से पहले और बाद वाली स्थिति की तुलना दिखाते हुए अपनी बात सरल तरीके से बैठाना। साल 2014 में इस पूर्व राज्य ने आखिरी बार मतदान किया था और वर्तमान में कुछ ही दिनों बाद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहां पूरे एक दशक बाद चुनाव होने जा रहे हैं। इन होर्डिंग्स पर मौजूद तस्वीरों में,एक तरफ है गहरा धुंआ, नारे लगाने वालों के लहराते हाथ और जलती कारें तो इसके विपरीत दूसरे हिस्से में हैं चमकदार छवियां, जो उम्मीद और समृद्धि का प्रतीक हैं। भाजपा के विज्ञापन अभियानों की विशिष्टता के अनुरूप, इनमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरे फ्रेम में केंद्रीय है। शब्दों के रूप में लिखा है: मातम-स्वागतम, डर-निडर, अशांति-शांति। और एक नारा है : शांति, स्थिरता और विकास जम्मू को मोदी पर विश्वास। लेकिन, यक्ष प्रश्न है कि क्या जम्मू का मतदाता मोदी के साथ-साथ भाजपा के स्थानीय उम्मीदवारों पर भी विश्वास करेगा, जो पीर पंजाल के दक्षिण में फैली इस विशाल और दुरूह भौगोलिकता के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी ताल ठोक रहे हैं, हालांकि वर्तमान विधानसभा चुनाव पहली बार बदले हुए, पुनर्गठित परिदृश्य में लड़े जा रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों के हालिया परिसीमन के बाद इस क्षेत्र में छह सीटें और जुड़ गई हैं। इसके अलावा नई विधानसभा में पांच विधायक मनोनीत होंगे,इस प्रकार विधानसभा में पूर्व में 87 की तुलना में कुल 95 विधायक होंगे। ऐसे चुनाव में, जहां हर सीट मायने रखती है, जीत और हार के बीच जम्मू संभाग संतुलन बना सकता है। दुनिया के इस हिस्से में, जहां पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पत्थर फेंकने जितनी दूरी पर है, सभी राजनीतिक दल लोगों का प्यार जीतने की खातिर चाणक्य के दिए प्राचीन सूत्र अर्थात साम-दाम-दंड-भेद पर अमल करने में निश्चित रूप से जुटे हुए हैं। भाजपा के लिए, जिसने 2014 के चुनाव में कुल 25 सीटें जीती थीं, सभी जम्मू संभाग से- लेकिन कश्मीर घाटी से एक भी नहीं थी, उसके लिए यह दांव स्पष्टतः बहुत बड़ा है।

राह चलते मतदाता से बात करें तो भ्रम की स्थिति है। हमें क्या मिला वाली टीस अगर भाजपा समर्थक जम्मू के दिल में इसी प्रकार बनी रही, जबकि 1 अक्तूबर को मतदान होना है,तो यह रोष किला ढहने का कारक बन सकता है। मतदाता रोज-ब-रोज भयानक यातायात के दुःस्वप्न से गुजर रहा है (भले ही नितिन गडकरी का मंत्रालय नए-नए पुल और फ्लाईओवर क्यों न बना रहा हो), जबकि स्मार्ट सिटी बनाने के सपनों के बावजूद खुले नालों को ढकने और कूड़े के ढेरों को साफ करने के वादे पूरे नहीं हुए। पेंशन मिलने में देरी हो रही है और सरकारी योजना के लाभार्थियों को मानव-रहित ऑनलाइन प्रणाली की प्रक्रियाओं से पार पाने में मुश्किल हो रही है, तिस पर लिंक बीच-बीच में लगातार टूटता रहता है-और फिर आपको अपना काम निकलवाने को उन्हीं पुराने लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। इसके अलावा, जब शेष भारत से लोग गर्मियों में सीधे कश्मीर घाटी के ट्यूलिप गार्डन, डल झील की सैर तो सर्दियों में गुलमर्ग-पहलगाम का रुख करते हों, जिससे कि इंस्टाग्राम इत्यादि पर डालने को नवीनतम मसाला भी मिल सके। ऐसे में, जम्मू घूमने वाले कम ही बचते हैं, यहां तक कि पर्यटकों से भरी 25 में से 15 रेलगाड़ियों के यात्री वैष्णो देवी तीर्थ के लिए सीधे कटरा स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन पकड़ते हैं। लिहाजा व्यापार ठंडा है। बाहरी लोगों के मन में बैठे डर- वास्तविक और अवास्तविक, दोनों कायम हैं, शायद इसीलिए यहां निवेश करने में इच्छुक कुछ कॉरपोरेट कंपनियां बड़ी रकम लगाने में अभी भी हिचकिचा रही हैं। हालांकि 2015 से 2018 तक चली भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार ने दो नए एम्स अस्पताल, एक आईआईएम और एक आईआईटी बनाने का वादा किया था। इसमें से कुछ भी नया नहीं है। जम्मू वालों ने जो आज पाया है वह यूपी और बिहार वालों को हमेशा से मिलता आया है, राजनेताओं के खोखले वादे, जो बाद में हवा-हवाई हो जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जम्मू को अपने लिए गरीब और दूर के चचेरे भाई सरीखा बर्ताव पसंद नहीं है। एक समस्या जो खासतौर पर काफी गहरी और साफ दिखाई देती है वह यह कि भाजपा नेतृत्व और इसके लोगों के बीच आपसी संपर्क बहुत कम है,बेशक इसे दूर किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए पहले ही काफी देर नहीं हो चुकी? ( हालांकि भाजपा के लिए जो एक स्थिति फायदेमंद है, वह यह कि इस इलाके में कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन या तो बुरी तरह छिताराया हुआ है या फिर है ही नहीं।) असल सवाल है कि आरएसएस विचारक राम माधव कितना कर पाएंगे,हालांकि उन्होंने भाजपा-पीडीपी गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी किंतु बाद में मोदी सरकार ने उन्हें किनारे कर दिया। हाल ही में उन्हें अनदेखी के अंधेरे कोने से बाहर निकालकर पुनः सक्रिय किया गया है।

https://t.me/epaperpdf

# बढ़ती उम्र और आयुष्मान का सहारा, सरकार को साधुवाद

पत्रलेखा चटर्जी

जै से-जैसे बुजुर्ग लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, खासकर वैसे बुजुर्गों की, जिनके पास न कोई पैतृक संपत्ति होती है, न पेंशन और न घर के किराये से होने वाली आमदनी, भविष्य में चिकित्सा खर्च की बढ़ती लागत उनकी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होती है। मेरे जैसे मध्यमवर्गीय परिवार के एक व्यक्ति को, जिसके पास थोड़ी बचत होती है और सिर पर एक छत होती है, थोड़ी सुविधा रहती है। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य देखभाल की बात है, तो सभी जानते हैं कि बीमा कंपनियां भी इलाज के सारे खर्चों को वहन नहीं करती हैं। ऐसे में, यह अच्छी बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल बीमा को मंजूरी दी है, चाहे वे किसी भी आय वर्ग के हों। ऐसे कई परिवार हैं, जो पहले से ही आयुष्मान योजना में शामिल हैं और उनमें वरिष्ठ नागरिक भी हैं। अब वैसे परिवारों को पांच लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा कवरेज मिलेगा। हालांकि इसका अंतिम प्रारूप अभी आना बाकी है, तभी पता चलेगा कि इसे विभिन्न राज्यों द्वारा जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाता है। लेकिन यह भी देखना होगा कि स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से किए जाने वाले खर्च के मामले में हम कहां खड़े हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24 में बताया गया है कि स्वास्थ्य देखभाल पर भारत में जेब से किया जाने वाला खर्च अब भी कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 50 प्रतिशत है। हालांकि पिछले दस वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से खर्च 47 प्रतिशत से अधिक था, जो निश्चित रूप से 2013-14 के 64 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम है, लेकिन यह अब भी तीन साल पहले आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाए गए 35 फीसदी की सीमा से बहुत ज्यादा है। ध्यान रहे कि ज्यादातर भारतीय असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास कोई निश्चित वेतन वाली कमाई नहीं है, जिसमें अन्य लाभ भी होते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का भी कोई प्रावधान नहीं होता है। भारत की पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली-संयुक्त परिवार तेजी से बिखर रहे हैं। बच्चे अक्सर दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं। ऐसे में, उनसे यह उम्मीद करना कि वे स्वास्थ्य देखभाल का पूरा खर्च उठाएंगे, नासमझी होगी। तो फिर उपाय क्या है? इस मामले में हम एशिया के कुछ अन्य देशों से सीख सकते हैं। जैसे, पड़ोसी देश थाईलैंड उच्च मध्यम आय वाला देश है। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद स्वास्थ्य देखभाल के मामले में इसका रिकॉर्ड बेहतर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, थाईलैंड में वर्ष 2021 में स्वास्थ्य पर नौ फीसदी खर्च जेब से हुआ था, जबकि भारत में यह आंकड़ा 49.82 प्रतिशत था। यह देखते हुए कि वर्ष 2007 में भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से किया जाने वाला खर्च कुल स्वास्थ्य व्यय का 70 प्रतिशत से अधिक था, हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति में पहले से सुधार हुआ है, लेकिन हमें अब भी एक लंबा रास्ता तय करना है। थाईलैंड में बूढ़ी होती आबादी के साथ अन्य चुनौतियां भी हैं, लेकिन वहां सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (यूएचसी) महज एक वादा नहीं, बल्कि हकीकत है। यूएचसी का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को बिना वित्तीय समस्या के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। वर्ष 2002 में ही वहां यूएचसी लागू किया गया और थाईलैंड स्वास्थ्य देखभाल पर अपनी जीडीपी का पांच फीसदी खर्च करता है, जिसका 70 फीसदी हिस्सा सरकार देती है। कई अन्य उच्च मध्य आय वाले देशों की तुलना में स्वास्थ्य पर कम खर्च करने के बावजूद थाईलैंड काफी कुछ करने में सफल रहा है। वर्ष 2000 से 2021 के बीच वहां जीवन प्रत्याशा 72.3 वर्ष से बढ़कर 78.7 वर्ष हो गई। नवजात मृत्युदर 1.67 फीसदी से घटकर मात्र 0.62 फीसदी रह गई है और स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से खर्च 34.2 फीसदी से घटकर नौ फीसदी रह गया है। थाईलैंड में तीन मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, जो लगभग वहां की पूरी आबादी के लिए हैं। इनमें शामिल हैं, लोक सेवक स्वास्थ्य लाभ योजना (सीएसएमबीएस), जिसमें सरकारी कर्मचारी और उनके रिश्तेदार आते हैं और इसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय करता है। सामाजिक सुरक्षा योजना (एसएसएस), जिसमें संगठित क्षेत्रों के निजी कर्मचारियों को कवर किया जाता है, जिसका खर्च कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार, तीनों उठाते हैं और इसका प्रबंधन श्रम मंत्रालय करता है और यूनिवर्सल कवरेज योजना (यूसीएस) के तहत शेष बची ज्यादातर आबादी को कवर किया गया है, जिसका खर्च सामान्य कराधान से पूरा किया जाता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यालय (एनएचएसओ) इसका प्रबंधन करता है। लोक स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी देखभाल करता है, जबकि एनएचएसओ यूसीएस के लिए देखभाल क्रेता के रूप में कार्य करता है, तथा देखभाल प्रदान करने में क्रय शक्ति और दक्षता सुनिश्चित करता है। यूसीएस को गोल्ड कार्ड भी कहा जाता है, जो थाईलैंड की तीनों योजनाओं में सबसे बड़ी है और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। यूसीएस ज्यादातर आबादी को कवर करती है और इसकी फंडिंग सीधे राष्ट्रीय बजट से होती है तथा एनएचएसओ द्वारा प्रति व्यक्ति आधार पर बजट आवंटित किया जाता है। यह कार्यक्रम वर्ष 2002 में शुरू हुआ था। अब वर्ष 2024 में थाईलैंड की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिसमें यूनिवर्सल कवरेज योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज किसी भी जगह कराने जैसे प्रयास शामिल हैं। थाईलैंड की स्वास्थ्य देखभाल सहित कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्ण नहीं है और न ही किसी स्वास्थ्य व्यवस्था की हूबहू नकल किसी दूसरे देश में की जा सकती है, खासकर भारत जैसे विशाल और विविधता पूर्ण देश में, लेकिन हम अपने एशियाई पड़ोसियों से काफी कुछ सीख सकते हैं। विशेषकर उन देशों से, जिनका अपना स्वास्थ्य तंत्र काफी मजबूत है। ऐसे में, यह अच्छी बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल बीमा को मंजूरी दी है, चाहे वे किसी भी आय वर्ग के हों। ऐसे कई परिवार हैं, जो पहले से ही आयुष्मान योजना में शामिल हैं और उनमें वरिष्ठ नागरिक भी हैं। अब वैसे परिवारों को पांच लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा कवरेज मिलेगा। हालांकि इसका अंतिम प्रारूप अभी आना बाकी है, तभी पता चलेगा कि इसे विभिन्न राज्यों द्वारा जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाता है। लेकिन यह भी देखना होगा कि स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से किया जाने वाला खर्च के मामले में हम कहां खड़े हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24 में बताया गया है कि स्वास्थ्य देखभाल पर भारत में जेब से किया जाने वाला खर्च अब भी कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 50 प्रतिशत है। हालांकि पिछले दस वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से खर्च 47 प्रतिशत से अधिक था, जो निश्चित रूप से 2013-14 के 64 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम है, लेकिन यह अब भी तीन साल पहले आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाए गए 35 फीसदी की सीमा से बहुत ज्यादा है। ध्यान रहे कि ज्यादातर भारतीय असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास कोई निश्चित वेतन वाली कमाई नहीं है, जिसमें अन्य लाभ भी होते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का भी कोई प्रावधान नहीं होता है। भारत की पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली-संयुक्त परिवार तेजी से बिखर रहे हैं। बच्चे अक्सर दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं। ऐसे में, उनसे यह उम्मीद करना कि वे स्वास्थ्य देखभाल का पूरा खर्च उठाएंगे, नासमझी होगी। तो फिर उपाय क्या है? इस मामले में हम एशिया के कुछ अन्य देशों से सीख सकते हैं। जैसे, पड़ोसी देश थाईलैंड उच्च मध्यम आय वाला देश है। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद स्वास्थ्य देखभाल के मामले में इसका रिकॉर्ड बेहतर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, थाईलैंड में वर्ष 2021 में स्वास्थ्य पर नौ फीसदी खर्च जेब से हुआ था, जबकि भारत में यह आंकड़ा 49.82 प्रतिशत था। यह देखते हुए कि वर्ष 2007 में भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से किया जाने वाला खर्च कुल स्वास्थ्य व्यय का 70 प्रतिशत से अधिक था, हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति में पहले से सुधार हुआ है, लेकिन हमें अब भी एक लंबा रास्ता तय करना है। थाईलैंड में बूढ़ी होती आबादी के साथ अन्य चुनौतियां भी हैं, लेकिन वहां सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (यूएचसी) महज एक वादा नहीं, बल्कि हकीकत है। यूएचसी का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को बिना वित्तीय समस्या के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। वर्ष 2002 में ही वहां यूएचसी लागू किया गया और थाईलैंड स्वास्थ्य देखभाल पर अपनी जीडीपी का पांच फीसदी खर्च करता है, जिसका 70 फीसदी हिस्सा सरकार देती है। कई अन्य उच्च मध्य आय वाले देशों की तुलना में स्वास्थ्य पर कम खर्च करने के बावजूद थाईलैंड काफी कुछ करने में सफल रहा है। वर्ष 2000 से 2021 के बीच वहां जीवन प्रत्याशा 72.3 वर्ष से बढ़कर 78.7 वर्ष हो गई। नवजात मृत्युदर 1.67 फीसदी से घटकर मात्र 0.62 फीसदी रह गई है और स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से खर्च 34.2 फीसदी से घटकर नौ फीसदी रह गया है। थाईलैंड में तीन मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, जो लगभग वहां की पूरी आबादी के लिए हैं। इनमें शामिल हैं, लोक सेवक स्वास्थ्य लाभ योजना (सीएसएमबीएस), जिसमें सरकारी कर्मचारी और उनके रिश्तेदार आते हैं और इसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय करता है।

**सुभाषित**

*क्षमा वह उपकार नहीं है, जो हम दूसरोंपर करते हैं, बल्कि यह उपकार हम अपने लिए करते हैं। क्षमा करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो।* ❐ **चन्द्रशेखर आजाद**

## बढ़ता व्यापार घाटा

देशका बढ़ता व्यापार घाटा न केवल गम्भीर चिन्ताका विषय है, बल्कि यह अर्थव्यवस्थाके लिए भी शुभ संकेत नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वैश्विक अनिश्चितता है जिससे निर्यात व्यापारपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अगस्त, २०२४ में निर्यात व्यापारमें ९.३ प्रतिशतकी गिरावट चिन्ता बढ़ानेवाली है। निर्यात व्यापार घटकर ३४.७१ अरब डालरके स्तरपर आ गया, जो १३ महीनेकी सबसे बड़ी गिरावट है। पिछले वर्ष अगस्त महीनेमें निर्यात व्यापार ३८.२८ अरब डालरके स्तरपर था। दूसरी ओर देशमें आयात ३.३ प्रतिशत बढ़कर ६४.३९ डालर हो गया। पिछले वर्ष अगस्त महीनेमें आयात ६२.३ अरब डालर था। आयात-निर्यातके बीच बढ़ता अन्तर ही व्यापार घाटेको बढ़ाता है। निर्यात घटनेसे विदेशी मुद्राकी आवक कम हो जाती है और आयात बढ़नेसे विदेश मुद्रा अधिक खर्च करनी पड़ती है। पिछले दस महीनोंमें व्यापार घाटा २९.६५ अरब डालर बढ़ना चिन्ताजनक है। वस्तु निर्यातमें जुलाई महीनेमें १.५ प्रतिशतकी गिरावट आयी थी। मंगलवारको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयकी ओरसे जारी आयात-निर्यातके आंकड़ोंसे स्पष्ट है कि जहां एक ओर निर्यातपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वहीं दूसरी ओर आयातमें वृद्धि हुई। आयातपर निर्भरता कम करनेकी जरूरत है, जबकि निर्यातको बढ़ावा देनेकी दिशामें मजबूत प्रयास करनेकी आवश्यकता है। विगत माहमें पेट्रोलियम उत्पादोंका आयात और निर्यात बढ़ा है। अगस्तमें इलेक्ट्रानिक सामान, फार्मा और इंजीनियरिंग निर्यातमें क्रमश: ७.८५ प्रतिशत ४.६७ प्रतिशत और ४.३ प्रतिशत बढ़ा है। अगस्तमें सेवाओंका निर्यात ३०.६९ अरब डालर रहा, जबकि आयात १५.७० अरब डालर रहा। पिछले वर्ष इसी महीनेमें निर्यात २८.७१ अरब डालर और आयात १५.०९ अरब डालर रहा। अगस्तमें भारतका कुल निर्यात ६५.४ अरब डालर रहा। इसमें वस्तु एवं सेवाएं दोनों शामिल हैं। सालाना आधारपर २.४ प्रतिशतकी गिरावट दर्ज की गयी है। अगस्तमें चीनको निर्यात २२ प्रतिशत घटा है, जबकि आयात १५.५५ प्रतिशत बढ़ा है। चीनसे १०.८ अरब डालर के सामान आयात किये गये। भारत-चीनके बीच सम्बन्धोंमें कटुताके बावजूद चीनी वस्तुओंका आयात बढ़ना अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार अगस्त माहमें सोनेका आयात दोगुनेसे अधिक १०.०६ अरब डालरके रिकार्ड उच्च स्तरपर पहुंच गया। इससे व्यापार घाटा बढ़ा है। यह सत्य है कि मौजूदा वैश्विक स्थितिमें निर्यात कारोबारके समक्ष बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो गयी हैं। अमेरिकामें जारी मंदीसे निर्यातपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चीनमें भी मंदीकी आशंका है। इसलिए भारतको अब निर्यात बढ़ानेके लिए नये बाजारोंको खोलना होगा तभी व्यापार घाटेको कम किया जा सकता है।

## जांचकी गोपनीयता जरूरी

कोलकाताके आरजी कर मेडिकल कालेज और अस्पतालमें जूनियर डाक्टरसे दुष्कर्म और हत्याके मामलेमें सर्वोच्च न्यायालयका यह कहना अत्यन्त महत्वपूर्ण और हैरान करनेवाला है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की स्थिति रिपोर्ट परेशान करनेवाली है। इससे इतना तो स्ष्ट है कि मामला गम्भीरसे गम्भीरतम है जिसमें बहुत कुछ छिपानेकी कोशिश की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रकी पीठका यह निर्देश हर किसीकी जिज्ञासा बढ़ानेवाला है कि जांचसे जुड़ा कोई और खुलासा सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। इसीके साथ शीर्ष न्यायालयने रिपोर्टमें दी गयी जानकारीका खुलासा करनेसे यह कहकर इनकार कर दिया कि इससे आगेकी जांच खतरेमें पड़ सकती है। सीबीआई जांच रिपोर्टमें काफी कुछ कहा गया है जो पहले सार्वजनिक हो चुका है लेकिन इस रिपोर्टमें कही गयी बातोंको उजागर करना जांचको प्रभावित करना है। पीठका सीबीआईको अस्पतालमें वित्तीय अनियमितताओंपर भी जांचकी रिपोर्ट दाखिल करनेका निर्देश भी महत्वपूर्ण है। इस क्रूरतम हत्याके मामलेमें जब्ती सूची और अपराध स्थलके रेखाचित्रमें विसंगतियोंपरपीठकी चिन्ता स्वाभाविक है। सचाईको सामने लानेके लिए जांच एजेंसीको समय देनेका निर्णय उचित है। डाक्टरोंकी सुरक्षाके सम्बन्धमें बंगाल सरकारने जो अधिसूचना जारी की है उसमें महिला डाक्टरोंको रात्रिमें ड्यूटी नहीं करने और उनकी शिफ्ट १२ घण्टेसे ज्यादा नहीं होनेकी बात कही गयी है जिसे शीर्ष न्यायालयने सिरेसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार महिला डाक्टरोंको रातमें काम करनेसे नहीं रोक सकती, न ही १२ घण्टेसे अधिक काम करनेपर रोक लगायी जा सकती है। शीर्ष अदालतका पश्चिम बंगाल सरकारके प्रति कड़ा रुख सही है। सरकारको पाबन्दीकी बजाय महिलाओंकी सुरक्षापर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। सीबीआईकी जांच रिपोर्ट और शीर्ष न्यायालयकी टिप्पणीसे इतना तो तय है कि आरजी कर अस्पतालकी वारदात साधारण या आकस्मिक नहीं है, बल्कि सोची-समझी साजिश है जिसकी सचाई उजागर होनी ही चाहिए।

## लोक संवाद

### बालमनमें विध्वंसकी चाहत

महोदय,-पिछले दिनों बिहारके सुपौलसे एक दहलाती खबर आयी, बैगमें पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंचा नर्सरीका बच्चा, तीसरी कक्षाके छात्रपर चलायी गोली। कानपुरकी एक खबर है कि यहां दसवींके छात्रने कक्षामें सहपाठीकी चाकूसे गोदकर हत्या कर दी। ऐसे समाचार हमें बेचैन कर देते हैं, जहां बच्चे या किशोर किसी हिंसा अथवा गम्भीर अपराधकी दिशामें अग्रसर दिखते हैं। मनमें स्वाभाविक सवाल उठता है कि जिस बालमनमें रंग-बिरंगी कल्पना और जिज्ञासाओंका निवास होना चाहिए, वहां अपराधकी दखलअंदाजी क्यों मानते हैं कि किशोरावस्थाकी ओर बढ़ते बच्चोंमें तेजीसे हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इस स्थितिमें फिल्मों और टेलीविजनमें दिखाये जानेवाले दृश्य उनके दिमागमें बैठ जाते हैं और वे उसी तरह प्रतिक्रिया देने लगते हैं। बालहिंसाके प्रकरण भी ऐसे किसी दृश्यके नकलके दुष्परिणाम होते हैं। दरअसल ऐसी घटनाओंके पीछे और भी कई उलझे मनो-सामाजिक द्वंद्व होते हैं। पहले किशोरावस्थाकी दिशामें बढ़ते बच्चोंमें हार्मोनल परिवर्तनकी आयु १२ वर्षके आसपास शुरू होती थी, तब किन्हीं बच्चोंमें एनिमल इंस्टिंक्ट्स प्रबल हो जाया करते थे। ये गुस्सैल, आक्रामक, चिड़चिड़े और आत्मनियंत्रणमें कमजोर होते थे। परन्तु अब जो निष्कर्ष सामने आ रहे हैं, उनके अनुसार झंझावातकी अवस्था डेढ़-दो वर्ष पहले ही आने लगी है। इसका कारण है, प्रकृतिसे कटा कृत्रिम जीवन, भौतिकवादसे उपजी जीवनशैली, रेडीमेड खानपान, बच्चोंमें बढ़ता अकेलापन और सूचना विस्फोट। सुपौल वाली घटनाका बच्चा तो मात्र पांच सालका है। संभवत: यह उन बच्चोंमेंसे हो सकता है जो अपना अधिक समय टीवीके आगे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मपर बिता रहे हैं। इस श्रेणीमें निम्नवर्गके बच्चे भी शामिल हैं। इनके परिवारमें स्मार्टफोन भले ही न हो, लेकिन अपने मध्यवर्गीय मित्रोंके बीच यह भी मोबाइलमें उपलब्ध वयस्क कंटेंट या क्राइम थ्रिलरका मजा लेनेमें पीछे नहीं रहते हैं। फिल्म, टीवीके क्राइमपर आधारित धारावाहिक और वीडियो गेमकी मारधाड़ और खूनखराबेको बार-बार देखनेवाला बच्चा हिंसाके प्रति संवेदनशून्य हो जाता है और हिंसात्मक कृत्य उसके लिए आनंदकी सामग्री बन जाते हैं। आजके बचपनकी स्थितियोंको लेकर जब हम अपने आसपास गंभीरतासे दृष्टिपात करते हैं तो बच्चोंका पूरा माहौल ही संवेदनाओंसे कटा हुआ मिलता है। शिक्षा यांत्रिक हो चुकी है, यह बच्चोंको तेज दिमागवाला रोबोट बनाने में लगी है। अध्यापकके सामने भारी-भरकम पाठ्यक्रम पूरा करनेकी जिम्मेदारी है और विद्यार्थीके सामने इसे याद करनेकी चुनौती! छात्र-अध्यापकके बीच होनेवाले अनौपचारिक संवाद समाप्तप्राय हैं। पारिवारिक परिवेशमें आये बदलाव भी बच्चेपर गलत असर डाल रहे हैं। पहले बच्चे अपना अधिकतर समय परिवारके सदस्योंके बीच बिताते थे। माता-पिता, दादा-दादीसे उनका सघन संवाद हुआ करता था। उन्हें भरपूर प्यार मिलता था तो गलतीपर डांट भी! किन्तु अब ऐसा नहीं है। रवींद्रनाथ ठाकुरका कथन है बच्चोंका सम्पूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास प्रकृतिकी गोदमें ही संभव है। इस कथनके पीछे बच्चोंके मनमें संवेदनात्मक और नैतिकताका भाव भरनेका विचार था। बच्चे प्रकृतिसे कोमलता और उदारता सीखते हैं। पहले पारिवारिक जीवनमें कई परम्पराएं थीं, जो बच्चोंको परिवेशसे जोड़ती थीं। रसोईमें सिंकनेवाली पहली रोटी गायकी और आखिरी रोटी कुत्तेको दी जाती थी। बुजुर्ग चींटियोंके बिलके आसपास आटा डालते थे। झारने-बीननेके बाद जो मरियल अनाज बचता था, उसे चिड़ियोंके चुगनेके लिए पेड़के नीचे डालनेकी परंपरा थी। छोटे बच्चोंके लिए इसमें भरपूर रोचकता थी। इससे वे गाय, कुत्ता, चींटी, चिड़ियासे ही नहीं, बल्कि धीरे-धीरे ढेर सारे जीव-जंतुओं, वनस्पति, नदी, पहाड़, झरनेसे जुड़ते थे। इनको लेकर वे ढेर सारी कल्पनाएं करते थे। उनकी कल्पनाएं बेसिर-पैरकी होती थीं, लेकिन यह उनके दिमागको झाड़-पोंछकर साफ और सक्रिय रखती थीं। आज कहा जाने लगा है कि दुनिया तर्क, विज्ञान, सूचना और वास्तविकतापर टिकी है। यथार्थके नामपर कल्पना, किस्से-कहानियों और कविताको भी खारिज कर दिया गया है। कल्पनाविहीन सृजनात्मकताकी दुनियामें नैसर्गिकताका अभाव है। परिणामत: हर दिन ऐसा कुछ घटित हो रहा है, जो हमें चौंकाता है। जबकि बचपनकी उमंगों भरी हरकतें ही एक मजबूत व्यक्तित्वका निर्माण करती हैं। मजबूत व्यक्तित्व आक्रामक, गुस्सैल और हिंसक नहीं होता, बल्कि वह सृजनशील होता है और सृजनात्मकता कल्पनाकी देन होती है। बचपनको कृत्रिम बेड़ियोंसे मुक्त करके सहज भावसे जीने दें, जिसमें पढ़ाईके साथ खेलकूद और यारी-दोस्तीकी मस्ती हो, साथ ही प्रेम भरे स्नेहिल अहसास भी! बस इतनेसे ही बच्चोंके मनमें घर करती विध्वंसकी धुंध साफ होने लगेगी। -**दिनेश प्रताप सिंह, वाया ईमेल।**

# एक देश, एक चुनावकी अमृत उपलब्धि

**केंद्रीय मंत्रिमंडलने देशमें लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायोंके चुनाव एक साथ करानेके मोदी सरकारके महत्वाकांक्षी लक्ष्य एक देश, एक चुनाव को लागू करनेके संबंधमें महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस बारेमें रामनाथ कोविंद समितिकी सिफारिशोंको मंजूरी दे दी। यह विकसित भारतके संकल्पका मुख्य आधार बन सकता है।**

❐ **एल गर्ग**

**दो** बड़े दलोंमेंसे एक जेडीयूने मोदीके एक देश एक चुनाववाले इरादेपर सहमति जता दी है। कहा गया कि राजग सरकार अपने वर्तमान कार्यकालके भीतर इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधारको लागू करानेको लेकर आशावादी है और उसके इस आशावादमें देशको एक नयी दिशा मिल सकेगी। भारतकी वर्तमान चुनावी प्रणालीमें निहित कई चुनौतियोंका समाधान करनेके लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा एक सम्भावित समाधानके रूपमें उभरी है। शासनके सभी स्तरों- पंचायत, नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीयमें एक साथ चुनाव करानेसे खर्चमें कमी, प्रभावशीलता और प्रशासनिक दक्षतासे लेकर बेहतर शासन और नीति निरन्तरतातक कई लाभ मिल सकते हैं। यह नये भारत, सशक्त भारत एवं विकसित भारतके संकल्पको आकार देनेका मुख्य आधार बन सकता है एवं आजादीके अमृतकालकी एक अमृत उपलब्धि बनकर सामने आ सकता है। भले ही स्पष्ट बहुमतके अभावमें नरेन्द्र मोदीके नेतृत्वमें राजगकी तीसरी पारीमें बदलावकारी फैसले लेना उतना सहज नहीं रह गया है, जितना पहली-दूसरी पारीमें नजर आता था। लेकिन भाजपाकी सरकार इतनी भी कमजोर नहीं है कि अपने चुनावी वायदों एवं विकासमूलक कार्ययोजनाओंको लागू न कर सके। नरेन्द्र मोदी जैसा साहसी एवं करिश्माई नेतृत्व है तो उसके द्वारा देशहितकी योजनाओंमें आनेवाले अवरोध वह दूर कर ही लेंगे। एक दशककी विकासमूलक कार्यशैलीके बाद अब भी भाजपा अपने सहयोगी दलोंके साथ मिलकर अपनी योजनाओंको अंजामतक पहुंचानेमें जुटी है। भले ही भाजपा-सरकार कई मुद्दोंपर यू टर्न लेते हुए भी नजर आयी। फिलहाल लोकसभामें पहलेके मुकाबले कमजोर स्थिति होनेके बावजूद खुदको साहसिक निर्णय लेनेवाली पार्टीके रूपमें एक बार फिर अपने एक मुख्य एजेंडे एक राष्ट्र, एक चुनावको आकार देनेके लिए तत्पर हो गयी है। इसके लिए सरकारने पक्ष-विपक्षके सभी नेताओंसे एक साथ आनेका अनुरोध किया था। निस्संदेह एक राष्ट्र, एक चुनावके लिए भाजपा द्वारा नयी पहल किये जानेके निहितार्थ राजनीतिसे ज्यादा राष्ट्रहितमें है। निश्चिय ही एक देश एक चुनावकी योजनाको लागू करना राजगके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस बार विपक्ष पहलेके मुकाबले मजबूत भी है और एकजुट भी है। इसमें दो राय नहीं कि यह बात तार्किक है कि एक राष्ट्र, एक चुनावका प्रयास शासनमें सुनिश्चितता लायगा। वहीं बार-बारके चुनाव खर्चीले होते हैं। दूसरे राज्य-दर-राज्य लम्बी आचार संहिता लागू होनेसे विकास कार्य भी बाधित होते हैं। साथ ही साथ शासन-प्रशासन एवं सुरक्षा बलोंकी ऊर्जाके क्षयके अलावा जनशक्तिका अनावश्यक व्यय होता है। विगत लोकसभा चुनावोंमें कुल सरकारी खर्च ६६०० करोड़ रुपये आया था जो भारत जैसे विविधतापूर्ण विशाल देशको देखते हुए भले ही जायज कहा जाये, लेकिन बार-बार होनेवाले चुनावोंसे होनेवाले ऐसे भारी-भरकम खर्चे देशकी अर्थव्यवस्थापर बोझ तो डालते ही है। भारतमें भ्रष्टाचारकी जड़ भी महंगी होती चुनाव व्यवस्था है, क्योंकि जब करोड़ों रुपये खर्च करके कोई विधानसभा या लोकसभाका प्रत्याशी जन-प्रतिनिधि बनेगा तो वह विजयी होनेके बाद सबसे पहले अपने भारी खर्चकी भरपाई करनेकी कोशिश करेगा। अत: असलमें बात सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्थाके सुधारकी होनी चाहिए। परन्तु इसकी बात करनेपर सभी राजनीतिक दलोंमें एक सन्नाटा पसर जाता है। पक्ष एवं विपक्षको अपने राजनीतिक हितोंकी बजाय देशहितको सामने रखकर आम सहमति बनानी चाहिए। पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनावके लिए एक साथ चुनावी मशीनरी तथा सुरक्षाबलोंकी उपलब्धताके यक्ष प्रश्नको भी सामने रखकर इसपर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए और इसके सभी पहलुओंको ध्यानमें रखते हुए आम सहमति बनानेका प्रयास किया जाना चाहिए। दुनियाके सबसे बड़े लोकतंत्रके रूपमें, भारत हमेशासे राजनीतिक विचारधाराओं, विविध संस्कृतियों और विशाल आबादीका मिश्रण रहा है। हर गुजरते चुनाव चक्रके साथ, राष्ट्र लोकतांत्रिक उत्साहका महाकुंभ देखता है, जहां लाखों लोग अपने वोटके अधिकारका प्रयोग करते हैं और अपने प्रतिनिधियोंको चुनते हैं। हालांकि इस जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रियाके बीच, विभिन्न स्तरों-स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीयपर चुनावोंके समन्वयको लेकर बहसने हालके वर्षोंमें काफी जोर पकड़ा है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने अपने एक दशकके शासन एवं पिछले महीने स्वतंत्रता दिवसके अवसरपर लाल किलेकी प्राचीरसे किये गये अपने संबोधनमें एक देश, एक चुनावकी जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार-बार चुनाव होनेसे देशकी प्रगतिमें बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने राजनीतिक दलोंसे लाल किलेसे और राष्ट्रीय तिरंगेको साक्षी मानकर राष्ट्रकी प्रगति सुनिश्चित करनेका आग्रह किया था। हालमें संपन्न लोकसभा चुनावसे पहले भाजपा द्वारा जारी चुनाव घोषणापत्रमें उसने एक देश, एक चुनावको प्रमुख वादोंके रूपमें शामिल किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदकी अध्यक्षतामें गठित एक उच्चस्तरीय समितिने इस साल मार्चमें पहले कदमके रूपमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओंके लिए एक साथ चुनाव करानेकी सिफारिश की। समितिने राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलोंके साथ परामर्श किया और संभावित अनुशंसाओंके साथ आम लोगों एवं न्यायविदोंके विचार आमंत्रित किये। समितिने लोकसभा और विधानसभा चुनावके सौ दिनोंके भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराये जानेकी भी सिफारिश की। इसके अलावा, विधि आयोग भी २०२९ से एक साथ चुनाव करानेकी सिफारिश कर सकता है। बात सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्थाके सुधारकी होनी चाहिए। परन्तु इसपर सभी राजनीतिक दलोंके सामने निजी हित एवं चुनाव जीतनेका गणित सामने आ जाता है। भारतकी असली विडम्बना यही है। जब भी सरकारी खर्चेसे चुनाव करानेकी बात होती है तो इस राहको अव्यावहारिक बता दिया जाता है। जबकि जर्मनी जैसे लोकतन्त्रमें यह प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है। दक्षिण अफ्रीकामें राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलोंके चुनाव एक साथ प्रत्येक पांच वर्षपर आयोजित किये जाते हैं, जबकि नगर निकाय चुनाव प्रत्येक दो वर्षपर आयोजित किये जाते हैं। स्वीडनमें राष्ट्रीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल/काउंटी कौंसिल और स्थानीय निकायों/नगर निकाय सभाओंके चुनाव एक निश्चित तिथि, यानी हर चौथे वर्ष सितंबरके दूसरे रविवारको आयोजित किये जाते हैं। ब्रिटेनमें ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकालको स्थिरता एवं पूर्वानुमेयताकी भावना प्रदान करनेके लिए निश्चित अवधि संसद अधिनियम, २०११ पारित किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया कि प्रथम चुनाव ७ मई २०१५ को और उसके बाद हर पांचवें वर्ष मई माहके पहले गुरुवारको आयोजित किया जायगा। जब दुनियाके अनेक देशोंमें एक राष्ट्र, एक चुनावकी परम्परा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है तो भारतमें इसे लागू करनेमें इतने किन्तु-परन्तु क्यों है। देशमें इसे लागू करनेसे सरकार हर समय चुनावी मोडमें रहनेके बजाय शासनपर अधिक ध्यान केन्द्रित कर सकती है। इससे समय एवं संसाधनोंकी भी बचत होगी। एक साथ चुनाव करानेसे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगोंके लिए एक साथ कई मत डालना आसान हो जायगा। इन सब स्थितियोंके साथ-साथ एक साथ चुनाव कराये जानेपर क्षेत्रीय पार्टियोंको होनेवाले नुकसान एवं अन्य स्थितियोंपर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि एक आदर्श एवं सशक्त लोकतंत्रमें सभी राजनीतिक दलोंके लिए समान अवसर उपलब्ध होना भी जरूरी है।




**जब दुनियाके अनेक देशोंमें एक राष्ट्र, एक चुनावकी परम्परा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है तो भारतमें इसे लागू करनेमें इतने किन्तु-परन्तु क्यों है। इसे लागू करनेसे सरकार हर समय चुनावी मोडमें रहनेके बजाय शासनपर अधिक ध्यान केन्द्रित कर सकती है। इससे समय एवं संसाधनोंकी भी बचत होगी। एक साथ चुनाव करानेसे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगोंके लिए एक साथ कई मत डालना आसान हो जायगा। एक आदर्श एवं सशक्त लोकतंत्रमें सभी राजनीतिक दलोंके लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकेगा।**

# सनातन परम्परा है श्राद्ध और तर्पण

**कहा गया है ऋषियोंसे पितरोंकी उत्पत्ति हुई। पितरोंने देवताओं और मनुष्योंको जन्म दिया और देवोंसे क्रमशः चर और अचर संसार उत्पन्न हुआ। मनुःस्मृतिमें कहा गया है- देवता, पितर और मनुष्योंके लिए वेदका ज्ञान शाश्वत है।**

❐ **शकुन्तला देवी**

**वै** दिक और पौराणिक परम्परामें श्राद्ध और तर्पण सनातन परम्पराका हिस्सा है। वेदों, गृहसूत्रों, धर्म सूत्रों और पुराणोंमें इस विषयमें अनेक तरहका वर्णन किया गया है। वेदोंमें पितर और उनके तर्पणके बारेमें अनेक मंत्र हैं। जिनमें यजुर्वेद मंत्रका विशेष उदाहरण दिया जाता है। मंत्र है-पितृभ्य: स्वधायेभ्य: स्वधा नम:। पितर: पितर: शुन्धध्वम्। यानी स्वधाके अधिकारी स्वधायी पिता, पितामह, प्रपितामह लोगोंको अन्न जल सत्कारपूर्वक दिया जाय। वे मोद मनाते तृप्त (तर्पण) और सन्तुष्ट हों और हमें पवित्र करें। यह मंत्र यह बताता है कि जीवित माता-पिताकी सेवा-सत्कार उन्हें हर तरहसे सन्तुष्ट करना ही श्राद्ध और तर्पण है। गौरतलब है पौराणिक परम्परामें आश्विन मासके पितृपक्षमें श्राद्ध-तर्पण कर्मकांडकी पुरातन परम्परा है। शास्त्रमें पितरोंके बारह स्थानोंपर रहनेका वर्णन है जिसमें वह स्थान जहां माता-पितादि रहते, प्रमुख हैं और राष्ट्ररक्षामें वृद्धजनोंकी रक्षा एवं पालन-पोषण करनेवाला विभाग पितृलोक कहा गया है। वैदिक और पौराणिक कर्मकांडोंका मानव जीवनके साथ गहरा रिश्ता है। सोलह संस्कारों और प्रतिदिन किये जानेवाले पंचयज्ञोंसे जीवनको पूर्ण बनानेका विधान वेद-शास्त्रोंमें बेहतर तरीकेसे विस्तारसे किया गया है। इन्हीं पंच यज्ञोंमें ब्रह्मयज्ञ (ईश्वरकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना) पितृयज्ञ (माता-पिता एवं बड़ोंकी सेवा) अतिथि यज्ञ (आये हुए महमानोंका सम्मान), देव यज्ञ (यज्ञ-हवन) और भूतयज्ञ (प्राणियोंको जल एवं भोजन देना) का विधान किया गया है। शास्त्रीय विधानके अनुसार श्रत् सत्यं दधाति यया क्रियया साश्रद्धा, श्रद्धया यत क्रियते तच्छाद्धम्। यानी जिस कर्म या क्रियासे सत्यका ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और श्रद्धाके साथ जो कर्म किया जाय उसे श्राद्ध कहते हैं। तर्पणके सम्बंधमें वेदका विचार है कि 'तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत् तर्पणम्। यानी जिस-जिस कर्मसे माता-पिता एवं गुरुजन सुखी या प्रसन्न हों उसे तर्पण कहा गया है। श्राद्ध और तर्पणका वैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्ष भी है। पौराणिक परम्परामें क्वार (अश्विन माह)में श्राद्ध और तर्पणका विधान कर्मकांडके रूपमें किये जानेकी परम्परा है। श्राद्ध और तर्पणका वैदिक और पौराणिक विधान अलग-अलग तरहका है। संस्कृतमें पिताका बहुवचन पितर कहलाता है। मनु:स्मृतिमें कहा गया है, ऋषय: पितरो देवा भूतान्यतियस्तथा। आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्य: कार्य विजानता। यानी ऋषिगण, पितर, देव, प्राणी तथा अतिथि लोग गृहस्थजनोंसे ही पोषण पानेकी आशा करते हैं। वहींपर अथर्ववेदमें कहा गया है-स्वधां पितृभ्य: अमृत: दुहाना आपोदेवीरुभययंस्तर्पयन्तु। यानी शक्तिवर्द्धक मिष्ठान्न, फल, शी, दूध एवं अन्नजलादि सब पदार्थ स्वधा होकर मेरे पितरोंको तृप्त करें। पितरोंके लिए श्रद्धाके साथ किये जानेवाला कर्तव्य 'श्राद्ध' कहा गया है और उन्हें हर तरहसे संतुष्ट यानी तृप्त करना 'तर्पण' कहा गया है। वेदोंमें पिता या पितर शब्द रक्षा करने, पालन करने और जन्म देनेवालेके अर्थमें आया है। शतपथ ब्राह्मणमें कहा गया है-'योऽपक्षीयते स पितर:' यानी जो कमजोर हों वे पितर हैं। वेदमें पितरकी विस्तारसे चर्चा की गयी है, जिसमें पितृलोककी बात कही गयी है। पितृलोकका मतलब पितरोंके विभाग और रहने की जगह पितर लोक है। यानी परिवारमें माता-पिता जहां रहते हैं वही पितृलोक है। यजुर्वेदमें कहा गया है- स्वयंकी आधारित शक्ति और ज्ञान भाग और स्वभाव 'स्वधा' कहा गया है। स्वधाका विस्तार करते हुए कहा गया है, जो स्वधाके अधिकारी पिता, पितामह (बाबा) प्रपितामह (परबाबा) जो जीवित हों, उन्हें श्रद्धा और भक्तिके साथ भोजन, वस्त्र और अन्य जरूरी चीजें देकर तृप्त करना भी आवश्यक है। इससे स्व-कर्तव्यका पालन होता है। पुराणोंमें श्राद्ध और तर्पणके बारेमें विस्तारसे वर्णन किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराणमें पितरका विस्तारसे वर्णन किया गया है। श्लोकमें कहा गया है अन्न देनेवाला, भयसे रक्षा करनेवाला, विद्या देनेवाला, पत्नीका पिता और जन्म देनेवाला, ये पांच मनुष्यको पितर या पिता कहा गया हैं। सनातन परम्पराओंमें कुछ परम्पराएं आज भी जीवित हैं। पौराणिक परम्परामें श्राद्ध एवं तर्पण अश्विन महीनेमें गया जाकर स्वर्गलोक गये परिवारके पूर्वजोंके लिए पिंडदान करनेकी परम्परा है। सिरके बाल साफ कर पन्द्रह दिनतक जलांजलि देकर पूर्वजोंके प्रति श्रद्धाका भाव रखना खास बताया गया है। इसके अलावा कुत्ता-चींटी, कौवे और दूसरे प्राणियोंको भोजन खिलानेकी परम्परा है। इसमें इसे बहाने परिवारके पूर्वजोंको याद कर उनके कार्योंके प्रति नतमस्तक होनेका भी यह पक्ष रखा गया है। सारे कर्मकांड श्रद्धा-भक्तिके साथ करना चाहिए। इससे परिजनोंके प्रति कृतज्ञताका भाव जागृत होता है। अच्छी परम्परापर आगे बढ़ानेके लिए भी यह पक्ष जाना जाता है। शास्त्रके अनुसार संतानको चाहिए है पितरोंके प्रति शास्त्रसम्मत कर्तव्यको करते हुए उन्हें हर तरहसे सन्तुष्ट करे। वेदमें इन कर्तव्योंको इस तरह समझाया गया है। यज्ञ यानी परोपकार करना, ज्ञान हासिल कर उनके जरूरतके मुताबिक उन्हें उनका भाग देना। माता-पिता एवं आचार्यका किसी भी तरह अनादर न करना और उनके साथ सम्माननीय व्यवहार करना, कृतज्ञता प्रकट करना और उनके अनुभवोंका लाभ लेना, राष्ट्र रक्षामें निपुण लोगोंके लिए भोजन और आवासकी व्यवस्था करना। परिवार एवं समाजके सभी उन ज्ञानीजनोंके लिए स्थायी जीविकाकी व्यवस्था करना। वेदमें पितरोंके खास तरहके कर्तव्य गिनाये गये हैं, जिसमें संतान पैदा करना, उनका पालन-पोषण करना, उनको उनकी प्रतिभा एवं योग्यताके मुताबिक शिक्षा-दीक्षा देना प्रथम कर्तव्य बताया गया है और अन्य कर्तव्योंमें ज्ञानी पितर विद्याका दान, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास तथा आत्मिक विकास करना है। युद्धकला, राष्ट्ररक्षा, शत्रुओंका दमन और संतानको वीर साहसी योद्धा बनानेवाले कार्योंको करते रहनेका भी विधान है। आज पितृ पक्षपर महज बाल बनवाने, पंडितको दान देने, हवन और पक्षियोंको चारा देनेतक सीमित हो गया है। इसकी शुरुआत एक आदर्श परिवार और समाज निर्माणके लिए की गयी थी, लेकिन सनातन वैदिक परम्पराका मूल स्वरूप कहीं गायब हो गया है। यदि नयी पीढ़ी धर्म शास्त्रों और अध्यात्मकी किताबोंको मन लगाकर पढ़े तो इस खास पर्व और उत्सवकी बेहतर जानकारी हो सकती है। सनातन परम्परामें यज्ञोंका खास अहमियत है। वैदिक परम्पराके मुताबिक प्रतिदिन जिन कर्तव्योंको करनेकी बात कही गयी है उनमें 'पितृयज्ञ' भी है जो रोज करना जरूरी है, वरना पाप लगता है। इस नजरियेसे भी श्राद्ध और तर्पण करना ही पितृयज्ञ है। यही सच्चे मायनेमें श्राद्ध और तर्पण है जिसे प्रतिदिन करनेका वैदिक विधान वेदोंमें बताया गया है। जैसे संतानका कर्तव्य पितरोंको श्रद्धा एवं भक्तिसे हर तरहसे तृप्त करना है उसी तरह संतानके प्रति पितरोंका भी कर्तव्य वेदमें बताया गया है। इसलिए जब तक पितर संतानके लिए और संतान पितरके लिए अपने कर्तव्य पूरा नहीं करते तबतक श्राद्ध और तर्पणकी क्रिया पूरी नहीं होती है।




## मोक्षकी प्राप्ति

❐ **धर्मेश कुशवाहा**

**म** नुष्यमें जब ज्ञान प्रस्फुटित होने लगता है या संसारसे मोह भंग हो जाता है तब वह संसार चक्रसे बाहर निकलेके लिए कोशिश करने लगता है और मोक्षके लिए प्रयत्न करता है। मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब नश्वर चीजोंसे मोह भंग हो जाये। मोहका क्षय ही मोक्षकी स्थिति है। संसार चक्रसे निकलनेके लिए मनुष्यको सतत स्वको जाननेकी कोशिश करनी चाहिए। स्वको जाननेके बाद ही परम तत्वको समझना आसान होगा और मोक्षका द्वार खुलेगा। संसारमें रहते हुए भी बंधनसे मुक्त रहेगा। इसलिए परमतत्व समझना आवश्यक है। इसके लिए सतत् चिंजन आवश्यक है। परमतत्व हमारे ही शरीरके अन्दर ही स्थित है। पुराणके अनुसार शरीरको पुर कहा जाता है। कोई पुर (संपूर्ण अंग) तभी पुर कहलाता है जिसमें द्वारपाल और उसका अधिष्ठाता(संभालने वाला) आदि अनेकों पुर संबंधी सामग्री उपलब्ध रहता है यह सब शरीरमें दिखाई देनेके कारण शरीर पुर कहलाता है। जिस प्रकार सम्पूर्ण सामग्रीके सहित संसारमें प्रत्येक शरीर अपनेसे बिना मिले हुए स्वतंत्र उपभोगके देखा जाता है। इस प्रकार अनेक संपन्न पृथक पुर आत्माके लिए होना चाहिए। (तच्चेदम शरीराख्यम पुरमेकादश द्वारमेकाश दश द्वाराण्यश्य सप्तशिर्षण्यानीनाभ्या सहार्वाञ्चीत्रिणी शिरस्येकम तैरेकादशद्वारम पुरम।) उपरोक्त कथन कठोपनिषद्के अनुसार यह शरीर नामक पुर ग्यारह दरवाजोंवाला है इसमें दो आंख, दो कान, दो नासारंध्र, एक मुख इस प्रकार सात उसके साथ मस्तक संबंधी, नाभि सहित उपदस्थ और गुदा तीन निम्नदेशीय तथा एक (ब्रह्मरंध्ररूप) सिरमें रहनेवाला इसी प्रकार सभी द्वारोंसे संयुक्त शरीर रूपी पुर एकादश द्वारवाला कहलाता है। यह पुर किसका है इसपर कठोपनिषदमें कहते है अजका है अर्थात् पुरके धर्मोंसे विलक्षण जन्म और मृत्यु आदि विकारोंसे रहित आत्माका है। इसके सिवाय जिसका चित्त चंचल, छल रहित, सत्य, दया, क्षमा, अडिग एकरूप है उसी परमतत्वका है। जिसका यह शरीर है उसके स्वामीको यानी परमतत्वका ही ध्यान अनुष्ठान करके जाना जा सकता है, क्योंकि समग्र परमतत्वके ध्यानमें अपनेको अर्पण करना उसका अनुष्ठान है। जब प्राणी सभी प्रकारके रसेंद्रीय विषयेंद्रीयको नियंत्रणमें रखकर सभी भूतों (संसार) में स्थित परमतत्वका चिंतन करता है उसी समय प्राणीको आनन्दकी प्राप्ति होती है। परमतत्वकी जानकारीसे अभय प्राप्त होता है। जिससे प्राणी शोक रहित होता है जब प्राणी शोक रहित हो जाता है तो भय दर्शन इसको कभी भी नहीं हो सकता है। प्राणी इस संसारमें अविद्याकृत काम और कर्म बंधनोंसे मुक्त हो जाता है इस प्रकार जीव संसार चक्रसे छूट जाता है। इसीको मोक्ष कहते हैं।

# सुनहरे सपनेके लिए विदेश गमनका मोह

❐ **सुरेश सेठ**

**भा** रतकी युवा आबादी पूरी कार्यशील आबादीका आधा हिस्सा है। कार्यशील, क्योंकि देशमें एक बड़ी संख्या ऐसी है जो सकल घरेलू उत्पादमें योगदान नहीं देती। देशकी आधी आबादी महिलाएं हैं और आर्थिक विशेषज्ञोंका मानना है कि हम उनकी क्षमताओंका आधेसे भी कम उपयोग कर रहे हैं। यदि हम इस शक्तिका प्रभावी ढंगसे उपयोग करें तो संभव है कि भारत दुनियाकी तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बननेमें बहुत कम समय ले। ३५ सालतककी उम्रकी आबादी देशकी वह श्रेणी है जिसमें काम करनेकी पूरी सामर्थ्य होती है। लेकिन इस सामर्थ्यका उचित उपयोग देशमें नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रोंमें छिपी हुई बेरोजगारी एक ज्ञात समस्या है। जब नौजवान खेतोंमें काम करते हैं तो इससे खेतोंकी कुल आयमें कोई वृद्धि नहीं होती। इसका मतलब यह है कि यदि ये लोग खेतोंको छोड़कर किसी अन्य व्यवसायमें चले जायं तो कृषिके स्तरपर कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं आयगी। लेकिन सवाल यह है कि वे जायं कहां। देशमें कोविड महामारीकी मारसे प्रभावित महानगरोंकी कामगार आबादी, जो गांवोंमें आश्रय खोजने आयी थी, अब भी उसी तलाशमें है। दावोंके बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्थामें न तो लघु और कुटीर उद्योगोंका विकास हुआ है और न ही फसलोंके विनिर्माणकी छोटी-छोटी फिनिश्ड पार्टिकल बनानेवाली फैक्टरियां कस्बोंमें स्थापित हो पायी हैं। डिजिटल भारतके युगमें निवेशकोंकी अपेक्षाएं इतनी बदल गयी हैं कि विश्वविद्यालयोंसे पारम्परिक शिक्षा प्राप्त करनेवाले युवा खुदको बेकार महसूस करते हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। जैसे-जैसे रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतमें अपनी जड़ें जमा रही हैं, इस आबादीके लिए उचित रोजगार पानेमें और भी कठिनाई होगी। अब नौजवानोंका सपना विदेशी मुद्राकी चमकती धरतीकी ओर उड़ान भरना है। खाड़ी देशोंके दीनार भी उन्हें लुभाते हैं। आर्थिक स्थिति सुधारनेके लिए वे इन देशोंकी ओर पलायनका सपना देखते हैं। इस बीच कई एजेंसियां भारतमें उभर आयी हैं, जो वैध या अवैध तरीकेसे विदेश भेजनेका दावा करती हैं। पिछले सालसे कनाडा, जो विदेशोंमें सबसे बड़ा आश्रय देनेवाला देश माना जाता है, ने भारतसे पलायन करनेवाले युवाओंके लिए अपनी नीतियोंमें बदलाव किया है। अब कनाडामें भारतसे आनेवाले छात्रोंके लिए वीजाकी संख्या ३.६ लाखतक सीमित कर दी गयी है और उनके आव्रजनकी लागत भी बढ़कर २२-२३ लाख रुपयेसे ३७ लाख रुपयेतक पहुंच गयी है। इसके साथ ही, डिग्री पूरी करनेके बाद छात्रोंको अब वहां वर्क परमिटके लिए आवेदन करनेकी अनुमति नहीं दी जा रही है। चाहे यह सूचना पुष्ट हो या अपुष्ट, वास्तविकता यही है कि इंग्लैंड, अमेरिका, और कनाडा अब भी भारतीय युवाओंके पलायनके लिए सबसे आकर्षक स्थल माने जाते हैं, जबकि वैध तरीकेसे जानेकी प्रक्रिया कठिन होती जा रही है, अवैध तरीकेसे पलायन करनेवाले डंकी रूट तेजीसे बढ़ रहे हैं।

पिछले दिनों दावा किया गया कि दिसंबर, २०२३ से अब तक ५००० से अधिक भारतीय अवैध रूपसे कनाडाकी सीमापार करके अमेरिकामें प्रवेश कर चुके हैं। अमेरिकाकी बड़ी सीमा दो प्रमुख स्थानोंपर है- एक मैक्सिकोके साथ और दूसरी कनाडाके साथ। कनाडाकी सीमा लगभग ९००० किलोमीटर लंबी है और इतनी लंबी सीमापर आव्रजनको पूरी तरहसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इसके विपरीत, मैक्सिकोकी सीमा इसके आधे आकारकी है। यही दो सीमाएं हैं जहां अवैध प्रवासनके डंकी रूट प्रचलित हैं। कोशिश यही है कि वहां अवैध तरीकेसे काम करके धीरे-धीरे वर्कफोर्समें शामिल हो जायं। अमेरिकामें उद्यमियोंको ऐसे कार्यबलको बहुत कम दामपर काम पर रखना लाभदायक होता है, जिससे उनके लिए यह एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।

शरण मांगनेवाले भारतीय नागरिकोंकी संख्यामें भी वृद्धि देखी जा रही है। २०२२ से इंग्लैंडमें शरण मांगनेवालोंकी संख्या १३६ प्रतिशत बढ़ गयी है और २०२३ में १३१९ अन्य नागरिकोंने शरण मांगी, जो सभी कनाडासे ट्रांजिट कर अमेरिका पहुंचे थे। ये सभी अवैध तरीकेसे विदेशी जमीनपर अपने ठिकानेकी तलाशमें हैं। दरअसल यह कड़वा सच दिखाता है कि भारतकी तेज आर्थिक वृद्धि दरके बावजूद युवाओंको ठिकाना नहीं मिल रहा है। सम्मानजनक रोजगारकी कमी ही वह कड़वा सच है जो हमारे युवाओंको रोजगारका विदेशोंमें ठिकाना खोजनेको मजबूर कर रहा है।विश्वके कई देशोंने अपनी आव्रजन नीतियां सख्त कर दी हैं, लेकिन अवैध घुसपैठका यह नया धंधा, जो विदेशी सरहदोंसे दूसरे देशोंमें जा रहा है, भारतकी छवि को धूमिल करता है। साथ ही हमारे आर्थिक संघर्षपर सवाल उठाता है। आत्मनिर्भरताका दावा तब पूरा होगा जब हम अपनी युवा शक्तिको उसकी क्षमताओंके अनुसार सम्मानजनक रोजगार प्रदान कर सकें।

## घाटे का सौदा

गठबंधन के मुद्दे पर राहुल गांधी और हरियाणा के पार्टी नेता समान धरातल पर नहीं थे। गांधी संभवतः इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों को एकता का संदेश देना चाहते थे, लेकिन (अति) आत्म-विश्वास से भरपूर प्रदेश नेताओं को यह घाटे का सौदा लगा। अब जाहिर है कि कांग्रेस नेतृत्व ने बिना होम वर्क किए आम आदमी पार्टी के सामने हरियाणा में गठबंधन करने का प्रस्ताव रखा। इस मुद्दे पर राहुल गांधी और हरियाणा के प्रमुख पार्टी नेता समान धरातल पर नहीं थे। गांधी संभवतः इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों को संदेश देने के लिए हरियाणा के चुनाव का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अपनी जीत के (अति) आत्म-विश्वास से भरपूर प्रदेश नेताओं को यह घाटे का सौदा लगा। आखिरकार बात आगे नहीं बढ़ी। इससे इंडिया गठबंधन में कुल मिलाकर नकारात्मक माहौल बना है। आ.आ.पा. नेताओं ने कहा है कि उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें ना देने की जिद किए कांग्रेस नेताओं को चुनाव नतीजा आने पर पछताना होगा। उधर अखिलेश यादव की टिप्पणी भी गौरतलब है। समाजवादी पार्टी के हरियाणा में चुनाव ना लड़ने का एलान करते हुए उन्होंने यह रेखांकित कर दिया कि प्रदेश विशेष में सबसे मजबूत पार्टी गठबंधन के स्वरूप के बारे में तय करे, वे इस सिद्धांत के अनुरूप यह निर्णय ले रहे हैं। परोक्ष रूप से उन्होंने कहा है कि जब बात उत्तर प्रदेश की आएगी, तो वहां कांग्रेस नेताओं को भी इसी सिद्धांत के तहत सपा जो फैसला करे, उसे स्वीकार करना चाहिए। वहां कांग्रेस के उतने दावे को ही सपा स्वीकार करेगी, जो उसके मुताबिक भाजपा को हराने के मकसद से उचित होगा। कुल सूरत यह उभरी है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां भाजपा को हराने के मकसद पर तो एकमत हैं, मगर इसके लिए वे अपने सियासी हितों से समझौता करने को राजी नहीं हैं। इस कारण इस गठबंधन की एकता सीट बंटवारे जैसे मुद्दे को लेकर अनेकता में बदल जाती है। उधर कांग्रेस के बारे में सवाल उठा है कि क्या पार्टी की राज्य इकाइयां केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकताओं से संचालित नहीं होतीं और क्या पार्टी में अंदरूनी संवादहीनता की स्थिति है? कांग्रेस नेतृत्व अगर आखिरी दौर में जाकर गठबंधन की पेशकश नहीं करता, तो ऐसे सवालों से बचा जा सकता था। आखिर आ.आ.पा. ने तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस से गठबंधन खत्म करने का एलान कर दिया था। कांग्रेस ने ही ये मुद्दा फिर जिंदा किया।

## घाटी में बसे दो प्रकार के वर्ग

अब्दुल्ला-मुफ्ती परिवारों का दोहरा मापदंड किसी से छिपा नहीं है। यह लोग जब दिल्ली में होते है, तब सेकुलरवाद, एकता, शांति, भाईचारे की बात करते हुए एकाएक भावुक हो जाते है। किंतु घाटी लौटते ही उनके भाषणों/वक्तव्यों में भारतीय एकता-अखंडता के प्रति घृणा, तो बहुलतावाद-लोकंतत्र विरोधी इस्लामी कट्टरपंथियों के लिए सहानुभूति दिखती है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 18 सितंबर से लेकर एक अक्टूबर के बीच तीन चरणों में संपन्न होंगे। चुनाव का मुद्दा क्या है? क्या कश्मीर वर्ष 2019 से पहले के उस कालखंड में लौटे, जब क्षेत्र में सभी आर्थिक गतिविधियां बंद थी, विकास कार्यों पर लगभग अघोषित प्रतिबंध था, सेना-पुलिसबलों पर लगातार पत्थरबाजी होती थी, गाए-बगाए अलगाववादियों द्वारा बंद बुला लिया जाता था और वातावरण पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे भारत विरोधी नारों से दूषित होता रहता था? या फिर इस केंद्र शासित प्रदेश में बीते पांच वर्षों की भांति वैसी विकास की धारा बहती रहे, जिसके कारण कश्मीर तुलमात्मक रूप से शांत है, देश के शेष हिस्सों की तरह संविधान-कानून का इकबाल है और बहुलतावादी संस्कृति के साथ समरसता से युक्त वातावरण है? यह प्रश्न इसलिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि इस चुनाव में जम्मू-कश्मीर के बड़े क्षत्रप दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, जिसका घोषणापत्र मतदाताओं से वादा करता है कि सत्ता में लौटने पर उस जहरीली धारा 370-35ए को भारतीय संविधान में बहाल करेंगे, जिसके सक्रिय रहते (अगस्त 2019 से पहले) पूरा सूबा अंधकार में था, पर्यटक आने से कतराते थे, सिनेमाघरों पर ताला लगा हुआ था, मजहब केंद्रित आतंकवाद, पाकिस्तान समर्थित अलगाववाद का वर्चस्व था और शेष देश की भांति दलित-वंचितों के साथ आदिवासियों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों (आरक्षण सहित) पर डाका था। धारा 370-35ए के संवैधानिक परिमार्जन के बाद जम्मू-कश्मीर पिछले पांच वर्षों से गुलजार हो रहा है। तिरंगामयी हो चुके श्रीनगर स्थित लालचौक की रौनक देखते ही बनती है। पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तीन दशक से अधिक के लंबे फासले के बाद नए-पुराने सिनेमाघर संचालित हो रहे हैं। देर रात तक लोग प्रसिद्ध शिकारा की सवारी का आनंद ले रहे हैं। स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। दुकानें भी लंबे समय तक खुली रहती हैं। स्थानीय लोगों का जीवनस्तर सुधर रहा है। जिहादी दंश झेलने के बाद वर्षों पहले घाटी छोड़कर गए कश्मीरी पंडित धीरे-धीरे लौटने लगे है। बदली परिस्थिति में जी-20 सम्मेलन हो चुका है, तो फिल्म निर्माता-निर्देशक घाटी की ओर फिर से आकर्षित होने लगे है।

# विपक्ष पर दबाव का केजरीवाली आतिशी दांव



आरती कुमारी

अरविंद केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने राजनीति में कुछ मौलिक प्रतिस्थापनाएं की है, बने-बनाये रास्तों पर न चलकर नये रास्ते इजाद किये हैं। वे संकटों को अवसर में बदलने वाले करिश्माई व्यक्तित्व भी हैं। उनकी राजनीति अनेक विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरी रही है, उनके व्यवहार एवं वचनों में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित होते रहे हैं, लेकिन ये ही विरोधाभास उनकी राजनीतिक चमक का कारण भी बने हैं। क्योंकि राजनीति में सब जायज माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने से खुद को बंधा महसूस करते हुए उन्होंने इस्तीफे का धारदार दांव चलाकर राजनीतिक जगत में एक हलचल पैदा कर दी। वहीं पार्टी में संभावनाओं भरे अनेक चेहरों के होने के बावजूद उन्होंने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वह वरिष्ठता क्रम में निचले पायदान पर खड़ी थी, लेकिन केजरीवाल ऐसे चौंकाने वाले फैसले पहले भी लेते रहे हैं। लेकिन इस तरह वे जनादेश का मज़ाक भी बनाते रहे हैं तो संवैधानिक स्थितियों की धता भी करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहस के कदम एवं चतुराई की आंख लेकर परम्परागत राजनीति की जंजीरों को तोड़कर आगे निकलते रहे हैं। संभावनाएं की जा रही थी कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अधिक संभावनाएं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाये जाने की थी। क्योंकि क्षेत्रीय दलों में किसी राजनीतिक या कानूनी संकट के चलते परिवार के ही किसी सदस्य को सत्ता की बागडोर सौंप देने परंपरा रही है। ताकि स्थितियां सामान्य होने पर फिर मुख्यमंत्री की गद्दी आसानी से वापस ली जा सके। इसके अनेक उदाहरण है, जिनमें बिहार में चारा घोटाले में घिरने के बाद लालू यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता की बागडोर सौंपी थी। बहरहाल, केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही अपने तरकश से जो तीर चले हैं, उनकी धार एवं तीक्ष्णता को महसूस किया जा सकता है। इन तीरों से हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव समेत अन्य राष्ट्रीय मुद्दों में उलझी भाजपा व कांग्रेस पर केजरीवाल ने मनोवैज्ञानिक राजनीतिक दबाव तो बना ही दिया है। हरियाणा में स्वतंत्र चुनाव लड़ने का निर्णय लेकर उन्होंने सत्ता के गठन में स्वयं को एक ताकतवर मोहरे के रूप में प्रस्तुत करने का चतुराई भरा खेल भी खेला है। दिल्ली में भी उन्होंने अपनी निस्तेज होती स्थितियों को मजबूती दी है। दरअसल, केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध में आन्दोलन के योद्धा के रूप में वर्ष 2014 के इस्तीफे के दांव की तरह 2015 में आम आदमी पार्टी को मिली भारी जीत का अध्याय दोहरा देना चाहते हैं। लेकिन इस बार की स्थितियां खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होने से खासी चुनौतीपूर्ण व जोखिमभरी हैं। निस्संदेह, यह दांव मुश्किल भी पैदा कर सकता है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। भले ही केजरीवाल अपने को, समय को पहचानने वाला साबित कर रहे हो, लेकिन वे अपने देश को, अपने पैरों की जमीन को एवं राजनीतिक मूल्यों को नहीं पहचान रहे हैं। 'आप' की राजनीति नियति भी विसंगति का खेल खेलती रहती है। पहले जेल जाने वालों को कुर्सी मिलती थी, अब कुर्सी वाले वाले जेल जा रहे हैं। यह नियति का व्यंग्य है या सबक? आप के शीर्ष नेताओं के लिये पहले श्रद्धा से सिर झुकता था अब शर्म से सिर झुकता है। कैसे आप की राजनीति इस शर्म के साथ जनता से मुखातिब होगी और जनता क्या जबाव देगी, यह भविष्य के गर्भ में है। जिन अप्रत्याशित हालात में एवं बहुत कम समय के लिये आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, वे बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के कई उदाहरण हाल के वर्षों में दिखे हैं, लेकिन यह मामला उन सबसे अलग है। पिछले करीब दो साल न केवल आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली सरकार के लिए भी इस मायने में चुनौतीपूर्ण रहे कि एक-एक कर उसके कई बड़े नेता और मंत्री जेल भेज दिए गए। दिल्ली का विकास मुफ्त की संस्कृति की भेट चढ़कर विकास को अवरुद्ध किये हुए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने के बाद संकट और गहराया। इन संकटपूर्ण हालातों में आतिशी ने पार्टी का प्रभावशाली ढंग से बचाव किया। उन्होंने सौरभ भारद्वाज और अन्य साथियों के साथ मिलकर सड़क से लेकर मीडिया तक आम आदमी पार्टी की जंग लड़ी, उससे कार्यकर्ताओं में उनकी एक जुझारू छवि बनी है। ऐसे में, उनसे उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। क्या अतिशी अपने राजनीतिक कौशल से यह पद पाया है या वे केजरीवाल की राजनीति का एक मोहरा-भर बनी है? उनके हिस्से में यह पद तब आया जब पार्टी के दो सबसे बड़े नेताओं-अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया-ने कह दिया कि वे नए सिरे से जनादेश हासिल करने के बाद ही पद पर बैठेंगे। अगर पार्टी जनादेश हासिल नहीं कर पाती तब तो उन्हें पद छोड़ना ही पड़ेगा, अगर पार्टी चुनाव जीतती है तब भी मुख्यमंत्री पद से उनका हटना लगभग तय है। इन स्थितियों में कांटोंभरा ताज पहनकर उनके कामकाज एवं प्रभावी नेतृत्व का क्या औचित्य है? अतिशी एक वफादार एवं जिम्मेदार नेता के रूप में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही है। पार्टी के लिये उनके समर्पण एवं अटूट निष्ठा की मुद्रा विधायक दल की नेता चुने जाने के वक्त भी सामने आयी, जब आतिशी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि वह सिर्फ अगले चुनाव तक पदभार संभाल रही हैं, पार्टी के भीतर किसी नए केंद्र की आशंका को तिरोहित करना तो है ही, कहीं न कहीं यह वरिष्ठ नेताओं की आहत महत्वाकांक्षाओं पर मरहम रखना भी है। आतिशी का यह पहला कार्यकाल है, और किसी गैर-राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की महिला का पांच साल के भीतर यूं मुख्यमंत्री की कुरसी तक पहुंचने का यह विरल उदाहरण भी है। अतिशी दिल्ली जैसे सुबे की मुखिया बनी हैं, जिस दिल्ली ने सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जैसी दिग्गज महिला नेताओं का शासन देखा है। कुल मिलाकर, दिल्ली में शुरू हुए आप के इस नए प्रयोग और उसके नतीजों पर सबकी नजरें होंगी। अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव कराने की मांग की है, उनकी यह मांग अस्वीकृत हो गयी है, फिर भी अगले साल फरवरी के पहले पखवाड़े तक दिल्ली में चुनाव कराने होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सोची-समझी रणनीति के तहत ही दिया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को अपनी ईमानदारी के जनमत संग्रह के रूप में दर्शा सकें। उनका मकसद भाजपा सरकार द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकाबला करने तथा खुद को राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार के रूप में दिखा जनता की सहानुभूति अर्जित करना भी है। लेकिन इस तरह की राजनीतिक चतुराई में अगर कोई आधार नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं होती तो दूसरों के लिए खोदे गए खड्डों में स्वयं एक दिन गिर जाने की स्थिति बन जाती है। कुछ लोग इस प्रकार से प्राप्त जीत की खुशी मनाते हैं, कुछ इस प्रकार की हार की खुशी मनाते हैं, जो कभी जीत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गलत तरीकों से प्राप्त जीत से सिद्धांतों पर अडिग रहकर हारना सम्मानजनक होता है। निस्संदेह, जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र हासिल करने की योजना उनकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा जान पड़ती है। केजरीवाल को अतिशी रूपी दांव से ज्यादा लाभ शराब घोटाले में नाम आने व गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस्तीफा दे देते तो मिलता। ऐसे में, आतिशी के पास अपनी शासकीय छाप छोड़ने के साथ आप की राजनीतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली में निश्चित रूप से उसकी लड़ाई भाजपा के साथ ही कांग्रेस से भी अपनी जमीन बचाने की होगी। दिल्ली के नागरिकों की अपेक्षाओ पर खरा उतरने के साथ-साथ पार्टी की चुनावी नैया पार लगाने की चुनौती तो है ही। जाहिर है, आम आदमी पार्टी उनसे यही अपेक्षा करेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का आलेख लिखे।

# पिछले 10 सालों में मोदी मजबूत वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं

अशोक भाटिया,मुंबई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 साल पहले देश की सत्ता की कमान संभाली। इन बीते 10 सालों में वह न केवल मजबूत वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं बल्कि मौजूद समय में वह सबसे बड़े संघर्ष के समाप्ति की उम्मीद भी बन गए हैं।ढाई साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध के खात्मे को लेकर पश्चिमी देश भी अब भारत और प्रधानमंत्री मोदी की ओर उम्मीद लगाकर देख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है युद्ध में शामिल दोनों पक्षों का भारत पर भरोसा। प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों का दौरा किया। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर साफ कर दिया है कि उन्हें शांति समझौते को लेकर भारत की मध्यस्थता मंजूर है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद कहा था कि अगली शांति वार्ता भारत में आयोजित होनी चाहिए। बताया जाता है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भरोसा है कि अगर भारत शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है तो यह युद्ध रुक सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया था प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि वह शांति के पक्ष में खड़ा है। यह संदेश न केवल रूस-यूक्रेन के लिए था बल्कि यह पूरी दुनिया को यह बताने के लिए है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका क्या होगी ?रूस-यूक्रेन के अलावा अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को भी रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन-पोलैंड यात्रा से लौटे तो 26 अगस्त को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर उनसे बात की। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर चर्चा हो चुकी है। अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि भारत और रूस के बीच संबंध कितने मजबूत हैं, पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने इस संघर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक मजबूती से रूस का साथ निभाया है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार शांति की अपील भी करते रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने साफ-साफ कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है। पिछले हफ्ते रूस दौरे पर गए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत युद्ध रुकवाने के प्लान पर अब तेज़ी से जुट गया है। माना जा रहा था कि डोभाल, राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का 'पीस प्लान' साझा कर सकते हैं। वहीं अगर पुतिन की ओर से सहमति बन जाती है तो फिर आने वाले दिनों में इसे लेकर कोई बड़ी कवायद शुरू होती नजर आ सकती है।खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए मॉस्को जा सकते हैं। NSA अजित डोभाल से मुलाकात के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव भी रखा है, लिहाजा सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री मोदी वाकई इस जंग को रुकवाने में बड़ी और सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के अलावा भारत मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयासों में भी अहम भूमिका निभा सकता है। मिडिल ईस्ट के कई इस्लामिक मुल्कों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। UAE, कतर, सऊदी अरब और ईरान जैसे इस्लामिक मुल्क हों या इजराइल सभी के साथ भारत के रिश्ते समय के साथ बेहतर और मजबूत होते जा रहे हैं।पिछले साल नवंबर में दिल्ली पहुंचे अरब देशों के राजदूतों ने मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण माना था, तो वहीं सोमवार को इजराइल के नए राजदूत रिवेन अज़ार ने बड़ा बयान दिया है, निजी अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यह भारत पर निर्भर करता है कि वह गाजा युद्ध के समाधान के लिए किस हद तक शामिल होना चाहता है। दरअसल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो भारत उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले इस आतंकी हमले की निंदा की थी। हमले के ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इजराइल के लिए भारत कितना अहम है। वहीं पिछले महीने नेतन्याहू के साथ फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष को खत्म करने लिए बातचीत और कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील की।फिलिस्तीन के नजरिए से देखा जाए तो भारत ने फिलिस्तीन-इजराइल विवाद में हमेशा से 'टू स्टेट' समाधान का समर्थन किया है। भारत आजाद फिलिस्तीन का समर्थक रहा है और वर्षों से इसके फिलिस्तीन के साथ राजनयिक संबंध हैं। करीब एक हफ्ते पहले भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अबू अल-हैजा ने भी शांति के लिए भारत पर भरोसा जताया, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन भी मध्यस्थता के लिए भारत जैसे दोस्त की तलाश में है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति में काफी बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने इन 10 सालों में कई ऐसे देशों की यात्रा की जहां कभी कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था, इससे एक ओर भारत के उन देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए तो वहीं दूसरी ओर विश्व पटल पर भारत की छवि विश्वबंधु वाली बनकर उभरी है।पिछले साल अगस्त में प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत को लेकर 23 देशों में सर्वे किया। भारत को लेकर इन देशों का रुख सकारात्मक रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल समेत 9 देशों में 50 फीसदी से ज्यादा लोग भारत को लेकर अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 11 साल के कार्यकाल के दौरान भारत ने अपनी विदेश नीति को काफी हद तक नया रूप दिया है। उनके कार्यकाल की पहचान अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रति दृढ़ और रणनीतिक दृष्टिकोण से रही है। भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना, भारत के वैश्विक कद को बढ़ाना और आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना उनकी विदेश नीति के कुछ हिट्स में से एक हैं। पिछले एक दशक में चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहीं हों, लेकिन भारत सरकार ने कई देशों से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने में सफलता हासिल की। सीरिया और यमन में युद्ध जैसे हालातों के बीच से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाया गया है, वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा के जरिए भारतीय छात्रों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि किसी भी नागरिक को हम पीछे नहीं छोड़ सकते।कोरोना महामारी के दौरान विकसित देशों ने छोटे और गरीब देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया था लेकिन भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए करीब 100 देशों को वैक्सीन मैत्री पहल के जरिए 200 मिलियन (20 करोड़) वैक्सीन की डोज़ इन देशों को भेजा। इस पहल में साउथ एशिया के देश, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश शामिल रहे। भारत की इस पहल से न केवल इन देशों में वैक्सीन की कमी को पूरा हुई बल्कि इन तमाम देशों के साथ भारत के डिप्लोमेटिक संबंध मजबूत हुए। साथ ही साथ इससे विश्व पटल पर भारत की ग्लोबल लीडर की छवि मजबूत हुई, जो सिर्फ बड़े और विकसित देशों की नहीं बल्कि छोटे और गरीब देशों की भी चिंता और मदद करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और ग्लोबल लीडरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला रूस-यूक्रेन युद्ध में, जब भारत ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस से रियायती दरों पर क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान मोदी सरकार ने देश के आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए जटिल जिओ-पॉलिटिकल परिदृश्यों को कुशलता से संभाला। भारत के इस कदम से न केवल घरेलू ऊर्जा डिमांड पूरी हुई बल्कि बदलते वैश्विक वातावरण में कूटनीतिक संवेदनशीलता और भारत की आर्थिक प्राथमिकता के बीच संतुलन बनाने की क्षमता को भी दिखाया है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid




**मेष राशिः** आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज कही रूका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नयी योजना बनायेंगे, जिसका फायदा भी होगा। आज आपका मन पूजा-पाठ में अधिक लगेगा। किसी प्रोजेक्ट को लेकर सीनियर से फोन पर बातचीत होगी। कठिन परिस्थितियों का हल भी आज आसानी से निकाल लेंगे। आपके भौतिक सुख-साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा।

**वृष राशिः** आज घर पर किसी रिश्तेदार के आने से परिवार में ख़ुशी का माहौल बना रहेगा। साथ में कहीं घूमने भी जायेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। सोचे हुए जरूरी काम समय पर पूरा हो जायेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कोई खुशखबरी मिलने से आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी। लवमेट एक-दूसरे को कुछ उपहार दें।

**मिथुन राशिः** आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की जरुरत है। आपको कुछ समय परिवार के लिए जरूर निकालना चाहिए। आज आप किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे। दूसरों की कोई सलाह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। बच्चों का मन आज पढ़ाई की अपेक्षा खेल-कूद में ज्यादा लगेगा। सेहत फीट रखने के लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ेगी।

**कर्क राशिः** आज माता-पिता की सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। संतान की सफलता से आपको ख़ुशी होगी। आपको गंभीर मामलों को शांति और बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आज आप थोड़े भावुक भी हो सकते हैं। साथ ही कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थी पिछले दिनों के छूटे काम को पूरा कर लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या से आज काफी हद तक आराम मिलेगा।

**सिंह राशिः** आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा। आज आपका पूरा ध्यान अपने करियर को आगे बढ़ाने पर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको काफी अच्छा महसूस होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को फायदा होगा। वकील वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन लाभ दिलाने वाला रहेगा।

**कन्या राशिः** आज आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे है। आज आपको ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसे पूरा करने में आप सफल भी होंगे। परिवार में ख़ुशी का माहौल बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी-खासी सफलता मिलेगी। अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नये कदम उठायेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

**तुला राशिः** आज व्यापार में उम्मीद से अधिक मुनाफा होने वाला है। परिवार वालों से कार्यों में मदद मिलती रहेगी। जीवनसाथी से फ़ोन पर लम्बी बात होगी, जिसमे कार्यों को बेहतर ढंग से करने की चर्चा होगी। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। उचित दिशा में मेहनत से छात्रों को अपने करियर में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

**वृश्चिक राशिः** आज परिवार के साथ कहीं घूमने जायेंगे। आज किसी अनजान व्यक्ति से आपकी दोस्ती होगी, जो लम्बे समय तक चलेगी। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को आज कही परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। कुछ जरूरी काम आपकी योजनाओं के अनुसार पूरे होंगे। आज अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न होंगे। मन पसंद जगह पर ट्रांसफर होने के योग बने हुये है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

**धनु राशिः** आज ऑफिस के काम को पूरा करने में आप पूरी तरह से सक्षम होंगे। इस राशि के लॉ की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढिया रहेगा। आपको किसी सीनियर्स वकील के साथ इंटरर्नशिप करने का मौका मिलेगा। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। आप जिससे भी मदद की उम्मीद करेंगे, उससे आपको समय पर मदद मिल जायेगी। कामकाजी महिलाओं का दिन अच्छा रहेगा।

**मकर राशिः** आज खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आयेंगे। आपके आसपास चहल-पहल बनी रहेगी। ऑफिस में आपको एक साथ कई काम करने पड़ पड़ेंगे। काम के प्रति आपकी मेहनत रंग लायेगी। आपको किसी नए व्यवसाय से जुडऩे के अवसर मिलेगा। लेखकों की लिखी किताब आज लोगों को पसंद आयेगी।

**कुंभ राशिः** आज आपका दिन बेहद शानदार रहने वाला है। लोग आज आपसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं रखेंगे, आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे भी उतरेंगे। विद्यार्थिओं को आज के दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। आज आप कुछ नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, जिनसे आपको फायदा भी होगा। अपना कार्य समय से पूरा करने में आप सफल होंगे। कार्यों को पूरा करने में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

**मीन राशिः** आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। आज कोई अनजान व्यक्ति आपका मुड खराब कर सकता है। किसी काम में अनुमान से ज्यादा ही मेहनत और समय लग सकता है। आज स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहने की जरूरत है। जंक फूड खाने से बचना चाहिए। दोस्तों के साथ रिश्तें बेहतर रहेंगे।

## शब्द सामर्थ्य -182

(भागवत साहू)

**बाएं से दाएं**
1. खूब कसा हुआ, फूर्तिला, जो शिथिल व आलसी न हो 3. सार्वजनिक स्थान, संस्था, अस्तित्व, समिति 4. पौरुष, पुरुषत्व, मर्द होने का भाव 6. अंधेरा, अंधकार 7. लिपाई करना 9. शरीर, काया, जिस्म 10. मां के पिता, विभिन्न 12. महीना, मास 14. प्रियतम, बलमा, सजना 15. पांडवों का सबसे छोटा भाई 17. नशा, घमंड, खाता 19. वनोपज, वन से प्राप्त सामाग्री 21. शक्तिशाली, बलवान 24. तीव्र इच्छा 25. हथेली।

**ऊपर से नीचे**
1. निंदा, बुराई 2. निर्जीव, निष्प्राण 3. ध्वनियों या स्वरों का विशिष्ट लय में प्रस्फुटन, धुन, म्युजिक 4. झुका हुआ, विनीत 5. रूठे हुए को प्रसन्न करना, राजी करना 8. आश्रय, शरण 11. जन्म, जिंदगी 12. इंसानियत, मनुष्यता 13. रास्ता, मार्ग 14. एक हिंदी महीना, श्रावण 15. सपाट, जो उबड़-खाबड़ न हो 16. पति का छोटा भाई 18. गहरा कीचड़, पंक 20. आत्मा, अंत:करण (उ.) 22. बीता हुआ या आने वाला दिन 23. बगुला।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ■ | 2 | ■ | 3 | | 4 | ■ |
| | ■ | 5 | | | | ■ | 6 | |
| 7 | 8 | | ■ | ■ | 9 | | ■ | ■ |
| ■ | 10 | | ■ | ■ | ■ | ■ | 11 | ■ |
| 12 | | ■ | 13 | ■ | 14 | | | ■ |
| | ■ | 15 | | 16 | | ■ | 17 | 18 |
| | ■ | | ■ | 19 | | 20 | ■ | |
| 21 | 22 | | 23 | | ■ | | ■ | |
| ■ | 24 | | | ■ | 25 | | | |

**शब्द सामर्थ्य क्रमांक 181 का हल**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गु | मा | न | ■ | ■ | प | यो | द | ■ |
| न | ■ | ह | क | दा | र | ■ | ल | य |
| ह | वा | ला | त | ■ | च | ■ | द | म |
| गा | ■ | ■ | रा | ज | म | ह | ल | ■ |
| र | ई | स | ■ | ग | ■ | स | ■ | अ |
| ■ | मा | ■ | प | त | वा | र | ■ | ल |
| ख | न | क | ना | ■ | ह | त | ■ | बे |
| स | दा | ■ | ह | ■ | वा | ■ | शो | ला |
| रा | र | ■ | ■ | ■ | ही | र | क | ■ |

## सूडोकु नवताल- 7193

मध्यम

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | | 6 |
| 3 | | | | | 2 | | | |
| | | 7 | 6 | 5 | | | | 4 |
| 9 | 6 | | 5 | | | 1 | | 7 |
| 5 | | 1 | 4 | | 9 | 8 | | 2 |
| 4 | | 8 | | | | | 5 | 3 |
| 2 | | | | 6 | 1 | 4 | | |
| | | | 7 | | | | | 8 |
| 7 | | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | | 1 |

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

**सूडोकु नवताल -7192 का हल**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 |

# संपादकीय

## केजरी का आतिशी दांव

एक बार फिर साबित हुआ कि अरविंद केजरीवाल राजनीति के चतुर सुजान हैं। वे भी आपदा को अवसर में बदलने का हुनर जानते हैं। शीर्ष अदालत से सशर्त जमानत मिलने से खुद को बंधा महसूस करते हुए उन्होंने इस्तीफे का दांव चलाकर राजनीतिक जगत में एक हलचल पैदा कर दी। वहीं पार्टी में वरिष्ठता क्रम में निचले पायदान पर खड़ी आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल ने एक बार फिर से चौंकाया है। कयास लगे थे कि अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं उनकी पत्नी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कहा जा रहा था। दरअसल, क्षेत्रीय दलों में एक परंपरा रही है कि किसी राजनीतिक या कानूनी संकट के चलते परिवार के ही किसी सदस्य को सत्ता की बागडोर सौंप दी जाती थी। ताकि स्थितियां सामान्य होने पर फिर मुख्यमंत्री की गद्दी आसानी से वापस ली जा सके। जैसे बिहार में चारा घोटाले में घिरने के बाद लालू यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता की बागडोर सौंपी थी। विगत के ऐसे प्रसंग भी हैं जब कानूनी बाध्यताओं के चलते पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री का पद दिया गया तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे लेने लगी। विगत में बिहार और झारखंड में ऐसे प्रसंग सामने आए। बहरहाल, केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही अपने तरकश से जो तीर चले हैं, वे कुल मिलाकर निशाने पर लगते नजर आए हैं। हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव समेत अन्य राष्ट्रीय मुद्दों में उलझी भाजपा व कांग्रेस पर केजरीवाल ने मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना दिया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के साथ कराने की मांग करके आप ने दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। लेकिन यदि केजरीवाल शराब घोटाले में नाम आने व गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस्तीफा दे देते तो शायद उन्हें इसका ज्यादा लाभ मिलता, जैसे कि लालकृष्ण आडवाणी ने कतिपय राजनीतिक आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया था।

बहरहाल, केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सोची-समझी रणनीति के तहत ही दिया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को अपनी ईमानदारी के जनमत संग्रह के रूप में दर्शा सकें। उनका मकसद भाजपा सरकार द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकाबला करने तथा खुद को राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार के रूप में दिखा जनता की सहानुभूति अर्जित करना भी है। निस्संदेह, जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र हासिल करने की योजना उनकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा जान पड़ती है। वहीं तय समय से तीन माह पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने की मांग करके उन्होंने जता दिया है कि आप चुनाव अभियान के लिये तैयार है। दरअसल, केजरीवाल वर्ष 2014 के इस्तीफे के दांव को दोहराना चाहते हैं, जिसके बाद 2015 में आम आदमी पार्टी को भारी जीत मिली थी। लेकिन इस बार की स्थितियां खासी चुनौतीपूर्ण व जोखिमभरी हैं। निस्संदेह, यह जुआ मुश्किल भी पैदा कर सकता है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। जिसे विपक्ष ने पार्टी की घटती लोकप्रियता के रूप में दर्शाया था। दरअसल,बुनियादी प्रशासनिक ढांचे की खामियां व भाजपा के लगातार हमलों ने आप को बचाव की मुद्रा में ला खड़ा कर दिया था। वहीं दूसरी ओर आप सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अभी भी मतदाताओं को पसंद आ रही हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस्तीफे का पैंतरा आप को राजनीतिक रूप से कितना रास आता है। वहीं दूसरी ओर कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल के इस पैंतरे से तेज हुई राजनीतिक सरगर्मियों का असर पड़ोसी राज्य हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी दिख सकता है। चुनाव में इंडिया गठबंधन से मुक्त आप राज्य की सभी सीटों पर ताल ठोक रही है। जिसका कुछ लाभ भाजपा को भी हो सकता है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि चुनौतियों से जूझती पार्टी अपना जनाधार किस हद तक मजबूत कर पाती है। वहीं दूसरी ओर जनता की अदालत में दिल्ली सरकार की फ्री पानी-बिजली व सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा कराने की नीति की भी परीक्षा होनी है।

## राज्य व राज्यपाल में विवेकपूर्ण संतुलन जरूरी

**निश्चित रूप से यह अच्छी स्थिति नहीं है। अब तो अक्सर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि राज्यपाल के कुछ करने, या कुछ न करने का परिणाम राज्यों की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृति के लिए भेजे गये विधेयकों या अन्य मामलों में राज्यपाल के कुछ न करने से काम रुका रह जाता है।**

शेक्सपियर का एक चर्चित नाटक है मैक्बेथ। स्कॉटलैंड के राजा के दो जनरल उसके खिलाफ हैं। लेडी मैक्बेथ इनमें से एक की पत्नी है। ये लोग मिलकर राजा की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं, पर मैक्बेथ हत्या के लिए साहस नहीं जुटा पा रहा। पत्नी उसकी मर्दानगी को चुनौती देती है, उसे कायर, नामर्द और न जाने क्या-क्या कहती है और अंततः मैक्बेथ अपने आप को प्रमाणित करने के लिए राजा की हत्या के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लेडी मैक्बेथ की आत्मा उसे धिक्कारती है और वह आत्महत्या कर लेती है। हाल ही में यह लेडी मैक्बेथ अचानक भारत के मीडिया में चर्चा का विषय बन गयी थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री की तुलना लेडी मैक्बेथ से की है। यह तो नहीं पता कि ऐसी तुलना करके वह क्या बताना-जताना चाहते थे, पर सवाल उठ रहे हैं कि कोई राज्यपाल इस तरह की बात कैसे कह सकता है। राज्यपाल और राज्य-सरकार के रिश्तों की खटास किसी से छिपी नहीं है। समय-समय पर सी.वी. आनंद बोस अपने राज्य की मुख्यमंत्री की आलोचना करते रहे हैं। अब एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में ममता बनर्जी की सरकार कटघरे में है। यह सही है कि ममता के विरोधी इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं, पर सही यह भी है कि इस निंदनीय प्रकरण में ममता बनर्जी बचाव की मुद्रा में हैं- विरोधी दल तो राज्य सरकार की आलोचना कर ही रहे हैं, राज्यपाल भी खुलकर पश्चिम बंगाल की सरकार की आलोचना में लगे हैं। उनका कहना है कि राज्य की सरकार अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही है 'और राज्य की जनता की भावनाओं को नहीं समझ रही।'

यहां तक तो बात फिर भी समझ में आती है, पर जब राज्यपाल यह कहते हैं कि 'ममता बनर्जी लेडी मैक्बेथ हैं और उनके साथ कोई मंच साझा नहीं करूंगा' तो मामला गंभीर बन जाता है। राज्यपाल ने अपने इस कदम को राज्य की जनता की भावनाओं के साथ खड़े होना बताया और कहा कि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 'सामाजिक बहिष्कार' करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी प्रतिबद्धता राज्य की जनता और आर.जी. कर अस्पताल की 'डॉ. अभया' के परिवार के प्रति है और वे विरोध प्रदर्शन कर रहे डाक्टरों के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहना ज़रूरी समझा कि उनकी प्रतिबद्धता भारत के संविधान के प्रति है।

पता नहीं राज्य के मुख्यमंत्री की तुलना लेडी मैक्बेथ से करके और राज्य सरकार को अपने कर्तव्य-पालन में असफल सिद्ध होना बताकर वे किस ओर इशारा कर रहे हैं। हमारे संविधान में राज्यपाल के पद की व्यवस्था करके संविधान-निर्माताओं ने एक तरह से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक सेतु बनाया था। अपेक्षा की जाती है कि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि की तरह काम करेंगे और राज्य की स्थिति के बारे में केंद्र को अवगत भी कराते रहेंगे। राज्यपालों की व्यवस्था करते हुए यह अपेक्षा भी की गयी थी कि राज्यपाल राज्य सरकार के परामर्शदाता भी होंगे। इसके साथ ही यह भी मान कर चला गया था कि इस पद पर सुयोग्य और रोज़मर्रा की दलगत राजनीति से पृथक रहने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा।

पिछले 75 सालों का अनुभव यह बताता है कि राज्यपालों की नियुक्ति में केंद्र में सत्तारूढ़ दल के हितों को ही देखा जाता है। अक्सर ऐसे लोगों को इस पद पर बिठाया गया है जो या तो उम्रदराज हो गये थे या जिन्हें केंद्र में सत्तारूढ़ पक्ष ने अपने हितों के लिये उचित समझा है। आज़ादी पाने के कुछ साल बाद तक तो परंपरा यह भी थी कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श भी कर लिया जाता था। तब राज्य सरकार और राज्यपाल में टकराव की स्थितियां भी कम आती थीं। लेकिन केंद्र और राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें बनने के बाद स्थिति बदल गयी। राज्यों में राज्यपाल को केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में देखा जाने लगा और दुर्भाग्य से कुछ राज्यपालों का व्यवहार भी यह बताने लगा कि वे केंद्र सरकार के हितों को अधिक महत्व दे रहे हैं। कुछ राज्यपालों पर केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने के आरोप भी लगे। कई बार ऐसी स्थितियां बन गयीं कि यह सवाल भी उठा कि राज्यपाल की आवश्यकता ही क्या है?

निश्चित रूप से यह अच्छी स्थिति नहीं है। अब तो अक्सर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि राज्यपाल के कुछ करने, या कुछ न करने का परिणाम राज्यों की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृति के लिए भेजे गये विधेयकों या अन्य मामलों में राज्यपाल के कुछ न करने से काम रुका रह जाता है।

बहरहाल, यह सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन देश को इस बारे में तो सोचना ही चाहिए कि राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच तनाव क्यों उत्पन्न हो और कैसे इस तनाव को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे सांविधानिक पदों पर बैठे लोगों से एक आदर्श व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। किसी मुद्दे पर मतभेद होने का मतलब किसी प्रकार की शत्रुता नहीं माना जाना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है किसी भी राज्य में ऐसी स्थितियों का बनना अपने आप में दुखद घटनाक्रम का विषय भी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पूरा अधिकार है कि वे वहां उत्पन्न स्थितियों पर अपनी चिंता प्रकट करें। सच कहें तो यह उनका कर्तव्य भी है। इसी कर्तव्य का एक पक्ष यह भी है कि वह स्थितियों में सुधार के प्रयासों का हिस्सा बनें। लेकिन, जिस तरह राज्यपाल ने राज्य की निर्वाचित मुख्यमंत्री की तुलना लेडी मैक्बेथ से की है, वह अनुचित की परिभाषा में ही आती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री का 'सामाजिक बहिष्कार' करने की घोषणा भी ग़लत संकेत ही देती है।

हमारी सांविधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल न तो राज्य में केंद्र का एजेंट है और न ही केंद्र सरकार का जासूस। उसकी भूमिका राज्य में शासन चलाने में सहयोग देने वाले की है। उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेक और अनुभव का उपयोग करते हुए राज्य सरकार को सलाह देने का काम भी करेगा। कुल मिलाकर यह भूमिका एक सलाहकार की है। राज्य सरकार और राज्यपाल में एक विवेकपूर्ण संतुलन ही स्थिति को बेहतर बना सकता है। इसी संतुलन का तकाज़ा है कि राज्यपाल इस तरह के बयानों से बचें जैसा पश्चिम बंगाल के महामहिम ने लेडी मैक्बेथ का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री के सामाजिक बहिष्कार की बात कहना भी राज्यपाल की मर्यादा के अनुकूल नहीं लगता। इस तरह की स्थितियों का बनना सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है।

## आज का इतिहास

- ब्रिटेन और रूस के बीच 1755 में सैन्य संधि हुई।
- विलियम शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक ￼मर्चेंट ऑफ वेनिस￼ का मैनचेस्टर में 1891 को पहली बार मंचन 1891 में किया गया।
- स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो (अमेरिका) के विश्व धर्मसंसद में ऐतिहासिक भाषण दिया।
- न्यूजीलैंड में निर्वाचन अधिनियम 1893 के तहत सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया।
- पहली बार इतिहास में 1907 को कृत्रिम तेल का निर्माण हुआ। इस नये पदार्थ का आविष्कार स्काटलैंड के रसायनशास्त्री जेम्ज़ यांग ने किया था। यांग, पत्थर के कोयले की खदान के मालिक थे और उनके पास एक प्रयोगशाला थी पत्थर के कोयले के आसवन से उन्होंने कृत्रिम तेल बनाने में सफलता प्राप्त की थी।
- हॉलीवुड फिल्मों के स्टार चार्ली चैपलिन को 1952 में अमेरिका वापस आने से रोक दिया गया।
- अर्जेंटीना की सेना और नौसेना ने 1955 में विद्रोह कर राष्ट्रपति जुआन पेरोन को पद से हटाया।
- अमेरिका ने 1957 को नेवादा के रेगिस्तान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
- भारत की उत्तरी सीमा पर 1962 में चीन द्वारा आक्रमण।
- स्कॉट फाहमैन ऑनलाइन संदेश का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति 1982 में बने।
- ब्रिटिश उपनिवेश कैरीबियन द्वीप, सेंट किट्स एवं नेविस 1983 को स्वतंत्र।
- मेक्सिको सिटी में 1985 को भूकंप से भारी तबाही हुई. वहां करीब 10,000 लोग मारे गए थे।
- इस्राइल ने 1988 में परीक्षण उपग्रह होरिजोन-आई का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
- इटली के आलप्स पर्वतों के बीच 1991 को बर्फ में पड़ा हुआ प्राकृतिक ममी मिला. यह करीब 5000 साल पुराना था।
- एलिजा इजेत्बोगोविक युद्धोत्तरकालीन 1996 में बोस्निया के प्रथम राष्ट्रपति बने।
- ग्वाटेमाला और वामपंथी विद्रोहियों की सरकार ने 1996 में लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए।
- कर्नम मल्लेश्वरी ने 2000 को ओलंपिक में भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
- इस्रायल के सैनिकों ने 2002 को पश्चिमी किनारे पर फ़िलिस्तीन नेता यासिर अराफ़ात की घेराबंदी की।
- थाईलैंड में 2006 को सैन्य तख्तापलट, जनरल सुरायुद प्रधानमंत्री बने।
- साइबर वॉर की सम्?भावना को देखते हुए अमेरिकी एयरफ़ोर्स ने 2007 में अस्?थायी कमांड का गठन किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 को छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए शुरू किए गये शलवाजुड्यूम के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया।
- गुजरात के गोधरा काण्ड के बाद भड़के दंगे की मामले की जाँच कर रहे नानावती आयोग ने 2009 को राज्य में मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा छह अन्य लोगों को तलब करने की मांग वाली याचिका का निबटारा किया।
- नासा ने 2011 में चांद और मंगल ग्रह के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रह्मांड के दूसरे ठिकानों पर भेजने के लिए स्पेस लॉंच सिस्टम (एसएलएस) नामक 100 टन तक वज़न को अंतरिक्ष में ले जा सकने वाले एक भव्य रॉकेट की रुपरेखा तैयार की।

## आसमान को कूड़ाघर बनने से बचाएं

जब भी साफ हवा, नीला आसमान, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस जैसे अवसर आते हैं, तो हम पृथ्वी के हित में अपने दायित्वों की बात करते हैं। भाषणबाज़ी से अलग, पृथ्वी के हित में हम सबसे महत्वपूर्ण कदम यह उठा सकते हैं कि आसमान को कूड़ा घर न बनाएं। जगह-जगह विशाल कूड़े के पहाड़, लैंडफिल्स में आग लगना और कई दिनों तक घुटन भरा धुआं उगलना यह दर्शाता है कि कूड़ा सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान में भी अपनी जगह बना रहा है। प्लास्टिक इस संदर्भ में एक बड़ा खलनायक है। जलने के साथ-साथ माइक्रो-प्लास्टिक के छोटे कण भी वायुमंडल में पहुंचते हैं।

हाल ही में एक आम दृश्य यह देखा जा रहा है कि लोग सड़कों पर पत्तियां इकट्ठा करके उन्हें जलाते हैं। चुनावी सामग्री का कूड़ा भी सड़कों पर फैल जाता है और उसे भी जला दिया जाता है। इस धुएं का आसमान में फैलना, हमें यह बताता है कि हम अपने कूड़े को सीधे आसमान में भेज रहे हैं।

देशभर में विकास की दौड़ में वायु गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। निर्माण कार्यों, कोयला बिजली उत्पादन, और ईंट-भट्ठों से उड़ने वाली धूल और कणीय प्रदूषक वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। जब वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो धूल और कणीय प्रदूषकों को रोकने के लिए जाली व कपड़े की दीवारें लगाई जाती हैं। नगरों में कूड़ा जलाने वाले संयंत्र और सड़क सफाई की मशीनें भी वायु में प्रदूषकों का अम्बार छोड़ देती हैं।



वातावरण में धूल और कणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन्स का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारें विशेषकर ठंड के मौसम में इन प्रदूषणों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ रहती हैं। अंततः स्कूलों और कार्यालयों को बंद करना पड़ता है। राजनीतिक कारणों से निर्माण कार्यों और कूड़े के ढेर की अनदेखी होती है, जिससे प्रदूषण और बढ़ जाता है।

वायु में कणीय प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। इससे बीमारियों में वृद्धि होती है। ये कण पानी में भी जमते हैं और वहां से मिट्टी और घास में पहुंच जाते हैं, जो जानवरों के भोजन में भी शामिल हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर 90 प्रतिशत लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं और हर साल वायु प्रदूषण के कारण लगभग 7.9 मिलियन लोग समय से पहले मर जाते हैं, खासकर कम और मध्यम आय वाले देशों में। अत्यंत महीन कणीय प्रदूषकों को नियंत्रित करना अत्यावश्यक है।

7 अक्तूबर, 2019 को यूरोप और अमेरिका के देशों ने एक साझा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और अमोनिया जैसे प्रदूषकों के अलावा पीएम 2.5 कणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन को भी तय सीमा में बांधने का फैसला किया गया। हालांकि, कणीय प्रदूषण केवल भौतिक परिमाण से नहीं मापा जाता, उसकी रासायनिक प्रकृति भी महत्वपूर्ण होती है। प्लास्टिक, कागज और रबर जलने पर उनके कणीय प्रदूषक भी हवा में चले जाते हैं।

भारत में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण उच्चतम है, और इसके कारण तेजाबी बारिश होती है। पेड़ों की पत्तियों पर प्रदूषण बैठ जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। आसमान को कूड़ाघर बनने से बचाने के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर सुधार आवश्यक हैं। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, वाहन ठीक रखना, और कूड़ा जलाने से बचना ये सभी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं।

दुनियाभर में बढ़ते ऊर्जा की मांग के कारण बड़े प्रदूषणकारी देश जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। भारत, जिसमें दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहर शामिल हैं, भी कोयले के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रहा है। इससे कणीय प्रदूषण और बढ़ेगा। नवीनतम खतरा माइक्रो-प्लास्टिक के वायुमंडल में पहुंचने का है। प्लास्टिक पर पाबंदी और इसके कम उपयोग से माइक्रो-प्लास्टिक भी कम होगा। हमें हताशा से बाहर निकलना होगा और अपनी आदतों में सुधार करना होगा। कूड़ा जलाने, पटाखे जलाने, धुआं छोड़ते वाहनों का उपयोग करने से बचना होगा। छोटे-छोटे बदलाव भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कूड़ा जलाने पर रोक और उचित कूड़ा प्रबंधन। प्राकृतिक कारणों से भी कणीय प्रदूषण बढ़ता है, जैसे आंधी-तूफान, खनन और ज्वालामुखी विस्फोट। पेड़ों की संख्या बढ़ाकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है।

अंततः, यदि हम कूड़ा करते रहें और सरकारों पर आरोप लगाते रहें कि वे प्रदूषण कम करने में असफल हैं, तो यह हमारे लिए हानिकारक होगा। हर व्यक्ति का जिम्मेदारी समझना जरूरी है ताकि प्रदूषित हवा की समस्या कम की जा सके। जैसे हम अपने जलस्त्रोतों को प्रदूषित नहीं करना चाहते, वैसे ही आसमान को भी प्रदूषण से बचाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण केवल एक राजनीतिक या सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालता है।

## कच्चे तेल के घटते दाम?

**पिछले दिनों तेल विपणन कम्पनियों के शेयरों में ?गिरावट भी इसलिए देखी गई क्योंकि ऐसी खबरें छन-छन कर आ रही हैं कि डीजल और पैट्रोल के भाव कम हो सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर देखें तो हर बार चुनावों से पहले तेल के दामों में कटौती की जाती है ताकि मतदाताओं को राहत दी जा सके और इसका लाभ चुनावों में उठाया जा सके।**

देश में शायद कोई शख्स होगा जिसका सीधा सरोकार पैट्रोल-डीजल से नहीं होगा। दिन की शुरूआत यानि कामकाज के लिए घर से निकलने से लेकर घर लौटने तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पैट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल होता है। तेल का खेल जीवन का अंग बन चुका है और उसके बिना दिनचर्या को सामान्य बनाया ही नहीं जा सकता। पैट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ती हैं, कीमतें घटती हैं तो महंगाई से राहत मिलती है। तेल के खेल का दुनियाभर में हिंसक इतिहास रहा है। तेल के कारण दुनियाभर में इंसानी खून की नदियां बही हैं। तेल भंडारों पर कब्जे के लिए वैश्विक शक्तियों ने विध्वंस का खेल खेला है। तेल के खेल में युद्ध, हिंसा, विनाश और हार-जीत तो लगी रहती है। दुनियाभर में तेल को लेकर जमकर राजनीति होती रही है लेकिन पैट्रोल-डीजल जिन्दगी को रफ्तार देने के लिए बहुत जरूरी है। यूक्रेन-रूस युद्ध होने के बाद अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने का बहुत दबाव बनाया। किसी दबाव में न आते हुए भारत ने कूटनीति से काम लिया।

भारत ने दो टूक शब्दों में अपने हितों का हवाला देकर रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखने का फैसला किया। रूस ने भी भारत को सस्ता तेल देने की पेशकश की और भारत ने इसका पूरा लाभ उठाया। भारत को 60 डॉलर से भी कम मूल्य पर रूस से तेल हासिल हुआ। भारत पहले इराक से सबसे ज्यादा तेल खरीदता था लेकिन अब इराक को पछाड़ कर रूस सबसे बड़ा देश बन गया है। सस्ता तेल मिलने से भारतीय रिफाइनरियों को बहुत लाभ हुआ। भारतीय रिफाइनरियों ने यूरोपीय बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। हुआ यूं कि जिन यूरोपीय कम्पनियों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे उन्हीं देशों को भारत ने तेल का निर्यात किया। पाकिस्तान ने भी भारत की तरह रूस से कच्चा तेल खरीदने की कोशिश की लेकिन अमेरिका के दबाव के आगे उसकी एक न चली। भारत की सफल कूटनीति के चलते कोरोना काल में और जंग से पहले घाटे में चल रही भारतीय तेल कम्पनियों की भरपाई हुई और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई।

कच्चे तेल के दाम मार्च 2024 के बाद से लगातार गिर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके दामों में 20 फीसदी ?गिरावट आई है और इसके भाव 72.48 डॉलर प्रति बैरल है। 2022 में कच्चे तेल की कीमत 116 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई थी। जिस ढंग से तेल की कीमतें गिर रही हैं उस हिसाब से भारत में उपभोक्ताओं को राहत मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि आम लोगों को राहत कब मिलेगी। माहौल तो?ऐसा बन रहा है कि पैट्रोल-डीजल के मूल्यों में 6-7 रुपए की कटौती किया जाना सम्भव है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सभी ऑयल मार्किटिंग कम्पनियों का कुल मुनाफा करीब 86 हजार करोड़ रुपए रहा। यह मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत ज्यादा है। कच्चा तेल तो सस्ते मिल ही रहा है जबकि बाजार कीमतों पर डीजल-पैट्रोल बेचने पर उन्हें और ज्यादा मुनाफा हो रहा है। तेल की कीमतों में ?गिरावट के चलते ऑयल कम्पनियों को ?सितम्बर में 13-14 रुपए प्रति लीटर का फायदा हुआ। तेल उत्पादक देशों ने भी उत्पादन में कटौती का फैसला नवम्बर-दिसम्बर तक टालने का फैसला किया है।

पिछले दिनों तेल विपणन कम्पनियों के शेयरों में ?गिरावट भी इसलिए देखी गई क्योंकि ऐसी खबरें छन-छन कर आ रही हैं कि डीजल और पैट्रोल के भाव कम हो सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर देखें तो हर बार चुनावों से पहले तेल के दामों में कटौती की जाती है ताकि मतदाताओं को राहत दी जा सके और इसका लाभ चुनावों में उठाया जा सके। इसी साल लोकसभा चुनावों से पहले मार्च में पैट्रोल और डीजल के रेट घटाए गए थे तब पैट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 2-2 रुपए की कटौती की गई थी। अब पिछली कटौती को 6 माह बीत चुके हैं। आम लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली। लोगों को उम्मीद थी कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनावों से पहले तेल की कीमतें घटेंगी लेकिन अभी तक कोई?घोषणा नहीं की गई है।

## राजनीति में बद-कलामी नहीं

**हमारी पूरी संसदीय प्रणाली का आधार ही मत भिन्नता पर रखा हुआ है। मगर संजय गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण समाप्त करने की बात कही। ऐसी बात सुनकर केवल रोया ही जा सकता है क्योंकि राहुल गांधी तो आरक्षण को तब तक अन्तनकाल तक जारी रखना चाहते हैं जब तक कि भारतीय समाज में समानता न आ जाये।**

लोकतन्त्र में हिंसा और घृणा फैलाने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसमें आलोचना करने का स्वतन्त्र अधिकार होता है मगर बदजुबानी या बद-कलामी के लिए भी कोई स्थान नहीं होता परन्तु वर्तमान दौर की राजनीति में हम लगातार देख रहे हैं कि राजनीतिज्ञों की जुबान नियन्त्रण से बाहर होकर समाज में नफरत और हिंसा फैलाने का काम करती रहती है। राजनीतिज्ञों की भाषा लगातार बाजारू होती जा रही है जिसमें व्यक्तिगत हिंसा का भी समावेश होता जा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के सत्ताधारी भाजपा-शिवसेना (शिन्दे गुट) गठबन्धन के एक विधायक संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस के लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के लिए कहा कि जो कोई भी उनकी जुबान काटेगा उसे वह 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। ऐसे व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी विधायक पद पर रहने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसने भारतीय संविधान को सीधे-सीधे तार-तार करने का काम किया है। संविधान की शपथ लेकर विधायक बनने वाले व्यक्ति के खिलाफ न्यायपालिका को तुरन्त संज्ञान लेना चाहिए और वाजिब कानून के तहत सजा सुनानी चाहिए क्योंकि उसने यह बयान एक सार्वजनिक भाषण में दिया है।

इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला पूरे देश में ही लागू है कि नफरत फैलाने वाले बयानों पर राज्य सरकारों व पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए मगर अभी तक इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है और बामुश्किल एक थाने में गायकवाड़ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो सकी है। राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा बयान देकर गायकवाड़ ने सिद्ध किया है वह भारत की लोकतान्त्रिक राजनीति में हिंसा फैलाना चाहते हैं अतः उनके भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबन्ध लगना चाहिए क्योंकि भारत का संविधान यह स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल अहिंसक रास्तों पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति या राजनैतिक दल ही भारत की चुनाव प्रणाली में हिस्सा ले सकता है। सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं जो कि एक संवैधानिक पद है बल्कि असली सवाल यह है कि श्री गांधी भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल एक व्यक्ति हैं। उन्होंने जो भी बयान अपने अमेरिका के दौरे के दौरान दिये हैं उन पर लोकतान्त्रिक दायरे में बहस हो सकती है और अलग-अलग विचारधारा के लोग अपने मत के अनुसार उनकी समीक्षा कर सकते हैं।

हमारी पूरी संसदीय प्रणाली का आधार ही मत भिन्नता पर रखा हुआ है। मगर संजय गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण समाप्त करने की बात कही। ऐसी बात सुनकर केवल रोया ही जा सकता है क्योंकि राहुल गांधी तो आरक्षण को तब तक अन्तनकाल तक जारी रखना चाहते हैं जब तक कि भारतीय समाज में समानता न आ जाये। अमेरिका में जाकर भी उन्होंने यही कहा और राय व्यक्त की कि आरक्षण तभी समाप्त किया जा सकता है जब भारतीय समाज से गैर बराबरी मिट जाये और सभी जाति वर्ग के लोगों के बीच समानता आ जाये। मगर गायकवाड़ ने तालिबानी तेवरों में राहुल गांधी की जुबान पर ही इनाम की घोषणा कर डाली। कयामत यह है कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्दे की पार्टी के विधायक हैं अतः श्री शिन्दे को ही इस मामले में तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। भारत तो वह देश है और इसके लोकतन्त्र का वह खूबसूरत इतिहास है जिसमें राजनैतिक भाषा के संयम पर विशेष ध्यान दिया जाता था और राजनैतिक नेताओं को यदि लगता था कि उनमें से ?किसी ने यह सीमा लांघने का प्रयास किया है तो वह खुलकर उस नेता की निन्दा करने से दूर भी नहीं रहते थे। इस मामले में 1969 में हुई वह घटना मील का पत्थर है जब दो विपक्ष के नेताओं में से ही एक ने दूसरे की भाषा के अनियन्त्रित हो जाने पर आलोचना की थी। इस वर्ष स्व. प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ (अब भाजपा) पार्टी के नये-नये अध्यक्ष बने थे।

देश में स्व. इन्दिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा सरकार तब चीन से 1962 में और पाकिस्तान से 1965 में युद्ध होने की वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना समय पर नहीं ला पाई थी। स्व. वाजपेयी हास्य व व्यंग्य की भाषा के महारथी माने जाते थे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत
सम्पादकीय

## पिंजरे में सीबीआई

**राजनीतिक** आकाओं के अनुसार काम करने लिए बदनाम देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी 'केंद्रीय जांच ब्यूरो' को एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां को कहना पड़ा है कि 'सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि तोड़नी चाहिए। उसे दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद नहीं, बल्कि स्वतंत्र एवं ईमानदार जांच एजेंसी है। उसे रत्तीभर भी शक के दायरे में नहीं होना चाहिए।' अदालत ने यह टिप्पणी आबकारी नीति घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत स्वीकार करने के आदेश में की है। न्यायालय ने कहा है कि 'जमानत नियम और जेल अपवाद है। कानून का प्रयोग किसी के उत्पीड़न के लिए नहीं हो सकता है। सीबीआई ने केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया, ताकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में केजरीवाल को मिली जमानत खारिज हो जाए।' पीठ के दूसरे न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी अपने आदेश में कहा कि केजरीवाल जमानत की शर्तें पूरी करते हैं। अतएव सीबीआई की यह दलील उचित नहीं है कि जमानत के लिए विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) जाना चाहिए। उन्हें ईडी के प्रकरण में भी जमानत मिली है। इसलिए उन्हें हिरासत में रखना अस्वीकार्य है। दरअसल न्यायालय को ऐसा इसलिए कहना पड़ा, क्योंकि सीबीआई पर पिंजरे में बंद तोते और सरकार की कठपुतली होने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। 9 मई 2013 को कोयला घोटाले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति आरएस लोढ़ा की पीठ ने कहा था कि 'सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह है, यह वही बात दोहराती रहती है, जो उसके मालिक कहते हैं। यह एक ऐसी अनैतिक कहानी है, जिसमें एक तोते के कई मालिक हैं। कोयला घोटाले की रिपोर्ट में अधिकारियों के कहने पर भी बदलाव हुआ है।' देश के राजनेता और दल सीबीआई पर नाजायज दबाव डालकर अपने तात्कालिक राजनीतिक हितों की पूर्ति करते हैं, यह अब कोई दबी-छिपी बात नहीं रह गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जितने भी राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय दल हैं, लगभग सभी परोक्ष-अपरोक्ष रूप से सत्ता में हिस्सेदारी कर चुके हैं और सत्ता से बाहर होने के बाद सत्ता पक्ष पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं। मसलन अपरोक्ष रुप से वे अपने ही अनुभव प्रकट करते हैं। दरअसल जिस दल की सरकार केंद्र में होती है, उसे शायद यह भ्रम हो जाता है कि अब आजीवन उन्हीं की सरकार का अस्तित्व बना रहेगा। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि सीबीआई राजनीतिक दबाव में काम करती है। इन सब बयानों से साफ होता है कि सीबीआई को सुपुर्द कर देने के बाद भी गंभीर से गंभीर मामला भी गंभीर नहीं रह जाता। बल्कि अपरोक्ष रुप से सीबीआई एक तो घोटाले पर आवरण डालने का काम करती है, दूसरे आरोपियों का सुरक्षा-कवच बन जाता है। हमारे यहां यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अपराध को सार्वजनिक रूप से स्वीकार लिए जाने के बावजूद नौकरशाहों पर दण्ड का शिकंजा नहीं कसता? इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारी शोहरत अथवा नया पद पा लेने की लालसा में कुछ तो भी बयान देते रहते हैं। इसीलिए देखने में आता है कि जो अधिकारी पिंजरे में तोते की भूमिका में मालिक की भाषा बोलते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद किसी महत्वपूर्ण आयोग या मंडल के पद पर मनोनीत कर दिए जाते हैं। जाहिर है, देश के लोकसेवकों को भी प्रसिद्धि और लालच की भावना से ऊपर उठकर कर्त्तव्य का पालन करने की जरुरत है।

## विपक्ष पर दबाव का आतिशी दांव

*जिन अप्रत्याशित हालात में एवं बहुत कम समय के लिये आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है,वे बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के कई उदाहरण हाल के वर्षों में दिखे हैं,लेकिन यह मामला उन सबसे अलग है। पिछले करीब दो साल न केवल आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली सरकार के लिए भी इस मायने में चुनौतीपूर्ण रहे कि एक-एक कर उसके कई बड़े नेता और मंत्री जेल भेज दिए गए।*



**- ललित गर्ग -**

**अरविंद** केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने राजनीति में कुछ मौलिक प्रतिस्थापनाएं की है, बने-बनाये रास्तों पर न चलकर नये रास्ते इजाद किये हैं। वे संकटों को अवसर में बदलने वाले करिश्माई व्यक्तित्व भी हैं। उनकी राजनीति अनेक विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरी रही है, उनके व्यवहार एवं वचनों में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित होते रहे हैं, लेकिन ये ही विरोधाभास उनकी राजनीतिक चमक का कारण भी बने हैं। क्योंकि राजनीति में सब जायज माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने से खुद को बंधा महसूस करते हुए उन्होंने इस्तीफे का धारदार दांव चलाकर राजनीतिक जगत में एक हलचल पैदा कर दी। वहीं पार्टी में संभावनाओं भरे अनेक चेहरों के होने के बावजूद उन्होंने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वह वरिष्ठता क्रम में निचले पायदान पर खड़ी थी, लेकिन केजरीवाल ऐसे चौंकाने वाले फैसले पहले भी लेते रहे हैं। लेकिन इस तरह वे जनादेश का मज़ाक भी बनाते रहे हैं तो संवैधानिक स्थितियों की धता भी करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहस के कदम एवं चतुराई की आंख लेकर परम्परागत राजनीति की जंजीरों को तोड़कर आगे निकलते रहे हैं। संभावनाएं की जा रही थी कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अधिक संभावनाएं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाये जाने की थी। क्योंकि क्षेत्रीय दलों में किसी राजनीतिक या कानूनी संकट के चलते परिवार के ही किसी सदस्य को सत्ता की बागडोर सौंप देने परंपरा रही है। ताकि स्थितियां सामान्य होने पर फिर मुख्यमंत्री की गद्दी आसानी से वापस ली जा सके। इसके अनेक उदाहरण है, जिनमें बिहार में चारा घोटाले में घिरने के बाद लालू यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता की बागडोर सौंपी थी। बहरहाल, केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही अपने तरकश से जो तीर चले हैं, उनकी धार एवं तीक्ष्णता को महसूस किया जा सकता है। इन तीरों से हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव समेत अन्य राष्ट्रीय मुद्दों में उलझी भाजपा व कांग्रेस पर केजरीवाल ने मनोवैज्ञानिक राजनीतिक दबाव तो बना ही दिया है। हरियाणा में स्वतंत्र चुनाव लड़ने का निर्णय लेकर उन्होंने सत्ता के गठन में स्वयं को एक ताकतवर मोहरे के रूप में प्रस्तुत करने का चतुराई भरा खेल भी खेला है। दिल्ली में भी उन्होंने अपनी निस्तेज होती स्थितियों को मजबूती दी है। दरअसल, केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध में आन्दोलन के योद्धा के रूप में वर्ष 2014 के इस्तीफे के दांव की तरह 2015 में आम आदमी पार्टी को मिली भारी जीत का अध्याय दोहरा देना चाहते हैं। लेकिन इस बार की स्थितियां खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होने से खासी चुनौतीपूर्ण व जोखिमभरी हैं। निस्संदेह, यह दांव मुश्किल भी पैदा कर सकता है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। भले ही केजरीवाल अपने को, समय को पहचानने वाला साबित कर रहे हो, लेकिन वे अपने देश को, अपने पैरों की जमीन को एवं राजनीतिक मूल्यों को नहीं पहचान रहे हैं। 'आप' की राजनीति नियति भी विसंगति का खेल खेलती रहती है। पहले जेल जाने वालों को कुर्सी मिलती थी, अब कुर्सी वाले वाले जेल जा रहे हैं। यह नियति का व्यंग्य है या सबक? आप के शीर्ष नेताओं के लिये पहले श्रद्धा से सिर झुकता था अब शर्म से सिर झुकता है। कैसे आप की राजनीति इस शर्म के साथ जनता से मुखातिब होगी और जनता क्या जबाव देगी, यह भविष्य के गर्भ में है।

जिन अप्रत्याशित हालात में एवं बहुत कम समय के लिये आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, वे बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के कई उदाहरण हाल के वर्षों में दिखे हैं, लेकिन यह मामला उन सबसे अलग है। पिछले करीब दो साल न केवल आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली सरकार के लिए भी इस मायने में चुनौतीपूर्ण रहे कि एक-एक कर उसके कई बड़े नेता और मंत्री जेल भेज दिए गए। दिल्ली का विकास मुफ्त की संस्कृति की भेट चढ़कर विकास को अवरुद्ध किये हुए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने के बाद संकट और गहराया। इन संकटपूर्ण हालातों में आतिशी ने पार्टी का प्रभावशाली ढंग से बचाव किया। उन्होंने सौरभ भारद्वाज और अन्य साथियों के साथ मिलकर सड़क से लेकर मीडिया तक आम आदमी पार्टी की जंग लड़ी, उससे कार्यकर्ताओं में उनकी एक जुझारू छवि बनी है। ऐसे में, उनसे उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। क्या अतिशी अपने राजनीतिक कौशल से यह पद पाया है या वे केजरीवाल की राजनीति का एक मोहरा-भर बनी है? उनके हिस्से में यह पद तब आया जब पार्टी के दो सबसे बड़े नेताओं- अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया-ने कह दिया कि वे नए सिरे से जनादेश हासिल करने के बाद ही पद पर बैठेंगे। अगर पार्टी जनादेश हासिल नहीं कर पाती तब तो उन्हें पद छोड़ना ही पड़ेगा, अगर पार्टी चुनाव जीतती है तब भी मुख्यमंत्री पद से उनका हटना लगभग तय है। इन स्थितियों में कांटोंभरा ताज पहनकर उनके कामकाज एवं प्रभावी नेतृत्व का क्या औचित्य है? अतिशी एक वफादार एवं जिम्मेदार नेता के रूप में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही है। पार्टी के लिये उनके समर्पण एवं अटूट निष्ठा की मुद्रा विधायक दल की नेता चुने जाने के वक्त भी सामने आयी, जब आतिशी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि वह सिर्फ अगले चुनाव तक पदभार संभाल रही हैं, पार्टी के भीतर किसी नए केंद्र की आशंका को तिरोहित करना तो है ही, कहीं न कहीं यह वरिष्ठ नेताओं की आहत महत्वाकांक्षाओं पर मरहम रखना भी है। आतिशी का यह पहला कार्यकाल है, और किसी गैर-राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की महिला का पांच साल के भीतर यूं मुख्यमंत्री की कुरसी तक पहुंचने का यह विरल उदाहरण भी है। अतिशी दिल्ली जैसे सुबे की मुखिया बनी हैं, जिस दिल्ली ने सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जैसी दिग्गज महिला नेताओं का शासन देखा है। कुल मिलाकर, दिल्ली में शुरू हुए आप के इस नए प्रयोग और उसके नतीजों पर सबकी नजरें होंगी।

अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव कराने की मांग की है, उनकी यह मांग अस्वीकृत हो गयी है, फिर भी अगले साल फरवरी के पहले पखवाड़े तक दिल्ली में चुनाव कराने होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सोची-समझी रणनीति के तहत ही दिया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को अपनी ईमानदारी के जनमत संग्रह के रूप में दर्शा सकें। उनका मकसद भाजपा सरकार द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकाबला करने तथा खुद को राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार के रूप में दिखा जनता की सहानुभूति अर्जित करना भी है। लेकिन इस तरह की राजनीतिक चतुराई में अगर कोई आधार नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं होती तो दूसरों के लिए खोदे गए खड्डों में स्वयं एक दिन गिर जाने की स्थिति बन जाती है। कुछ लोग इस प्रकार से प्राप्त जीत की खुशी मनाते हैं, कुछ इस प्रकार की हार की खुशी मनाते हैं, जो कभी जीत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गलत तरीकों से प्राप्त जीत से सिद्धांतों पर अडिग रहकर हारना सम्मानजनक होता है। नि:स्संदेह, जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र हासिल करने की योजना उनकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा जान पड़ती है। केजरीवाल को अतिशी रूपी दांव से ज्यादा लाभ शराब घोटाले में नाम आने व गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस्तीफा दे देते तो मिलता। ऐसे में, आतिशी के पास अपनी शासकीय छाप छोड़ने के साथ आप की राजनीतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली में निश्चित रूप से उसकी लड़ाई भाजपा के साथ ही कांग्रेस से भी अपनी जमीन बचाने की होगी। दिल्ली के नागरिकों की अपेक्षाओ पर खरा उतरने के साथ-साथ पार्टी की चुनावी नैया पार लगाने की चुनौती तो है ही। जाहिर है, आम आदमी पार्टी उनसे यही अपेक्षा करेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का आलेख लिखे।

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट 25 आई पी एक्सटेंसन, पटपड़गंज दिल्ली-110092)

## प्राचीन जल के साधन एवं प्रदूषण से मुक्त के उपाय

**- संजय वर्मा 'दृष्टि'**



**वैदिक** ग्रंथों में जुताई, बुआई, कटाई और गहाई सहित कई कृषि कार्यों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 'रुद्ध' जल और जल चक्र का भी उल्लेख है। जिसे सिंचाई का उपयोग एवं वैदिक संहिताओं में भी विशेष सिंचाई नहरों का उल्लेख है। मोट, थाले जो कि पतरे के बने होते थे उनका भी उपयोग हुआ। पखाल, रेहट आदि भी सिंचाई किये जाने के साधन रहे। पहाड़ी क्षेत्र में खजूर, ताड़ी के वृक्ष की लकड़ी को दो भागों में बाट कर नहर बनाकर उपयोग किया जाता था। बाद में बिजली से मोटर पंप आदि से सिंचाई की जाने लगी। अब माइक्रो पाइप पद्धति से सिंचाई की जाने लगीं। सार ये है की विकास के आधार पर साधन नए होते गए। वर्तमान में बड़े जल स्त्रोतों के निर्माण से ही जल को बचाया जाकर, भूमिगत वाटर टेबल को बढ़ाया जाकर जल का उपयोग बेहतर तरीके से सिंचाई, पेयजल, निस्तार, औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जल की शुद्धता के लिए चिंतन आवश्यक है। जल को स्वच्छ रखने में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। नदियो व अन्य जल संरचनाओ यथा तालाब, झील, कुएं, बावडी आदि हमारी संस्कृति व परंपरा मे पूजा के स्थल रहे है, इनकी अनुपलब्धता या दूषित होने पर हेंड पम्प व नलकूप की पूजा करके भी परंपरा का निर्वाह किया जाता रहा है लेकिन प्राकृतिक जल संसाधनों के रख-रखाव के प्रति समुचित जिम्मेदारी का अभाव सा हो रहा है. नदियों व जल संरचनाओं के क्षरण व विलुप्तिकरण के प्रमुख कारण रहे है - नगरीय निकायों द्वारा सीवरेज (मल मूत्र) निकासी की समुचित व्यवस्था न करते हुए सीधे नदी, सहायक नदी, नालों, तालाबों मे इसे छोड़ देना, औधोगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के वचनो का पालन न करते हुए अपशिष्ट को अनुपचारित ही इनमे प्रवाहित कर देना। उदगम से संगम तक नदी के पुनर्जीवन के लिए करना चाहिए। कई नदियों के तट स्थित रहने वाले कई रहवासी अपने घर के निकले गंदे पानी का निकास घर के पीछे करते है और उस गंदे पानी को सोख्ता गड्ढे में समाहित करते है। साथ ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की योजना बनावे ताकि गन्दा पानी स्वच्छ जल में न मिल पाए। वर्तमान में ऐसी ही प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है। ताकि सीधे तौर पर गंदा पानी पावन नदियों के नदियों में न मिल पाए। नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए नागरिकों आगे आना चाहिए। नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने का दायित्व निभाने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत कर उन्हें शासन से सहायता मुहैया होना चाहिए ताकि नदियों के शुद्धिकरण से सभी को शुद्ध जल का लाभ मिलकर जल संक्रमण से होने वाली बीमारियों से निजात मिल सके। स्वच्छता का संदेश और जागरूकता लाना हर इंसान का कर्तव्य है क्योंकि स्वच्छता से ही बीमारियों, प्रदूषण को मुक्त रख कर स्वास्थ्य का लाभ हमें एक नई दिशा प्रदान कर सकता है।

**(125, बलिदानी भगत सिंह मार्ग, मनावर जिला -धार)**

## कहीं ये पब्लिक सिटी स्टंट तो नहीं है

**- मनमोहन राजावतराज**

**अमेरिका** के पूर्व राष्ट्रपति एवं वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर दूसरी बार जानलेवा हमला किया गया है एवं इस बार भी वे बच गए हैं तब ऐसे में उनके अच्छे स्वास्थ्य की हर भारतीय कामना करता है।कह सकते हैं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो वे परम मित्रों में से एक है। जानलेवा हमले की 64 दिन में यह दूसरी वारदात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने महिला उम्मीदवार कमला हैरिस चुनाव लड़ रही है तब यह भी कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति ट्रंप के सामने काफी अच्छी है, अत: ऐसे में कयास यह भी लगाया जा रहा है कि अपने लिए अमेरिकियों की सहानुभूति लेने के लिए कहीं यह स्वयं ट्रंप का ही कोई शगुफा तो नहीं।

तब अगर ऐसा भी है तो यह हरकत किसी बड़े खतरे से खाली नहीं कह सकतें है, अगर ट्रंप अमेरिका में एक बार फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर भारत अमेरिका के संबंध एक बार फिर उरूज पर भी पहुंचेंगे इसमें कोई शक नहीं कारण ट्रंप, नरेंद्र मोदी को काफी पसंद करते हैं अत: अमेरिका में एक बार फिर नमो- नमो होने की भी संभावना है। खैर जो भी हो हमारा तो यहां यही कहना है कमला हैरिस जीते या ट्रंप भारत के लिए दोनों के ही राष्ट्रपति बनने से फायदे ही फायदे हैं। **(एमपी, शाजापुर)**

## पहाड़ों का सोना कहलाने वाले बांज पर मंडराता खतरा

**- सुनील कुमार महला**

**प्राकृतिक** वनस्पति, पेड़-पौधों, औषधीय पौधों की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का एक सम्पन्न राज्य है और यहां प्राकृतिक हरियाली देखते ही बनती है। यहां की वनस्पति अक्षत वनस्पति है। अक्षत यानी कि एक प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति। वास्तव में प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति की देन होती है जो कि अपने आप पैदा होती है और जिस पर लंबे समय तक मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है। फसलें, फल और बागान इसके अंतर्गत नहीं आते, हालांकि ये भी वनस्पति ही हैं। उत्तराखंड की जलवायु व मिट्टी अपने आप में अनोखी है और इसमें पेड़-पौधे और विभिन्न वनस्पतियां प्राकृतिक रूप से अपने आप विकास करतीं हैं। ओलियंडर, पॉइन्सेटिया और अमरूद यहां मुख्य पेड़ हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि ये पेड़ राज्य की सीमाओं के भीतर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक और पारिस्थितिक मूल्य रखते हैं। वैसे तो यह पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं लेकिन कुछ प्रमुख प्रजातियों में क्रमश: बांज, बुरांस (उत्तराखंड का राज्य वृक्ष), कांस, देवदार, कुळें, चीड़, पय्यां, अयांर, माळू, ग्वीर्याळ, रंसुळा, कैल, रिंगाळ, सेमल, तोण, डेंकण, भ्योल या भीमल, खड़ीक, गैंठी, पीपळ, खर्सु, मोरु, कण्डाळ, मळसु, भंगेलु शामिल हैं। वैसे उत्तराखंड में देवदार, स्प्रूस और फर जैसे शंकुधारी वृक्षों का प्रभुत्व है। साल, सागौन और ओक जैसे चौड़े पत्तों वाले पेड़ भी यहां प्रमुख हैं। सच तो यह है कि उत्तराखंड भारत के कुछ सबसे विविध और सुंदर जंगलों का घर है। यहां उप-उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर अल्पाइन वनों तक, विभिन्न प्रकार के वनों की एक श्रृंखला है। ये जंगल पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं, साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए संसाधन भी प्रदान करते हैं। वैसे उत्तराखंड उपोष्णकटिबंधीय वन, उपोष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, कोणीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, अल्पाइन वन, अल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान और टुंडा वन समेत कुल आठ प्रकार के वनों का घर है। ओलियंडर, पाइंसेंटिया, लालफ्रैन्जी पैनी, अमरूद, गोल्डन शावर ट्री, काला टिड्डा, रेशमी ओक, पवित्र अंजीर, आड़ू, नीम, मीठी चेरी, नीला जकारांडा, देवदार, पीला ओलियंडर, पपीता, कपूर का पेड़, आर्किड वृक्ष, नोरफोक द्वीप पाइन, अनार और आम यहां के प्रमुख पेड़ हैं। इन सभी के बीच जानकारी देना चाहूंगा कि बांज नामक पेड़ को उत्तराखंड का सोना कहां जाता है। बांज नामक पेड़ का बहुत महत्व है। बाँज या बलूत या शाहबलूत एक तरह का वृक्ष है जिसे अंग्रेज़ी में 'ओक' कहा जाता है। बाँज फागेसिई कुल के क्वेर्कस गण का एक पेड़ है। इसकी लगभग 400 के आसपास किस्में ज्ञात हैं, जिनमें कुछ की लकड़ियाँ बड़ी मजबूत और रेशे सघन होते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसके पेड़ भारत के अलावा अनेक देशों, पूरब में मलयेशिया और चीन से लेकर हिमालय और काकेशस क्षेत्र होते हुए, सिसिली से लेकर उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र तक में पाये जाते हैं। इसकी पहचान इसके पत्तों और फलों से होती है। इसके पत्ते खाँचेदार होते हैं और फल सामान्यत: गोलाकार और ऊपर की ओर नुकीला होता है। नीचे प्याले के ऐसे अनेक सहचक्र शल्क लगे रहते हैं। कुछ बाँज फल मीठे होते हैं और कुछ कड़ुए। कुछ बाँज फल खाए जाते हैं और कुछ से टैनिन प्राप्त होता है, जो कि चमड़ा पकाने में काम आता है। बाँज के फल सूअरों को भी खिलाए जाते हैं। खाने के लिए फलों को उबालकर, सुखाकर और आटा बनाकर केक बनाते हैं। उबालने से टैनिन निकल जाता है। यह सबसे अधिक उपयोग में आने वाला पर्यावरण का अहम् रक्षक पेड़ है। इस पेड़ की उत्तराखंड में कुल पांच प्रजातियां पाई जाती हैं। सच तो यह है कि बांज का पेड़ सदाबहार पेड़ है जो वर्षभर हरा भरा रहता है।

जानकारी मिलती है कि प्राय: 20 वर्ष पुराना होने पर बांज के पेड़ पर फल लगते हैं। पेड़ दो से तीन सौ वर्षों तक जीवित रहता है। इसकी ऊँचाई साधारणतया 100 से 150 फुट और घेरा 3 से 8 फुट तक होता है। कुछ बाँज सफेद होते हैं, कुछ लाल या काले। कुछ बाँजों से कॉर्क भी प्राप्त होता है। सफेद और लाल दोनों बाँज अमरीका में उपजते हैं। भारत के हिमालय में केवल लाल या कृष्ण बाँज उपजता है। बाँज का काष्ठ 900 वर्षों तक अच्छी स्थिति में पाया गया है। काष्ठ सुंदर होता है और उससे बने फर्नीचर उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। एक समय जहाजों के बनाने में बाँज का काष्ठ ही प्रयुक्त होता था। अब तो उसके स्थान पर इस्पात प्रयुक्त होने लगा है। आज मानव कुप्रभावों के कारण बांज के पेड़ शिकार हुए हैं और इसको बीजों को अनेक जंगली पशु खाते हैं और नष्ट करते हैं। विभिन्न कीटों, फंफूद व रोगों के कारण इस वृक्ष पर संकट बना हुआ है। फलियांट, फनियांट, हरिन्ज, रियाज, बांज, सांज बांज, तिलंज, मोरू, तिलोंज, खरसू या खरू बांज की ही विभिन्न प्रजातियां हैं, जो उत्तराखंड में मिलती हैं। पशुओं के भोजन से लेकर, कृषि यंत्रों के निर्माण, मकान निर्माण, ईंधन में बांज का प्रयोग किया जाता है। इस की हरी पत्तियों को पशुओं के चारे के रूप में तथा पत्तियों के गलने पर खाद के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसकी इमारती लकड़ी बहुत काम की मानी जाती है। जीव जंतुओं ही नहीं विभिन्न पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर भी बांज के पेड़ कटने का प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण विकास और संतुलन को बनाए रखने वाले बांज के पेड़ों का संरक्षण आज समय की आवश्यकता है। इसे बचाया जाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

**(फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड)**

*आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्सर बड़े बजट वाले दलों के विज्ञापनों को अधिक दृश्यता देकर उनका पक्ष लेते हैं,अभियान को अमीर राजनीतिक संस्थाओं के पक्ष में झुकाते हैं,जिससे चुनावी निष्पक्षता कम हो जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विभाजनकारी कंटेंट को बढ़ा सकते हैं,जिससे राजनीतिक विचारों का ध्रुवीकरण हो सकता है एवं अधिक खंडित तथा शत्रुतापूर्ण चुनावी माहौल को बढ़ावा मिल सकता है,जिससे रचनात्मक बहस कम हो सकती है।*

## चुनावों में डिजिटल अभियान, झूठे-सच्चे वादों का ऐलान

**- प्रियंका सौरभ**

**गूगल** विज्ञापन पारदर्शिता केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान, राजनीतिक दलों एवं उनके सहयोगियों ने 1 जनवरी से 10 अप्रैल के बीच अकेले गूगल विज्ञापनों पर लगभग 117 करोड़ खर्च किए। डिजिटल अभियान खर्च में यह वृद्धि चुनावों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है, जबकि राजनीतिक दलों के बीच कंटेंट विनियमन तथा निष्पक्षता के बारे में चिंता बढ़ाती है। आधुनिक चुनावों में डिजिटल अभियान एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है, मतदाताओं तक इसकी व्यापक पहुँच है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों सहित लाखों मतदाताओं तक पहुँचने की अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी जनसांख्यिकीय अभियान से वंचित न रह जाए।

वर्ष 2019 के चुनावों के दौरान व्हाट्सएप के व्यापक उपयोग ने राजनीतिक दलों को पूरे भारत में ग्रामीण मतदाताओं से जुड़ने में मदद की, जिससे चुनाव परिणाम काफी प्रभावित हुए हैं। डिजिटल अभियान पारंपरिक मीडिया की तुलना में कहीं अधिक किफायती हैं, जिससे सीमित बजट वाले छोटे लोगों को भी प्रतिस्पर्धा करने एवं मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुँचने की अनुमति मिलती है। वर्ष 2015 के दिल्ली चुनावों में आप की डिजिटल-संचालित रणनीति जैसे उभरते क्षेत्रीय राजनीतिक दल बड़ी पार्टियों की तुलना में न्यूनतम खर्च के बावजूद सफल साबित हुए हैं। डेटा एनालिटिक्स पार्टियों को विशिष्ट मतदाता वर्गों के लिए अनुरूपित संदेश बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे उनके मूल्यों एवं चिंताओं से मेल खाने वाले संदेशों के साथ सही दर्शकों तक पहुँचने की संभावना में सुधार होता है। ब्रेक्सिट सहित वैश्विक चुनावों के दौरान कैम्ब्रिज एनालिटिका की सूक्ष्म-लक्ष्यीकरण रणनीतियों ने दिखाया है कि कैसे लक्षित डिजिटल संदेश मतदाता व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। सोशल मीडिया मतदाताओं के साथ वास्तविक समय पर बातचीत करने में सक्षम बनाता है, जिससे राजनीतिक नेताओं को चिंताओं को तेजी से संबोधित करने, जनता की राय को आकार देने एवं तत्काल प्रतिक्रिया के आधार पर अभियान रणनीतियों को समायोजित करने की अनुमति मिलती है। प्रधानमंत्री की सक्रिय ट्विटर उपस्थिति ने उन्हें अपने पूरे राजनीतिक जीवन में मतदाताओं के साथ सीधा एवं निरंतर संवाद बनाए रखने की अनुमति दी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से सोशल मीडिया, युवा मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो राजनीतिक कंटेंट का ऑनलाइन उपभोग करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे महत्वपूर्ण मतदाता आधार के साथ प्रभावी जुड़ाव सुनिश्चित होता है। वर्ष 2024 के चुनावों में राजनीतिक दलों की इंस्टाग्राम रणनीति विशेष रूप से युवा मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई थी। डिजिटल अभियान, जब जिम्मेदारी से उपयोग किए जाते हैं, तो मतदाताओं को सीधे नीतियों के बारे में सूचित करके, उन्हें सूचित विकल्प चुनने में मदद करके एवं समग्र चुनावी भागीदारी को बढ़ाकर अधिक पारदर्शिता प्रदान कर सकते हैं। वर्ष 2020 के अमेरिकी चुनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के डिजिटल टाउन हॉल ने महामारी प्रतिबंधों के बावजूद मतदाताओं को उनके साथ सीधे बातचीत करने की अनुमति दी। आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्सर बड़े बजट वाले दलों के विज्ञापनों को अधिक दृश्यता देकर उनका पक्ष लेते हैं, अभियान को अमीर राजनीतिक संस्थाओं के पक्ष में झुकाते हैं, जिससे चुनावी निष्पक्षता कम हो जाती है। गूगल के विज्ञापन वैश्विक चुनावों के दौरान उच्च-बजट वाली पार्टियों के पक्ष में पाए गए, जिससे उन्हें मतदाता पहुँच में लाभ मिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विभाजनकारी कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, जिससे राजनीतिक विचारों का ध्रुवीकरण हो सकता है एवं अधिक खंडित तथा शत्रुतापूर्ण चुनावी माहौल को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे रचनात्मक बहस कम हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विभाजनकारी कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है एवं अधिक खंडित, शत्रुतापूर्ण चुनावी माहौल बन सकता है, जो रचनात्मक बहस को कम कर देता है। 2019 में फेसबुक विज्ञापनों पर राष्ट्रीय पार्टियों का भारी खर्च छोटे क्षेत्रीय दलों के बजट से कहीं अधिक हो गया। डार्क विज्ञापनों एवं अत्यधिक लक्षित राजनीतिक संदेशों के उपयोग से नियामकों तथा जनता के लिए यह ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि विशिष्ट मतदाता समूहों को कौन सी जानकारी प्रसारित की जा रही है, जिससे पारदर्शिता कम हो जाती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्सर पर्याप्त तथ्य-जाँच उपायों को लागू करने में विफल रहते हैं, जिससे झूठे दावे जारी रहते हैं एवं संभावित रूप से गलत या जानबूझकर हेरफेर की गई जानकारी के साथ मतदाताओं को गुमराह किया जाता है। भारत के वर्ष 2019 चुनावों के दौरान फर्जी खबरों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करने के लिए व्हाट्सएप की आलोचना की गई, जिसने मतदाताओं की धारणा को प्रभावित किया। उल्लंघनों के माध्यम से मतदाता डेटा का शोषण राजनीतिक अभियानों को व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर लक्षित संदेश भेजकर मतदाताओं को हेरफेर करने की अनुमति दे सकता है, जिससे मतदाता स्वायत्तता से समझौता हो सकता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले ने उजागर किया कि भारत सहित विश्व भर में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए मतदाता डेटा का अनैतिक रूप से उपयोग किया गया था।सरकारों एवं चुनाव निकायों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों को गलत सूचना के लिए जिम्मेदार ठहराने तथा झूठे कंटेंट के प्रसार के लिए दंड लागू करने के लिए सख्त नियम लागू करने चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनियमित खर्च के माध्यम से प्राप्त अनुचित लाभ को रोकने के लिए राजनीतिक दलों को अपने डिजिटल विज्ञापन व्यय का पूरी तरह से खुलासा करने की आवश्यकता होनी चाहिए। डिजिटल विज्ञापन खर्च पर विस्तृत रिपोर्ट अनिवार्य करने से चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित हो सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म को झूठी सूचनाओं की निगरानी एवं हटाने के लिए स्वतंत्र तथ्य-जाँचकर्ताओं के साथ सहयोग करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल सटीक राजनीतिक संदेश ही मतदाताओं तक पहुँचें। राजनीतिक कंटेंट की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष के तथ्य-जांचकर्ताओं के साथ फेसबुक की मौजूदा साझेदारी का विस्तार किया जा सकता है। चुनावी समानता बनाए रखने के लिए, राजनीतिक दलों द्वारा डिजिटल विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली राशि पर सीमाएँ लगाई जानी चाहिए, जिससे अमीर पार्टियों को डिजिटल क्षेत्र पर हावी होने से रोका जा सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिदम को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, कि सभी पार्टियों के राजनीतिक विज्ञापनों को पार्टी के वित्तीय संसाधनों की परवाह किए बिना समान प्रदर्शन मिले। लोकतांत्रिक निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छोटे दलों के विज्ञापनों को बड़े दलों के समान दृश्यता मिले। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों वाला एक केंद्रीकृत डेटाबेस जनता के लिए सुलभ होना चाहिए, जिससे संदेश भेजने में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके एवं गुप्त अभियानों को रोका जा सके। गूगल का विज्ञापन पारदर्शिता केंद्र एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसे सभी राजनीतिक विज्ञापनों पर अधिक व्यापक डेटा की आवश्यकता है। सरकारों एवं डिजिटल प्लेटफॉर्मों को हानिकारक राजनीतिक कंटेंट के प्रसार को रोकने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए सहयोगी ढाँचे के साथ निगरानी को मजबूत करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। डिजिटल अभियान, परिवर्तनकारी होते हुए भी, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निरीक्षण की आवश्यकता है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने जोर दिया था, 'लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए' होना चाहिए। डिजिटल अभियानों में समान पहुँच एवं कंटेंट विनियमन सुनिश्चित करने से लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होंगे तथा डिजिटल युग में चुनावी प्रक्रियाओं की अखंडता बरकरार रहेगी।

(रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)

https://t.me/newspaperpaid

## सम्पादकीय

### कश्मीर घाटी में खत्म होने के कगार पर आतंकी घटना, हकीकत कुछ और ही बता रही कहानी

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को लेकर परस्पर विरोधी बातें सुनने को मिलती रही हैं। सरकार का दावा है कि अब वहां आतंकवाद खत्म होने को है। कुछ दिनों पहले गृह मंत्रालय ने दावा किया था कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद काफी कम हो गया है, अब केवल कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गया है। जल्दी ही उसे समाप्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी वही बात दोहराई है। उन्होंने डोडा से विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही वहां आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक अधिकारी समेत दो सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। सेना के जवाबी हमले में तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया। घाटी में सक्रिय विपक्षी राजनीतिक दलों का आरोप है कि पिछले दस वर्षों में वहां आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। बहुत सारे निरपराध लोग मारे गए हैं, अनेक सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। इससे पहले आतंकवादी घटनाएं इतनी नहीं होती थीं, केंद्र सरकार ने तब स्थानीय लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया था और आतंकी गतिविधियां काफी कम हो गई थीं। मगर सरकार इन बातों को सिरे से खारिज करती है। हालांकि दो वर्ष पहले गृह मंत्रालय ने भी माना था कि विशेष दर्जा खत्म होने और राज्य में कर्फ्यू के दौरान स्थानीय युवाओं की आतंकी समूहों में भर्ती बढ़ी है।

पहले नोटबंदी के समय दावा किया गया था कि इससे आतंकी समूहों की कमर टूट जाएगी। उन्हें वित्तीय मदद मिलनी बंद हो जाएगी। फिर अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने के बाद कहा गया कि इससे दहशतगर्दी पर लगाम लग जाएगी। मगर हकीकत यह है कि करीब दो वर्ष तक सघन तलाशी और कड़ी पहरेदारी के बावजूद आतंकी घटनाओं पर कोई उल्लेखनीय अंकुश लगा नजर नहीं आया। फिर जैसे-जैसे वहां जनजीवन सामान्य बनाने के लिए कुछ ढिलाई दी जाने लगी, दहशतगर्दी एकदम से बढ़नी शुरू हो गई। आतंकवादियों ने अपने हमले के तरीके बदल लिए। कभी वे बाहरी लोगों और कश्मीरी पंडितों पर लक्षित हिंसा करने लगे, तो कभी सेना के काफिले पर घात लगा कर हमला। पिछले पांच वर्षों में थोड़े-थोड़े समय बाद सुरक्षाबलों पर घात लगा कर हमले बढ़े हैं। उन हमलों की समीक्षा से यह भी तथ्य सामने आया कि उनके पास बाहर से अत्याधुनिक हथियार पहुंचने लगे हैं, वे सुरक्षाबलों के सूचना तंत्र में सेंध लगाने के नए तरीके तलाश चुके हैं। ऐसे में यह सवाल बार-बार पूछा जाता रहा है कि आतंकी समूहों को वित्तीय मदद पहुंचाने वालों और बाहर से हथियार वगैरह मुहैया कराने वालों पर शिकंजा कसे जाने के बावजूद उन तक ये चीजें कैसे पहुंच जा रही हैं।

केंद्र सरकार का शुरू से दावा रहा है कि वह घाटी में आतंकवाद समाप्त करके ही दम लेगी। इसके लिए निस्संदेह उसने सख्त कदम भी उठाए, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ कम हो गई। मगर आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं, तो इसके पीछे बड़ा कारण है कि दहशतगर्दों को स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है और वहां के युवाओं को हथियार उठाने से रोका नहीं जा पा रहा।

# विपक्ष पर दबाव का केजरीवाली आतिशी दांव

**अरविंद केजरीवाल साहस के कदम एवं चतुराई की आंख लेकर परम्परागत राजनीति की जंजीरों को तोड़कर आगे निकलते रहे हैं। संभावनाएं की जा रही थी कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अधिक संभावनाएं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाये जाने की थी। क्योंकि क्षेत्रीय दलों में किसी राजनीतिक या कानूनी संकट के चलते परिवार के ही किसी सदस्य को सत्ता की बागडोर सौंप देने परंपरा रही है। ताकि स्थितियां सामान्य होने पर फिर मुख्यमंत्री की गद्दी आसानी से वापस ली जा सके। इसके अनेक उदाहरण है, जिनमें बिहार में चारा घोटाले में घिरने के बाद लालू यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता की बागडोर सौंपी थी।**

ललित गर्ग

अरविंद केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने राजनीति में कुछ मौलिक प्रतिस्थापनाएं की है, बने-बनाये रास्तों पर न चलकर नये रास्ते इजाद किये हैं। वे संकटों को अवसर में बदलने वाले करिश्माई व्यक्तित्व भी हैं। उनकी राजनीति अनेक विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरी रही है, उनके व्यवहार एवं वचनों में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित होते रहे हैं, लेकिन ये ही विरोधाभास उनकी राजनीतिक चमक का कारण भी बने हैं। क्योंकि राजनीति में सब जायज माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिलने से खुद को बंधा महसूस करते हुए उन्होंने इस्तीफे का धारदार दांव चलाकर राजनीतिक जगत में एक हलचल पैदा कर दी। वहीं पार्टी में संभावनाओं भरे अनेक चेहरों के होने के बावजूद उन्होंने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वह वरिष्ठता क्रम में निचले पायदान पर खड़ी थी, लेकिन केजरीवाल ऐसे चौंकाने वाले फैसले पहले भी लेते रहे हैं। लेकिन इस तरह वे जनादेश का मज़ाक भी बनाते रहे हैं तो संवैधानिक स्थितियों की धता भी करते रहे हैं। केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही अपने तरकश से जो तीर चले हैं, उनकी धार एवं तीक्ष्णता को महसूस किया जा सकता है। इन तीरों से हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव समेत अन्य राष्ट्रीय मुद्दों में उलझी भाजपा व कांग्रेस पर केजरीवाल ने मनोवैज्ञानिक राजनीतिक दबाव तो बना ही दिया है। हरियाणा में स्वतंत्र चुनाव लड़ने का निर्णय लेकर उन्होंने सत्ता के गठन में स्वयं को एक ताकतवर मोहरे के रूप में प्रस्तुत करने का चतुराई भरा खेल भी खेला है। दिल्ली में भी उन्होंने अपनी निस्तेज होती स्थितियों को मजबूती दी है।

दरअसल, केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध में आन्दोलन के योद्धा के रूप में वर्ष 2014 के इस्तीफे के दांव की तरह 2015 में आम आदमी पार्टी को मिली भारी जीत का अध्याय दोहरा देना चाहते हैं। लेकिन इस बार की स्थितियां खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होने से खासी चुनौतीपूर्ण व जोखिमभरी हैं। निस्संदेह, यह दांव मुश्किल भी पैदा कर सकता है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। भले ही केजरीवाल अपने को, समय को पहचानने वाला साबित कर रहे हो, लेकिन वे अपने देश को, अपने पैरों की जमीन को एवं राजनीतिक मूल्यों को नहीं पहचान रहे हैं। 'आप' की राजनीति नियति भी विसंगति का खेल खेलती रहती है। पहले जेल जाने वालों को कुर्सी मिलती थी, अब कुर्सी वाले वाले जेल जा रहे हैं। यह नियति का व्यंग्य है या सबक? आप के शीर्ष नेताओं के लिये पहले श्रद्धा से सिर झुकता था अब शर्म से सिर झुकता है। कैसे आप की राजनीति इस शर्म के साथ जनता से मुखातिब होगी और जनता क्या जबाव देगी, यह भविष्य के गर्भ में है। जिन अप्रत्याशित हालात में एवं बहुत कम समय के लिये आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, वे बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के कई उदाहरण हाल के वर्षों में दिखे हैं, लेकिन यह मामला उन सबसे अलग है। पिछले करीब दो साल न केवल आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली सरकार के लिए भी इस मायने में चुनौतीपूर्ण रहे कि एक-एक कर उसके कई बड़े नेता और मंत्री जेल भेज दिए गए। दिल्ली का विकास मुफ्त की संस्कृति की भेट चढ़कर विकास को अवरुद्ध किये हुए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने के बाद संकट और गहराया। इन संकटपूर्ण हालातों में आतिशी ने पार्टी का प्रभावशाली ढंग से बचाव किया। उन्होंने सौरभ भारद्वाज और अन्य साथियों के साथ मिलकर सड़क से लेकर मीडिया तक आम आदमी पार्टी की जंग लड़ी, उससे कार्यकर्ताओं में उनकी एक जुझारू छवि बनी है। ऐसे में, उनसे उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। क्या अतिशी अपने राजनीतिक कौशल से यह पद पाया है या वे केजरीवाल की राजनीति का एक मोहरा-भर बनी है? उनके हिस्से में यह पद तब आया जब पार्टी के दो सबसे बड़े नेताओं-अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया-ने कह दिया कि वे नए सिरे से जनादेश हासिल करने के बाद ही पद पर बैठेंगे। अगर पार्टी जनादेश हासिल नहीं कर पाती तब तो उन्हें पद छोड़ना ही पड़ेगा, अगर पार्टी चुनाव जीतती है तब भी मुख्यमंत्री पद से उनका हटना लगभग तय है। इन स्थितियों में कांटोंभरा ताज पहनकर उनके कामकाज एवं प्रभावी नेतृत्व का क्या औचित्य है? अतिशी एक वफादार एवं जिम्मेदार नेता के रूप में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही है। पार्टी के लिये उनके समर्पण एवं अटूट निष्ठा की मुद्रा विधायक दल की नेता चुने जाने के वक्त भी सामने आयी, जब आतिशी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि वह सिर्फ अगले चुनाव तक पदभार संभाल रही हैं, पार्टी के भीतर किसी नए केंद्र की आशंका को तिरोहित करना तो है ही, कहीं न कहीं यह वरिष्ठ नेताओं की आहत महत्वाकांक्षाओं पर मरहम रखना भी है। आतिशी का यह पहला कार्यकाल है, और किसी गैर-राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की महिला का पांच साल के भीतर यूं मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का यह विरल उदाहरण भी है। अतिशी दिल्ली जैसे सुबे की मुखिया बनी हैं, जिस दिल्ली ने सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जैसी दिग्गज महिला नेताओं का शासन देखा है। कुल मिलाकर, दिल्ली में शुरू हुए आप के इस नए प्रयोग और उसके नतीजों पर सबकी नजरें होंगी। अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव कराने की मांग की है, उनकी यह मांग अस्वीकृत हो गयी है, फिर भी अगले साल फरवरी के पहले पखवाड़े तक दिल्ली में चुनाव कराने होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सोची-समझी रणनीति के तहत ही दिया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को अपनी ईमानदारी के जनमत संग्रह के रूप में दर्शा सकें। उनका मकसद भाजपा सरकार द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकाबला करने तथा खुद को राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार के रूप में दिखा जनता की सहानुभूति अर्जित करना भी है। लेकिन इस तरह की राजनीतिक चतुराई में अगर कोई आधार नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं होती तो दूसरों के लिए खोदे गए खड्डों में स्वयं एक दिन गिर जाने की स्थिति बन जाती है। कुछ लोग इस प्रकार से प्राप्त जीत की खुशी मनाते हैं, कुछ इस प्रकार की हार की खुशी मनाते हैं, जो कभी जीत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गलत तरीकों से प्राप्त जीत से सिद्धांतों पर अडिग रहकर हारना सम्मानजनक होता है। निस्संदेह, जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र हासिल करने की योजना उनकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा जान पड़ती है।

केजरीवाल को अतिशी रूपी दांव से ज्यादा लाभ शराब घोटाले में नाम आने व गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस्तीफा दे देते तो मिलता। ऐसे में, आतिशी के पास अपनी शासकीय छाप छोड़ने के साथ आप की राजनीतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली में निश्चित रूप से उसकी लड़ाई भाजपा के साथ ही कांग्रेस से भी अपनी जमीन बचाने की होगी। दिल्ली के नागरिकों की अपेक्षाओ पर खरा उतरने के साथ-साथ पार्टी की चुनावी नैया पार लगाने की चुनौती तो है ही। जाहिर है, आम आदमी पार्टी उनसे यही अपेक्षा करेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का आलेख लिखे।

## शख्सियत

नरेश चन्द्र
( सेवा निवृत एएसपी )

नमस्कार दोस्तों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं राजस्थान पुलिस की शान एडिशनल एसपी से रिटायर्ड हुए श्री नरेश चन्द्र शर्मा इनका जन्म 16 नवंबर, 1961 को राजगढ़ जिला अलवर में हुआ। पिता स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र शर्मा,वर्ष 1950 में राजस्थान पुलिस मे उप निरीक्षक के पद पर इलाके के प्रथम सब इंस्पेक्टर। राजगढ़, गोविंदगढ़, बांदीकुई में थानाधिकारी रहे। वर्ष 1983 में वृताधिकारी आमेर के पद से रिटायर हुए। मूल निवासी चावा का बास, तहसिल घेवर,जिला अलवर माध्यमिक शिक्षा मानक चौक स्कूल जयपुर,वर्ष 1982 में स्नातक राजस्थान कॉलेज जयपुर, सर्विस में आने के बाद प्राइवेट एम.ए राजस्थान विश्वविद्यालय से किया। इनका जीवन काल शायद ऐसा रहा कि पूरा जीवन ही पुलिस के प्रति समर्पित किया हो। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की शानदार पुलिसिंग का कारण शायद यही रहा उनका प्रोबेशन पीरियड नरेश चन्द्र शर्मा जी के पास रहा। उस समय भरतपुर ये पुलिस इंस्पेक्टर थे। मार्च 1983 में पुलिस विभाग में सहा.उप.निरीक्षक के पद पर भर्ती हुए। 988 में उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति हुई। वर्ष 1990 से 1998 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंह सिंह शेखावत साहब के सुरक्षाधिकारी रहे। वर्ष 1988 से 1999 तक महामहीम राज्यपाल राजस्थान के सुरक्षा में रहे। वर्ष जून 1999 से 2001 तक जयपुर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर रहे जिस समय जयपुर चारदीवारी के बरामदे खाली कराए गए। 2001 में पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हुई। तत्पच्यात पुलिस थाना बाली, सोजत सिटी जिला पाली में एसएचओ। 2004 व 2005 में थानाधिकारी पीपाड़ सिटी जिला जोधपुर ग्रामीण। जनवरी 2006 से जून 2007 तक थानाधिकारी सेवर,जिला भरतपुर। जुलाई 2007 से दिसंबर 2008 तक थानाधिकारी गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर मार्च 2009 से दिसंबर 2010 तक थानाधिकारी अलवर गेट,जिला अजमेर। 2011 से 2013 तक स्टेट कंट्रोल रूम। 2014 से 2015 तक थानाधिकारी । कोतवाली,रूपवास, भुसावर जिला भरतपुर। 2016 में जयपुर विकास प्राधिकरण। 2017 पुलिस उप अधीक्षक पद पर पदोन्नति हुई। वृताधिकारी एससी एसटी,सवाईमाधोपुर, सीओ जीआरपी अजमेर, सीओ सांचौर जिला जालोर। जुलाई 2019 में सीओ सिटी अलवर उत्तर। कोविड महामारी मे विशेष कार्य किया। यहीं से सितंबर 2020 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति पर स्थानांतरण सीआईडी सीबी, जयपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,सुरक्षा सीआईडी एस एस बीए जयपुर पुलिस। सर्विस के दौरान अनेको नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र मिले तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर रहते हुए ही डी जी पी डिस्क से भी नवाजा गया। विशेष उपलब्धि ये रही कि वर्ष नवंबर 1997 में पुलिस निरीक्षक पद की पदौनत्ती परीक्षा में व्यग्तिगत नाराजगी के चलते बोर्ड अधिकारी द्वारा लिखित परीक्षा में फेल कर दिया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में फरवरी 1998 मे विभाग के विरुद्ध 1452/98 रिट दायर कर 19 वर्षो तक न्याय की लड़ाई लड़ी और 19 वर्ष बाद कोर्ट के आदेश पर दुबारा बोर्ड बना और तत्कालीन कॉपीज दुबारा चैक हुई और विभाग ने अपनी गलती स्वीकार कर न्यायालय में पुन: पास का रिजल्ट पेश किया और राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 से उप अधीक्षक की पदोन्नति प्रदान करते हुए करीब पांच लाख रुपए बैक डेट से मिले। इसीके परिणामस्वरूप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सलेक्शन ग्रेड और प्राप्त हुई।राजस्थान पुलिस के इतिहास में यह पहला उदाहरण है कि किसी परीक्षा की कॉपी 19 वर्ष बाद दुबारा बोर्ड से चैक हुई हो। ये इतने शानदार अधिकारी रहे कि इनके नीचे काम करने वाले अन्य अधिकारी व कर्मचारी इनसे प्रसन्न रहते थे। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य व दीर्गायु जीवन की कामना करती है। व्यक्तिगत रूप से मैं इनसे अधिक प्रभावित रहा हूं मुझे बड़े भाई के रूप में इनका सानिध्य प्राप्त होने का सौभागय मिला है।

**जय हिन्द**
**रूपक शर्मा**

## आज का इतिहास

### 19 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- ब्रिटेन और रूस के बीच 1755 में सैन्य संधि हुई।
- विलियम शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का मैनचेस्टर में 1891 को पहली बार मंचन 1891 में किया गया।
- स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो (अमेरिका) के विश्व धर्मसंसद में ऐतिहासिक भाषण दिया।
- न्यूजीलैंड में निर्वाचन अधिनियम 1893 के तहत सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया।
- पहली बार इतिहास में 1907 को कृत्रिम तेल का निर्माण हुआ। इस नये पदार्थ का आविष्कार स्काटलैंड के रसायनशास्त्री जेम्ज़ यांग ने किया था। यांग, पत्थर के कोयले की खदान के मालिक थे और उनके पास एक प्रयोगशाला थी पत्थर के कोयले के आसवन से उन्होंने कृत्रिम तेल बनाने में सफलता प्राप्त की थी।
- हॉलीवुड फिल्मों के स्टार चार्ली चैपलिन को 1952 में अमेरिका वापस आने से रोक दिया गया।
- अर्जेंटीना की सेना और नौसेना ने 1955 में विद्रोह कर राष्ट्रपति जुआन पेरोन को पद से हटाया।
- अमेरिका ने 1957 को नेवादा के रेगिस्तान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
- भारत की उत्तरी सीमा पर 1962 में चीन द्वारा आक्रमण।
- स्कॉट फाहमैन ऑनलाइन संदेश का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति 1982 में बने।
- ब्रिटिश उपनिवेश कैरीबियन द्वीप, सेंट किट्स एवं नेविस 1983 को स्वतंत्र।
- मेक्सिको सिटी में 1985 को भूकंप से भारी तबाही हुई. वहां करीब 10,000 लोग मारे गए थे।

## विशेष आलेख

# भारत की विदेश नीति : मोदी के नेतृत्व में वैश्विक भूमिका और शांति की ओर कदम

अशोक भाटिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 साल पहले देश की सत्ता की कमान संभाली। इन बीते 10 सालों में वह न केवल मजबूत वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं बल्कि मौजूद समय में वह सबसे बड़े संघर्ष के समाप्ति की उम्मीद भी बन गए हैं।ढाई साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध के खात्मे को लेकर पश्चिमी देश भी अब भारत और प्रधानमंत्री मोदी की ओर उम्मीद लगाकर देख रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है युद्ध में शामिल दोनों पक्षों का भारत पर भरोसा। प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों का दौरा किया। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर साफ कर दिया है कि उन्हें शांति समझौते को लेकर भारत की मध्यस्थता मंजूर है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद कहा था कि अगली शांति वार्ता भारत में आयोजित होनी चाहिए।

बताया जाता है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भरोसा है कि अगर भारत शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है तो यह युद्ध रुक सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया था प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि वह शांति के पक्ष में खड़ा है। यह संदेश न केवल रूस-यूक्रेन के लिए था बल्कि यह पूरी दुनिया को यह बताने के लिए है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका क्या होगी ?रूस-यूक्रेन के अलावा अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को भी रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन-पोलैंड यात्रा से लौटे तो 26 अगस्त को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर उनसे बात की। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर चर्चा हो चुकी है। अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि भारत और रूस के बीच संबंध कितने मजबूत हैं, पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने इस संघर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक मजबूती से रूस का साथ निभाया है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार शांति की अपील भी करते रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने साफ-साफ कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है। पिछले हफ्ते रूस दौरे पर गए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत युद्ध रुकवाने के प्लान पर अब तेज़ी से जुट गया है। माना जा रहा था कि डोभाल, राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का 'पीस प्लान' साझा कर सकते हैं। वहीं अगर पुतिन की ओर से सहमति बन जाती है तो फिर आने वाले दिनों में इसे लेकर कोई बड़ी कवायद शुरू होती नजर आ सकती है।खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर में होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए मॉस्को जा सकते हैं। ह्न अजित डोभाल से मुलाकात के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव भी रखा है, लिहाजा सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री मोदी वाकई इस जंग को रुकवाने में बड़ी और सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के अलावा भारत मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयासों में भी अहम भूमिका निभा सकता है।

मिडिल ईस्ट के कई इस्लामिक मुल्कों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं।श्च, कतर, सऊदी अरब और ईरान जैसे इस्लामिक मुल्क हों या इजराइल सभी के साथ भारत के रिश्ते समय के साथ बेहतर और मजबूत होते जा रहे हैं।पिछले साल नवंबर में दिल्ली पहुंचे अरब देशों के राजदूतों ने मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण माना था, तो वहीं सोमवार को इजराइल के नए राजदूत रिवेन अज़ार ने बड़ा बयान दिया है, निजी अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यह भारत पर निर्भर करता है कि वह गाजा युद्ध के समाधान के लिए किस हद तक शामिल होना चाहता है। दरअसल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो भारत उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले इस आतंकी हमले की निंदा की थी। हमले के ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इजराइल के लिए भारत कितना अहम है। वहीं पिछले महीने नेतन्याहू के साथ फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष को खत्म करने लिए बातचीत और कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील की।फिलिस्तीन के नजरिए से देखा जाए तो भारत ने फिलिस्तीन-इजराइल विवाद में हमेशा से 'टू स्टेट' समाधान का समर्थन किया है। भारत आजाद फिलिस्तीन का समर्थक रहा है और वर्षों से इसके फिलिस्तीन के साथ राजनयिक संबंध हैं। करीब एक हफ्ते पहले भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अबू अल-हैजा ने भी शांति के लिए भारत पर भरोसा जताया, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन भी मध्यस्थता के लिए भारत जैसे दोस्त की तलाश में है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति में काफी बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने इन 10 सालों में कई ऐसे देशों की यात्रा की जहां कभी कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था, इससे एक ओर भारत के उन देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए तो वहीं दूसरी ओर विश्व पटल पर भारत की छवि विश्वबंधु वाली बनकर उभरी है।पिछले साल अगस्त में प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत को लेकर 23 देशों में सर्वे किया। भारत को लेकर इन देशों का रुख सकारात्मक रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल समेत 9 देशों में 50 फीसदी से ज्यादा लोग भारत को लेकर अनुकूल दृष्टिकोण रखते हैं।

## आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताए और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

### मेष

आपका आज का दिन अनुकूलता से भरा रहेगा। जीवनसाथी के साथ आप निकटता के क्षण का आनंद उठा सकेंगे। दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

### वृष

आप का दिन अस्वस्थता और चिंता में गुजरेगा। सर्दी, कफ और बुखार आपको हो सकता है। किसी का भला करने की जगह आज अपने काम में ही व्यस्त रहें। किसी से पैसों का लेन-देन न करें। जमीन और संपत्ति के काम आज ना ही करें।

### मिथुन

किसी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय आज ना लें। चिंता में वृद्धि होगी। अधिक लाभ के लालच में आपकी हानि हो सकती है। धन वृद्धि तथा पदोन्नति होने के योग हैं। व्यापार के लिए किए गए सौदे में सफलता मिल सकती है।

### कर्क

परिजनों से उपहार मिल सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सांसारिक जीवन आनंदमय रहेगा। आज आप धार्मिक काम और पूजा-पाठ में व्यस्त रहेंगे। मंदिर या किसी धार्मिक आयोजन में जाने का प्रसंग बन सकता है। परिजनों के साथ वाद-विवाद हो सकता है।

### सिंह

नौकरी में सिद्धि और सफलता मिलेगी। ननिहाल पक्ष की तरफ से कोई समाचार मिलेगा। आर्थिक लाभ की संभावना रहेगी। सहकर्मियों और अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा। आप के गृहस्थ जीवन में शांति एवं आनंद का वातावरण होगा।

### कन्या

परिवार में झगड़े के वातावरण से खिन्नता होगी। शरीर में ताजगी और स्फूर्ति का अभाव होगा। रिश्तेदारों से मनमुटाव हो सकता है। छाती में दर्द या कोई विकार हो सकता है। चैन की नींद नहीं आएगी। मानहानि की आशंका बनी रहेगी। वाणी पर संयम रखें।

### तुला

भागीदारों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। उत्तम भोजन और वस्त्र आभूषण तथा वाहन की प्राप्ति होगी। घर में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा। सुखदायक घटनाएं घटेंगी। कार्य में यश और सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य बना रहेगा।

### वृश्चिक

आज आपको हर काम संभलकर करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। स्वास्थ्य बिगड़ने से आकस्मिक खर्च आ सकता है। ईश्वर-स्मरण तथा आध्यात्मिकता आपको शांति प्रदान करेगी।

### धनु

नए संपर्क से आपको लाभ होगा। आज का दिन शुभ तथा अनुकूलता से भरा होगा। ऑफिस में सहकर्मचारी तथा अधिकारी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सामाजिक दृष्टि से आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। पदोन्नति के योग हैं।

### मकर

साहित्य एवं कला के प्रति आज आपकी रुचि रहेगी। काल्पनिक दुनिया में आप सैर करेंगे। दोस्तों के साथ समय अच्छा गुजरेगा। तार्किक एवं बौद्धिक चर्चा से दूर रहें। आज आप का शारीरिक स्वास्थ्य और मनोदशा अच्छी नहीं होगी।

### कुंभ

आज आप यात्रा प्रवास टालें, क्योंकि पेट संबंधी बीमारी और समस्या हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य और पढ़ाई की चिंता बनी रहेगी। किसी काम में सफलता नहीं मिलने से मन व्याकुल रहेगा। क्रोध की भावना पर संयम रखें।

### मीन

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। बीमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। दफ्तर में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रों से मुलाकात होगी और महिलाओं को मायके से अच्छे समाचार मिलेंगे। धन लाभ होगा।

https://t.me/AANewsPaperGroup

## प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

### सरकार के सौ दिन

**प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी** की सरकार ने सौ दिन में काफी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, हालांकि उसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने अपने कार्यकाल के सौ दिन पूरे कर लिए हैं। सरकार लगातार 'न्यू इंडिया' का अपना दृष्टिकोण आगे बढ़ा रही है जो विकास, वैश्विक नेतृत्व तथा समावेशी प्रगति से संचालित है। लेकिन प्रशासनिक जटिलताओं तथा विकसित होते राजनीतिक परिदृश्य से कुछ नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं जिन पर सरकार सावधानी से ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोटेतौर से अपनी पुरानी कैबिनेट बनाए रखी है। तीसरे कार्यकाल में पहले दो कार्यकालों की तुलना में भाजपा की सहयोगियों पर निर्भरता थोड़ी बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद नीतियों में निरंतरता बनी हुई है। सरकार ने लचीलापन दिखाते हुए 'लेटरल इंट्री' तथा 'प्रसारण विधेयक' पर गहन विचार-विमर्श का फैसला किया है। मोदी के तीसरे कार्यकाल की एक प्रमुख उपलब्धि भारत की वैश्विक पहचान में लगातार विस्तार है। यूक्रेन और रूस की उनकी हाई-प्रोफाइल यात्राओं ने प्रशंसा प्राप्त की है जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों पक्षों से 'एकसाथ बैठने और बातचीत करने' का सुझाव दिया था। इसके साथ ही सिंगापुर और ब्रूनेई की उनकी यात्रा से भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट' पहल को बल मिला है। वास्तव में सरकार ने अपनी विदेश नीति मजबूत करने के साहसी कदम उठाए हैं जिसमें अमेरिका, रूस और चीन के साथ संतुलन बनाना शामिल है।
पहले सौ दिन में सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूर किया है जो सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाईअड्डों पर केन्द्रित हैं। रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ा कर 11.11 लाख करोड़ किया गया है। 9.3 करोड़ किसानों को 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपये वितरित करने के साथ ही कृषि क्षेत्र में प्रगति के उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा एमएसपी वृद्धि से 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा। दूसरी और तीसरी श्रेणी वाले शहरों में स्टार्टअप की सहायता के लिएए 'जेनेसिस' कार्यक्रम शुरू किया गया है तथा युवा रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज पेश किया गया है जिससे पांच साल में 41 मिलियन नौजवान लाभान्वित होंगे। एक करोड़ से अधिक 'लखपती दीदियां' बनने के साथ महिला सशक्तीकरण को गति मिली है। सुरक्षा मोर्चे पर त्रिपुरा में एक शांति समझौता किया गया है तथा 'समन्वय' प्लेटफार्म व 'साइबर फ्राड मिटिगेशन सेंटर' जैसे कदम साइबर अपराधों का मुकाबला करने के लिए उठाए गए हैं। वास्तव में मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के अंत में ही अगली सरकार के सौ दिन का रोडमैप तैयार कर लिया था और सरकार अब उस पर तेजी से आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार संसद से 'एक देश एक चुनाव' तथा 'वक्फ संशोधन विधेयक' पास कराएगी। 'एक देश एक चुनाव' की रूपरेखा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने बनाई थी। विपक्ष की आलोचनाओं और आशंकाओं के बावजूद राजग के प्रमुख घटकों जदयू और टीडीपी ने इसका समर्थन किया है। नीतीश कुमार और चंद्र बाबू नायडू का मानना है कि देश में बार-बार चुनाव होने से प्रगति में बाधा आती है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए अनेक संविधान संशोधनों की आवश्यकता होगी, लेकिन सरकार का विश्वास है कि वह इसमें सफल होगी। पहले सौ दिन के कामकाज से स्पष्ट है कि मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में अभूतपूर्व तेजी और दृढ़ता से काम करेगी जिसका वादा उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किया था।

# म्यांमार में सैनिक शासन पर संकट

**म्यांमार में पहली बार सैनिक शासक शक्तिशाली नस्ली सैन्य संगठनों तथा जन रक्षा बलों के गठबंधन के मुकाबले में पीछे हट रहे हैं। ऐसे में भारत को सतर्क और सावधान रहना होगा।**

**अशोक के. मेहता**
(लेखक, सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं)

म्यांमार में पहली बार सैनिक शासक शक्तिशाली नस्ली सैन्य संगठनों तथा जन रक्षा बलों के गठबंधन के मुकाबले में पीछे हट रहे हैं। 3 सितंबर को मांडले में सरकारी सेनाओं के सेंट्रल कमांड के मुख्यालय 'पैलेस आफ मांडले' पर पहली बार राकेट हमला हुआ। मांडले म्यांमार में राजधानी यंगून के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सैनिक शासकों के खिलाफ जन-विद्रोह व नस्ली सेनाओं के सामने दक्षिण पश्चिमी राखीन प्रांत में जल्द ही सैनिक शासन समाप्त हो सकता है। इस कारण दो रणनीतिक बंदरगाह भी विद्रोहियों के कब्जे में आ सकते हैं जिनमें से सिटवे को भारत को तथा कायुकफू को चीन को पट्टे पर दिया गया था। इस प्रकार सैनिक शासक के कब्जे में केवल मानुंग ही बचेगा। इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि अतीत में म्यांमार में सैनिक विद्रोह कभी विफल नहीं हुए थे।

म्यांमार के पास दक्षिणपूर्व एशिया में सबसे बड़ी सेना है और वह अतीत में भी विद्रोहों से निपटती रही है। 1932 के बाद से थाईलैंड में रिकार्ड 32 सैनिक विद्रोह हुए हैं और इस दृष्टिकोण से वह कुख्यात है। इसके लगभग चार साल बाद से जनरल मिन आंग हिलांग नीत सैनिक शासक म्यांमार में युद्ध कर रहा है और पराजय की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार उसकी लड़ाई बौद्ध भिक्षुओं या सिविल सोसाइटी के बजाय सुसंगठित बलों से हो रही है। यह 'इथनिक आर्म्ड आर्गेनाइजेशन्स'-ईएओ, स्थानीय मिलिशिया तथा नए जन-रक्षा बल के खिलाफ युद्ध कर रहा है जिसका जन्म सत्ता से बेदखल की गई नेता आंग सान सूकी की 'नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी' से हुआ है जो स्वयं को 'नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट'-एनयूजी कहती है। ये म्यांमार में सैनिक शासक का मुकाबला करने वाले प्रतिरोधी बल हैं।

म्यांमार में सैनिक शासक अब तक विद्रोहियों से निपटने तथा विद्रोहों को कुचलने में सफल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने युद्धविराम समझौतों के माध्यम से स्वायत्ता या स्वतंत्रता की घोषणा की है। म्यांमार की सेना जल-थल-नभ, यानी तीनों अंगों वाली सेना है और यह विद्रोहों से निपटने में माहिर है। ऐसे में सैनिक शासक का पीछे हटना आश्चर्यजनक लगता है। सैनिक शासक को युद्धभूमि में भयानक नुकसान हुए हैं। उसने लगातार अपने कब्जे वाला क्षेत्र खोया है तथा बड़ी संख्या में हताहत सैनिकों के कारण अब उसकी सेना लड़ाई से थक गई है। अपनी ही जनता के खिलाफ लड़ने के कारण सैनिकों और जनरलों की 'सोच' पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

ऐसे में सेना के भीतर से अपने शासकों के खिलाफ विद्रोह की संभावना लगातार मजबूत हो रही है। विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार, सैनिक शासन अपना 70 प्रतिशत क्षेत्र खो चुका है। हालांकि, प्रतिरोधी बलों का उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा नहीं है जो सैनिक शासन ने खोया है क्योंकि उनके पास क्षेत्र को अपने कब्जे में लगातार बनाए रखने की क्षमता नहीं है।

लेकिन प्रतिरोधी बलों का उन प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा है जो सीमाओं से सटे हैं और जिनको सैनिक शासन को छोड़ना पड़ा है अथवा वहां से उसके सैनिक भाग गए हैं। सैनिक शासक वर्तमान समय में सैनिकों की कमी का अनुभव कर रहे है और इस कारण वे व्यापक रूप से विनाशकारी हमले करते हुए 'स्कार्चड अर्थ' नीति पर काम कर रहे हैं। इसमें तोपखाने, हेलीकाप्टरों व विमानों से भारी बमबारी शामिल है। इस प्रकार यूएनएचआरसी के वोल्कर टोल्कर के अनुसार वे अपनी पराजय से बचने के लिए नरसंहार कर रहे हैं। इस कारण लगभग 400,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और उनमें से बहुत से सीमायें पार कर बांग्लादेश, भारत, चीन और थाईलैंड चले गए हैं। उत्तरी शान प्रांत में सैनिक शासन को चीन के साथ व्यापार मार्ग छोड़ने पड़े हैं।

इसके साथ ही थाईलैंड सीमा पर स्थित म्यावाडी में करेनी नेशनल आर्मी का नियंत्रण है। इसके साथ ही सैनिक शासक विद्रोहियों या पीडीएफ का बांग्लादेश और मिजोरम से सटे चिन राज्य तथा मणिपुर सीमा से सटे सैगांग क्षेत्र पर कब्जा है। चिनलैंड में रहने वाले कुकी-जो-चिन नस्ली रूप से मिजो के समान हैं। चीनियों के राखीन राज्य में सक्रिय अराकान सेना के साथ सक्रिय संबंध हैं। यह क्षेत्र भारत की मल्टी-मोडल कलादान नदी के सामने है और राखीन में भारत द्वारा संचालित सिट्वे बंदरगाह को जोड़ती है। सिट्वे बंदरगाह परियोजना भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार म्यांमार के सैनिक शासक को चिन, राखीन, सैगांग व मागवे से पीछे धकेला गया है। यह क्षेत्र भारतीय सीमा से सटा है। अत: वर्तमान स्थितियों को देखते हुए नई दिल्ली को वहां नए सत्तारूढ़ बलों से संपर्क करना चाहिए। लेकिन यह समस्या का कारण भी बन सकता है क्योंकि चीनी इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में उथलपुथल का प्रभाव मणिपुर पर पड़ सकता है जो वर्तमान समय में अंतर-नस्ली टकराव का सामना कर रहा है।

सितंबर के प्रारंभ में विद्रोह का सामना कर रहे जनरल हिलांग ने प्रतिरोधी बलों द्वारा कब्जा किए क्षेत्रों में रहने वाले सिविलियनों को चेतावनी दी थी कि वे जल्द ही क्षेत्र पर कब्जे के लिए जवाबी हमला करेंगे। उन्होंने घोषणा की थी कि शान राज्य में सक्रिय 'थ्री ब्रदरहुड एलायंस' एक आतंकी संगठन है। इसमें सेना की सम्मानित नार्थईस्ट कमांड पर कब्जा करने वाली अराकान आर्मी शामिल है जिसने शान राज्य में लाशियो पर कब्जा किया है और अब उसके हमलों से मांडले में सेंट्रल कमांड मुख्यालय भी खतरे में पड़ गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सैनिक शासक अनेक मोर्चों पर कहां तक लड़ सकेंगे। जनरल हिलांग ने लगातार आपातकाल बढ़ाया है तथा वे चुनावों की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं लगता है। उन्होंने सैनिक शासन समर्थक देशों जैसे आशियान के लाओस से सहायता लेने से इनकार कर दिया है जो वर्तमान समय में इस संगठन का अध्यक्ष है। इसके साथ ही उन्होंने पीडीएफ और ईएओ के साथ संवाद शुरू करने के कंबोडिया और थाईलैंड के प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिए हैं। उनको लगता है कि वे अभी भी लाभ की स्थिति में हैं। देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, इसलिए युद्ध अनिश्चित काल तक नहीं चलाया जा सकता है। चीन ने लगातार सैनिक शासक तथा उत्तर और पश्चिम में कुछ ईएओ को समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन और रूस सैनिक शासन को हथियारों की सप्लाई के मुख्य स्रोत हैं, हालांकि भारत ने भी उसे गैर-घातक हथियार दिए हैं। म्यांमार की सेना में टैंक, तोपखाना और छोटे हथियार चीनी हैं। यही स्थिति परिवहन और लड़ाकू विमानों की है। इसी प्रकार नौसेना को भी चीन हथियार दे रहा है, जबकि भारत ने कुछ तटरक्षक पोत दिए हैं।

रूसी मिग 29 व एसयू 30 की मरम्मत एचएएल में होती है और भारत ने उसे हवाई ईंधन भी दिया है। नई दिल्ली ने युद्धविराम तथा लोकतंत्र की वापसी का आह्वान किया है, पर सैनिक शासक को उसका समर्थन जारी है। भारत ने दो दशक पहले सैनिक शासक के बजाय एनएलडी का समर्थन किया था जिससे चीन का उभार हुआ। भारत ने इससे सबक सीखा। हालांकि बीजिंग के साथ सैनिक शासक के संबंध भी उतार-चढ़ाव वाले हैं, पर निकटता व अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व के कारण वह उसका समर्थन लेने को मजबूर है। बदलती हुई जमीनी स्थितियों को देखते हुए भारत को अपनी नीति की समीक्षा करने के साथ सीमान्त क्षेत्रों पर नियंत्रण करने वाले बलों से संपर्क करना चाहिए। मणिपुर में स्थिति सुधारने के लिए अराकान आर्मी तथा चिनलैंड अधिकारियों के साथ कामकाजी संबंध होने चाहिए।

भारत को बमबारी के कारण अपने घरों से पलायन को मजबूर लोगों के लिए मानवीय सहायता के गलियारे बनाने पर विचार करना चाहिए। भारत आशियान पड़ोसियों के साथ अपनी 'एक्ट ईस्ट' नीति पर लगातार जोर दे रहा है, लेकिन इसका क्रियान्वयन म्यांमार से थाईलैंड को जोड़ने वाले 'ट्राईलैटरल हाईवे' को कारगर बनाने तथा सिट्वे बंदरगाह से पलेटवा व मिलोराम कें बीच कलादान नदी परियोजना को अमल में लाने से ही संभव होगा। भारत के पूर्वी व पश्चिमी सिरे तथा खासकर पूर्वी क्षेत्र बांग्लादेश व म्यांमार के बीच होने के कारण संकटग्रस्त है। ऐसे में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से पैदा खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

# आजीवन चलती है सीखने की प्रक्रिया

**जीवन में शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। हर अनुभव हमारी समझ को आकार देता है**

**ब्रह्मकुमार निकुंज**
(लेखक आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

जब से हम पैदा होते हैं, तब से लेकर मरने तक, हम जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। चाहे हम चाहें या न चाहें, हम सीखना बंद नहीं कर सकते क्योंकि सीखने की प्रक्रिया के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा पूरा जीवन अनुभवों का एक समूह है और बदले में, एक शिक्षा है, जहां हम सभी हर पल और हर जगह सीखने की मुद्रा में रहते हैं। चेतन प्राणी होने के नाते, इंद्रियों के होने के कारण, जिन्हें ज्ञान के पांच द्वार भी कहा जाता है, हम अपने स्वभाव से ही धारणा बनाए बिना नहीं रह सकते।

हमारे कान हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए हम लगातार सुनते रहते हैं। हमारे कानों से हमारे दिमाग तक पहुँचने वाले शब्द ऐसे होते हैं जैसे हम लगातार सबक लेते रहते हैं। इसी तरह, हम पूरी दुनिया को अपनी आँखों से देखते हैं, जिससे हम अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ें सीखते हैं। हमारी त्वचा या स्वाद कलिकाओं के माध्यम से हमें जो विद्युत आवेग प्राप्त होते हैं, वे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं जो हमारे लिए एक तरह की सीख भी है। हालाकि, हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि सीखने की उपरोक्त सभी प्रक्रियाएँ हमारे मस्तिष्क में मौजूद जागरूकता या चेतना द्वारा होती हैं, जिसके बिना सीखना असंभव है।

एक बार जब हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे जीवन का शिक्षा चरण आखिरकार खत्म हो गया है और अब समय आ गया है कि हम दुनिया में जाकर सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करें। लेकिन क्या यह बहुत ही सामान्य और अजीब विचार नहीं लगता? कि हमें अपने जीवन का केवल एक चौथाई हिस्सा सीखने के लिए समर्पित करना चाहिए, और फिर हमें अपने जीवन के बाकी हिस्से में बस अपनी उपलब्धियों पर आराम करना चाहिए? अच्छा!! ऐसा कहा जाता है कि सीखने से दिमाग कभी नहीं थकता, तो हम औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने तक सीखने की प्रक्रिया को क्यों सीमित रखते हैं? सिर्फ़ इसलिए कि आपने अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी कर ली है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी शिक्षा समाप्त हो गई है!

यह एक बहुत ही गलत विचार है, लेकिन दुर्भाग्य से, हममें से अधिकांश लोगों ने इसे अवचेतन रूप से आत्मसात कर लिया है। ? याद रखें!! केवल एक मृत शरीर ही सीखने की प्रक्रिया में भाग लेना बंद कर देता है, न कि वे जो जीवन के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। हमारा जीवन अनुभवों की एक श्रृंखला है, जिनमें से प्रत्येक हमें प्रबुद्ध बनाता है, भले ही कई बार इसे महसूस करना कठिन हो।

हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो असफलताएँ और दुख सहते हैं, वे हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसलिए हमें हमेशा हर चीज के बारे में कुछ न कुछ सीखना चाहिए और हर चीज के बारे में कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जीवन की यात्रा के दौरान हम लगातार कुछ ऐसे सबक सीखते रहते हैं, जिनके परिणामस्वरूप हमारे कर्मों के अनुसार संस्कार बनते हैं। इसलिए अगर हम यह स्पष्ट रूप से जानते हैं कि सीखना अपरिहार्य है और हम हमेशा अच्छी या बुरी चीजें सीखते रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अच्छे या बुरे संस्कार बनते हैं, जो हमें खुशी या दुख देते हैं, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे पास सीखने के लिए समय नहीं है या कोई रुचि नहीं है। इसी तरह अगर हम जानते हैं कि हमारे संस्कार हमारे जन्म-जन्मांतर के साथ चलते हैं, तो हम अच्छी चीजें सीखने और बुरी चीजों को छोड़ने में अधिक सावधान रहेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा अमृत है जो हमें स्वस्थ मन और शरीर के साथ-साथ एक स्थायी फलदायी जीवन दे सकता है।

हम सभी को प्रबुद्ध होने की आवश्यकता है और हमें अपने विचारों, वाणी और कार्यों की गुणवत्ता में तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है। चूंकि हम चाहकर भी सीखने से बच नहीं सकते, तो फिर हम अपने अंदर नैतिक मूल्यों, सद्गुणों या अच्छे गुणों को क्यों नहीं अपनाते, ताकि हम पूर्णता की ओर प्रगति कर सकें? हम यह कहकर कि हमारे पास समय नहीं है या हमारी कोई रुचि नहीं है, बेकार के बहाने बनाकर क्या हासिल करते हैं? हमें किसमें रुचि है? क्या हमें अपने पतन, क्षय या विनाश में रुचि है? बुराइयों, बुराइयों और कीचड़ के दलदल में डूबते-उतराते रहना है? याद रखें!! हम जितना विलंब करेंगे, हमारी स्थिति उतनी ही खराब होगी और हमारे लिए अपने तरीकों को सुधारना उतना ही मुश्किल होगा।

जैसा कि पहले कहा गया था, सीखने की प्रक्रिया निरंतर और निरंतर होती है और इसलिए किसी ने सही कहा है कि हम हर दिन सीखते हैं और अहंकार और इस धारणा को त्याग देते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। इसलिए हम इसे रोक नहीं सकते, भले ही हम अपनी पूरी कोशिश करें, अपनी पूरी ताकत लगा दें। तो क्यों न हम सतर्क रहें और सही रास्ते पर चलें जो हमें जीवन की त्रासदियों, आघातों, तनावों और उथल-पुथल से बचाए? इसका जवाब हमारे भीतर है।

## आप की बात

### केजरीवाल का दांव

**अरविंद केजरीवाल** को अंतत: समझ में आ ही गया कि बिना अधिकारों के मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। यदि यही समझ अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से पहले आ जाती तो उनकी छवि खराब न होती। ईमानदारी से राजनीति करने की शपथ लेने वाले केजरीवाल को अनेक अवसरों पर अपनी ही शपथ झूठी सिद्ध करनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल का आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाने का दांव भले ही आम आदमी पार्टी-आप को अंदरूनी कलह से बचाने में सफल हुआ हो मगर आतिशी की पारिवारिक पृष्ठभूमि गंभीर सवालों के घेरे में है। वैसे भी दिल्ली में आप की विश्वसनीयता घटी है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री दिल्ली का क्या भला कर पाएगी, यह सर्वविदित है। सवाल यह भी है कि आम आदमी के रूप में सत्तासुख न भोगने का दम भरने वाल मुखिया केजरीवाल क्या करोड़ों की हवेली का राजसी ठाठ बाट छोड़कर दो कमरों के भवन में रहने हेतु पहल करेंगे। पिछले एक दशक से देश अरविंद केजरीवाल के अनेक चेहरे देख चुका है। केजरीवाल के इस दांव से दिल्ली की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। देखना होगा कि केजरीवाल हरियाणा तथा दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी इस नौटंकी या दांव का कितना लाभ उठा पाएंगे।

– **सुधाकर आशावादी,** मेरठ

### आतिशी का भविष्य

**दिल्ली** के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अरविंद केजरीवाल के फैसले ने एक स्तर पर लोगों को चौंकाया जरूर है। मगर समझदार लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जिन शर्तों पर जमानत दी है। उसके बाद वे मात्र आम आदमी बन कर रह गए। अब इस्तीफा देकर उन्होंने आतिशी मर्लेना को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब मर्लेना न लिखने वाली आतिशी के माता-पिता ने यह नाम मार्क्स और लेनिन का संक्षिप्तीकरण कर दिया था। भाजपा ने यह तथ्य पूरी मजबूती से उठाया है कि आतिशी मर्लेना के परिवार ने संसद पर हमले की योजना बनाने वाले अफजल गुरु का न केवल समर्थन किया था, बल्कि उनके पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया था। भाजपा यह मांग कर सकती है कि आतिशी इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की चाल चली, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उनकी सारी कुटिलताएं हर बार जनता को भ्रमित करने में सफल होंगी। यदि वे दिल्ली में जल्दी चुनाव करवाना चाहते हैं तो आसानी से विधानसभा भंग करके नए चुनाव के रास्ते खोल सकते हैं। मगर वह इसके लिए केंद्र से मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि आतिशी मर्लेना का भविष्य कैसा रहेगा।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

### बलात्कार की सजा

**जघन्य अपराधों** की सजा के प्रति आम आदमी की विचारधारा उचित दंड की रहती है, मगर कई बार उम्र के बहाने अपराधी को उस अनुपात में सजा नहीं दी जाती। लेकिन अब न्यायालय का सख्त रवैया उचित सजा की राह प्रशस्त करेगा। एक नाबालिग को 4 वर्ष की बच्ची के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार करने पर 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका इस कठोर टिप्पणी के साथ खारिज कर दी गई कि नाबालिग है तो क्या दुष्कर्मी से उदार रवैया बरता जाना चाहिए? उच्च न्यायालय का यह फैसला उचित लगता है। निश्चित तौर पर इंदौर का यह मामला अपराधियों पर नकेल की नजीर बन सकता है। वाकई यह चिंता का विषय है कि अपराधी को सजा के समय उसके नाबालिग होने की दुहाई देकर रहम की अपील की जाती है, मगर पीड़िता के अबोध होने और उसके साथ क्रूरता के सवाल पर कोई कठोर सजा की दलील नहीं दी जाती। समय आ गया है कि देश की संसद निर्भया कांड के लगभग एक दशक बाद और पश्चिम बंगाल के अभया कांड के बाद बलात्कार की सजा पर कठोरतम कानून बनाए तथा नाबालिगों को छूट का प्राविधान यथासंभव समाप्त करने अथवा उसे अधिकाधिक सीमित करने की व्यवस्था करे।

– **अमृतलाल मारू,** इंदौर

### मोदी का चुनाव प्रचार

**प्रधानमंत्री मोदी** ने चुनावी शंखनाद करते हुए माहौल भाजपा के पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए जहां राहुल गांधी को साढ़े आठ हजार रुपए की मासिक सौगात पर घेरा, वहीं कांग्रेस को दलित एवम ओबीसी आरक्षण विरोधी करार दिया है। प्रधानमंत्री ने नई पेंशन योजना, 24 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जोरदार ढंग से रखा है। परिवारवाद पर भी मोदी ने क्षेत्रीय और अन्य दलों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कश्मीर के दौरे में प्रधानमंत्री ने सभी विपक्षी दलों को परिवारवाद, नफरत वाली राजनीति और आतंकवाद पर चुप्पी साधने वाली पार्टी बताया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इस बार यहां विपक्षी दल भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। परिणाम चाहे जो भी हो लेकिन यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि दशकों बाद जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। इसका सभी भारतीयों को स्वागत करना चाहिए। जम्मू कश्मीर व हरियाणा में अधिकाधिक मतदान लोकतंत्र को मजबूत करेगा।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव**, दिल्ली

**पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से**
**responsemail.hindipioneer@gmail.com**
**पर भी भेज सकते हैं।**

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

Want to get these Newspapers Daily at earliest

1. AllNewsPaperPaid
2. आकाशवाणी (AUDIO)
3. Contact I'd:- https://t.me/Sikendra_925bot

Type in Search box of Telegram
@AllNewsPaperPaid And you will find a Channel
Name All News Paper Paid Paper join it and receive
daily editions of these epapers at the earliest

Or you can tap on this link:

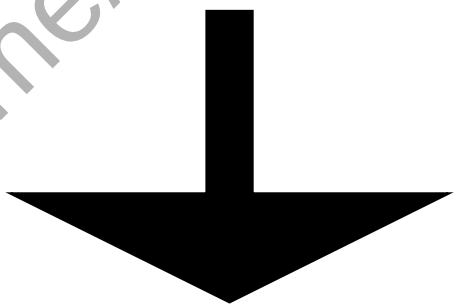

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid